बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 107

कम हो सरकारी व्यय पर निर्भरता

महामारी के बाद के समय में सरकार का पूंजीगत व्यय वृद्धि का अहम कारक रहा है। यही वजह है कि उद्योग जगत से ऐसे सुझाव प्राप्त हुए हैं कि केंद्र सरकार को चालू वर्ष के आने वाले पूर्ण बजट में आवंटन और अधिक बढ़ाना चाहिए। बहरहाल, सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय की मदद से वृद्धि को गति देने की अपनी सीमाएं हैं। मुख्य तौर पर इसकी दो वजह हैं। पहली वजह, सरकार को धीरे-धीरे राजकोषीय घाटे को कम करके प्रबंधनयोग्य स्तर पर लाना होगा। दूसरी बात, खपत के मामले में भी व्यवस्थित क्षमता की अपनी सीमा है। अधिक व्यापक तौर पर देखें तो बढ़ता पूंजीगत व्यय अपने आप में एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पूंजीगत व्यय उत्पादन में इजाफा करेगा लेकिन लाभ उस स्थिति में अधिक होंगे जबकि परियोजनाओं का चयन गुणवत्ता और क्षमताओं के आधार पर किया जाए। ऐसे में संतुलन कायम करना जरूरी है। केंद्र सरकार जहां आवंटित राशि खर्च करती रही है, वहीं राज्य इसमें पीछे हैं। इससे खपत क्षमता की सीमाएं उजागर होती हैं।

हाल ही में इसी समाचार पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा 25 राज्यों के प्रारंभिक आंकड़ों ने यह दिखाया कि 2023-24 में उन्होंने बजट में आवंटित कुल पूंजीगत व्यय में से 84 फीसदी खर्च किया। केवल चार राज्य ही लक्ष्य को पार कर सके। विशेषज्ञों का कहना है कि कमी की एक वजह व्यवहार्य परियोजनाओं की अनुपलब्धता भी हो सकती है। दूसरा कारण यह है कि राज्य वित्त वर्ष के अंत तक राशि जारी करने की प्रतीक्षा करते हैं जिससे परिणाम प्रभावित होते हैं। ऐक्सिस बैंक के अर्थशास्त्रियों के एक हालिया नोट में इस बात को रेखांकित किया गया कि क्रियान्वयन के स्तर पर जोखिम हो सकता है। राज्यों का वास्तविक पूंजीगत व्यय बीते दो वित्त वर्षों के संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 10-15 प्रतिशत कम था। कमी की एक वजह पूंजीगत व्यय आवंटन में अच्छा खासा इजाफा भी हो सकती है। ऐसे में जरूरत है कि राजकोषीय हस्तक्षेप और अपेक्षाओं में संतुलन कायम किया जा सके।

समस्त राजकोषीय नतीजों के संदर्भ में उपरोक्त शोध नोट जिसमें सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 95 फीसदी का योगदान देने वाले 20 बड़े राज्यों की वित्तीय स्थिति पर गौर किया गया है, उससे पता चलता है कि इन राज्यों ने चालू वर्ष में जीडीपी के 3.2 फीसदी तक के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है। बहरहाल, अतीत में वास्तविक घाटे के संशोधित आंकड़े से कम रहने के रुझान को देखते हुए अंतिम आंकड़ा जीडीपी के 2.8 फीसदी के करीब रह सकता है। इसके अलावा चूंकि राज्यों के घाटे में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया ऋण भी शामिल होता है इसलिए सामान्य सरकारी घाटे में जीडीपी के 2.5 फीसदी तक का इजाफा होगा। पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए राजकोषीय प्रबंधन चुनौतीपूर्ण बना रहेगा। इन राज्यों की बकाया देनदारी जीडीपी के 40 फीसदी से अधिक है।

इस बीच केंद्र सरकार को आने वाले वर्षों में राजकोषीय सुधार करने होंगे ताकि सामान्य सरकारी घाटे और ऋण को समुचित स्तर पर स्थिर किया जा सके। व्यय की सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी भी आवश्यक होगी। चालू वर्ष में राजकोषीय घाटे के जीडीपी के 5.1 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है। ऐसे में निजी निवेश को बढ़ाना होगा ताकि आर्थिक वृद्धि की गति बरकरार रखी जा सके। बहरहाल, शीर्ष पर स्थित करीब 1,000 कंपनियों (वित्तीय सेवा कंपनियों को छोड़कर) के इस अखबार द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि 2023-24 में निवेश वृद्धि घटकर 7.6 फीसदी रह गई जबकि इससे पिछले वर्ष यह 12.2 फीसदी थी। निवेश वृद्धि में कमी को सही तरीके से समझने की जरूरत है। आगामी बजट के संदर्भ में बात करें तो चूंकि सरकार पहले ही निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए जीडीपी के तीन फीसदी के बराबर पूंजीगत व्यय पर खर्च कर रही है, तो शायद हमें सक्षम कारोबारी हालात तैयार करने और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने पर ध्यान देना चाहिए।

विनय सिन्हा

विकास नीति में बढ़े वंचितों पर ध्यान

हमारी विकास संबंधी नीति का मुख्य ध्यान निर्णायक तौर पर वंचितों के लिए अवसरों के विस्तार पर केंद्रित होना चाहिए। बता रहे हैं नितिन देसाई

हालिया चुनाव के नतीजे बताते हैं कि देश के मतदाता हमारी मौजूदा और भविष्य की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुप्रचारित आशावाद को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। ऐसा भी नहीं है कि अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि को चिह्नित नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश में लोगों का सर्वेक्षण करने वाले एक व्यक्ति के मुताबिक जब लोगों से उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा जाता तो अक्सर उनका जवाब होता, 'हां, अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी है लेकिन हम ठीक नहीं हैं।' वृद्धि और वंचितों के लिए आय के अवसरों की कमी ही नीतिगत प्रदर्शन को लेकर लोगों के आकलन के मूल में है।

सन 1991 के उदारीकरण के सुधारों के तीन दशक बाद देश की आर्थिक वृद्धि दर करीब 6 फीसदी रही है। इस अवधि में देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी छह गुना बढ़ गया। इसका एक मानक देश के जीडीपी की क्रय शक्ति समता का अनुमान भी है जो विश्व बैंक के हालिया अनुमानों के मुताबिक 10 लाख करोड़ डॉलर या कहें तो वैश्विक जीडीपी के 7.2 फीसदी के बराबर है।

जीडीपी में छह गुना इजाफे के साथ विशुद्ध गरीबी में कमी आई है। परंतु असमानता में भी इजाफा हुआ है। विश्व असमानता डेटाबेस के अनुसार देश की राष्ट्रीय आय में सबसे अमीर 10 फीसदी लोगों की हिस्सेदारी 1992 के 35 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में 58 फीसदी हो गई। इसी अवधि में सबसे अमीर एक फीसदी लोगों की हिस्सेदारी 10 फीसदी से बढ़कर 23 फीसदी हो गई। दूसरी ओर सबसे निचले 50 फीसदी लोग 1992 के 22 फीसदी से घटकर 2022 में 15 फीसदी रह गए। संपत्ति के वितरण की बात करें तो असमानता और अधिक है।

इस दौर की विकास रणनीति निजी क्षेत्र के उदारीकरण, विदेशी निवेश और संबंधित संस्थागत सुधारों पर आधारित है। परंतु इसमें कुछ कंपनियों के लिए पक्षपात भी शामिल रहा जिसके चलते वे तेजी से शीर्ष पर पहुंचने में कामयाब रहे। आज शीर्ष 10 कंपनियां 22 फीसदी पूंजी की मालिक हैं जबकि 5,000 से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में शीर्ष 100 कंपनियां 64 फीसदी पूंजीकरण की मालिक हैं।

कंपनियों के विस्तार पर इस प्रकार ध्यान केंद्रित करना ही वृद्धि को गति देने वाला अहम कारक रहा है। इसके बावजूद चुनिंदा आईटी कंपनियों को छोड़ दिया जाए तो भारत की कंपनियों ने वह नहीं हासिल किया है जो अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक वृद्धि संभावनाओं के लिए जरूरी है। यानी वह वैश्विक कद जो चीन और पूर्वी एशिया की कंपनियां पहले ही हासिल कर चुकी हैं। कंपनियों ने मोटे तौर पर घरेलू मांग पूरी करने पर ध्यान दिया है और साथ ही बढ़ती असमानता के कारण उपभोग की वस्तुओं की वृद्धि कम हुई जिससे कई कंपनियों की वृद्धि और निवेश योजनाओं में धीमापन आया है। सार्वजनिक नीति में बदलाव के बाद अधोसंरचना विकास में उनकी बढ़ती संबद्धता एक अपवाद है।

कुछ मायनों में निजी कारोबारियों की इस वृद्धि और सरकार तथा कुछ कारोबारी समूहों के बीच का गठजोड़ वैसा ही है जैसा कि अमेरिका में 1870 से 1900 के बीच गील्डेड युग में देखने को मिला था। उस समय तेज आर्थिक वृद्धि हुई थी और अधोसंरचना खासकर रेल मार्गों में जमकर निवेश हुआ। इसके साथ ही निजी पूंजी का विस्तार और कंपनियों की ताकत में भी इजाफा देखने को मिला था। इसमें अहम बात थी कंपनियों के साथ गठजोड़। अमेरिकी सरकार व्यवस्था बनाए रखने के लिए निष्पक्ष दिखने की कोशिश कर रही थी लेकिन वह अमीरों के हितों का पालन कर रही थी।

वास्तव में दिलचस्प बात है गील्डेड युग का उस दौर के चुनावों पर प्रभाव। बीसवीं सदी के शुरुआती वर्षों में हुए चुनावों में थियोडोर रूजवेल्ट राष्ट्रपति बने थे। उस समय राजनीति का ध्यान तेजी से उन समस्याओ को हल करने की ओर गया जो उस दौर आर्थिक बदलावों के कारण उत्पन्न हुई थीं। राजनीतिक भ्रष्टाचार और औद्योगिक स्वामित्व के एकीकरण की समस्या को दूर करने का प्रयास किया गया। प्रगतिशील दौर की राजनीति सामाजिक सक्रियता से प्रेरित थी। हालिया लोक सभा चुनावों का एक आशावादी पाठ यह हो सकता है कि हमें भारत में भी ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है। मुफ्त राशन और अन्य लोक लुभावन घोषणाओं की बात करें तो उनसे गरीबों के लिए अवसर नहीं बदलते। हालिया चुनाव नतीजे बताते हैं कि सामाजिक सक्रियता नजर आ रही है जो वंचितों के लिए बेहतर अवसरों की तलाश से संबंधित है।

इसके पीछे की शक्ति शायद यह भय रहा होगा कि जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था का क्या होगा। राजनीतिक पहलू को जाति जनगणना और मराठा जैसी जातियों की आरक्षण की मांग को समर्थन के रूप में देखा जा सकता है। इस तरह की जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था असमानता से ध्यान हटाने की कोशिश नहीं है, जिसे प्रमुख कारक नीति होना चाहिए था। देश में असमानता की हकीकत यह है कि यह जाति से बहुत हद तक संबद्ध है। ऐसा इसलिए कि अतीत में भी जाति और असमानता का बहुत करीबी संबंध रहा है। बढ़ते बहुसंख्यकवाद की वजह से इसका संबंध धर्म से भी है। आरक्षण पर ध्यान देने की तुलना पश्चिम में कामगारों के अधिकारों की मांग से की जा सकती है। क्या विपक्ष के वोटों में अप्रत्याशित वृद्धि को भारत में प्रगतिशील युग की शुरुआत के संकेतक के रूप में देखा जा सकता है? उत्तर प्रदेश में जहां सीटों में बहुत फर्क आया वहां मतों का सर्वेक्षण दिखाता है कि दलित और मुस्लिम मतों का बड़ा हिस्सा विपक्ष को और उच्च जातियों का मत सत्ताधारी दल को गया। इसके साथ ही वंचितों और वरीयता प्राप्त समुदायों को मिलने वाले अवसरों में भी भारी अंतर रहा। परंतु हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यह नहीं देखने को मिला जबकि वह उत्तर प्रदेश से ज्यादा अलग नहीं है।

मेरी नजर में चुनाव नतीजे बताते हैं कि विकास नीति का प्राथमिक स्रोत समेकित जीडीपी या देश को दुनिया की चुनिंदा शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना नहीं होना चाहिए। बल्कि उसकी जगह वंचितों और रोजगार से वंचित लोगों के लिए अवसरों में सुधार करना चाहिए।

गत माह मैंने नई सरकार की प्राथमिकताओं से संबंधित अपने स्तंभ में कहा था कि रोजगार तैयार करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। खासतौर पर कम वृद्धि वाले राज्यों में ऐसा करने की आवश्यकता है जहां कामकाजी आयु वाली आबादी तेजी से बढ़ रही है। मेरा यह अनुमान नहीं था कि वंचितों की चिंताएं इस तरह मुखर होंगी जैसी कि वे चुनाव नतीजों में नजर आईं। इससे स्पष्ट होता है कि विकास नीतियों को अब तेज गति से उत्पादक रोजगार तैयार करने पर काम करना चाहिए। करीब एक दशक तक उसे कामकाजी आयु की आबादी में वृद्धि की दर से अधिक तेजी से रोजगार तैयार करने चाहिए। स्थानीय मांग के लिए अंतिम उत्पाद तैयार करने में छोटे आपूर्तिकर्ताओं को बढ़ावा देना चाहिए। भौतिक और डिजिटल अधोसंरचना में सुधार तथा ई-कॉमर्स एवं डिजिटल भुगतान प्रणालियों के तेजी से उभार का उपयोग करके रोजगार की आवश्यकता वाले उत्तरी राज्यो को राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखलाओं में उच्च विकास वाले दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों से जोड़ा जा सकता है। एक ऐसी व्यापार नीति बनाई जानी चाहिए जा कारोबारियों को निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करे। दीर्घावधि में कौशल विकास के लिए बेहतर व्यवस्था की आवश्यकता होगी।

रोजगार निर्माण का काम वृद्धि आधारित रणनीति का सह उत्पाद नहीं होना चाहिए। बल्कि तेज वृद्धि रोजगार निर्माण के कारण आनी चाहिए। क्या केंद्र सरकार इस दिशा में बढ़ेगी?

बेरोजगार युवा और हमारी शिक्षा पद्धति

कुछ बेरोजगारी स्वाभाविक होती है। युवाओं में स्वाभाविक बेरोजगारी दर कुल स्वाभाविक दर से अधिक हो सकती है। परंतु, भारत में वास्तविक आंकड़े चौंका देने वाले हैं। स्नातक उत्तीर्ण युवाओं में एक तिहाई से थोड़े कम बेरोजगार हैं और माध्यमिक या उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण युवाओं में पांच में एक बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। आखिर, यह हालत क्यों हैं और इसके समाधान के लिए क्या किया जा सकता है? रोजगार बाजार में मांग और आपूर्ति पक्ष दोनों ही महत्त्वपूर्ण हैं। हालांकि, यहां चर्चा रोजगार की मांग पर केंद्रित रहेगी।

कई युवा रोजगार की तलाश कर रहे है मगर वास्तव में रोजगार की उनकी मांग केवल सांकेतिक ही मानी जा सकती है। यह अलग बात है कि ऐसे लोग पूरी गंभीरता से रोजगार की तलाश में जुटे रहते हैं। रोजगार की मांग वास्तविक तब होती है जब उपयुक्त हुनर, शिक्षा और भविष्य में कुछ संभावित योगदान देने में सक्षम लोग जीविकोपार्जन का माध्यम यानी नौकरी तलाश रहे होते हैं। उक्त बातों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि रोजगार की मांग वास्तव में अधिक नहीं है। इसका कारण बिल्कुल सीधा-सपाट है। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा केवल कुछ सीमित छात्रों तक ही उपलब्ध है। कई नियोक्ता विभिन्न तरीकों से इन अच्छे उम्मीदवारों को नौकरियों की पेशकश करते हैं। इस समस्या की जड़ कहीं और है।

युवा बेरोजगारी उन लोगों में अधिक देखी जा रही है जिनके पास डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र तो हैं मगर वे सही मायने में शिक्षित या हुनरमंद नहीं हैं। मगर इन छात्रों एवं उनके परिवारों के बीच धारणा यह है कि उन्हें अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। दुर्भाग्य से यह एक सुहावना विचार है और संभवतः एक कटु सत्य भी है। यहां उद्देश्य ऐसे छात्रों या उनके परिवारों को और दुखी नहीं करना है। ऐसे लोगों की हालत के लिए शिक्षा पद्धति में मौजूद त्रुटियां जिम्मेदार हैं। ये त्रुटियां एक दिन में नहीं बल्कि समय के साथ अपनी जड़ें जमाती गई हैं। वास्तव में शिक्षा प्रणाली में संकट की स्थिति है मगर अफसोस कि यह समाचार माध्यमों की सुर्खी नहीं बन पाती है। वस्तुतः कहीं न कहीं शिक्षा प्रणाली बीमार है और इस संदर्भ में भीषण युवा बेरोजगारी इसका एक लक्षण है। अक्सर यह लक्षण समाचार माध्यमों का ध्यान खींचता है मगर बीमारी पर कोई चर्चा नहीं होती है। शिक्षा पद्धति से जुड़ी इन सभी समस्याओं का क्या निराकरण हो सकता है?

गुरबचन सिंह

हमें शिक्षा की संरचना में व्यापक बदलाव करने होंगे, यद्यपि यह काम चरणबद्ध तरीके से करना होगा। शिक्षा पर सरकार की तरफ से अधिक व्यय करना महत्त्वपूर्ण है मगर केवल इससे बात नहीं बनने वाली है। हमें दूसरे कदम भी उठाने होंगे, जैसे शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण नीति का विकल्प खोजना होगा। शिक्षा में राजनीति एवं विचारधारा कम करनी होगी। यह मामला उन पाठ्यक्रमों से भी जुड़ा हुआ है जिनकी पेशकश की जाती है और जिनकी नहीं की जाती है। इसके साथ ही संकाय सदस्यों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। यहां तक कि शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भूमि आवंटन नीति पर भी विचार करने की आवश्यकता है। हमें 'स्किल इंडिया' कार्यक्रम और नई शिक्षा नीति से परे जाकर काम करने की आवश्यकता है। छात्रों के प्रमाणन की विश्वसनीयता पर किसी का ध्यान नहीं जाता है मगर यह पक्ष बहुत महत्त्वपूर्ण है। ऊंचा ग्रेड या दर्जा पाने वाले ज्यादातर छात्रों में कई वास्तव में बहुत शिक्षित या प्रतिभावान नहीं होते हैं। बिना तथ्यों को समझे ही उन्हें कंठस्थ कर परीक्षा में लिखने के बाद मिलने वाले अंक, पर्चा लीक, परीक्षा कक्षों में चोरी, परिणामों में धांधली, पक्षपात आदि शिक्षा व्यवस्था की विभिन्न समस्याओं का हिस्सा भर हैं। कई दूसरे मुद्दे भी जुड़े हैं। भारत में परीक्षाएं मोटे तौर पर प्रतिभा का निर्धारण सटीक रूप से नहीं करती हैं। चूंकि, अधिक अंक गुणवत्ता का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं होते हैं, इसलिए साफ-सुथरी परीक्षाओं में भी ऊंचे अंक पाने वाले छात्रों में बेरोजगारी की दर अधिक देखी गई है। जो लोग कम अंक लाते हैं जरूरी नहीं है कि वे अक्षम हैं। त्रुटिपूर्ण परीक्षा प्रणाली के कारण भी कुछ लोगों के अंक कम आते हैं।

युवाओं का एक ऐसा समूह भी है जो प्रतिभावान है मगर उनकी क्षमता अन्य क्षेत्रों जैसे स्टैंड-अप कॉमेडी, जूलरी डिजाइनिंग, यूट्यूब वीडियो तैयार करने में हैं। मगर इनके लिए शायद ही मुख्यधारा में विश्वसनीय प्रमाणन की कोई व्यवस्था उपलब्ध है। लिहाजा, वे तब तक बेरोजगार हैं जब तक बिना हिम्मत हारे कोई रास्ता नहीं खोज लेते हैं।

कुछ लोगों को लगता है कि कई छात्रों को शिक्षित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपूर्ति के मोर्चे पर रोजगार सृजन की सीमित संभावनाएं हैं। मगर ऐसे कह कर वे एक बड़ी सच्चाई को समझ नहीं पा रहे हैं। रोजगार उन लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हैं जो सही मायने में प्रशिक्षित नहीं हैं। अगर कोई उम्मीदवार दुरुस्त है तो उसे देर-सबेर रोजगार या कोई पेशा अपनाने का अवसर हाथ लग ही जाता है। इस तरह, शिक्षा काफी उपयोगी है, बशर्ते इसकी गुणवत्ता कम नहीं हो और आर्थिक नीति इस तरह तैयार की जाए कि जिससे एक तार्किक, अवसर सृजित करने वाली और सभी को सक्षम बनाने वाली अर्थव्यवस्था का निर्माण संभव हो पाए।

अंत में, हम इस चर्चा के एक दूसरे महत्त्वपूर्ण पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन लोगों का ध्यान रखने की जरूरत है जो परीक्षा तो 'पास' कर चुके हैं मगर उन्हें इसलिए रोजगार नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त हुनर या प्रशिक्षण नहीं है। ऐसे लोगों को दोबारा प्रशिक्षित करना जरूरी है। यद्यपि, यह काम दूसरे रूप में भी किया जा सकता है। इस बीच, अंतरिम में पर्याप्त बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इस पूरी चर्चा का यही निष्कर्ष निकलता है कि जब अगली बार भारत में युवाओं में ऊंची बेरोजगारी दर पर बहस छिड़ी तो वित्त मंत्री के साथ शिक्षा मंत्री की भूमिका पर भी चर्चा की जानी चाहिए।

(लेखक अर्थशास्त्री हैं और अशोक विश्वविद्यालय, आईएसआई (दिल्ली) और जेएनयू में पढ़ा चुके हैं)

आपका पक्ष

ट्रेन हादसे रोकने के लिए कड़े कदम जरूरी

हाल ही में हुई कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना में 10 यात्रियों की मौत हो गई तथा 40 से अधिक यात्री घायल हो गए। पिछले साल 2 जून को ओडिशा में ही हुए ट्रेन हादसे में 300 से अधिक यात्रियों की मौत हुई तथा 900 से अधिक यात्री घायल हो गए थे। दुनिया में भारतीय रेलवे का नेटवर्क चौथे स्थान पर है। रेलवे को प्राकृतिक (बारिश, भूस्खलन, धुंध) कारणों से होने वाले हादसों के साथ साथ मानव-जनित लापरवाहियों के चलते होने वाले हादसों पर लगाम लगाने के लिए विशेष ध्यान देना होगा। एक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति जाहिर करती है कि ओडिशा जैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले हादसे से कोई सबक नहीं सीखा गया है। विभाग प्रमुख होने के कारण रेल मंत्री की यह नैतिक जवाबदारी है कि ट्रेनें अधिक से अधिक सुरक्षित हों, कंचनजंगा व ओडिशा जैसे हादसे घटित न हों।

हेमा हरि उपाध्याय, उज्जैन

पश्चिम बंगाल के रंगापानी रेलवे स्टेशन के पास कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी

रेलवे की फिर लापरवाही

कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना रेलवे की लापरवाही को उजागर करता है। पिछले साल ओडिशा में तीन ट्रेनें आपस में टकरा गई थी। इस हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली गई और बहुत से लोग घायल हुए थे। ऐसा ही एक हादसा आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में दो ट्रेन की टक्कर कारण हुआ था। वहां विशाखापत्तनम-पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापत्तनम-रायगढ़ पैसेंजर स्पेशल ट्रेन की टक्कर हुई थी, इसमें कुछ लोगों की मौत हो गई और कुछ घायल हो गए थे। ट्रेन हादसे को रोकने के लिए उचित कदम क्यों नहीं उठाए जाते। रेल मंत्रालय और रेल उच्च अधिकारियों को अपना सुस्त रवैया छोड़कर यात्रियों की सुरक्षा के लिए ओर ज्यादा चुस्त होना चाहिए। रेलवे को ऐसी तकनीक अपनाना चाहिए जिससे एक ही पटरी पर सामने ट्रेन हो तो ब्रेक लग जाए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

जनांदोलन बने पर्यावरण

लेख 'जलवायु परिवर्तन के दौर में एजेंडा' समाज और सरकार को बहुत महत्त्वपूर्ण विषय पर संवेदित करता है। यह विषय अब शोध, व्याख्यान, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार का नहीं रह गया है बल्कि अब प्रश्न अपने अस्तित्व पर खड़े हो रहे हैं। सरकार, जनमानस और समाज की अपनी अपनी जिम्मेदारी है और कोई एक पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण का दायित्व नहीं उठा सकता। पिछले कुछ वर्षों में हम भयंकर बाढ़, सूखा, तूफान, सुनामी, पहाड़ दरकने, अत्यधिक गर्मी, जल स्रोतों के सूखने, पेयजल की कमी, जल प्रदूषण से जूझ रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकारें पर्यटन योजनाओं के अंतर्गत पहाड़ काटना बंद करें। सभी पोखरों और तालाबों को पुनर्जीवित करने का दायित्व स्थानीय प्रशासन और जनता उठाए।

विनोद जौहरी, दिल्ली

आर्थिक व सामाजिक खुशहाली की उम्मीद

नई सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है। देश को नई सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। देश आर्थिक और सामाजिक रूप में खुशहाल होगा। सरकार जनता के सपनों को पूरा करने का प्रयास करती रहेगी। पर राजनीतिक रूप में सरकार को कई अवरोध झेलने पड़ेंगे।

डॉ. उमेश मित्तल, सहारनपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष माइकल मैकॉल के नेतृत्व में अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को धर्मशाला में तिब्बती धार्मिक गुरु दलाई लामा से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पूर्व अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी, सांसद मैरिएनेट मिलर, ग्रेगरी मीक्स, निकोल मैलियोटाकिस, जिम मैकगवर्न और एमी बेरा शामिल थे।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सघन होते संबंध

भारत और अमेरिका क्वांटम विज्ञान, जैव-निर्माण, दवा, दूरसंचार समेत विभिन्न अत्याधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं. इस संबंध में पहली बैठक जनवरी 2023 में हुई थी. सोमवार को नयी दिल्ली में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों- अजीत डोभाल और जैक सुलिवन- की बैठक में एक साझा रणनीतिक कार्यक्रम का निर्णय लिया गया. उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सहयोग के लिए पहले से ही एक रणनीतिक समझौता है तथा हाल के वर्षों में द्विपक्षीय सहकार निरंतर सघन होता गया है. विकास में तकनीक का आधारभूत महत्व होता है. देशों के बीच में तकनीकों का आदान-प्रदान तो हमेशा से होता रहा है, पर भू-राजनीतिक और सामरिक कारक इस प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभाते हैं. ऐसे में बाइडेन प्रशासन द्वारा उन्नत कंप्यूटिंग और सोर्स कोड तकनीकों के भारत के निर्यात में बाधाओं को कम करने का निर्णय यह दर्शाता है कि दोनों देशों का एक-दूसरे पर भरोसा बढ़ता जा रहा है. भारत ने हाइड्रोजन ऊर्जा, क्वांटम विज्ञान शोध, 6जी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए विशेष प्रयास किया है. अब भारत के 6जी अलायंस और अमेरिका के नेक्स्ट जी अलायंस के बीच साझेदारी से बड़ी प्रगति का रास्ता खुला है. इसके लिए आवश्यक धन का इंतजाम भी अमेरिका करेगा. डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा का लोहा दुनिया मानती है, जिसका लाभ इस कार्यक्रम को मिलेगा. क्वांटम विज्ञान में दोनों देशों के संस्थानों एवं प्रयोगशालाओं के एक साथ काम करने से शोध को नयी गति मिलने की आशा है. भारत सरकार द्वारा शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं तथा आवंटन में भी बढ़ोतरी की गयी है. लेकिन समुचित कोष एवं संसाधनों का अभाव अभी भी है. इसमें अमेरिकी सहायता बहुत मददगार साबित हो सकती है. दवाई और वैक्सीन उत्पादन में अग्रणी होने के कारण भारत को 'दुनिया की फार्मेसी' भी कहा जाता है. जैव-तकनीक और दवा निर्माण के क्षेत्र में शोध एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ ने एक साझा मंच बनाया है. कोरोना महामारी के अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है. उन्नत तकनीक और वैज्ञानिक अनुसंधान के विकास के ऐसे प्रयासों से हमारी अर्थव्यवस्था को भी नयी गति मिलेगी. इसलिए अत्याधुनिक तकनीक की उपलब्धता का महत्व बहुत बढ़ जाता है. इस दृष्टि से परस्पर सहयोग बढ़ना उत्साहजनक है.

क्वांटम विज्ञान में दोनों देशों के संस्थानों एवं प्रयोगशालाओं के एक साथ काम करने से शोध को नयी गति मिलने की आशा है.

ज्ञान के अविरल प्रवाह का नाम है नालंदा

प्रो रवींद्र नाथ श्रीवास्तव 'परिचय दास'
नव नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय, नालंदा
parichaydaspoet@gmail.com

लगभग एक दशक पहले स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर के नये भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह एक विकास यात्रा है. 'नालंदा' सिर्फ नाम नहीं, पहचान है, गौरव है, सम्मान है. आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकतीं. उनका संकेत श्री नालंदा महाविहार के पुस्तकालय को जलाये जाने की ओर था. ज्ञान हृदय का उजाला है. अंधकार से प्रकाश की ओर जाना हमारा अभीष्ट रहा है. नालंदा एक नयी शुरुआत कर सकता था. उसने यही किया है. विश्व में आज विद्या व ज्ञान के माध्यम से नालंदा भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा. वह यह भी बतायेगा कि हम मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भविष्य की नींव रखना जानते हैं. अब नालंदा विश्व के अतीत ही नहीं, भविष्य को भी उद्घाटित करेगा. नालंदा ज्ञान के अविरल प्रवाह का नाम है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आरंभिक वैश्विक आधारशिला है बिहार. इस बहाने भी संसार में लोकतंत्र के प्रसार का संदेश जायेगा. इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नालंदा क्षेत्र पांच धर्मों का केंद्र है. प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का संदेश विश्व में सहमति एवं असहमति के बीच सेतु के रूप में कार्य करेगा.

आधुनिक समय में भी नालंदा विद्या व संस्कृति के नये केंद्र के रूप में उभरा है. इसमें दक्षिण एशिया व विश्व को नयी समझ, शांति व मनुष्यता को विकसित करने की अपार क्षमता है. यह उसके अतीत से आता है. नालंदा विश्व का ऐसा पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जो सामान्य व्यक्ति के लिए भी उपलब्ध था. इस विश्वविद्यालय से शिक्षा की व्यवस्थित व वैज्ञानिक प्रणाली का विकास संभव हुआ था. तब विश्वविद्यालय शब्द चलन में नहीं था. इसके लिए अमूमन महाविहार शब्द प्रयुक्त होता था. प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को श्री नालंदा महाविहार के रूप में जाना जाता था. नालंदा विचार के साथ-साथ साहित्य का केंद्र भी था. यह कम लोगों को ज्ञात है कि नालंदा में हिंदी कविता का जन्म हुआ. यह अपभ्रंश के रूप में हुआ. महापंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, सरहपा हिंदी कविता के प्रथम कवि थे. उनकी रचना 'दोहा कोश' राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत में अनूदित मिली, जिसका अपभ्रंश में रूपांतरण उन्होंने किया. एक नयी दृष्टि, भाव बोध व काव्य व्याकरण को जन्म देने का श्रेय सरहपा की रचना को जाता है. सरहपा की जैसी चर्चा नालंदा के परिप्रेक्ष्य में होनी चाहिए थी, नहीं हुई. कोई पीठ, मार्ग, भवन, चौराहा तक नहीं है उनके नाम पर. कथ्य है कि राहुल श्रीभद्र यानी सरहपा प्राचीन श्री नालंदा विश्वविद्यालय के अंतिम दिनों में आचार्य थे, उसके बाद यह धरोहर में तब्दील हो गया. गुप्त काल में विकसित उदार सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं नालंदा के बहुविषयक शैक्षणिक पाठ्यक्रम का मूल आधार बनीं, जिसमें बौद्धिक बौद्ध धर्म को विभिन्न क्षेत्रों में उच्च ज्ञान के साथ मिश्रित किया गया. नालंदा आरंभ से ही जैन, बौद्ध व सनातन का समन्वित केंद्र रहा है. पावापुरी में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ था. महाभारतकालीन अवशेष, जरासंध का अखाड़ा, विश्वस्तरीय मलमास मेला, गर्म जल का कुंड, गया में पितरों का विसर्जन आदि की सनातन परंपरा रही है. बिंबिसार ने भगवान बुद्ध का प्रथम बार राजगीर में स्वागत किया था. स्पष्ट है कि नालंदा केवल बुद्ध का ही आभा क्षेत्र नहीं रहा है, इसलिए नालंदा के माध्यम से केवल बुद्ध धर्म को रेखांकित करना एकांगिकता है.

विचारकों में असहमति है कि पांचवीं शताब्दी में स्थापित श्री नालंदा महाविहार के बाद राजगीर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय, जो 2014 में स्थापित हुआ, सीधे उत्तराधिकारी है. सच यह है कि नव नालंदा महाविहार, जो नालंदा में स्थित है, वह प्राथमिक रूप से 1951 में ही भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद के सौजन्य से स्थापित हो चुका था. भिक्षु जगदीश काश्यप ने इस इलाके में नया जागरण किया था. वे और प्रख्यात हिंदी लेखक व तब बिहार के शिक्षा सचिव जगदीश चंद्र माथुर ने इसकी कल्पना की थी. आज नव नालंदा महाविहार संस्कृति मंत्रालय (भारत सरकार) का सम विश्वविद्यालय है, जिसमें अनेक देशों के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं. नालंदा ने प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में एक प्रमुख शैक्षणिक प्रतिष्ठान के रूप में कार्य किया है. उस अवधि के मंदिरों, मठवासी आवासों, प्रार्थना संरचनाओं, कांस्य और पत्थर से बनी कलाकृतियों के अवशेष देखे जा सकते हैं. प्राचीन महाविहार में आर्यभट्ट प्रमुख रह चुके थे. प्रवेश के इच्छुक छात्रों को शीर्ष आचार्यों के साथ कठोर मौखिक साक्षात्कार में भाग लेना पड़ता था. इसकी तीन पुस्तकालय इमारतों में से एक को तिब्बती बौद्ध विद्वान तारानाथ ने नौ मंजिला बताया था. प्रख्यात चीनी भिक्षु और यात्री ह्वेनत्सांग ने नालंदा में अध्ययन और अध्यापन किया था. गुप्त काल के बाद भी नालंदा को शाही संरक्षण प्राप्त रहा. यहां चीन, जापान, कोरिया और दक्षिण-पूर्व और मध्य एशिया के देशों से छात्र आते थे. माना जाता है कि नालंदा का पाठ्यक्रम धार्मिक ग्रंथों से आगे बढ़कर साहित्य, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, दर्शन, कला और तत्वमीमांसा को भी शामिल करता था. ह्वेनत्सांग ने महाविहार की शोभा बढ़ाने वाले गुणमति, स्थिरमति, प्रभामित्र, जिनमित्र, ज्ञानचंद्र, संतरक्षित, शीलभद्र, धम्मपाल और चंद्रपाल जैसी प्रसिद्ध हस्तियों का उल्लेख किया है.

नालंदा ने महायान, वज्रयान व सहज यान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. शांति व धर्मकीर्ति की रचनाओं ने नया उन्मेष दिया. नागार्जुन ने शून्यवाद का नया दर्शन दिया. महाविहार को वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति माना जाता था और इसकी पहचान एक ऊंची दीवार एवं द्वार से थी. नालंदा में आठ अलग-अलग परिसर और दस मंदिरों के साथ कई अन्य ध्यान कक्ष और कक्षाएं भी थीं. माना जाता है कि कुमारगुप्त ने पांचवीं शताब्दी में महाविहार की स्थापना की थी. बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय आदि कई गुप्त राजाओं की मुहरें नालंदा में पायी गयी हैं. नालंदा दुनिया में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था, जो 13वीं शताब्दी तक 800 से अधिक वर्षों तक चला. चीन के तीन भिक्षु छात्रों के यात्रा वृत्तांतों में पांचवीं से सातवीं शताब्दी तक के भारत के सामाजिक जीवन और नालंदा में शैक्षणिक जीवन के बारे में आकर्षक जानकारी है. उनमें शहरी जीवन, कानून, चिकित्सा, शुद्धता और प्रदूषण मुक्ति के प्रति जुनून, भोजन संबंधी वर्जनाओं, अस्पृश्यता और सामाजिक संघर्षों का वर्णन है. आज समकाल में भी नालंदा इन सभी प्रश्नों के प्रति संवेदनशील है तथा गतिशील भी. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

प्रख्यात चीनी भिक्षु और यात्री ह्वेनत्सांग ने नालंदा में अध्ययन और अध्यापन किया था. गुप्त काल के बाद भी नालंदा को शाही संरक्षण प्राप्त रहा. यहां चीन, जापान, कोरिया और दक्षिण-पूर्व और मध्य एशिया के देशों से छात्र आते थे. माना जाता है कि नालंदा का पाठ्यक्रम धार्मिक ग्रंथों से आगे बढ़कर साहित्य, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा, दर्शन, कला और तत्वमीमांसा को भी शामिल करता था.

महिला नेताओं के प्रति निंदनीय मर्दवादी नजरिया

क्षमा शर्मा
वरिष्ठ पत्रकार
kshamasharma1@gmail.com

हाल ही में इटली में जी-7 समूह का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था. सम्मेलन की मेजबान वहां की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थीं. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आमंत्रित थे. सोशल मीडिया में दोनों नेताओं को लेकर तमाम किस्म के आपत्तिजनक मीम और चुटकुले गढ़े गये. मेलोनी के औरत होने का मजाक भी उड़ाया गया तथा बहुत से लोगों को राजनीति या बैठक के महत्व की जगह उनकी सेक्स अपील ही दिखी. बड़े अफसोस की बात है कि दुनियाभर में चाहे जितना स्त्री विमर्श का राग गाया जाता हो, ग्लास सीलिंग को तोड़ने की बातें की जाती हों, पर बड़े पदों पर बैठने वाली स्त्रियों को देखने का मर्दवादी नजरिया जरा भी नहीं बदला है. आपको याद होगा कि अमेरिका में वोट देने के अधिकार के लिए स्त्रियों को सत्तर साल तक कठिन संघर्ष करना पड़ा था. तब उनका मजाक तरह-तरह के कार्टून, चुटकुले, लेखों आदि में इसी तरह से बनाया जाता था कि ये औरतें आखिर वोट देकर क्या करेंगी, करना तो इन्हें चौका-चूल्हा ही है. औरतों ने लंबी लड़ाई के बाद इस छवि को तोड़ा है कि उनकी प्रतिभा मात्र चौके-चूल्हे तक ही सीमित रह सकती है. लेकिन स्त्री की आजादी का दम भरने वाले लोग जैसे ही किसी स्त्री को शासक की हैसियत में देखते हैं, तो उनका अहंकार हिलोरें मारने लगता है. वे इस तरह की स्त्रियों को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं.

स्त्री के बड़े पद पर पहुंचने का मतलब पुरुषवादी सोच में मात्र उसका शरीर ही है. इसीलिए दुनियाभर में स्त्रियों को इस तरह के अपमान झेलने पड़ते हैं. उनके अच्छे विचार और योग्यता की जगह उन्हें उनकी सुंदरता, उनके शरीर, उनकी सेक्स अपील से ही मापा जाता है. ऐसी सोच के निशाने पर हाल के वर्षों में ब्रिटेन की भूतपूर्व प्रधानमंत्री टेरेसा मे, स्कॉटलैंड की पूर्व प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन (जिन्होंने पांच प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया था), जर्मनी की एंजेला मर्केल, फिनलैंड की साना मरीन, न्यूजीलैंड की जेसिंडा जैसी कई नेता रही हैं. इन महिलाओं ने किस तरह से शासन किया, उनकी योजनाओं से लोगों को कितना लाभ मिला, वे अपने देश को किस ऊंचाई तक ले गयीं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उन्होंने कितनी सफलता पायी, बातचीत और गॉसिप के विषय अक्सर ये नहीं होते. लोगों और मीडिया के एक बड़े वर्ग को बस उनका महिला होना और उनका शरीर ही दिखता है. मान लिया जाता है कि कोई स्त्री यदि किसी बड़े पद पर पहुंचती है, तो अपनी योग्यता, प्रतिभा, निर्णय लेने की शक्ति के कारण नहीं, बल्कि अपने शरीर और रूप के कारण वे ऐसा कर पाती है. स्त्री की सफलता माने अपने शरीर का इस्तेमाल.

बाहर क्या देखना, अपने देश में भी यह कोई कम नहीं रहा है. हाल में जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी की तस्वीरें वायरल हुईं, तो सोशल मीडिया ने अश्लीलता और अभद्रता की सारी हदें तोड़ दीं. कई पोस्ट तो ऐसी थीं कि उनके बारे में यहां लिखा भी नहीं जा सकता. वैसे यह देश नारी को पूजने का दम भरता है. वर्षों से प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और माउंटबेटन की पत्नी एडविना को लेकर ऐसी ही खराब बातें होती रही हैं. इंदिरा गांधी, जिन्हें देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त है, के ऊपर इतने घटिया किस्म के लांछन आज भी लगाये जाते हैं कि अफसोस होता है. उनकी बुआ विजयलक्ष्मी पंडित भी इसका शिकार रही थीं. देश की अन्य महिला नेताओं, जिनमें जयललिता, मायावती जैसी बड़ी शख्सियतें भी शामिल हैं, की प्रतिभा और योग्यता को दरकिनार कर उन्हें भी सिर्फ पुरुषवादी नजरिये से देखा जाता है. किसी महिला की सफलता का मतलब यह क्यों है कि वह महिला है और सारे पुरुष उसके शिकार भर हैं. ऐसा भी महसूस होता है कि स्त्रियों को देखने के इस नजरिये का जितना विरोध हुआ है, यह उतना ही बढ़ रहा है. औरतों को पीटने के तरह-तरह के नये अस्त्र-शस्त्र रोज खोजे जा रहे हैं.

दिलचस्प यह भी है कि बहुत से स्त्री विरोधी अपने राजनीतिक दस्तावेजों, लेखों या भाषणों में तमाम तरह के स्त्रीवादी नारों का उपयोग करते हैं और अपने को भारी स्त्री समर्थक बताते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं. मौका मिलते ही औरतों का शिकार करने वाले सारे नख-दंत बाहर आ जाते हैं. लाख आरक्षण दे दीजिए, जब तक दिमाग में कूड़ा भरा है, कुछ नहीं किया जा सकता. अमेरिका को ही देख लीजिए. दुनिया को औरतों के अधिकारों पर ज्ञान देता फिरता है, लेकिन आज तक किसी स्त्री को वहां राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सका है. और तो और, वहां समाज में आज भी ये बहसें चलती हैं कि क्या कोई स्त्री देश को चला सकती है. लेकिन खुशी की बात यह है कि दुनिया के सार्वजनिक परिदृश्य में औरतों की संख्या लगातार बढ़ रही है. वे उन मंजिलों को छू रही हैं, जिनके बारे में पचास साल पहले कोई स्त्री सोच भी नहीं सकती थी. यह भी सच है कि जितना किसी का मजाक उड़ाया जाता है, वह उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ता है. यह उत्साहजनक है कि स्त्रियों ने यह गति पकड़ ली है, जो उनके सुखद भविष्य का ठोस संकेत है. **(ये लेखिका के निजी विचार हैं.)**

औरतों ने लंबी लड़ाई के बाद इस छवि को तोड़ा है कि उनकी प्रतिभा मात्र चौके-चूल्हे तक ही सीमित रह सकती है. लेकिन स्त्री की आजादी का दम भरने वाले लोग जैसे ही किसी स्त्री को शासक की हैसियत में देखते हैं, तो उनका अहंकार हिलोरें मारने लगता है. वे इस तरह की स्त्रियों को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं.

https://t.me/AllNewsPaperPaid

देश दुनिया

शांति बहाली के लिए फिलिस्तीन को मान्यता दे ऑस्ट्रेलिया

ALJAZEERA

बीते आठ महीनों में, हमने आत्मरक्षा की आड़ में इस्राइल द्वारा की गयी फिलिस्तीनियों की सामूहिक हत्या तथा विस्थापन और गाजा की तबाही एवं विनाश देखा है. चूंकि इस्राइली सरकार नागरिकों की सुरक्षा और नरसंहार रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपने दायित्वों की उपेक्षा कर रही है, सो प्रभावशाली देशों का ठोस निष्कर्ष पर पहुंचना अति आवश्यक है. ऑस्ट्रेलिया अपनी वैश्विक स्थिति और लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, शांति स्थापना के लिए मजबूत स्थिति में है. इस दिशा में फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देना महत्वपूर्ण कदम होगा. ऐसा करना नैतिक रूप से अनिवार्य भी है. उनत्तीस मई को ऑस्ट्रेलियाई संसद के निचले सदन में ग्रीन्स ने एक प्रस्ताव रखा था कि ऑस्ट्रेलिया को फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने में स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, स्लोवेनिया और दुनिया के अधिकांश देशों का अनुसरण करना चाहिए, परंतु यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका. मेरी पार्टी, द ऑस्ट्रेलियन लेबर पार्टी, ने लगातार तर्क दिया है कि इस तरह के प्रस्ताव लोकप्रियता हासिल करने और जनता को प्रभावित करने के लिए ग्रीन्स का राजनीतिक षड्यंत्र है. यदि ऐसा मामला है, तो भी राजनीति इस अंतर्निहित तथ्य को कम करके नहीं आंक सकती कि नरसंहार जारी है और ऑस्ट्रेलियाई जनता इसे जानती है. हजारों फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी गयी है, जिनमें 15,000 बच्चे भी शामिल हैं. संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के अनुसार, इस्राइल ने बीते आठ महीनों में नरसंहार के कम से कम तीन कृत्य को अंजाम दिया है. इसी कारण 1967 की सीमाओं के भीतर फिलिस्तीन देश की मान्यता आवश्यक है. ऑस्ट्रेलिया की मान्यता फिलिस्तीनी लोगों को मिटाने की इस्राइल की वर्तमान कोशिश की एक प्रतीकात्मक और साहसिक अस्वीकृति होगी. फिलिस्तीन देश की मान्यता शांति प्रक्रिया को विफल नहीं करेगी, बल्कि यह शांति प्रक्रिया को बचायेगी और उसे जीवित रखेगी. **-फातिमा पयमान**

बोधि वृक्ष

जुनून और करुणा

सामान्यतः करुणा को दयालुता के रूप में बताया जाता है. दयालुता तभी प्रासंगिक है जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार की असहाय अवस्था में हो. अधिकांश मनुष्य जब अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तो वे अपने प्रति दयाभाव नहीं चाहते. वे स्वीकृति, सम्मान, प्यार पाना चाहते हैं. वास्तव में करुणा एक सर्वव्यापी जुनून है. जब मैं सर्वव्यापी कहता हूं, तो जुनून अनिवार्य रूप से एक विशिष्ट प्रक्रिया है. जब दो लोग जुनूनी होते हैं, तो उनके लिए दुनिया गायब हो जाती है. जुनून की यही सुंदरता है कि यह विशिष्ट है, आपके जुनून में दुनिया गायब हो जाती है. करुणा जुनून से कई गुना बड़ी होती है. करुणा दयाभाव की एक शुष्क स्थिति नहीं है कि आप हर किसी से ऊपर खड़े हैं और सबके प्रति दयाभाव रख रहे हैं. यह सक्रिय जुड़ाव की अवस्था है जो जुनूनी है. जिस पर भी आप अपनी नजर डालते हैं, उसके प्रति आप जुनूनी हो जाते हैं. वह हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, वह पृथ्वी जिस पर आप चलते हैं, वह भोजन जो आप खाते हैं और जिन लोगों को आप देखते हैं तथा नहीं देखते हैं, आप जिस भी चीज के प्रति सचेतन हैं, आप उसके प्रति पूरी तरह से जुनूनी हैं. जब आपके जुनून में सब कुछ शामिल हो जाता है, तब वह करुणा बन जाती है. तो करुणा जुनून से रहित नहीं है, यह जुनून का एक बड़ा आयाम है. करुणा निश्चित रूप से जुनून की क्रमिक वृद्धि नहीं है. ऐसा नहीं है कि आज आप एक व्यक्ति के साथ, कल दो के साथ, परसों दस से पच्चीस के साथ करुणामय हो सकते हैं... नहीं. जब आप मनोवैज्ञानिक अवस्था में होते हैं, तो आपके विचार और भावनाएं आपके अस्तित्वगत अनुभव से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं. इस अवस्था में आप अधिक से अधिक केवल जुनून को ही जानेंगे. दुर्भाग्य से, अधिकांश लोग जुनून को उसकी संपूर्णता में नहीं जानते. जुनून एक शानदार चीज है. यदि आपका बोध आपके मन के दायरे को पार कर जाता है, और आपका जीवन बहुत अस्तित्वगत हो जाता है, तब आप अपने अनुभव में स्पष्ट रूप से समझते हैं- कि जो यहां है वह एक विशाल व्यापक जीवन है और आप उसमें केवल एक छोटी सी घटना हैं. **-सद्‌गुरु जग्गी वासुदेव**

विश्व शरणार्थी दिवस

शरणार्थियों के लिए स्थायी समाधान की जरूरत

देवेंद्रराज सुथार
टिप्पणीकार
devendrakavi1@gmail.com

हर वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है. यह दिन दुनियाभर में शरणार्थियों और विस्थापितों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है. इसका उद्देश्य संघर्ष, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपने घरों से पलायन करने को मजबूर शरणार्थियों के लिए सुरक्षा, सहायता और स्थायी समाधान की आवश्यकता को उजागर करना है. इस वर्ष इस दिवस का विषय है, 'घर से दूर आशाः एक ऐसी दुनिया जहां शरणार्थी हमेशा शामिल हों.' यह विषय शरणार्थियों के लिए समावेश और समर्थन के महत्व पर जोर देता है. यह सुनिश्चित करता है कि उनका स्वागत किया जाए और समुदायों में एकीकृत किया जाए, जिससे उन्हें अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने की अनुमति मिले.

उल्लेखनीय है कि 2023 के अंत तक दुनियाभर में 11.4 करोड़ (114 मिलियन) से अधिक लोग जबरन विस्थापित हो चुके हैं. आज भारत में तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान और कम संख्या में ही सही, पर सोमालिया और फिलिस्तीन से भी शरणार्थी आ रहे हैं. यह ध्यान देने योग्य है कि भारत शरणार्थी संरक्षण से संबंधित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कानून शरणार्थी अभिसमय, 1951 और इसके 1967 के प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है. इस प्रकार कानूनी तथ्यों के अभाव तथा नीतिगत अस्पष्टता के कारण भारत की शरणार्थी नीति दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों द्वारा निर्देशित होती है. साथ ही, यह कहीं न कहीं 'राजनीतिक हित' से भी प्रेरित होती है. भिन्न-भिन्न कारणों से रिकॉर्ड संख्या में लोगों को अपने घरों से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. इसलिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को शरणार्थियों को घर से दूर रहने के दौरान अधिक उम्मीद और अवसर देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए. शरणार्थियों का समर्थन करने का सबसे प्रभावी तरीका उन्हें उन समुदायों में शामिल करना है जहां उन्हें सुरक्षा मिली है. इसका अर्थ है कि वे नौकरियों के लिए आवेदन, स्कूलों में प्रवेश और आवास तथा स्वास्थ्य जैसी सेवाओं का उपयोग कर सकें.

समावेशन शरणार्थियों और विस्थापित लोगों के लिए दीर्घकालिक समाधान का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे उन्हें एक नये देश में पनपने या अपने गृह देश में सुरक्षित वापसी के लिए तैयार होने का अवसर मिलता है. बहरहरल, शरण चाहने वाले अनिश्चित स्थिति में हैं और एक खुला राष्ट्र उनके लिए आशा की किरण है. शरणार्थियों को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनका समर्थन किया जाना चाहिए, परंतु यह स्थानीय जनसंख्या के मूल्य पर नहीं होना चाहिए. इसलिए जरूरी है कि भारत एक परिभाषित शरणार्थी नीति बनाये.

आपके पत्र

जलवायु परिवर्तन से बढ़ा संकट

जलवायु में आये आसामान्य परिवर्तन से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. धरती का तापमान काफी बढ़ गया है, जिसके कारण देश के कई प्रदेशों में भीषण गर्मी पड़ रही है. अधिकतम व न्यूनतम तापमान में मामूली अंतर के कारण रात में भी मौसम गर्म रह रहा है. इसका सीधा असर खेती-किसानी पर पड़ रहा है. समय पर बारिश नहीं हो रही है. बेमौसम अधिक बारिश तबाही ला रही है. यह परिवर्तन आम लोगों के लिए चेतावनी है. यदि समय रहते पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे नहीं आये, तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.

अवनीश कुमार गुप्ता, पटना

अपने बयान को वापस लें सांसद

बिहार के एक निर्वाचित सांसद ने जाति विशेष को लेकर कहा कि इनका काम नहीं करूंगा. यह बयान समाज के लिए धातक है. किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए. क्योंकि वह अपने क्षेत्र की जनता की ओर चुना गया है. सांसद को अपनी शपथ याद रखनी चाहिए. बिना किसी विद्वेष व दुर्भावना के क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी इन पर होती है. उन्हें सार्वजनिक रूप से अपने क्षेत्र की जनता से माफी मांगते हुए अपना बयान वापस ले लेना चाहिए. यह समाज के हित में होगा. नहीं तो नयी परंपरा शुरू हो जायेगी.

आनंद पांडेय, समस्तीपुर

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। –वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

मौसम चक्र में बदलाव से नित नई आपदाओं के खतरे

जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में मौसम चक्र गड़बड़ा रहा है। तापमान बढ़ने के पुराने आंकड़े पीछे छूटते जा रहे हैं। भीषण गर्मी का यह दौर इसलिए ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि इससे लोगों की जान पर बन आई है। मक्का में हज के लिए गए यात्रियों की मौत को लेकर सामने आया ताजा आंकड़ा बताता है कि बढ़ते तापमान और इससे होने वाले वैश्विक संकट के मुकाबले की दिशा में अभी समुचित प्रयास नहीं हो पाए हैं। न ही विभिन्न देशों की सरकारें वैज्ञानिकों की ओर से जारी चेतावनियों को लेकर ज्यादा गंभीर नजर आ रही हैं।

गर्मी से होने वाली मौतों की खबर उन सब देशों से आ रही है, जहां जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम चक्र ने भी करवट बदली है। होने यह लगा है कि गर्मी के मौसम में तेज गर्मी और सर्दी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोगों को शायद यह लगता है कि भीषण गर्मी का यह दौर भी मौसम चक्र का हिस्सा है और कुछ समय बाद इसकी तीव्रता अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन, राहत मिलने की जगह हालात विकट हो रहे हैं। मौसम में यह बदलाव आपदा में बदल रहा है। यही कारण है कि तापमान की मार से लोगों की जान तक जा रही है। बड़ी संख्या में हज यात्रियों की मौतें भी इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि सऊदी अरब सरकार ने भीषण गर्मी से हज यात्रियों को बचाने के पर्याप्त उपाय नहीं किए। साथ ही हज यात्रियों ने भी गर्मी के तेवर को गंभीरता से नहीं लिया। इन दिनों भारत के विभिन्न हिस्से भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं। इसकी वजह से मौतों के मामले भी सामने आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार और उत्तरप्रदेश में गर्मी के कारण 25 मतदान कर्मियों की मौत ने भी गर्मी की भीषणता को उजागर किया था। यह सही है कि गर्मी ने अचानक ही रौद्र रूप नहीं लिया है। पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल, वनों की कटाई और अन्य स्रोतों से होने वाला ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन पृथ्वी को अपेक्षाकृत काफी तेजी से गर्म कर रहा है। इससे वैश्विक औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। समुद्री स्तर के साथ तूफान की तीव्रता में भी वृद्धि हो रही है।

बार-बार कहा जा रहा है कि यदि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया और इसे कम करने के प्रयास नहीं किए गए तो हालात लगातार गंभीर होते जाएंगे। गर्मी की भयावहता और उससे हो रही मौतों से सभी देशों को सबक लेना चाहिए और गर्मी से बचाव के उपाय करने के साथ ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के लिए ठोस कदम उठाने पर ध्यान देना चाहिए।

विश्व शरणार्थी दिवस आज : पलायन से लेकर पुनर्वास तक के बीच कतार में हैं करोड़ों वैध-अवैध विस्थापित

अस्तित्व के संघर्ष के साथ बढ़ता शरणार्थी संकट

नवनीत शर्मा
हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्यापनरत
@patrika.com

सभ्यताओं के टकराव के सभ्यतापूर्वक हल की गुंजाइश ही इस संतप्तता से बचा सकती है। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं 'मुहाजिरों' को रिहायश तो मुहैया करा सकती हैं, पर वतन की सरजमीं नहीं।

'अपनी माटी' की संकल्पना शायद घुमंतु जीवन के अवसान के साथ ही शुरू हुई होगी। इसी संकल्पना के विस्तारण ने अपनी गली, मोहल्ला, गांव, देस-परदेस की अवधारणाओं को जन्म दिया। बसने के लिए एक खोह या कंदरा भी घर के नाम से सुशोभित होती है और कोई घर अपने निवासियों को नहीं निकालता और यदि निकालता है तो उसे सीमांत पर ले जाकर पलायन करने को मजबूर करता है। पलायन का शब्द और संगीत दोनों ही वीभत्स भाव पैदा करते हैं। पलायन के साथ ही व्यक्ति न केवल बेघर हो निराश्रित हो जाता है, साथ ही वैयक्तिक नागरिकता खो शरणार्थी के सर्वनाम में तब्दील हो जाता है।

शरणागत की रक्षा करने वालों की प्रशंसा में अनेकों वीरगाथाएं हैं पर शरणागत होना हमेशा ही एक अभिशाप रहा है। अपना और अपनों की जीवन रक्षा के लिए किया गया पलायन हमेशा रणछोड़ बनाता है, कमजोर नहीं। दुनिया भर में अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई हमेशा ताकत और वर्चस्व से तय हुई, जिसमें अल्पसंख्यक और हाशिये के लोग या तो हताहत हुए अथवा पलायन करने को मजबूर हुए।

इस समय दुनिया भर में लगभग बारह करोड़ 'वैध' शरणार्थी हैं। इनमें अवैध शरणार्थियों की संख्या नहीं जोड़ी जा सकती क्योंकि उन्हें कोई नहीं गिनता, न पलायन को मजबूर करने वाला देश, न ही शरण देने वाला देश। ये शरणार्थी तो वे हैं जो राजनीतिक, धार्मिक, भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, भाषायी, नस्लीय, जातीय, रंग, यौनिकता इत्यादि चिह्नित भेदों की वजह से पलायन करते हैं। अपने ही देश में 'परदेसी' होने की व्यथा हम ने कोरोना काल में सड़कों पर पैदल चलते देखी है। जीवन, सुरक्षा और बेहतर कल की आस लिए सैकड़ों लोग अपने घरों से भागते हैं। इस संख्या का एक तिहाई हिस्सा उस पीढ़ी का है जो अभी 18 बरस की भी नहीं हुई। ये वे नाबालिग हैं जिन पर वैध वयस्क नागरिक होने से पहले ही शरणार्थी होने का ठप्पा लग जाता है। इस आबादी में बहुत-से अबोध तो देश और भूगोल के बीच अंतर भी नहीं कर पाते।

12 करोड़ विस्थापितों में लगभग 68 प्रतिशत अपने ही देश में इस दंश से पीड़ित हैं तो लगभग चार करोड़ राष्ट्र के स्तर पर शरणार्थी हैं। 60 लाख की जनसंख्या राजनीतिक शरणार्थी के दर्जे के लिए कतार में है और 50 लाख लोग अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। जिस दुनिया में पूरी आबादी की तुलना में दोगुनी बंदूक की गोलियों का निर्माण और खपत हो, वहां कौन कब तक परलोक से यहां शरणार्थी है, कहा नहीं जा सकता। इन शरणार्थी-विस्थापित लोगों को घुसपैठिया करार देकर एक अलग तरह की राजनीति भी जन्म लेती है जिससे एक अलग तरह का उग्र राष्ट्रवाद पनपता है। लड़ना हमेशा पर्याय रहा है भागने का, भागना विपर्यय है और मानवजीवन की मानवरचित विद्रूपता भी। नदी की बाढ़ की चपेट से भागे हुए व्यक्ति और युद्ध की चपेट से भागे हुए व्यक्ति में एक बड़ा अंतर होता है। बाढ़ का उन्माद उतर सकता है, युद्ध और विभेदीकरण का उन्माद केवल स्वरूप बदल सकता है, मिटता नहीं है। पलायन को मजबूर व्यक्ति की खलनायक के प्रति हिंसा और नफरत पनपती है और हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है। यह खलनायक प्रायः भिन्न देश, धर्म, रंग, नस्ल, जाति, भाषा के होते हैं और पलायनकर्ता केवल उस खलनायक से ही नहीं अपितु उसकी पूरी सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ लड़ने का भाव रखता है। पलायन से अभिशप्त व्यक्ति अपनी वैयक्तिक नागरिकता की खोज में हर सामूहिक अस्मिता या पहचान का परस्पर विरोध करता है।

शरणार्थी व्यक्ति अवसाद, कुंठा, प्रतिकार इत्यादि मनोभाव लेकर नई जमीन की तलाश में होता है। धान और आदमी में शायद यही अंतर है। धान का बेहन लगता है जबकि अपनी जड़-जमीन से उखाड़ा हुआ व्यक्ति कहीं और नहीं पनप पाता, क्योंकि उसके सपनों का भूगोल उसे वह जलवायु नहीं देता जहां से वह पलायन करके निकला था। शरणार्थी बच्चों के सपने में उसके वर्तमान और उसके मां-बाप के अतीत के देश-जलवायु में फर्क होता है जो उसे कहीं का स्पष्ट सपना नहीं देखने देता।

कुछ देश शरणार्थी अथवा पलायनकर्ता को न चाहते हुए भी उनको पहले की तरह बसने में सहायता करते हैं और कुछ देश उन्हें घुसपैठिया कह कर भगाने के बारे में विचार करते हैं। कुछ देशों के विराटमना होने से मामला नहीं सुलटेगा। सभ्यताओं के टकराव के सभ्यतापूर्वक हल की गुंजाइश ही इस संतप्तता से बचा सकती है। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं 'मुहाजिरों' को रिहायश तो मुहैया करा सकती हैं, पर वतन की सरजमीं नहीं।

फैक्ट फ्रंट

विक्टोरिया को बनाया गया ब्रिटेन की रानी

विलियम चतुर्थ की मृत्यु के बाद 20 जून 1837 को विक्टोरिया को ब्रिटेन की रानी बनाया गया। उनके शासनकाल के दौरान ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। भारत का शासन प्रबन्ध 1858 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ से लेकर ब्रिटिश राजसत्ता को सौंप दिया गया। इसकी उद्घोषणा महारानी विक्टोरिया के नाम से की गई थी। वे भारत में काफी लोकप्रिय थीं। अपने अधिकारों और शासन को लेकर महारानी विक्टोरिया इतनी सख्त थीं कि उन्होंने अपनी मां तक का दखल स्वीकार नहीं किया।

बदलता युद्धक्षेत्र: तकनीक को महत्त्व देने के साथ बढ़ाना होगा बजट

यूक्रेन के नौसैनिक ड्रोन की सफलता से यूएस को सीखने की जरूरत

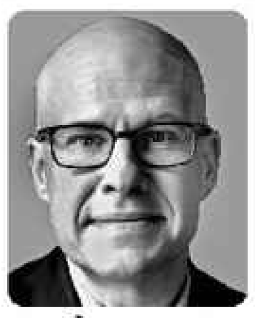

मैक्स बूट
'द रोड नॉट टेकन: एडवर्ड लैंसडेल एंड द अमेरिकन ट्रेजेडी इन वियतनाम' के लेखक
द वाशिंगटन पोस्ट से विशेष अनुबंध के तहत

काला सागर में यूक्रेन की अप्रत्याशित सफलता नौसेना के युद्धपोतों के इतिहास में ऐतिहासिक उपलब्धि हो सकती है। अपनी कोई नौसेना नहीं होने के बाद भी यूक्रेन ने रूस के कम से कम एक तिहाई काला सागर बेड़े को क्षतिग्रस्त कर दिया है, रूसी नौसैनिक नाकाबंदी को तोड़ा है और अपना अनाज निर्यात करने के लिए काला सागर मार्ग को फिर खोल दिया है। यूक्रेन का निर्यात अब युद्ध-पूर्व के दौर में लौट रहा है। यह उसकी युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को बड़ा वरदान है। बड़ा सवाल: यूक्रेन ने यह असंभव उपलब्धि कैसे हासिल की? इस सवाल के जवाब का एक हिस्सा यूक्रेन का शक्तिशाली एंटी-शिप क्रूज मिसाइलों, जिसमें घरेलू स्तर पर निर्मित नेपच्यून भी शामिल है, का इस्तेमाल करना है। नेपच्यून ने ही 2022 में रूस के काला सागर बेड़े के जंगी जहाज मोस्क्वा को डुबोया था। अब यूक्रेन ने भी अपने खुद के मानवरहित सतह जहाजों (यूएसवी) जिसे आम बोलचाल की भाषा में समुद्री ड्रोन कहा जाता है, को विकसित कर शानदार नवाचार किया है। ये ड्रोन रूसी युद्धपोतों के लिए काफी घातक साबित हुए हैं।

यूक्रेन द्वारा विकसित नौसैनिक ड्रोन मागुरा वी5 और सी बेबी दोनों ही मानवरहित स्पीडबोट्स हैं जिनमें भारी मात्रा में विस्फोटक लादा जा सकता है और इससे मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। कैमरे और सैटेलाइट लिंक्स से लैस ये ड्रोन 50 मील प्रति घंटे तक की रफ्तार से उड़ सकते हैं और राडार की पकड़ से भी दूर हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनकी उत्पादन लागत काफी कम है और इससे किसी भी यूक्रेनी कर्मचारी की जान जोखिम में नहीं पड़ती। जबकि दूसरी ओर युद्धपोतों के निर्माण में वर्षों का समय और करोड़ों डॉलर खर्च हो जाते हैं। 'न्यू अमरीका' के एक थिंकटैंक पी डब्ल्यू सिंगर कहते हैं- 'जो भी यह सोचते हैं कि यह भविष्य में युद्ध के लिए गेमचेंजर नहीं है, वे अपनी आंखों पर स्वेच्छा से पट्टी बांधे हुए हैं।' पूर्व नाटो कमांडर और रिटायर्ड एडमिरल जेम्स स्टावरिडिस भी ऐसा ही मानते हैं। वह कहते हैं-'हम समुद्री युद्ध में निर्णायक मोड़ पर हैं। अमरीका जैसी शक्तिशाली नौसेनाएं जितनी जल्दी इसके सफल कारकों को समझ लेंगी, अशांत 21वीं सदी में बड़ी लड़ाई में जीवित रहने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। समय आ गया है कि अब ध्यान मानवयुक्त युद्धपोतों से हटाकर सस्ते मानवरहित जहाजों की ओर केंद्रित किया जाए।' अमरीकी सेना के बड़े अधिकारी वैचारिक स्तर पर युद्ध की बदलती प्रकृति को स्वीकार करते हैं। नेवी कमांडरों को यह अहसास है कि ड्रोन, जो समुद्र की सतह के साथ-साथ इसके ऊपर और नीचे भी अपना दम दिखा सकते हैं, ताइवान पर हमले की चीन की किसी भी कोशिश को शिकस्त देने में महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं। पर अमरीकी सेना अभी भी अत्याधुनिक मानवरहित प्रणालियों के लिए आवश्यक संसाधन नहीं जुटा रही है। वजह उसका अपनी मानवयुक्त 'विरासत' के साथ काफी मजबूती से जुड़ा होना है। सारी गलती नौसेना की भी नहीं है। अन्य सेवाओं की तरह यह भी 'आयरन ट्राइएंगल' यानी डिफेंस कॉन्ट्रेक्टरों, पेंटागन के नौकरशाहों और कांग्रेस के सदस्यों पर आश्रित है। 2022 में नौसेना ने यांत्रिक खराबियों से घिरे नौतटीय लड़ाकू जहाजों को सेवानिवृत्त करने की कोशिश की, पर कांग्रेस ने आदेश दिया कि इनमें से पांच जहाज सेवा में बने रहें क्योंकि उन्हें रिटायर करने से नुकसान होगा। नौसेना रिसर्च के पूर्व प्रमुख लोरिन सेल्बी का कहना है- 'निश्चित रूप से नौसेना की ड्रोन प्रौद्योगिकी अपनाने की गति बहुत धीमी है। अच्छी खबर है कि यह मान्यता मिल गई है कि ड्रोन नौसैनिक युद्ध में भूमिका निभाएंगे। बुरी खबर यह है कि बजट इसके अनुकूल नहीं है।'

सिर्फ यूएस नेवी ही नहीं है जो इसका लाभ उठाने में बहुत धीमी है। ताइवान भी अपने सैन्य बलों में मानवरहित प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए कम आगे आया है। ताइवान मानवयुक्त युद्धपोतों, एयरक्राफ्ट, यहां तक कि टैंकों पर भारी-भरकम खर्च करना जारी रखे हुए है। जबकि कम आर्थिक संसाधनों वाला यूक्रेन हर साल कम से कम 1 मिलियन ड्रोन बना रहा है और उसे युद्ध में हर महीने 10,000 से अधिक ड्रोन की क्षति हो रही है। अमरीका के एक अन्य सहयोगी फिलीपींस को भी ड्रोन की ओर रुख करने की जरूरत है।

23 डी एनरो: 'सिर पर छत' की भीड़

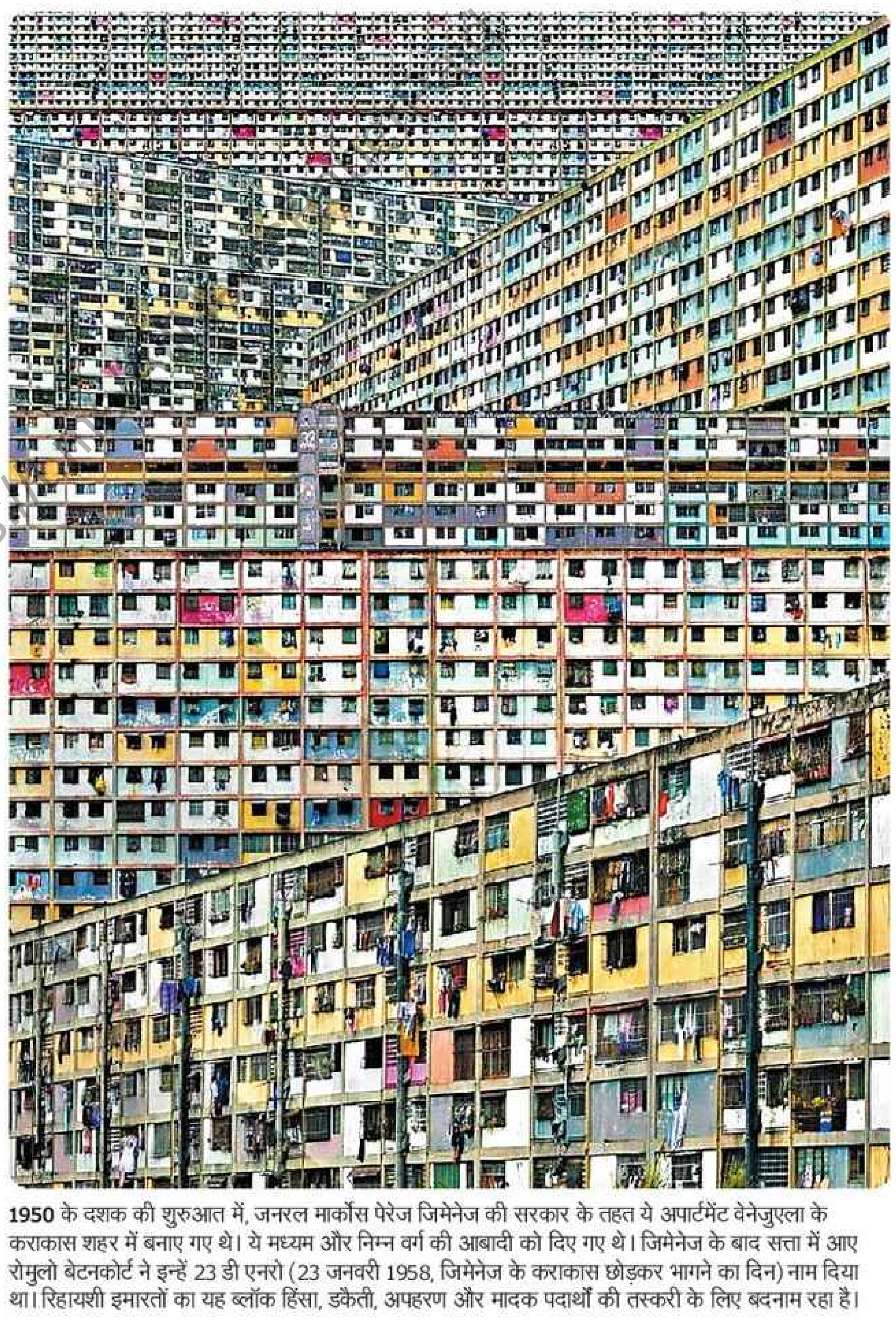

1950 के दशक की शुरुआत में, जनरल मार्कोस पेरेज जिमेनेज की सरकार के तहत ये अपार्टमेंट वेनेजुएला के कराकास शहर में बनाए गए थे। ये मध्यम और निम्न वर्ग की आबादी को दिए गए थे। जिमेनेज के बाद सत्ता में आए रोमुलो बेटनकोर्ट ने इन्हें 23 डी एनरो (23 जनवरी 1958, जिमेनेज के कराकास छोड़कर भागने का दिन) नाम दिया था। रिहायशी इमारतों का यह ब्लॉक हिंसा, डकैती, अपहरण और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए बदनाम रहा है।

प्रसंगवश

'ऊंट के मुंह में जीरा' साबित हो रहे प्रदेश के सरकारी कॉलेज

सरकारी कॉलेजों में प्रवेश को लेकर मारामारी से सरकारी दावों और हकीकत में अंतर साफ नजर आता है

शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी अहम सुविधाएं हैं जिन तक नागरिकों की पहुंच को सहज बनाना कल्याणकारी सरकारों की पहली जिम्मेदारी होती है। सरकारें ऐसी व्यवस्था बनाने का दावा तो खूब करती हैं लेकिन राजस्थान में सरकारी कॉलेजों में दाखिले के लिए जिस तरह मारामारी चल रही है, वह सरकारी दावों और हकीकत में अंतर का एक ताजा उदाहरण है। पिछले दिनों ही सीनियर सेकंडरी स्तर की कक्षाओं के परिणाम आए हैं और अब उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थी सरकारी कॉलेजों के चक्कर लगा रहे हैं। इसकी वजह है इन कॉलेजों में उपलब्ध सीटों की संख्या, जो कि विद्यार्थियों के लिए 'ऊंट के मुंह में जीरा' साबित हो रही है। यह स्थिति तब है जबकि पिछली सरकार ने प्रदेश में तीन सौ से ज्यादा सरकारी कॉलेज खोलने का दावा किया था। प्रवेश से वंचित रहने की आशंका के चलते बड़ी संख्या में छात्र महंगे निजी कॉलेजों में प्रवेश लेने के लिए मजबूर हैं।

प्रदेश में ऐसे कई इलाके हैं जहां उच्च शिक्षा के लिए सरकारी कॉलेजों के अलावा कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। ऐसे में यदि इन सरकारी कॉलेजों में भी सीट की अनुपलब्धता के कारण किसी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं मिले तो गृहनगर से दूर किसी निजी कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए वह मजबूर हो जाता है। जिला मुख्यालयों की ही बात नहीं है, राजधानी जयपुर के भी तमाम सरकारी कॉलेजों में प्रवेश को लेकर खूब मारामारी है। अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 12वीं पास करने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या लाखों में है जबकि सरकारी कॉलेजों में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए सीटें हजारों में। ऐसे में प्रवेश के लिए कटऑफ भी बहुत ऊंचे स्तर पर रहती है। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया था कि विद्यार्थियों को उनके घर के पास ही उच्च शिक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से उनके कार्यकाल में 303 कॉलेज खोले गए थे। हकीकत यह है कि इनमें से अधिकांश की खुद की इमारतें तक नहीं हैं। सरकार यदि स्कूल-कॉलेज खोलती है तो जरूरी सुविधाएं जुटाना भी उसकी जिम्मेदारी बनती है। चिंता अब यही है कि उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश का संकट सिर पर आ गया है और सरकार की इससे निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं है। सरकार न तो अपने कॉलेजों में सीट और सुविधाओं के विस्तार को लेकर हरकत में नजर आ रही है और न ही मनमानी फीस वसूलने वाले निजी कॉलेजों पर शिकंजा कसने को लेकर।

-नितिन मित्तल
nitin.kumar@in.patrika.com

सामयिक: उपभोक्ता व्यय के आंकड़े हमारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसकी भी समीक्षा जरूरी है

बढ़ती महंगाई और सरकारी आंकड़ों की भूलभुलैया

प्रो. सी.एस. बरला
कृषि अर्थशास्त्री, विश्व बैंक और योजना आयोग से संबद्ध रह चुके हैं
@patrika.com

हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी किए आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ महीनों में देश में खुदरा महंगाई में कमी हुई है, जबकि थोक महंगाई में वृद्धि हुई है। एक आम व्यक्ति के लिए यह एक पहेली है।

पिछले दो वर्षों में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि 2022-23 के बीच विश्व में भूख से पीड़ित लोगों की संख्या 69 करोड़ से बढ़कर 78.3 करोड़ हो गई। इसका यह अर्थ हुआ कि 2023 में विश्व की लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या भुखमरी से पीड़ित थी। इसी के विपरीत भारत में राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन यानी एनएसएसओ द्वारा उपभोक्ता व्यय पर एकत्रित आंकड़ों से ज्ञात हुआ था कि 2011–12 तथा 2022–23 के बीच शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में परिवारों का उपभोग पर किया जाने वाले व्यय का जिनी गुणांक कम हुआ है। इसका अर्थ यह है कि इस अवधि में ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्र में उपभोक्ता व्यय की विषमताओं में कमी हुई है।

उपभोक्ता व्यय के तथ्य : जिनी गुणांक विभिन्न वर्गों के बीच उपभोक्ता व्यय की विषमताओं का प्रतीक है। यह गुणांक जितना अधिक है उसका आशय यह है कि कुछ ही व्यक्ति उपभोक्ता व्यय का अधिक भाग व्यय करते हैं। परोक्ष रूप में यह देश में व्याप्त गरीबी के उच्च स्तर का प्रतीक है। अन्य शब्दों में, उपभोक्त व्यय का जिनी गुणांक यदि कम है तो यह गरीबों के कम स्तर का परिचायक होगा। भारत के नीति आयोग के प्रमुख इसी आधार पर यह निष्कर्ष देते हैं कि 2011-12 तथा 2022-23 के बीच भारत में गरीबों का अनुपात 5% से कम हो गया। 2011-12 में शहरी क्षेत्र में उपभोक्ता का जिनी गुणांक 0.363 था और 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता व्यय का जिनी गुणांक 0.283 था। 2022-23 में शहरी क्षेत्र का जिनी गुणांक 0.314 था और 2022-23 में ग्रामीण क्षेत्र का जिनी गुणांक 0.286 था। इस प्रकार दोनों ही क्षेत्रों में उपभोक्ता व्यय में कमी हुई है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वे से यह बात सामने आई कि आलोच्य अवधि में उपभोक्ता परिवारों में निचले 50 प्रतिशत परिवारों की उपभोक्ता व्यय के अनुपात में अपेक्षाकृत अधिक तेजी से वृद्धि हुई है। यह एक अच्छा संकेत भी माना जा सकता है क्योंकि उपभोक्ता परिवारों में हम जितनी नीचे की पायदान पर जाएंगे हमें निर्धन लोग ही अधिक दिखाई देंगे।

राज्यवार उपभोक्ता व्यय में अंतर: इस तथ्य को एनएसएसओ ने स्वीकार किया है कि खाद्य पदार्थों की कीमतों तथा उपभोक्ताओं की आदतों में पर्याप्त अंतर होने के कारण सारे राज्यों के परिवारों के उपभोक्ता व्यय की तुलना करने में कठिनाई होती है। इसका एक समाधान प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय की तुलना द्वारा हो सकता है। इन स्तरों में भी विभिन्न राज्यों में काफी विषमताएं हैं। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता व्यय 2468 रुपए है जबकि शहर में इसका स्तर 4462 रुपए है। इसके विपरीत केरल में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय 2920 रुपए तथा शहरी क्षेत्र में 8175 रुपए है। अस्तु, उपभोक्ता व्यय के जिनी गुणांक में कमी या वृद्धि से यह तो ज्ञात हो सकता है कि उपभोक्ता व्यय के वितरण में विषमताएं बढ़ीं या कम हुई लेकिन इसकी सार्थकता कितनी है तथा नीति निर्धारण में यह कहां तक उपयोगी है, यह कहना संभव नहीं है। परिवारों के लिए महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों का स्तर कितना है तथा उसकी आय के स्तर में अनुपात कितना है। यह भी उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता व्यय के आंकड़े हमारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसकी भी समीक्षा जरूरी है।

मुद्रास्फीति का आकलन: हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी किए आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ महीनों में देश में खुदरा महंगाई में कमी हुई है, जबकि थोक महंगाई में वृद्धि हुई है। एक आम व्यक्ति के लिए यह एक पहेली है। वह इन आंकड़ों के आधार पर यह निर्णय नहीं कर पाता कि मुद्रास्फीति की यह दर उसके लिए प्रतिकूल है अथवा अनुकूल।

वस्तुतः खुदरा तथा थोक मूल्य सूचकांकों की गणना करते समय न केवल वस्तुओं की संख्या में अंतर है और न ही मूल्य में समरूपता है। इस कारण स्थिति के बारे में सटीक जानकारी नहीं मिलती। आवश्यकता इस बात की है कि सैद्धांतिक पृष्ठभूमि में समरूपता लाई जाए जिससे आम व्यक्ति किसी प्रकार के भ्रम में ना रहे ।

आपकी बात

बनी रहे विश्वसनीयता

ईवीएम को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए, ताकि चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे। किसी के मन में कोई संदेह नहीं रहना चाहिए।
-राकेश शर्मा, जयपुर

आज का सवाल

गर्मी की भीषणता से निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

इसे स्कैन करें

पत्रिकायन का सवाल था, 'ईवीएम पर बार-बार सवाल क्यों उठते हैं? पाठकों की प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।
https://rb.gy/9dsusa

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, गुरुवार 20 जून 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

क्या नालंदा ज्ञान की वापसी करेगा ?

बुधवार को बिहार के उस नालंदा विश्वविद्यालय के नये भवन का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकार्पण किया जो करीब दो हजार साल स्थापित हुआ था। तकरीबन 600 वर्षों तक भारत ही नहीं, सम्पूर्ण दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण विद्या-केन्द्र रहा। मूलत: यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा द्वारा बनाया गया था परन्तु इसमें हीनयान शाखा के साथ अन्य धर्मों के दर्शन तथा कई विषयों का अध्ययन होता था। इसमें भारत से बाहर के कई छात्र व विद्वान रहकर पढ़ने आते थे। कई विदेशियों, विशेषकर चीन के ह्वेनसॉंग और इत्सिंग के यात्रा वृत्तांतों में भी इसका वर्णन है जो इसमें रहे भी। कहते हैं कि इसमें 10 हजार छात्रों के लिये 2000 शिक्षक हुआ करते थे। मोदी ने जब इसका लोकार्पण किया तो उस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा 17 देशों के राजदूत मौजूद थे। कुछ समय पहले भारत में सम्पन्न हुए जी-20 के सम्मेलन में दिये अपने भाषण में मोदी ने इसका एक बड़ा सा चित्र सभी को दिखलाया था और भारत की गौरवमयी विरासत के परिप्रेक्ष्य में इसका जिक्र किया था।

इसमें कोई शक नहीं कि नालंदा विवि भारत की ज्ञान परम्परा का एक बड़ा संस्थान रहा था। दूसरा तक्षशिला विश्वविद्यालय भी था जो अब पाकिस्तान (रावलपिंडी) के हिस्से में चला गया है। बहरहाल, इतिहास बताता है कि साल 1199 में इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने आग लगवा दी थी। अब मोदी सरकार इसका पुनरुत्थान करने जा रही है। बिहार की राजधानी पटना से करीब 88 किलोमीटर दूर नालंदा जिले के राजगीर में स्थित इस विश्वविद्यालय में 24 कक्ष हैं जिनका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। देश की हर ऐसी विरासत का लौटना खुशी व गर्व का विषय है। इसलिये यह एक स्वागत योग्य कदम है। वैसे यह तो सच है कि नालंदा विवि के जलने से भारत की विशाल ज्ञान सम्पदा को बड़ा नुकसान हुआ था; और जैसा कि कहा जाता कि उनमें इतनी पुस्तकें थीं कि उसकी लाइब्रेरी कई माह तक जलती रही। दूसरी तरफ यह भी सच है कि इस सम्पदा के नुकसान को भारत ने जल्दी ही वापस पा लिया था। कालांतर में जो मुसलमान शासक आये, उन्होंने अरबी, फारसी के साथ उर्दू, रेख़्ता और हिन्दी साहित्य को बढ़ावा ही दिया। संस्कृत के साथ अनेक भाषाएं फलती-फूलती रहीं। अवधी, ब्रज जैसी कई लोकभाषाओं में कई रचनाएं लिखी गयीं और उनके जरिये भी ज्ञान गंगा सतत प्रवाहित होती रही। अमीर खुसरो से प्रारम्भ खड़ी बोली के बाद अंग्रेज जब आये तो वे अंग्रेजी के साथ पाश्चात्य देशों का ज्ञान लेते आये। उनके जरिये औद्योगिक, तकनीकी व व्यवसायिक विकास हुआ। उन्हीं के खोले गये स्कूलों व कॉलेजों-विश्वविद्यालयों में आधुनिक शिक्षा दी जाने लगी। मध्ययुगीन ज्ञान का स्थान नूतन ज्ञान ने लिया। यह कहने में किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिये कि आजादी के बाद भारत ने बहुत कम समय में जो विकास किया उसका बड़ा कारण देश में पहले से पहुंच चुकी आधुनिक शिक्षा पद्धति थी। यह अलग बात है कि वाट्सएप यूनिवर्सिटी ने लोगों को अब बेमिसाल ज्ञान यह दिया है कि विदेशियों ने परम्परागत भारत की गुरुकुल परम्परा को खत्म कर दिया ताकि भारत की संस्कृति को नष्ट किया जा सके।

यह बात तो सही है कि प्राचीन शिक्षा पद्धति समाप्त हो गयी लेकिन यह भी सच है कि उसमें वर्तमान समय की चुनौतियों का कोई जवाब नहीं था और कथित गुरुकुल पद्धति अभिजात्य वर्ग के लोगों तक ही सीमित थी। कुछ धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन पर टिकी प्राचीन शिक्षा का दायरा बहुत संकीर्ण था और वह व्यवहारिक जीवन से मेल नहीं खाती थी। ऐसा नहीं कि वह सारा ही अध्ययन बेकार था जो वेद-वेदांगों, पुराणों, उपनिषदों सहित धर्म ग्रंथों पर केन्द्रित था लेकिन जैसे-जैसे पूरी दुनिया विकसित होती गयी, यह ज्ञान व्यापक परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक होता चला गया। जिन्हें दिलचस्पी है, वे आज भी इनका अध्ययन कर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं।

भारत के विकास में विदेशों से आए ज्ञान ने भारत को कल-कारखाने, बड़े बांध, अस्पताल, सड़कें, पुल, इमारतें दीं, कृषि उत्पाद बढ़ाने के उपाय बताये, विभिन्न बीमारियों से मुक्ति के टीके व दवाएं दीं, कपड़ा मिलें खोलीं और देश को आत्मनिर्भर बनाया। भारत की इस ज्ञान परम्परा को आजाद भारत ने इसलिये जारी रखा क्योंकि हमारे राष्ट्र निर्माता जानते थे कि आधुनिक शिक्षण संस्थानों से न केवल हमारी समस्याओं के हल निकलेंगे वरन ऐसे नागरिक बनेंगे जिनका दृष्टिकोण उदार हो तथा वे विवेकवान हों। इसे जो सबसे बड़ा झटका लगा वह भारतीय जनता पार्टी के इसी दस साल के कार्यकाल में। ज्ञान की जितनी तौहीन और उपेक्षा इस काल में हुई वैसी भारत के बुरे से बुरे काल में भी नहीं हुई थी। नालंदा को जलाने का जो वक्त था वह मध्यकालीन था जब सब कुछ तलवारों से तय होता था। पिछले दशक भर से देखा यह गया कि सत्ता और तकनीकों का उपयोग आधुनिक ज्ञान को दबाने व मिटाने के लिये किया जा रहा है। राजनीतिक हिसाब चुकता करने के लिये ज्ञान के मुकाबले अज्ञान का साम्राज्य खड़ा किया गया ताकि उसके जरिये उस राजनैतिक विरासत को अपमानित किया जा सके जिसकी विचारधारा भाजपा व उसकी मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से नहीं मिलती। इसी दुर्भावना ने नालों से गैस बनाई, पकौड़े बनाने को रोजगार बताया और बादलों से राडार की नज़रों से लड़ाकू विमानों को छिपाया। इसलिये यह सवाल अपनी जगह से बिलकुल नहीं हटता कि पिछले दस वर्षों में देश में ज्ञान की जो दुर्दशा हुई है उसकी भरपायी क्या नालंदा के पुनर्जीवित

नीट और नालंदा के बीच उलझा देश

दुनियादारी

■ सर्वमित्रा सुरजन

एनडीए की सरकार गठित होने और नरेन्द्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के साथ ही उद्घाटनों का सिलसिला भी शुरु हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून को बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया और यहां एक बोधि वृक्ष का पौधा भी रोपा। भारत की ऐतिहासिक धरोहरों में जिन नामों का हमेशा उल्लेख होता है, नालंदा उनमें से एक है। इतिहासकारों के मुताबिक साल 427 में गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। 13वीं शताब्दी यानी 800 से अधिक वर्षों तक यहां विश्वविद्यालय संचालित होता रहा। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। नालंदा मगध काल में एक प्रसिद्ध बौद्ध महाविहार भी था। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 10 हजार छात्र पढ़ते थे, जिनके लिए 1500 अध्यापक हुआ करते थे। अधिकतर छात्र एशियाई देशों जैसे चीन, कोरिया , जापान, भूटान से आने वाले बौद्ध भिक्षु थे। जो औषधिविज्ञान, तर्कशास्त्र, गणित और बौद्ध सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने 7वीं शताब्दी में नालंदा की यात्रा की थी। जब ह्वेन त्सांग 645 ईसवी में चीन लौटे तो वे अपने साथ नालंदा से 6 सौ से अधिक बौद्ध धर्मग्रंथों को लेकर गए थे। जिनमें से अधिकतर का उन्होंने चीनी में अनुवाद भी किया था। नालंदा में एक अति समृद्ध पुस्तकालय भी था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने 12वीं सदी में नालंदा पर आक्रमण कर इसे तहस-नहस किया, तो कहा जाता है कि पुस्तकालय को आग लगा दी और यह आग कई महीनों तक धधकती रही। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि किसी आपदा को अतिरंजना के साथ पेश करना इंसानी फितरत है। लेकिन फिर भी यह तो तथ्य है ही कि एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय राजनीति का शिकार होकर खंडहर में बदल गया।

आज भले हम कहते रहें कि नालंदा आक्सफोर्ड से भी पुराना विश्वविद्यालय है। लेकिन ज्ञान का दरिया तो तभी तक जिंदा रहता है, जब तक वह निर्बाध, अविरल बहता रहे। आक्सफोर्ड हो या हार्वर्ड, ये पुराने विश्वविद्यालय अब तक विश्व में श्रेष्ठ इसलिए माने जाते हैं कि यहां शिक्षा को राजनीति की बिसात के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन भारत में अब ऐसा हो रहा है। इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय के पुन: उद्घाटन पर खुशियां तो अवश्य मनाई जानी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में उभर चुकी विसंगतियों से मुंह फेर लेंगे तो ये खुशियां भी चंद दिनों की मेहमान बनकर रह जाएंगी।

प्रधानमंत्री मोदी नालंदा को किस तरह राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी मिसाल उनके भाषण में ही मिल जाती है, जब उन्होंने कहा कि मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है साथ ही मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। श्री मोदी ने कहा कि नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा इस सत्य का उद्घोष है कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकतीं। ये नया कैंपस, विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा कि जो राष्ट्र, मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं।

> आज भले हम कहते रहें कि नालंदा आक्सफोर्ड से भी पुराना विश्वविद्यालय है। लेकिन ज्ञान का दरिया तो तभी तक जिंदा रहता है, जब तक वह निर्बाध, अविरल बहता रहे। आक्सफोर्ड हो या हार्वर्ड, ये पुराने विश्वविद्यालय अब तक विश्व में श्रेष्ठ इसलिए माने जाते हैं कि यहां शिक्षा को राजनीति की बिसात के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन भारत में अब ऐसा हो रहा है।

इस भाषण में मूल्य, मंत्र, इतिहास, भविष्य, गौरव, गाथा, भारत का सामर्थ्य जैसे शब्दों को भली-भांति फेंटा गया है, लेकिन इसके बावजूद यह समझ नहीं आया कि किन मानवीय मूल्यों की बात श्री मोदी कर रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर कितने हजार करोड़ में बना और यहां कितने सभागार हैं, कितनी जमीन पर बागीचा है, ये सारी बातें दोयम हैं। पहला सवाल तो यह है कि आखिर इस विश्वविद्यालय में क्या केंद्र सरकार उस स्तर की शिक्षा विद्यार्थियों को उपलब्ध करा पाएगी, जिसके लिए नालंदा का नाम दुनिया भर में फैला था। क्या यहां के छात्र खुलकर तर्क-वितर्क कर पाएंगे, क्या यहां उस पोंगापंथ पर लगाम कसी जाएगी, जो इस समय अधिकतर उच्च शिक्षण संस्थानों में बौद्धिकता के नाम पर बढ़ चुका है।

देश के अनेक नामी विश्वविद्यालयों को पिछले 10 सालों में कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ा है और यहां हुई राजनैतिक नियुक्तियों के कारण शिक्षकों और छात्रों दोनों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम आते ही अब जेहन में विवाद शब्द आ जाता है, क्योंकि यहां कभी छात्रों पर टुकड़े-टुकड़े गैंग का ठप्पा लगाया गया, कभी नकाबपोशों ने यहां हमला किया, कभी मेस में आमिष और निरामिष भोजन पर संघर्ष हुआ तो कभी यहां के छात्रों के उन्मुक्त व्यवहार को चर्चा का विषय बनाया गया। इन मुद्दों के आगे पढ़ाई का माहौल, छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं, संसाधन, छात्रवृत्ति, शोध की व्यवस्था, स्नातकोत्तर के लिए कम होती सीटें, स्थायी अध्यापकों की जगह तदर्थ नियुक्तियां, ऐसे कई जरूरी सवाल दरकिनार हो गए। कमोबेश यही स्थिति बाकी विश्वविद्यालयों की भी हो चुकी हैं। सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया विवि के पुस्तकालय में घुसकर किस तरह छात्रों के साथ मारपीट की गई थी, वो दृश्य लोगों को याद रखना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विवि से लेकर हैदराबाद और जाधवपुर विवि तक उच्च शिक्षा केंद्र विवादों के अड्डे बनते रहे। आईआईटी, आईआईएम जैसे नामी संस्थानों में हाल ऐसा ही हो गया है।

इसके अतिरिक्त परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा हो या व्यापमं और नीट जैसे घोटाले, शिक्षा के क्षेत्र में व्यापार और मुनाफे के नाम पर की जा रही धांधलियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अभी जिस बिहार में नरेन्द्र मोदी नालंदा विवि का उद्घाटन करने पहुंचे, उसी बिहार में पटना विवि केन्द्रीय विवि का दर्जा पाने की राह एक अरसे से देख रहा है। अगर इसे केन्द्रीय विवि बना दिया जाता तो बिहार के हजारों छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन नरेन्द्र मोदी सरकार ऐसी महत्वपूर्ण बातों को अक्सर नजरंदाज कर देती है।

इस पूरे चुनाव में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बना और कांग्रेस ने इसमें बाकायदा युवाओं को न्याय दिलाने की बात कही थी। लेकिन भाजपा ने इसे कभी मुद्दा नहीं माना और संयोग ऐसा था कि जिस दिन चुनावी नतीजे आए, उसी दिन एनआईआईटी यानी नीट के नतीजे भी आए, जिसमें बड़ी धांधली का खुलासा हुआ। परीक्षा से पहले ही कुछ बच्चों को पेपर मिल गए थे, एक ही केंद्र से एक जैसे अंक कई बच्चों को हासिल हुए। जब इस धांधली पर सवाल उठे तो नए शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने बिना जांच के ही फैसला सुना दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जहां नीट आयोजित कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) से शीर्ष अदालत ने कई तीखे सवाल किए। साथ ही कहा कि अगर नीट परीक्षा में 0.001 फीसदी भी लापरवाही हुई है तो उससे निपटा जाना चाहिए। कांग्रेस नीट में हुई धांधली को लेकर 21 जून को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है।

विपक्ष में बैठी कांग्रेस के लिए इस तरह के कदम उठाना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार इस बारे में क्या करेगी। मध्यप्रदेश में हुए व्यापमं घोटाले में न्याय अब तक नहीं हुआ है, बल्कि इस प्रक्रिया में हुई कई संदिग्ध मौतों के बाद धीरे-धीरे इस पर चर्चा होना ही बंद हो गई। किसी हादसे या घोटाले के बाद अगर सत्ताधारी दल को फिर से जीत मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसाफ भी मिल गया है। लेकिन अब ऐसी ही रवायत चल पड़ी है। नीट में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बावजूद परीक्षाओं में धांधली होना खत्म हो जाएगा, यह दावा नहीं किया जा सकता। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अब तक नीट मामले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। नालंदा पहुंच कर ज्ञान और इतिहास की बड़ी-बड़ी बातें करने वाले श्री मोदी जेएनयू से लेकर रोहित वेमुला और व्यापमं से लेकर नीट तक अगर दो वाक्यों का बयान दे सकें और देश को यह आश्वस्ति दें कि इतिहास में जिन राजनैतिक कारणों से नालंदा जैसे उच्च शिक्षा केंद्र को नष्ट कर दिया गया, वैसा वे अपने शासनकाल में किसी विश्वविद्यालय के साथ नहीं होने देंगे। शिक्षा को राजनीति और व्यापार का केंद्र नहीं बनने देंगे, तभी इस बात पर यकीन किया जा सकेगा कि श्री मोदी ने वाकई नालंदा को मंत्र, गौरव और गाथा माना है। वर्ना 2013 में श्री मोदी नालंदा के साथ तक्षशिला को भी बिहार का गौरव बता ही चुके हैं।

चंद्रबाबू नायडू की मोदी की एनडीए सरकार में स्थिति महत्वपूर्ण

■ कल्याणी शंकर

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रबाबू नायडू का शपथ ग्रहण नायडू के लिए व्यक्तिगत रूप से, तथा उनकी पार्टी और भारतीय राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष भाजपा नेताओं ने 74 वर्षीय राजनेता को चौथी बार शपथ लेते हुए देखा, जो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक वापसी का प्रतीक है। दो दशकों से अधिक समय तक राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में हाशिए पर रहने के बावजूद, नायडू आभारी हैं। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि किसी राजनेता को तब तक कम नहीं आंकना चाहिए जब तक कि वह खेल से बाहर न हो जाये।

केंद्र में मोदी की एनडीए सरकार में दूसरे सबसे बड़े समूह के रूप में तेलुगु देशम पार्टी के साथ-साथ मुख्यमंत्री के रूप में नायडू की वापसी, सत्ता की गतिशीलता में बदलाव का संकेत देती है।

एक साल पहले, चंद्रबाबू के पूर्ववर्ती जगन मोहन रेड्डी एक और कार्यकाल जीतने के लिए आरामदायक स्थिति में थे। उस समय विपक्ष विभाजित था, पवन कल्याण टीडीपी के साथ नहीं थे, और भाजपा अभी भी यह तय कर रही थी कि टीडीपी को फिर से एनडीए गठबंधन में शामिल होने दिया जाये या नहीं। बाबू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था, और टीडीपी कार्यकर्ता निराश थे।

> राज्य के लिए, चंद्रबाबू फिर से राज्य के सीईओ बन गए हैं। मुख्यमंत्री के रूप में, नायडू ने अपने पहले के कार्यकाल में बिल गेट्स जैसे तकनीकी दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उन्होंने हैदराबाद में निवेश के अवसर लाये और इसे साइबराबाद में बदल दिया। उन्होंने विश्व बैंक जैसी एजेंसियों से बुनियादी ढांचे के लिए धन प्राप्त किया और हैदराबाद का समग्र विकास किया।

नायडू की वापसी में कई कारकों ने योगदान दिया। सत्ता विरोधी भावना के अलावा, पवन कल्याण की जनसेना, भाजपा और टीडीपी के जातीय गठबंधन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जगन द्वारा बुनियादी ढांचे और कृषि की उपेक्षा ने भी लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, जिसने नायडू के पुनरुत्थान में और योगदान दिया।

नायडू अपने राजनीतिक संकट से बच निकले हैं। उन्होंने 1978 में एक जूनियर मंत्री के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और तब से तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) में विभिन्न पदों पर रहे हैं। उन्होंने कई बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है, महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की देखरेख की है और राजनीतिक विवादों का सामना किया है। इन सबके दौरान, नायडू ने अपनी अडिग भावना को बनाये रखा।

नायडू ने घोषणा की है कि 2024 का चुनाव उनका आखिरी चुनाव होगा, यह कदम मतदाताओं को भावनात्मक रूप से आकर्षित करने के साथ-साथ अपने बेटे लोकेश को अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए उठाया गया है। यह रणनीतिक निर्णय आंध्र प्रदेश की राजनीति में नायडू वंश के भविष्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है।

पहले, चंद्रबाबू अपने ससुर और तेलुगु देशम प्रमुख एनटी रामा राव की छाया में रहे, लेकिन अंतत: अपरिहार्य बन गये। उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा और संयुक्त मोर्चा सरकारों के दौरान राष्ट्रीय राजनीति में बहुमूल्य अनुभव और अंतर्दृष्टि प्राप्त की। उनकी पार्टी वी पी सिंह, देवेगौड़ा, आई के गुजराल और वाजपेयी सरकारों का हिस्सा थी, जो दर्शाता है कि कोई भी पार्टी अछूती नहीं थी।

नायडू और उनकी पार्टी का विभिन्न केंद्र सरकारों के साथ उतार-चढ़ाव भरा रिश्ता रहा है। हालांकि, मोदी सरकार में उनकी वर्तमान भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मोदी सरकार के लिए टीडीपी के समर्थन के साथ, नायडू आंध्र प्रदेश के हितों के लिए बातचीत करने और वकालत करने की स्थिति में हैं।

राज्य के लिए, चंद्रबाबू फिर से राज्य के सीईओ बन गए हैं। मुख्यमंत्री के रूप में, नायडू ने अपने पहले के कार्यकाल में बिल गेट्स जैसे तकनीकी दिग्गजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उन्होंने हैदराबाद में निवेश के अवसर लाये और इसे साइबराबाद में बदल दिया। उन्होंने विश्व बैंक जैसी एजेंसियों से बुनियादी ढांचे के लिए धन प्राप्त किया और हैदराबाद का समग्र विकास किया। हालांकि, गलती यह थी कि उन्हें राज्य के अन्य हिस्सों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए था।

अपने चौथे कार्यकाल में, नायडू को देश के चावल के कटोरे के रूप में कभी आंध्र प्रदेश के महत्व को वापस लाने का अवसर लेना चाहिए। नायडू की सर्वोच्च प्राथमिकता आंध्र प्रदेश के लिए अतिरिक्त धन प्राप्त करना है, जो राज्य के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आंध्र प्रदेश के विकास के लिए नायडू के दृष्टिकोण में राज्य के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पोलावरम परियोजना जैसी लंबे समय से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना शामिल है। अपनी पार्टी के समर्थन से, नायडू राज्य के संसाधनों को अधिकतम करने और विकास को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ हैं।

मोदी कैबिनेट में टीडीपी द्वारा केवल एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री को सुरक्षित करने के बारे में पूछे गये सवाल पर उन्होंने कहा, 'जब राज्य के हितों की बात आती है तो हम नरेंद्र मोदी कैबिनेट की संरचना पर बातचीत नहीं कर रहे हैं।' हालांकि, टीडीपी को अभी भी अगले विस्तार के दौरान अधिक पद हासिल करने की उम्मीद है।

दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती का निर्माण करना है। उनके पूर्ववर्ती जगन मोहन रेड्डी ने अपने दो कार्यकालों के दौरान इस महत्वाकांक्षी परियोजना को स्थगित कर दिया था। अब जब चंद्रबाबू वापस प्रभारी बन गये हैं, तो उनका लक्ष्य अमरावती को पूरा करना है। वह राजधानी के निर्माण और विभिन्न नयी परियोजनाओं के लिए धन सुरक्षित करने के साथ-साथ अपनी छह कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्र पर दबाव डालेंगे। शो मैन होने के नाते, वह अमरावती को एक आदर्श राजधानी के रूप में पेश करना चाहेंगे।

राज्य गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। धन की भारी कमी है, कुल ऋण लगभग 14 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें विभिन्न स्रोतों से उधार लिये गये1 2 लाख करोड़ रुपये और 1.5 लाख करोड़ रुपये के लंबित बिल शामिल हैं।

अपने चार दशक के राजनीतिक जीवन के दौरान, 74 वर्षीय नायडू ने खुद को जीवित रहने वाला साबित किया है। वह अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने खुद को एक दूरदर्शी, प्रौद्योगिकी समर्थक और तकनीक-प्रेमी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया।

माहौल बहुत बढ़िया है, क्योंकि नायडू को किंगमेकर का श्रेय मिला है। मोदी सरकार का हिस्सा होने से उन्हें सत्ता साझा करने का मौका मिलता है। विधानसभा में उनके पास कोई विपक्ष नहीं है, वाईएसआरसीपी सिर्फ 11सीटों पर सिमट गई है।

टीडीपी को मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे को संबोधित करने की ज़रूरत है। यह विषय भाजपा के साथ टकराव का कारण बन सकता है। मोदी के साथ नायडू के सकारात्मक संबंध एक साल तक चलने की उम्मीद है, जिसके बाद वे इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर दबाव बना सकते हैं। इसके अलावा, टीडीपी को भ्रष्टाचार के मामले को सुलझाना चाहिए क्योंकि नायडू फिलहाल जमानत पर हैं। अपने चौथे कार्यकाल में उनका आचरण उनके और उनके बेटे लोकेश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

पावन प्रसंग

जीवन जीने का उत्तम मार्ग

बहुधा हम अपनी इच्छा पूरी नहीं होने के कारण दुखी रहते हैं। हमारे मन में कई प्रकार की भौतिक इच्छाएं बलवती रहती हैं। जब कोई इच्छा पूरी हो जाती है, तब हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं। कभी-कभी तो व्यक्ति इतना हताश, निराश हो जाता है कि जीवन उसके लिए बोझ सा बन जाता है। वह जीवन को बोझ समझ कर ढोता फिरता है। कभी सम्मान पाकर वह हर्षित हो उठता है, तो कभी अपमान मिलने पर अवसादग्रस्त हो जाता है।

जीवन में लाभ प्राप्त होने पर वह हर्षित हो उठता है और जीवन व्यापार में उद्योग में, व्यवसाय में हानि होते ही इतना निराश हो जाता है कि वह आत्महत्या तक करने का विचार करने लगता है। धन प्राप्त करने, सुख प्राप्त करने के लिए वह बुरे से बुरे कर्म करने को आतुर रहता है। कुल मिलाकर उसका जीवन सुख-दुख, हानि-लाभ, मान-अपमान आदि द्वंद्वों में ही फंसा हुआ रहता है, जिसके कारण वहजीवन में कभी भी वास्तविक सुख-शांति प्राप्त नहीं कर पाता। वह स्थायी सुख-शंति प्राप्त नहीं कर पाता। तब हमारे मन में सहज ही कई प्रश्न आते हैं। ऐसा भला क्यों और कैसे होता है ? क्या जीवन जीने का कोई ऐसा उपाय भी है, जिस पर चलकर व्यक्ति स्थायी सुख प्राप्त कर सके ? और यदि कोई मार्ग है तो वह कौन सा है ? ऐसे अनेक प्रश्न हमारे मन में उभर आते हैं।

ऐसा ही निराश एक व्यक्ति इन्हीं प्रश्नों को लेकर एक तपस्वी के पास पहुंचा। उसने उस तपस्वी से कहा- मैं अपने जीवन से बहुत निराश हो चुका हूं। अब मैं गृहत्याग कर आपके साथ ही रहना चाहता हूं. आप कृपा कर के मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। उस तपस्वी ने उसकी इच्छा के अनुसार उसे अपने शिष्य के रूप स्वीकार कर लिया। महात्मा जी ने उसे गायत्री मंत्री की दीक्षा दी और कहा- ब्रह्ममुहुर्त में उठकर उदीयमान सूर्य देव का अपने हृदय में ध्यान करते हुए नित्य गायत्री मंत्र का श्लोक पढ़ना और स्वाध्याय किया करो। वह महात्मा के बताए अनुसार वैसा ही करने लगा। महात्मा जी ने उसे एक गाय भी दी और कहा- वत्स, इसकी सेवा करो और इसके दूध का सेवन करो। वह नित्य संध्या वंदन करने लगा। साथ ही वह प्रतिदिन गाय को जंगल में ले जाकर चराता, दोनों समय उसका दूध पीता और नित्य स्वध्याय किया करता।

एक दिन वह महात्मा जी के पास गया और बोला- गुरुदेव, आपकी कृपा से अब मैं बहुत आनंदित रहने लगा हूं। महात्मा ने पूछा- वत्स, आनंद क्या है ? आनंद से तुम्हारा क्या अभिप्राय है ? वह बोला- मैं नित्य संध्या वंदन करता हूं. स्वाध्याय करता हूं, गाय चराता हूं, खूब दूध पीता हूं और सुखपूर्वक दिन व्यतीत करता हूं। यह सुनकर महात्मा बोले- ठीक है। कुछ दिन बाद संयोग से एक दिन गाय कहीं गुम हो गई उसे अब दूध पीने को नहीं मिलता था इसी चिंता में उसने स्वाध्याय में मन नहीं लगता था। उसने घबराकर महात्मा से अपनी व्यथा सुनाई। कुछ दिनों बाद वह गाय मिल गई वह फिर से उसका दूध पीने मिलने लगा उसने महात्मा जी से अपनी खुशी बताई महात्मा जी ने कहा यह भी ठीक है। तब उस शिष्य ने कहा-जब गाय गुम हो गई थी तब भी आपने कहा ठीक है और जब वह मिल गई तब भी। महात्माजी ने कहा-वत्स जीवन जीने का यही सर्वोत्तम मार्ग है। जैसी परिस्थिति हो वैसा ही स्वीकार करना। न मिलने पर दुखी न हो, प्राप्त हो जाने पर खुश न हो। प्रत्येक स्थिति में इंसान को खुश रहना है।

अखंड ज्योति

आपके पत्र

आधुनिक होते आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं की कमी

इस माह के पहले सप्ताह में राजस्थान के गृह सचिव ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में राज्य के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन या टैबलेट उपलब्ध कराने का निर्देश जारी किया है ताकि केंद्र के कामों की ऑनलाइन मॉनेटरिंग की जा सके। इससे आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों और उनके स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड के साथ-साथ महिलाओं और किशोरियों को मिलने वाले लाभों का आंकड़ा भी एकत्र करने में मदद मिलेगी। बैठक में मुख्य सचिव ने प्राथमिकता के आधार पर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल और शौचालयों की सुविधा को बेहतर बनाने के साथ- साथ बिजली कनेक्शन को ठीक करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी केंद्रों पर पोषाहार सप्लाई की मात्रा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

आंगनबाड़ी केंद्रों को आधुनिक और डिजिटलाइज करने की राज्य सरकार की यह पहल सराहनीय है। इससे पहले भी इसी वर्ष अप्रैल में राजस्थान सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहयोगिनियों और सहायिकाओं के मानदेय में 10 प्रतिशत की वृद्धि की थी। इस वक्त पूरे राजस्थान में करीब 62,020 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किये जा रहे हैं। जिसके माध्यम से लाखों बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण मुक्त बनाया जा रहा है। जिसका सफलतापूर्वक संचालन इन्हीं कार्यकर्ताओं, सहयोगिनियों और सहायिकाओं के कारण मुमकिन होता है। लेकिन इसके बावजूद कई बार केंद्र पर सुविधाओं की कमी के कारण इन्हें बहुत कठिनाइयों के बीच काम करना पड़ता है। इसका एक उदाहरण राजस्थान के चूरू जिला स्थित घड़सीसर गांव है। जहां संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं की कमी के बीच कार्यकर्ताओं, सहयोगिनियों और सहायिकाओं को काम करना पड़ रहा है।

राजधानी जयपुर से करीब 254 किमी दूर और चुरु जिला के सरदारशहर ब्लॉक से 50 किमी की दूरी पर बसे घड़सीसर गांव की आबादी करीब 3900 है। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम प्रतिदिन इस चुनौती का सामना करने को तैयार रहते हैं। अब सरकार ने जब आंगनबाड़ी केंद्रों की सुध ली है और यहां सुविधाओं को बेहतर बनाने की बात कही है तो यह हमारे काम में नई ऊर्जा का संचार कर देगी।

इस संबंध में घड़सीसर गांव के सरपंच मनोज भी इन आंगनबाड़ी केंद्रों में सुविधाओं की कमी को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि फिलहाल इन्हें सामुदायिक केंद्र और स्कूल भवन में शिफ्ट किया गया है। लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं है। पंचायत की ओर से इस सिलसिले में महिला एवं बाल विकास विभाग को पत्र लिख कर स्थिति से अवगत करा दिया गया है और सुविधाओं को पूरा करने के लिए बजट भी बना कर भेज दिया गया है। जैसे ही बजट स्वीकृत हो जायेंगे तो इन भवनों में बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। बहरहाल, राजस्थान सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन या टैबलेट के साथ साथ भवनों को बुनियादी सुविधाओं से लैस करने की पहल न केवल इसके कामकाज को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा बल्कि राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगा।

भारती सुथार, बीकानेर राजस्थान

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770

ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

दैनिक जलते दीप
जोधपुर, गुरुवार 20 जून 2024

मणिपुर में शांति बहाली के लिए गंभीर प्रयास हों

मणिपुर में शांति बहाली को लेकर अब केंद्र सरकार कुछ गंभीर नजर आई है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में वहां सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने, हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने और जल्दी ही मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करने का फैसला किया गया। एक वर्ष से ऊपर हो गया वहां हिंसा होते, मगर न तो केंद्र और न राज्य सरकार ने कोई उल्लेखनीय कदम उठाया। इसे लेकर लगातार दोनों सरकारों पर अंगुलियां उठती रही हैं। पिछले वर्ष मई में जब वहां हिंसा भड़की, तब सेना की गश्त बढ़ा दी गई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि हिंसा पर एकदम से काबू पा लिया गया था। मगर फिर महीने भर के भीतर ही फिर से हिंसा भड़क उठी थी। उसके बाद उस पर काबू पाने का कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। उपद्रवियों ने पुलिस शस्त्रागार से बड़े पैमाने पर हथियार लूट लिए, दोनों समुदाय घात लगा कर एक-दूसरे पर हमले करने लगे थे। उस दौरान केंद्रीय गृहमंत्री ने वहां का दौरा किया था। तब भी उन्होंने हिंसा करने वालों को कड़ी चेतावनी दी थी, लूटे गए हथियार वापस करने का आह्वान किया था, मगर उसका कोई खास असर नहीं हुआ। तब से जैसे वहां के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और केंद्र सरकार ने कोई कड़ाई नहीं दिखाई। इसका नतीजा यह हुआ कि बहुत सारे घर जला दिए गए, पूजा स्थलों को ध्वस्त कर दिया गया, साठ हजार से ऊपर लोग अपने घरों से विस्थापित होकर राहत शिविरों में रह रहे हैं, दो सौ से ऊपर लोग मारे जा चुके हैं, कई महिलाओं से सामूहिक बलात्कार किया गया, कुछ को निर्वस्त्र घुमाया गया। इन सबके बावजूद सरकारें तमाशबीन बनी रहीं। प्रधानमंत्री पर आरोप है कि वे आज तक मणिपुर पर कुछ नहीं बोले। इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए अपनी निगरानी में जांच समिति गठित की और राज्य पुलिस को कड़ी चेतावनी दी। मगर उसका भी कोई उल्लेखनीय नतीजा नहीं निकल पाया है। अभी स्थिति यह है कि इंफल से ऊपर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी समुदाय के लोग खुद अपनी सुरक्षा चौकियां बना कर पहरेदारी करते हैं। राहत शिविरों में रह रहे लोगों को न तो ढंग का भोजन मिल पाता है, न पीने का पानी, न स्वास्थ्य सुविधाएं। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई सब कुछ बाधित है। इस तरह एक पूरे राज्य के लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना किसी भी कल्याणकारी सरकार की जवाबदेही पर स्वाभाविक ही सवाल खड़े करता है। इसे लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी कुछ दिनों पहले सरकार को कड़े शब्दों में निंदा की। शायद उसी का असर हो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर की सुरक्षा को लेकर फिक्र जताई है। लोकसभा चुनाव में मणिपुर के हालात की अनदेखी के नतीजे भी सामने हैं। विपक्ष उसे लेकर लगातार सत्तापक्ष को घेरता रहा है। नई सरकार में अब विपक्ष इसे और मजबूती के साथ उठाता, इसलिए भी संसद का सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने मणिपुर पर बैठक बुलाई और कड़ाई से पेश आने का आश्वासन दिया। देखने की बात होगी कि मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार कितनी गंभीर है, गृहमंत्रालय की बैठक में किए गए फैसले केवल घोषणा तक सीमित रहते हैं या वास्तव में उन पर गंभीरता से अमल भी किया जाता है।

रेल हादसों से सबक सीखने की जरूरत

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जनपद में कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी द्वारा पीछे से टक्कर मारे जाने से हुई क्षति बताती है कि बीते वर्ष ओडिशा में कोरोमंडल एक्सप्रेस के भीषण हादसे से हमने कोई सबक नहीं सीखा। कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे में मरने वालों की संख्या ग्यारह बतायी जा रही है और चालीस से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि बीते साल रेलवे इतिहास की बड़ी दुर्घटनाओं में शामिल कोरोमंडल एक्सप्रेस और दो अन्य ट्रेनों में हुई टक्कर में 290 से अधिक लोगों की जान चली गई थीं। उल्लेखनीय है कि कंचनजंगा ट्रेन हादसे में मरने वालों में मालगाड़ी के चालक व सहचालक भी शामिल हैं। हालांकि दुर्घटना का वास्तविक कारण जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन बताया जा रहा है कि रानीपतरा रेलवे स्टेशन व छत्तर हाट जंक्शन के बीच स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली दुर्घटना से तीन घंटे पहले से ही खराब थी। हमेशा की तरह मृतकों के परिजनों को दस-दस लाख का मुआवजा देने की घोषणा हुई है। साथ ही दुर्घटना की वजह तलाशने और जवाबदेही तय करने की बात कही जा रही है। पहले उम्मीद जगी थी कि बालासोर त्रासदी से सबक लेकर रेल दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में कारगर कदम उठाए जाएंगे, जबकि जमीनी स्तर पर हालात बदलते नजर नहीं आ रहे हैं। रेलवे तंत्र में कोताही का नमूना इस साल फरवरी में देखने को मिला था जब कठुआ से दासुया (पंजाब) के बीच लगभग सत्तर किलोमीटर दूरी तक एक मालगाड़ी बिना चालक के चली गई थी। सौभाग्य की बात है कि इस ट्रैक पर किसी रेल के न आने से दुर्घटना टल गई थी। बहरहाल, कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। बढ़-चढ़कर बताया जा रहा है कि सत्ता व विपक्ष में से किसके कार्यकाल में ज्यादा रेल दुर्घटनाएं हुईं। बहरहाल, रेल दुर्घटनाएं रोकने के लिये बनायी गई टक्कर रोधी तकनीक के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा कि व्यस्त पूर्वोत्तर मार्ग पर यदि इसका क्रियान्वयन होता तो शायद इस दुर्घटना को टाला जा सकता था। सवाल यह है कि रेल मंत्रालय मानवीय भूल के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को टालने के लिए गंभीर पहल क्यों नहीं करता। क्यों रेल दुर्घटनाएं रोकना सत्ताधीशों की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं होता? जिस ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली 'कवच' को चरणबद्ध तरीके से जल्दी से लागू किया जाना चाहिए था, उस पर कछुआ गति से काम क्यों हो रहा है? एक ओर देश में बुलेट ट्रेन और तेज गति से चलने वाली अन्य ट्रेनों की बात की जा रही है, वहीं सामान्य गति से चलने वाली ट्रेनों को भी दुर्घटनाओं से निरापद बनाने में हम विफल साबित हो रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि देश में फास्ट ट्रेनों की चकाचौंध व ग्लैमर के बजाय सामान्य गति की ट्रेनों की सुरक्षा को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। वहीं विपक्ष का आरोप है कि रेलवे में रिक्त पड़े लाखों पदों को नहीं भरा जा रहा है, जिससे रेलवे बढ़ती आबादी के दबाव में सुरक्षित रेल सेवा उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। आखिर हम इन रेल हादसों से सबक कब लेंगे? निस्संदेह, रेल यातायात को दुर्घटनाओं से निरापद बनाने के लिये बुनियादी ढांचे में सुधार व अधिक निवेश की जरूरत है। हम अतीत के हादसों से सबक लेकर परिचालन व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करें। हादसों की जवाबदेही तय हो ताकि दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। वक्त की जरूरत है कि दुर्घटनाओं को टालने के लिये, जितना जल्दी हो सके अधिक दबाव वाले इलाकों में 'कवच' योजना को क्रियान्वित किया जाए। इसके अलावा पटरियों के रख-रखाव के लिये आवंटित फंड का उचित उपयोग किया जाए। साथ ही बुनियादी ढांचे में सुधार, दुर्घटना टालने को आधुनिक तकनीकों का उपयोग तथा नई चुनौतियों से मुकाबले के लिये रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की भी जरूरत है। यह भी कि रेलवे के आधुनिकीकरण के लिये वित्तीय संसाधन जुटाए जाएं ताकि यह न कहा जा सके कि असुरक्षित पटरियों पर लचर संचालन प्रणाली दुर्घटनाओं की वजह बन रही है। दुर्घटनाओं का सिलसिला तभी थमेगा जब यात्रियों की सुरक्षा रेल मंत्रालय व सरकार की प्राथमिकता बनेगी।

प्रसंगतः अनोखा फैसला

पुरानी कथा है। चीन में एक विचारक की काफी धूम थी। लोग उससे बेहद प्रभावित थे। राजा ने उसकी तारीफसुन उसे न्यायाधीश बना दिया। उन्हीं दिनों नगर के सबसे धनवान सेठ के घर में चोरी हो गई। सब जानते थे कि सेठ ने इतनी अकूत संपत्ति बेईमानी व लोगों का शोषण करके इकट्ठा की है। किंतु चोरी तो चोरी थी इसलिए चोर को पकड़ने के लिए अभियान छेड़ा गया। चोर पकड़ा गया। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली। न्यायाधीश ने उसे चोरी के जुर्म में एक साल की सजा सुना दी। चोर को सजा सुनाने के बाद न्यायाधीश ने सेठ की संपत्ति की जांच शुरू करवा दी लेकिन सेठ की दलील थी कि उसने सारी कमाई तिजारत से हासिल की है। उसने किसी का शोषण कर या गलत तरीके से धन अर्जित नहीं किया है। लेकिन न्यायाधीश ने इस बात को नहीं माना। उसने फैसला सुनाते हुए कहा, 'इस संपत्ति का कुछ हिस्सा चुराने वाले चोर को तो एक वर्ष की सजा दी गई है मगर इस संपत्ति के मालिक को दो वर्ष की सजा दी जाती है।' सेठ ने फैसले पर सवाल उठाया तो न्यायाधीश ने कहा, 'चोर ने तो चोरी की बात मान ली। उसके हृदय परिवर्तन की गुंजाइश है। लेकिन तुमने तो झूठ बोलकर सही रास्ते पर आने के सारे रास्ते बंद कर लिए हैं। चोर को सजा जरूर मिलनी चाहिए किंतु जब तक केवल चोरों को सजा मिलती रहेगी और आम आदमी का शोषण करने वाले खुलेआम घूमते रहेंगे तब तक चोरी बंद नहीं होगी। इसलिए तुम्हें सजा सुनाई गई है।'

खनिज दोहन हेतु रूस-चीन ने बदली तालिबान नीति

वर्ष 2022 में अफ़ग़ान अमीरात सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने जब पहली बार सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच का दौरा किया, तो यह चर्चा का विषय था कि पुतिन क्या फिर से ग्रेट गेम खेलना चाहते हैं? हालांकि, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आदतन कोई बात सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा कि इस्लामिक अमीरात के साथ संबंध बनाने के लिए यह क़दम ज़रूरी था। मार्च, 2022 में, रूस-अफ़ग़ानिस्तान ने आधिकारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए। कजाकिस्तान 2023 में तालिबान को आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने वाला पहला देश था। विशेषज्ञों का मानना है कि मास्को के इशारे पर ऐसा कुछ हुआ था।

रूस के खेल से पश्चिमी देश अबूझ हों, यह गलतफहमी कोई नहीं पालता। इसकी काट के वास्ते संयुक्त अरब अमीरात को हर समय आगे रखा जाता है। मई, 2023 में अफगानिस्तान पर पहली दोहा बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने की। लेकिन 18-19 फरवरी, 2024 को दूसरी दोहा बैठक में इस्लामिक अमीरात शर्तें पूरी न होने के कारण शामिल नहीं हुआ। जिसके लिए बैठक हो, और वही अनुपस्थित रहे, तो दोहा-टू का मज़ाक बनना स्वाभाविक था। अब, तीसरी बैठक 30 जून और 1 जुलाई, 2024 को निर्धारित है।

पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक मामलों के अवर महासचिव रोजमेरी डिकालो, कतर के उपविदेश मंत्री, इस्लामिक सहयोग संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल और यूरोपीय संघ के विशेष प्रतिनिधि थॉमस निकलसन ने काबुल का दौरा किया था। इससे पहले सुरक्षा परिषद के अनुरोध पर 25 अप्रैल, 2024 को, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए तुर्की के राजनयिक फरीदुन सिनिरलियोग्लू को विशेष समन्वयक नियुक्त किया था। लेकिन फरीदुन सिनिरलियोग्लू ने जो मसौदे दोहा-3 बैठक के लिए तैयार किये, उसमें काफ़ी रद्दोबदल किये जा चुके हैं। यह सब होने के बाद ही अमीरात के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने तीसरी दोहा बैठक में अंतरिम सरकार के प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी की घोषणा की है। दोहा-3 बैठक में अमीरात के विदेश मंत्री वित्तीय, बैंकिंग, ड्रग नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर विमर्श के लिए सहमत हैं। अब सवाल यह है कि क्या पश्चिमी देश मान लेंगे कि अफ़ग़ान औरतों को शिक्षा-रोज़गार से दूर रखने का जो जघन्य कर्म अमीरात ने किया, मानवाधिकारों का दमन किया, वो सही है?

रूस ने भी अमीरात पर औरतों के हक़ को लेकर शायद ही कभी दबाव बनाया हो। इस्लामिक अमीरात अक्सर रूसी सुरक्षा सम्मेलनों में साझेदार बना है। 8 फरवरी, 2023 को भारत, ईरान, किर्गिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (एनएसए) ने अफगानिस्तान पर पांचवें बहुपक्षीय सुरक्षा वार्ता के लिए मास्को में मुलाकात की। इसके प्रकारांतर सितंबर, 2023 में चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विशेष प्रतिनिधियों को जुटाकर 'अफ़ग़ानिस्तान पर मास्को प्रारूप परामर्श' की पांचवीं बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेशमंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने भी भाग लिया था।

- पुष्परंजन

इतना ही नहीं, रूस-चीन की पहल पर शंघाई कोऑपरेशन आर्गेनाइजेशन संपर्क समूह में भी अफ़ग़ानिस्तान को लाने के प्रयास किये गये।

यह रोचक है कि 29 जनवरी, 2024 को तालिबान प्रशासन ने काबुल में 'अफ़ग़ानिस्तान क्षेत्रीय सहयोग पहल' नामक पहली अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेज़बानी की, जिसमें रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडोनेशिया और भारत सहित यूरेशियन क्षेत्र के 11 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ऐसे में कैसे कह सकते हैं, कि अमीरात शासन को 'आइसोलेट' कर दिया गया?

बर्लिन स्थित काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट (सीईपी) के मध्य-पूर्व विशेषज्ञ, हैंस जैकब शिंडलर का मानना है कि रूस का विदेश मंत्रालय तालिबान को आतंकवादी समूह की सूची से हटाने के बदले में काफी-कुछ उम्मीद कर सकता है। लेकिन ऐसा कहना आसान है, करना मुश्किल। शिंडलर ने कहा, 'तालिबान हमेशा रियायतें स्वीकार करने के लिए इच्छुक होते हैं, लेकिन जब उन्हें बदले में देने की बात आती है, तो उनके लिए चीजें जटिल हो जाती हैं।' अफगानिस्तान एनालिस्ट नेटवर्क के सह-संस्थापक थॉमस रुटिग ने भी क्रेमलिन के हालिया प्रयासों को मल्टी टास्क रणनीति के रूप में व्याख्यायित किया, जो इस्लामिक अमीरात को आधिकारिक मान्यता देने की दिशा में बढ़ रही है।

शिंडलर और रुटिग दोनों इस बात पर सहमत हैं कि तालिबान को आतंकवादी संगठन के रूप में सूची से हटाने के बाद अगला कदम उसे वैध राज्य शक्ति के रूप में आधिकारिक मान्यता देना हो सकता है। दोनों की बात कुछ हद तक सही है। ऐसी कवायद दोहा से मास्को तक चल रही है। थोड़ी देर के लिए हम यदि इसे तालिबान नीति की सफ़लता मान भी लें, तो आने वाले समय के लिए यह सुखद संदेश नहीं देता है। तालिबान पहले 1996 और 2001 के बीच अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज़ थे। दो दशक बाद, तालिबान की वापसी का मतलब, इस्लामी कानून की संकीर्ण व्याख्या की बहाली भी रही है। यदि मल्टीपोलर वर्ल्ड्स अपने कूटनीतिक स्वार्थों की वजह से मानवाधिकारों का हनन, विशेष रूप से महिलाओं-बच्चियों पर व्यापक प्रतिबंध को भी स्वीकार करता है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या भारत को भी अमीरात इसी रूप में सुहाता है?

तालिबान प्रतिबंधित है, दूसरी ओर सेंट पीटर्सबर्ग इकोनॉमिक फोरम में वह आमंत्रित भी है। रूसी अधिकारियों के अनुसार, 'पिछले साल दोनों देशों के बीच व्यापार में पांच गुना वृद्धि हुई और यह एक अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है।' चीन भी 2023-24 में डेढ़ अरब डॉलर एक्सपोर्ट के साथ अफगानिस्तान में खनिजों का दोहन करता है, तो उसे मान्यता देने न देने का मतलब क्या रह जाता है? यह तो समझ में आ चुका है कि तालिबान से संबंधों को सुदृढ़ करना, चीनी-रूसी विदेश नीति का हिस्सा है।

खनिजों से समृद्ध अफगानिस्तान सबके लिए प्रासंगिक है, जिसका दोहन तभी किया जा सकता है, जब इस देश में शांति लाई जाए, और अधोसंरचना, फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से लैस किया जाए। मॉस्को, अफगानिस्तान के इन्फ्रा में दिलचस्पी ले, उससे पहले संयुक्त अरब अमीरात वहां अपनी गहरी पैठ बना चुका है। यूएई में तीन लाख से ज़्यादा अफ़गान रहते हैं। इन दिनों अफ़गानिस्तान को संचालने में यूएई सबसे आगे है। यूएई में अफ़गान व्यापार परिषद के प्रमुख हाजी ओबैदुल्ला सदर खैल बताते हैं कि अमीराती मुल्क में 200 अस्पताल बनाने, राजमार्ग निर्माण, स्कूली किताबें प्रकाशित करने, अफ़ीम की फसल की जगह केसर उत्पादन में सुधार करने और कालीन उद्योग विकसित करने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। लेकिन कड़वा सच यह भी है कि अफ़ग़ानिस्तान में खनिज दोहन की प्रतिस्पर्धा ने दुनियाभर के ताक़तवर देशों को कम्प्रोमाइज़ के कगार पर ला खड़ा किया है!

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक दिवस अर्थात हिंदू साम्राज्य दिवस (ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी) पर विशेष

लोकमंगल था शिवाजी के 'हिंदवी स्वराज' का शासन मंत्र

सुशासन, समरसता और सामाजिक न्याय से जीता जनविश्वास

शिवाजी का नाम आते ही शौर्य और साहस की प्रतिमूर्ति का एहसास होता है। अपने सपनों को सच करके उन्होंने खुद को न्यायपूर्ण प्रशासक के रूप में स्थापित किया। इतिहासकार भी मानते हैं कि उनकी राज करने की शैली परंपरागत राजाओं और मुगल शासकों से अलग थी। वे सुशासन, समरसता और न्याय को अपने शासन का मुख्य विषय बनाने में सफल रहे। सन् 1674 में ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी के दिन शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। यह दिन हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिखरे हुए मराठों को एक सूत्र में पिरोकर उन्होंने जिस तरह अपने सपनों को साकार किया वह प्रेरित करने वाली कथा है। एक अप्रतिम सैनिक, कूटनीतिज्ञ, योद्धा के साथ ही वे कुशल रणनीतिकार के रूप में भी सामने आते हैं। वे अपनी मां जीजाबाई और गुरु के प्रति बहुत श्रद्धाभाव रखते थे। शायद इन्हीं समन्वित मानवीय गुणों से वे ऐसे शासक बने जिनका कोई पर्याय नहीं है।

- प्रो. संजय द्विवेदी

इतिहासकार ईश्वरी प्रसाद कहते हैं- प्रशासन की उनकी प्रणाली कई क्षेत्रों में मुगलों से बेहतर थी। इतिहास के पन्नों में ऐसा शासक कभी-कभी आता है, जिसने लोकमन में जगह बनाई हो। शिवाजी एक ऐसे शासक हैं जिनके प्रति उनकी प्रजा में श्रद्धाभाव साफ दिखता है क्योंकि लोकमंगल ही उनके शासन का मूलमंत्र था। उनकी राज्य प्रणाली, प्रशासन में आम आदमी के लिए, स्त्रियों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए ममता है, समरसता का भाव है। वे न्यायपूर्ण व्यवस्था के हामी हैं। प्रख्यात इतिहासकार डा. आरसी मजूमदार की मानें तो शिवाजी न केवल एक साहसी सैनिक और सफल सैन्य विजेता थे,बल्कि अपने लोगों के प्रबुद्ध शासक भी थे। बाद के इतिहासकारों ने तमाम अन्य भारतीय नायकों की तरह शिवाजी के प्रशासक स्वरूप की बहुत चर्चा नहीं की है। आज भारतीय पुनर्जागरण का समय है और हमें अपने ऐसे नायकों की तलाश है, जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा सकें। ऐसे समय में शिवाजी की शासन प्रणाली में वे सूत्र खोजे जा सकते हैं, जिससे देश में एकता और समरसता की धारा को मजबूत करते हुए समाज को न्याय भी दिलाया जा सकता है। शिवाजी अपने समय के बहुत लोकप्रिय शासक थे। उन पर जनता की अगाध आस्था दिखती थी। साथ ही उनके राजतंत्र में बहुत गहरी लोकतांत्रिकता भी दिखती है। क्योंकि वे अपने विचारों को थोपने के बजाए या 'राजा की बात भगवान की बात है' ऐसी सोच के बजाए अपने मंत्रियों से सलाह लेते रहते थे। विचार-विमर्श उनके शासन का गुण है। जिससे वे शासन की लोकतांत्रिक चेतना को सम्यक भाव से रख पाते हैं।

शिवाजी ऐसे शासक हैं जो सत्ता के विकेंद्रीकरण की वैज्ञानिक विधि पर काम करते हुए दिखते हैं। समाज के सभी वर्गों, जातियों, सामाजिक समूहों की अपनी सत्ता में वे भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, जिनमें मुसलमान भी शामिल हैं। उन्होंने मंत्रियों को अलग-अलग काम सौंपे और उनकी जिम्मेदारियां तय की ताकि अनुकूल परिणाम पाए जा सकें। वे परंपरा से अलग हैं इसलिए वे अपने नागरिकों या सैन्य अधिकारियों को कोई जागीर नहीं सौंपते। किलों (दुर्ग) की रक्षा के लिए उन्होंने व्यवस्थित संरचनाएं खड़ी की ताकि संकट से जूझने में वे सफल हों। रक्षा और प्रशासन के मामलों को उन्होंने सजगता से अलग-अलग रखा और सैन्य अधिकारियों के बजाय प्रशासनिक अधिकारियों को ज्यादा अधिकार दिए। उनकी यह सोच बताती है कि नागरिक प्रशासन उनकी चिंता के केंद्र में था। उन्होंने राजस्व प्रणाली में व्यापक सुधार करते हुए किसानों से सीधा संपर्क और संवाद बनाने में सफलता पाई। उन्होंने केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन की साफ रचना खड़ी की और उनके अधिकार व कर्तव्य भी सुनिश्चित किए। उन्होंने 'अष्ट प्रधान' नाम से केंद्रीय मंत्रियों की टोली बनाई जिसमें आठ मंत्री थे। उनमें कुछ पेशवा कहे गए जो वरिष्ठ थे। चार प्रांतों में विभक्त शिवाजी की राज्य रचना एक अनोखा उदाहरण थी। प्रत्येक प्रांत को जिलों और गांवों में बांटा गया था। गांव का प्रमुख देशपाण्डेय या पटेल कहलाता था। शिवाजी ने गांवों में राजस्व प्रणाली को वैज्ञानिक बनाने का काम किया और उनको किसानों के लिए उपयोगी बनाया। इस व्यवस्था में किसान किस्तों में भी भुगतान कर सकते थे। राजस्व अधिकारियों पर नियंत्रण रहे इसलिए नियमित उनके खातों की गहन जांच भी की जाती थी। उन्होंने न्यायिक प्रशासन को भी जवाबदेह बनाया।

शिवाजी स्वयं योद्धा थे। जाहिर तौर पर उनकी सैन्य प्रणाली बहुत अग्रगामी थी। पूर्व की परंपरा में सैनिक छः माह काम करते थे फिर छः माह दूसरे कामों से अपना जीवन यापन करते थे। शिवाजी ने नियमित सेना को स्थापित किया, उन्हें पूरे साल सैनिक जीवन जीना होता था। सैनिकों को नियमित भुगतान के साथ उनकी योग्यता और देशभक्ति के आधार पर जगह मिलने लगी। शिवाजी ने लगभग 280 किलों के माध्यम से अभेद्य रचना खड़ी की। उनकी सेना में कठोर अनुशासन था। सेना में सभी वर्गों के सैनिक थे। 700 से अधिक मुस्लिम भी उनकी सेना में थे। अपने सैनिकों को उन्होंने गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित कर बड़ी सफलताएं पाईं। मृत सैनिकों के परिजनों का खास ख्याल रखा जाता था। इसके साथ ही उन्होंने बहुत अनुशासित सेना खड़ी की। सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिवाजी बहुत सख्त थे। महिलाओं और बच्चों को मारना या प्रताड़ित करना, ब्राह्मणों को लूटना, खेती को खराब करना आदि युद्ध के दौरान भी दंडनीय अपराध थे। अनुशासन के रखरखाव के लिए विस्तृत नियम सख्ती से लागू किए गए थे। किसी भी सैनिक को अपनी पत्नी को युद्ध के मैदान में ले जाने की अनुमति नहीं थी। शिवाजी ने अपनी सेना को सब तरह से सुसज्जित किया जिसमें एक प्रकार का विभाग थे। जो इस प्रकार हैं- घुड़सवार सेना, पैदल सेना, ऊंट और हाथी बटालियन, तोपखाने और नौसेना। यह विवरण बताता है कि उनका राज्यतंत्र किस तरह लोगों की सुरक्षा और शांति के लिए काम कर रहा था। वे प्रेरित करने वाले नेता थे। इसलिए उनकी शक्ति बढ़ती चली गयी। उनके कट्टर दुश्मन औरंगज़ेब को स्वयं स्वीकार करना पड़ा कि मेरी सेनाओं को उन्नीस वर्षों से उनके खिलाफ काम में लगाया गया है और फिर भी उनकी (शिवाजी की) स्थिति हमेशा बढ़ती रही है। शिवाजी जी ने अपनी जंग मुगलों के विरूद्ध लड़ी, किंतु वे सामाजिक समरसता और सामाजिक न्याय के मंत्रदृष्टा थे। उन्होंने कभी किसी जाति और धर्म के विरुद्ध कभी कुछ न किया, न ही कहा। उनके शासन में सभी सुखी थे क्योंकि वे सबको अपना मानते थे। अपनी आठ सदस्यीय केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उन्होंने सात ब्राह्मणों को जगह दी। वे बेहद सहिष्णु हिंदू शासक थे। उन्होंने साफ कहा कि वे हिंदुओं, ब्राह्मणों और गायों के रक्षक हैं। उन्होंने सभी पंथों और उनके ग्रंथों के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित किया। किसी मस्जिद को अपने राज में किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाया न पहुंचने दिया। युद्ध के दौरान महिलाओं और बच्चों के सम्मान और सुरक्षा उनकी चिंता का मूल विषय थे।

मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने की उनकी अनेक कथाएं बहुश्रुत हैं। उन्होंने मुस्लिम विद्वानों और आलिमों को हमेशा आर्थिक मदद दी। सरकारी विभागों में उन्होंने मुस्लिम अधिकारियों को नियुक्त किया। औरंगजेब द्वारा सभी हिंदुओं पर जजिया कर लगाने पर शिवाजी ने उसे एक पत्र भी लिखा। बहुत खराब सामाजिक परिस्थितियां और मुगल शासकों द्वारा हिंदू विरोधी कृत्यों के बाद भी शिवाजी ने अपने राज्य में मुस्लिम जनता को कभी पराएपन का एहसास नहीं होने दिया और उनका संरक्षण किया। उन्होंने यह नियम ही बना दिया था कि किसी भी युद्ध, छापामार युद्ध में महिलाओं, मस्जिदों और पवित्र पुस्तक कुरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।

शिवाजी ऐसे भारतीय शासक के रूप में सामने आते हैं, जिसने अपनी बाल्यावस्था में जो सपना देखा, उसे पूरा किया। भारतीय समाज में आत्मविश्वास का मंत्र फूंका और भारतीय लोकचेतना के मानकों के आधार पर राज्य संचालन किया। मूल्यों और अपने धर्म पर आस्था रखते हुए उन्होंने जो मानक बनाए वे आज भी प्रेरित करते हैं। ऐसे महापुरुष सदियों में आते हैं, जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व लंबे समय तक लोगों के लिए आदर्श बन जाता है।

(लेखक भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) के पूर्व महानिदेशक हैं।)

नई सरकार के समक्ष ज्वलंत सुरक्षा चुनौतियां

नवगठित एनडीए सरकार में राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया है। वे पिछली सरकार में भी रक्षा मंत्रालय का कामकाज देख रहे थे। रक्षा मंत्री के तौर पर दूसरे कार्यकाल में राजनाथ सिंह के लिए अग्निपथ योजना की समीक्षा करके उसे आकर्षक बनाने का काम अत्यन्त सामयिक एवं ज्वलंत है। इसके अलावा सैन्य सुधारों को लागू करना, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का गठन, हथियारों के आयात में कमी करना, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाना, पाकिस्तान व चीन सीमा पर बने तनाव से निपटने के रास्ते निकालने की जिम्मेदारी के साथ ही रक्षा बजट अधिक करवाना है।

अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने को लेकर युवाओं ने शुरुआत से ही नाराजगी जाहिर कर दी थी। यह बात अलग है कि बाद में नवयुवक इस योजना में भर्ती होने लग गए थे। सेवानिवृत्त सैनिकों ने इस योजना का विरोध करते हुए सवाल उठाए थे। इसके अलावा कुछ विपक्षी दलों ने अग्निपथ योजना का मुद्दा जोर-शोर से उठाया। उल्लेखनीय है कि इस योजना में युवाओं को चार साल के लिए भर्ती किया जाता है। इस योजना के 25 प्रतिशत जवानों को ही स्थाई होने का अवसर मिलेगा। शेष जवानों को अन्य क्षेत्रों में रोजगार तलाशना पड़ेगा। स्थाई सैनिकों की तुलना में इन्हें केवल 30 दिन की छुट्टी मिलती है। अब इस योजना में सुधार को लेकर सेना के भीतर से ही कुछ सुझाव मिले हैं। इसलिए इसकी समीक्षा किए जाने की बात चल रही है। रक्षा मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि अग्निपथ योजना में यदि बदलाव की आवश्यकता हुई तो वे करने को तैयार हैं।

सैनिक सुधार करना सरकार के एजेंडे में शामिल है। सैन्य सुधारों में सबसे प्रमुख सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायु सेना एवं नौसेना को मिलाकर एकीकृत थिएटर कमांड का गठन करना है। इसमें नए सेनाध्यक्ष की भूमिका प्रमुख होगी। विदित हो कि मोदी सरकार के नेतृत्व में वर्ष 2019 में थिएटर कमांड बनाए जाने का निर्णय हुआ था। उसी समय जनरल बिपिन रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। इस योजना का उद्देश्य छोटी-बड़ी लड़ाइयों के समय अपने निश्चित सामरिक लक्ष्यों के साथ विशिष्ट शत्रु आधारित थिएटरों में संयुक्त अभियानों के लिए थल सेना, वायु सेना एवं नौसेना को एकीकृत करना है। भारतीय सशस्त्र बल थिएटर कमांड के गठन की तैयारियों को पूरा करने में लगे हुए हैं। वर्ष 2019 से अब तक की अवधि में निचले स्तर पर सेवाओं को एकीकृत करने के कुछ प्रयास किए गए हैं। बीते पांच वर्षों में थिएटर कमांड के लिए उत्तम संभव मॉडल पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए अनेक मसौदे तैयार किए गए। अब सरकार गठन के बाद इस पर विचार किए जाने की उम्मीद है।

मार्च, 2024 में स्वीडन स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) यानी सिपरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत संसार के शीर्ष हथियार आयातक देशों में शामिल है। यह संस्था दुनियाभर में हथियारों की खरीद-फरोख्त पर नजर रखती है और प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट जारी करती है। सिपरी की रिपोर्ट में बताया कि भारत ने 2019 से 2023 तक पांच वर्षों में दुनिया से 9.8 फीसदी हथियार आयात किए। आवश्यक है कि हथियारों के मामले में दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम की जाए। यह कार्य कैसे किया जाए इससे रक्षा मंत्री को निपटना होगा। बीते दो दशकों से मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया पर जोर दिया है। इसी अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता को काफी बढ़ावा दिया है। परिणाम यह हुआ कि भारत के रक्षा उद्योग में सैन्य साजो-सामान का उत्पादन काफी बढ़ गया है। स्वदेशी तकनीक से बनी मिसाइलों, हल्के लड़ाकू विमान तेजस, ध्रुव हेलीकॉप्टर, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों ने देश के रक्षा क्षेत्र को काफी आगे बढ़ा दिया है। इस कारण भारत के रक्षा निर्यात में काफी बढ़ोतरी हो गई।

- डॉ. लक्ष्मी शंकर यादव

सम्पादकीय

स्पेशल सर्विसेज से आरक्षण खत्म होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट में नीट विवाद पर ग्रेस मार्क्स से जुड़ी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी। अदालत ने कहा, अगर किसी की ओर से 0.001 फीसदी भी लापरवाही हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते हैं। बेंच ने सरकार और एनटीए से यह भी कहा कि कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, वह समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। इससे पहले 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की टिप्पणी कर ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट की परीक्षा रद्द की थी। तब कोर्ट का कहना था, एक भी फर्जी डॉक्टर बनता है तो पूरी परीक्षा रद्द होनी चाहिए। इस बात के सबूत हैं कि परीक्षा में इलेक्ट्रानिक डिवाइसेज का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कितने स्टूडेंट्स ने इसका इस्तेमाल किया, ये नहीं कहा जा सकता। ऐसे में परीक्षा रद्द करना जरूरी है। दरअसल, स्पेशल सर्विसेज में तो आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक जैसे पेशों में आरक्षण एक बुराई की तरह है। यदि आरक्षण से कम अंक वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है तो वो जनजीवन के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। नीट आरक्षण मानदंड के सरकारी नियमों के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत सीटें, ईब्ल्यूएस के लिए 10, एससी के लिए 15 और एसटी के लिए 7.5 फीसदी आरक्षण बताया जाता है। इसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण तो फिर भी लागू रखा जा सकता है क्योंकि ये जातिगत नहीं है। ये आर्थिक कमजोर वर्ग है। और आर्थिक कमजोर कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आरक्षण का सहारा लेकर कम नम्बरों में चिकित्सक बन गया तो उसके इलाज की क्या गारन्टी हो सकती है। ऐसा ही कुछ इंजीनियरिंग की सर्विसेज में होता है। इंजीनियर वह होता है जो देश के विकास में बड़ा भागीदार होता है। बड़ी-बड़ी परियोजनाएं उसके जिम्मे होती है। बड़े पुल, ओवरब्रिज, अन्डरब्रिज, फ्लाईओवर और बड़े-बड़े भवन उसके जिम्मे होते हैं। यहां भी आरक्षण के बलबूते नौकरी पाने वाला व्यक्ति जनजीवन के लिए बड़ा हानिकारक साबित हो सकता है। इसी तरह का मामला वैज्ञानिकों से जुड़ा हुआ है। इन विशेष सर्विसेज में तो जो पढ़ाई में अव्वल है, उसी का नम्बर आना चाहिए, चाहे वह फिर किसी भी जाति का हो।

योग मात्र व्यायाम नहीं , प्रकृति के साथ एकाकार हो जाने का भाव है

मोहन मंगलम

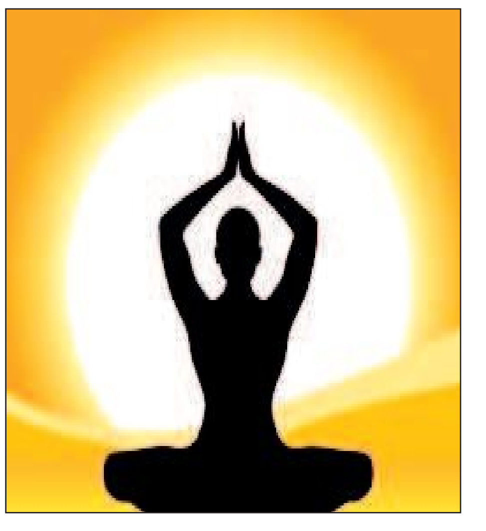

योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसमें शरीर और आत्मा को एकरूप करने का प्रयास किया जाता है। मन को शब्दों से मुक्त करके अपने आपको शांति और रिक्तता से जोड़ने का एक तरीका है योग। योग समझने से ज्यादा करने की विधि है। योग साधना के बल पर ही हमारे ऋषि-मुनियों एवं योग साधकों ने सुदीर्घ जीवन प्राप्त किया। अलग-अलग संप्रदायों, परंपराओं, दर्शनों, धर्मों एवं गुरु-शिष्य परंपराओं के चलते भिन्न-भिन्न सोपानों में योग का अलग-अलग मार्ग प्रशस्त हुआ।

प्राचीन काल से ही ऋषियों का उद्घोष रहा है – 'शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्' यानी कर्म करने से लेकर जीवन में आनंद प्राप्त करने तक का एकमात्र साधन स्वस्थ शरीर ही है। अनुलोम-विलोम प्राणायाम से जटिल से जटिल व्याधियों को दूर किया जा सकता है। कपालभाति तथा भस्त्रिका से धमनी में आए अवरोध दूर होते हैं। नियमित रूप से प्राणायाम किया जाए तो ह्दय गति और वायु तंत्र की गति नियंत्रित होती है। अत: प्राणायाम ही आध्यात्मिक उन्नति एवं शरीर को निरोग रखने का सबसे सरल एवं सस्ता साधन है।

प्रसन्नचित्त जीवन जीने की इच्छा हर किसी की होती है। इसके लिए योग, ध्यान, प्राणायाम, आसन, व्यायाम से लेकर न जाने कितने अनुसंधानात्मक प्रयोगों से प्राचीन भारतीय ग्रंथ भरे पड़े हैं। तमाम वैदिक ग्रंथों का एक लक्ष्य भी रहा है कि शारीरिक एवं मानसिक आंतरिक ऊर्जा को समेट कर व्यक्ति को उन्नतशील बनाया जाए। अत: योग को अपनाकर हम आरोग्य संवर्धन के साथ ही तनावमुक्त, प्रसन्नचित्त जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। आवश्यकता है नियमित एवं अनुशासित रूप से योग को आत्मसात करने की।

योग प्राचीनतम भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विद्या है। यह आत्मदर्शन से युक्त एवं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैज्ञानिक एवं प्रमाणित विधि है। प्राचीन भारतीय परंपरा एवं संस्कृति की अमूल्य देन है योग। योग मात्र व्यायाम नहीं है बल्कि स्वयं के विश्व एवं प्रकृति के साथ एकत्र हो जाने का भाव है। यह हमारी जीवनशैली में परिवर्तन लाकर हमारे अंदर जागरुकता पैदा करता है।

''योग'' शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। उपनिषदों में भी इसका उल्लेख आया है। योग के पुरातन साक्ष्य की ओर चलें तो सिंधु घाटी सभ्यता (2700 ई. पू.) में अनेक आकृतियां एवं मुहरें प्राप्त हुई थीं, जिनमें योग करती हुई आकृतियां उत्कीर्ण थीं। योग का अभ्यास पूर्व वैदिक काल से किया जाता रहा। वैदिक एवं उपनिषद् परंपरा, वैष्णव संप्रदाय में भी योग का साक्ष्य मिलता है।

भारतीय दर्शन में 'योग' अति महत्वपूर्ण शब्द है। श्रीमद्भगवद्गीता में योग शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है – बुद्धि योग, संन्यास योग, कर्म योग। श्रीमद्भगवद्गीता में योगेश्वर श्रीकृष्ण ने योग को विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त करते हुए कहा, ''अनुकूलता, प्रतिकूलता, सिद्धि, सफलता, विफलता, जय, पराजय इन समस्त भावों के साथ में रहते हुए सम रहना ही योग है।''

भारतीय दर्शन में छह दर्शनों में से एक है योग। यह हमारे ऋषियों, महर्षियों और तपस्वियों की अनुभूत साधना का वैचारिक आदर्श है। योग विद्या भारतवर्ष की अमूल्य संपत्ति है जो सुदूर अतीत काल से गुरु परंपरा पूर्वक चली आ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में योग को परिभाषित करते हुए कहा, ''चित्तवृत्ति निरोध:'' यानी मन को चंचल होने से रोकना ही योग है। इसकी शुरुआत ही अनुशासन एवं मन की वृत्तियों को रोकने से होती है। चित्तवृत्ति का निरोध हो जाने पर व्यक्ति सांसारिक उलझनों से मुक्त हो जाता है। पतंजलि ने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के रूप में जाने जाते हैं।

इनमें संयमित जीवन पद्धति पर प्रकाश डाला गया है। हमारे शरीर को प्रेरणा देने का कार्य प्राण और मन करते हैं। संपूर्ण शारीरिक तंत्र को 24 घंटे गतिशील रखने का प्रमुख कार्य प्राण का ही है। प्राण संपूर्ण शरीर में विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रेरित करता है। योग सूत्र में प्राण के पांच मुख्य भेद बताए गए हैं- प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। इन प्राणों की साधना समस्त सफलताओं और सिद्धियों का आधार है। प्राणों के नियमन की प्रक्रिया ही योग शास्त्र में 'प्राणायाम' कहलाती है। धारणा और ध्यान के रूप में मन को तेजस्वी, ओजस्वी और ऊर्जावान बनाने का एक व्यवस्थित कार्यक्रम योग शास्त्र में सुझाया गया है। हमारे शरीर में फेफड़ों, ह्दय और मस्तिष्क का विशेष महत्व है और इन तीनों का एक-दूसरे से गहरा सामंजस्य भी है। योग एवं प्राणायाम करने से ये तीनों अवयव बलिष्ठ होते हैं एवं शरीर निरोग रहने के साथ ही जीवन उन्नत होने लगता है।

ऐसे हुई योग दिवस की शुरुआत-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में दुनियाभर में योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया और 11 दिसम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रत्येक वर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मान्यता दी। इसके अगले ही साल 2015 में पहली बार 21 जून को विश्व योग दिवस दुनिया भर में मनाया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है।

आज का इतिहास

- 1837 में आज ही के दिन विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी बनीं थी।
- 1840 में 20 जून को ही सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ का पेटेंट कराया था।
- 1862 में आज ही के दिन रोमानिया के प्रधानमंत्री बार्बू कटारगिउ की हत्या की गई थी।
- 1863 में 20 जून को ही पश्चिमी वर्जीनिया अमेरिका का 35वां राज्य बना था।
- 1877 में आज ही के दिन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कनाडा के ओंटारियो में दुनिया का पहला वाणिज्यिक टेलीफोन सेवा शुरू की थी।
- 1887 में 20 जून को ही भारत का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनस (छत्रपति शिवाजी टर्मिनस) लोगों के लिए खुला था।
- 1916 में आज ही के दिन पुणे में एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई।
- 1921 में 20 जून को ही चेन्नई, भारत शहर में बकिंघम और कर्नाटक मिल्स के श्रमिकों ने 4 महीने की हड़ताल शुरू की थी।
- 1960 में 20 जून को ही माली फेडरेशन (बाद में माली और सेनेगल में विभाजन) को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी।
- 1976 में आज ही के दिन अमेरिकी राजदूत की हत्या के बाद लेबनान से अमेरिका ने सैकड़ों अपने नागरिकों को वहां से निकाला था।
- 1990 में आज ही के दिन ईरान में भूकंप से 40 हजार से अधिक की मृत्यु हो गई थी।
- 1991 में 20 जून को ही एकीकृत जर्मनी की राजधानी फिर से ?बर्लिन को बनाने के प्रस्ताव को संसद ने मंजूरी दी थी।
- 2001 में 20 जून को ही जनरल परवेज मुशर्रफ़ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे।
- 2002 में आज ही के दिन अमेरिकी कोर्ट ने मानसिक बीमारों की फांसी की सजा पर रोक लगाई थी।
- 2005 में आज ही के दिन रूस मालवाहक यान एम-53 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा था।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारम्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताप और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
परोपकार के लिए किए काम आपको आंतरिक खुशी देंगे। आज आपकी वाणी का जादू किसी को अभिभूत करके आपको लाभ दिलाएगा। वाणी की सौम्यता नए संबंध स्थापित करने में सहायक होगी।

वृष
स्नेहीजनों एवं मित्रों से उपहार मिल सकता है। उच्च अधिकारियों की कृपादृष्टि बनी रहेगी। सांसारिक जीवन में आनंद का अनुभव करेंगे। कार्यक्षेत्र में उच्च अधिकारियों के खुश रहने से पदोन्नति की संभावना बढ़ेगी।

मिथुन
लंबी अवधि की आर्थिक योजना के लिए दिन अनुकूल है। आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टि से दिन लाभदायक होगा। शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव होगा। मित्रों तथा स्वजनों की ओर से उपहार मिलेगा।

कर्क
पठन-लेखन जैसी साहित्यिक प्रवृत्तियों में अभिरुचि बढ़ेगी। परिश्रम का अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने से थोड़े निराश हो सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। पेट की तकलीफ से परेशानी हो सकती है। सगे-संबंधियों के साथ अनबन होगा।

सिंह
उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। निर्धारित कार्यों में कम सफलता मिलेगी। आज आपकी वैचारिक समृद्धि बढ़ेगी। मीठी वाणी से आप लाभप्रद, सौहार्द्रपूर्ण संबंध विकसित कर सकेंगे। उत्तम भोजन, भेंट उपहारों और वस्त्रों की प्राप्ति होगी।

कन्या
मानसिक दुविधा में होने के कारण आप महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले सकेंगे। पानी वाली जगहों तथा अन्य गर्म तरल पदार्थों से सावधान रहें। परिवार या जमीन से संबंधित मामलों पर चर्चा और कहीं जाने की योजना टालें। दुर्घटना से बचें। नए काम करने की प्रेरणा मिलेगी।

तुला
शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थता बनी रहेगी। आनंद की प्राप्ति, जीवनसाथी की निकटता और प्रवास-पर्यटन से आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज के दिन ज़रा सा भी असंयमित और अनैतिक व्यवहार आपको तकलीफ में डाल सकते हैं।

वृश्चिक
वाणी की शिथिलता के कारण उग्र तकरार हो सकती है। सगे-संबंधियों के साथ अनबन होगा। मनोरंजन या घूमने-फिरने के पीछे पैसे खर्च होंगे। शारीरिक, मानसिक व्यग्रता कम करने के लिए आध्यात्मिकता सहायक साबित होगी।

धनु
पारिवारिक सदस्यों के साथ सुख-शांति में दिन व्यतीत होगा। उनका सहयोग मिलेगा। दूरस्थ मित्र और स्नेहीजनों के साथ संपर्क लाभदायक साबित होंगे। अपनी प्रभावशाली वाणी से अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकेंगे।

मकर
शारीरिक और मानसिक ताजगी के साथ घर में भी आनंद का वातावरण रहेगा। दोस्तों से लाभ होगा। कार्य सफलता और प्रिय व्यक्ति का साथ आनंदप्रद रहेगा। आर्थिक लाभ और भाग्य वृद्धि की संभावनाएं हैं।

कुंभ
नौकरी-धंधे या व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति होगी। मित्रों के साथ मुलाकात, प्रवास का आयोजन होगा। विवाहोत्सुक युवक-युवतियों के लिए सुनहरे अवसर आएंगे। पुत्र तथा पत्नी से लाभ होगा। घर के बुजुर्गों के जरिए लाभ मिलेगा।

मीन
स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा। पिता तथा सरकार से लाभ मिलेगा। आर्थिक योजना अच्छी तरह पूरी कर सकेंगे। व्यापार-धंधे के लिए प्रवास की संभावना है। अन्य लोगों की सहायता करने का प्रयत्न करेंगे। मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

स्वास्थ्य समाचार

पेट में कीड़ों (पिनवॉर्म) की समस्या ठीक करने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय

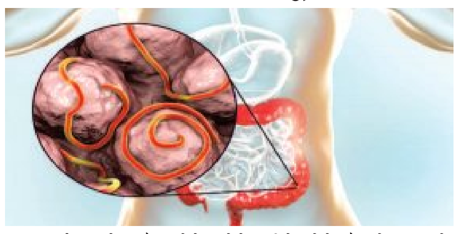

पिनवॉर्म पतले और छोटे-छोटे कीड़े होते हैं जो मनुष्यों की आंतों और पेट को संक्रमित करते हैं। अधिकतर यह बच्चों में पाए हैं और इन्हें बच्चों के मल में आसानी से देखा भी जा सकता है। अगर सावधानी न बरती जाए तो यह बड़ी उम्र के लोगों में भी हो सकते हैं। हालांकि इन्हें कुछ घरेलू नुस्खों से ठीक किया जा सकता है लेकिन ये कीड़े बहुत अधिक संक्रामक होते हैं और कपड़ों से भी फैल सकते हैं। पिनवर्म इंफेक्शन इनके अंडो का दूषित खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थों के जरिए शरीर में जाने से फैलता है। एक बार शरीर में पहुंचने के बाद कुछ हफ्तों में ही यह अंडे कीड़ों में बदल जाते हैं और इन कीड़ों से शरीर के अंदर अन्य कीड़े बनने लगते हैं। आपके बच्चे या आप में इनके लक्षण देखने को मिलते हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

नारियल का तेल : इसमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-ऑक्सीडेंट्स और एंटी-फंगल गुण होते हैं जो शरीर से पिन वॉर्म को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसके लिए आपको केवल एक चम्मच नारियल के तेल की जरूरत होगी। इसे रोजाना सुबह सुबह पीएं या रूई की सहायता से गुदा द्वार में लगाएं।

एप्पल साइडर विनेगर : इसमें 6% एसिटिक एसिड होता है और यह शरीर के पीएच बैलेंस को काफी कम कर सकता है। इससे कीड़ों को पनपने में दिक्कत होती है जिस वजह से वह आपके पेट में ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाते। दो चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को एक गिलास पानी में मिला कर पी लें। इसे थोड़ा मीठा बनाने के लिए शहद को भी डाल सकते हैं।

लहसुन : यह एक ऐसी जड़ी-बूटी है जिसमें एंटी-बैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं। ये पिनवॉर्म इंफेक्शन को ट्रीट करने में काफी सहायक माने जाते हैं। आपको केवल एक से दो लहसुन की कलियों की जरूरत है और साथ ही थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली भी ले सकते हैं। आप रोजाना इन लहसुन की कलियों को चबाएं या खाने में मिला सकते हैं। आप लहसुन को पेट्रोलियम जेली में मिला कर प्रभावित क्षेत्र पर अप्लाई भी कर सकते हैं।

गर्म पानी : पिन वॉर्म काफी ज्यादा संक्रामक होते है इसलिए अपने पूरे घर को ही डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। गर्म पानी की मदद से आप इसमें आराम पा सकते हैं। इससे यह कीड़े बार बार नहीं आएंगे। इसके लिए आपको गर्म पानी, साबुन और डिटर्जेंट की जरूरत होती है। सारे कपड़े बर्तनों और फैब्रिक को धोने से आधा घंटा पहले गर्म पानी में भिगो दें। आप वाशरूम आदि को भी रोजाना डिसइंफेक्ट कर सकती हैं।

टी-ट्री ऑयल : इसकी एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल प्रॉपर्टी इन कीड़ों से निजात दिलाने में मदद कर सकती हैं। टी-ट्री ऑयल में एंटी पैरासिटिक गुण भी होते हैं। एक या दो बूंद टी ट्री ऑयल लें और उसमें एक दो चम्मच नारियल का तेल मिक्स कर लें।

आप इसे प्रभावित भाग पर अप्लाई कर सकते हैं। इसे डायरेक्ट स्किन पर अप्लाई करने से स्किन इरिटेट हो सकती है।

एक्सरसाइज करने के बाद ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? बीपी के मरीज एक्सरसाइज करते समय बरतें ये सावधानियां

हाई ब्लड प्रेशर आजकल 40 पार की उम्र के बाद सामान्य समस्या बनती जा रही है। अगर आप हाइपरटेंशन से जूझ रहे हैं तो रेगुलर एक्सरसाइज आपके लिए बहुत फायदेमंद है। लेकिन यह बात जान कर आपको हैरानी होगी कि एक्सरसाइज करने के बाद आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप वर्क आउट करते हैं तब आपकी मसल्स सिकुड़ती हैं ताकि दिल तक ब्लड पंप हो सके। कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विनय भट्ट के मुताबिक एक्सरसाइज करने के दौरान सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। लेकिन लंबे समय तक इसका असर नहीं होता। कुछ समय बाद आपका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। इसका मतलब है कुछ समय के लिए तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है लेकिन जल्द ही ये कम होकर सामान्य हो जाता है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे लोगों के लिए एक्सरसाइज करना लाभदायक ही होता है।

एक्सरसाइज करने के बाद ब्लड प्रेशर कब तक नॉर्मल होता है?

एक्सरसाइज करने के दो घंटे के बाद तक भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा ही रहता है। इसलिए इतने समय तक इंतजार करना चाहिए। इसलिए दोनों ब्लड प्रेशर में अंतर जानने के लिए एक्सरसाइज करने के पहले ब्लड प्रेशर चेक करें और एक्सरसाइज करने के दो घंटे बाद ही दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर एक्सरसाइज करने के दौरान आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो इस दौरान बीपी बढ़ा हुआ ही मिलेगा। इसलिए दो से तीन घंटों तक इंतजार जरूर करें।

हाइपरटेंशन के मरीजों के लिए कुछ सुरक्षित एक्सरसाइज

- आपको एक्सरसाइज के बारे में पहले अपने डॉक्टर से बात जरूर करनी चाहिए। बहुत से लोग जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वह रनिंग, साइकिलिंग, वेट ट्रेनिंग, जैसी एक्सरसाइज आराम से कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज में व्यक्ति को शरीर पर अधिक प्रेशर डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है।
- अगर आप इन एक्सरसाइज को पूरी इंटेंसिटी से नहीं कर सकते हैं तो आप इसमें थोड़ा बदलाव करके, इन्हें आसान भी बना सकते हैं। अगर आपको इन्हें करने से चक्कर आने लगते हैं या जी मिचलाने लगता है तो इनके बजाए अन्य एक्सरसाइज भी कर सकते हैं।
- अगर आप सबसे सामान्य एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिल चलाना, मॉडरेट स्विमिंग, वेट ट्रेनिंग आदि ट्राई कर सकते हैं।

हाइपर टेंशन में न करें यह एक्सरसाइज

कुछ रिस्की एक्टिविटी जो हाई इंटेंसिटी वाली होती हैं, उन्हें करने से बचना चाहिए। जैसे 100% क्षमता के साथ वेट लिफ्ट नहीं करना चाहिए। स्कूबा डाइव, स्काई डाइव जैसी चीजें भी नहीं ट्राई करनी चाहिए। टेनिस, फुटबॉल और बास्केट बॉल जैसे खेल भी आपको ट्राई नहीं करने चाहिए। स्प्रिंटिंग, हाई इंटेंस वर्कआउट और आउटडोर स्पोर्ट्स को भी ज्यादा ट्राई न करें।

क्या एक्सरसाइज करने से लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है?

एक्सरसाइज करने के बाद ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। जिससे लो ब्लड प्रेशर वाले इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होने लगता है तो दिल के लिए ब्लड पंप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।

जब भी एक्सरसाइज करते समय आपको यह लगने लगे कि आपको चक्कर आ रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका ब्लड प्रेशर लो है। ऐसी स्थिति में एक्सरसाइज बंद करके कुछ समय आराम करें और परेशानी महसूस होने पर डॉक्टर से संपर्क करें।

गर्मियों में खीरा खाने से पहले जान लें ये बात वरना सेहत को होगा भारी नुकसान

गर्मियों का मौसम शुरू होते ही हमारे खाने में एक चीज शामिल हो जाती है, और वो है खीरा। खीरे का ठंडा-ठंडा रायता, सलाद, या खीरे की सब्जी या कच्चा खीरा। लोग कई तरीकों से इसे अपने खाने में शामिल करते हैं। चिलचिलाती गर्मी में खीरा ठंडक तो देता ही है, इसके साथ ही यह हमारी सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। खीरे में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सिडेंट्स और विटामिन मौजूद होते हैं और इसमें कैलोरी बहुत कम होती है। यही वजह है कि जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वे ज़्यादा मात्रा में खीरे का सेवन करते हैं। खीरे में बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है इसलिए गर्मियों में खीरे के सेवन से शरीर में पानी की कमी नहीं होती। कुल मिलकर खीरे में बहुत से गुण मौजूद होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन खीरा खाने का फायदा तभी होता है जब इसे सही तरीके से खाया जाए। डॉक्टर्स के मुताबिक खीरा खाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए वरना इससे हमारे स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है।

खीरे में बहुत कम मात्रा में कैलोरी होती है इसलिए लोग वेट लॉस के लिए खीरा ज़्यादा खाते हैं। कई लोग रात में डिनर में अधिक मात्रा में खीरा खाते हैं। हालांकि, डॉक्टर्स के मुताबिक, रात में खीरा खाने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। लोगों को लगता है कि खीरे में पानी की अधिक मात्रा होती है इसलिए अगर वे रात में खाने की जगह खीरा ज़्यादा मात्रा में खा लेंगे तो इससे उन्हें भूख कम लगेगी और वे वजन जल्दी घटा पाएंगे। हालाँकि, खीरे को पचाना इतना आसान नहीं। इसलिए रात को खीरे का ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए।

इसके साथ ही डॉक्टर्स रात में सोने से 2-3 घंटे पहले खीरा खाने की सलाह देते हैं। रात में ज़्यादा मात्रा में खीरा खाने से अपच और नींद न आने की समस्या हो सकती है। न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक, खीरे में कुकुरबिटेसिन नामक तत्व पाया जाता है, जो खीरे की कड़वाहट के लिए भी जिम्मेदार होता है। डॉक्टर्स के मुताबिक, फूलगोभी और ब्रोकोली की तरह, रात में ज़्यादा मात्रा में खीरा खाने से गैस, पेट फूलना और अपच की समस्या हो सकती है। यह सभी समस्याएं कुकुरबिटेनिस के कारण ही होती हैं। खीरे में 95 प्रतिशत मात्रा तक पानी होता है इसलिए खीरा खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खीरे में कुकुरबिटेसिन, खीरे के छिलके में ज्यादा पाया जाता है इसलिए खीरा को खाने से पहले हमेशा अच्छी तरह धोकर, छीलकर और इसका ऊपरी भाग हटा कर ही खाना चाहिए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

योग सशक्त माध्यम है महिला सशक्तीकरण एवं शांति का

अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस, 21 जून, 2024 पर विशेष

-ललित गर्ग

मनुष्य के सम्मुख युद्ध, महामारी, महंगाई, बेरोजगारी, प्रतिस्पर्धा के कारण जीवन का संकट खड़ा है। मानसिक संतुलन अस्त-व्यस्त हो रहा है। मानसिक संतुलन का अर्थ है विभिन्न परिस्थितियों में तालमेल स्थापित करना, जिसका सशक्त एवं प्रभावी माध्यम योग ही है। योग एक ऐसी तकनीक है, एक विज्ञान है जो हमारे शरीर, मन, विचार एवं आत्मा को स्वस्थ करती है। यह हमारे तनाव एवं कुंठा को दूर करती है। जब हम योग करते हैं, श्वासों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, प्राणायाम और कसरत करते हैं तो यह सब हमारे शरीर और मन को भीतर से खुश और प्रफुल्लित रहने के लिये प्रेरित करती है। योग ने सिर्फ शरीर को बल्कि मंन को भी शांति और एकाग्रचित करता है। योग के अभ्यास से शांतिपूर्ण मन से व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए एक बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। इस बार 10वीं बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2024 को पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जायेगा। इस साल योग दिवस की थीम महिलाओं पर आधारित महिला सशक्तिकरण के लिए योग है। भारत ने योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और योग के जरिए सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग लाभकारी है। यह शरीर को रोगमुक्त रखता है और मन को शांति प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति से जुड़ी ये क्रिया अब विदेशों तक फैल चुकी है।

योग एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है। ध्यान व योग मानसिक शांति देता है, जिससे सकारात्मक विचार आते हैं और लोग स्वस्थ जीवनशैली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। योग एक प्राचीन भारतीय परंपरा है, जो अब वैश्विक संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है। योग से परस्पर देश विदेश के योगी एक दूसरे से जुड़ते हैं और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देते हैं। इस वर्ष योग दिवस का लक्ष्य योग के माध्यम से महिलाओं के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देना है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि महिलाएं स्वस्थ और आत्मविश्वास से भरपूर हों और समाज में अग्रणी भूमिका निभा रहीं है। इस वर्ष महिलाओं को प्रभावित करने वाली विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों जैसे- मासिक धर्म की परेशानी, रजोनिवृत्ति के लक्षण और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर शोध करने की योजना है। योग आत्म-जागरूकता और आत्म-स्वीकृति को बढ़ावा देता है, जो महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्म-सम्मान बढ़ा सकता है, जिससे महिलाओं को अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने की शक्ति मिलती है। योग के माध्यम से विश्व शांति, उन्नत व्यक्तित्व विकास, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, गुस्सा एवं तनाव कम करने जैसे लक्ष्यों को भी हासिल किया जायेगा। पिछले दिनों कनाडा के ओंटेरियो यूनिवर्सिटी में हुए एक अध्ययन के अनुसार कुंठा और तनाव के लगभग 64 प्रतिशत मरीजों ने माना कि उन्हें इस बात का अंदाज नहीं था कि उनकी खास बीमारी की वजह अंदर दबा गुस्सा हो सकता है। गुस्से की वजह से कुछ मामलों में मरीजों ने अपने आपको नुकसान भी पहुंचाया। एबी कहते हैं, ह्यआपको पता ही नहीं होता कि आपने अपने दिल में क्या-क्या भर रखा है। इसके लिए जरूरी है कि अपने आपको जानें। अगर कोई पुरानी बात आपको मथ रही है तो उसे जाने न दें। आप उस व्यक्ति को माफ कर दें और खुद को भी। इस तरह बिना बोझ के आप जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे ह्व मन की गंदगी को धोने का माध्यम है योग। पवित्र अंतःकरण ही वह दर्पण है जिसमें आत्मा का दर्शन, प्रकृति का प्रदर्शन और ब्रह्म का संदर्शन होता है। शुद्ध अंतःकरण में बुद्धि आकाशवत निर्मल और स्वच्छ रहती है, मन गंगा जैसा पवित्र रहता है, चित्त ऐसा स्थिर रहता है जैसे बिना वायु के अविचल दीपक की ज्योति और सम्पूर्ण चेतना भगवान में मिलने के लिए ऐसी बहती है जैसे समुद्र में मिलने के लिए नदियां। जैसे शीशे में अपना चेहरा तभी दिखलायी पड़ता है जबकि शीशा साफ और स्थिर हो, इसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण से ही परम ब्रह्म के दर्शन होते हैं।

अभी कुछ दिन पहले ही एक बात समाचारपत्रों में पढ़ी कि कैंसर क्यों होता है, इसके कई कारण हैं। एक कारण यह है कि जो लोग मस्तिष्क का सही उपयोग करना नहीं जानते उनके कैंसर हो सकता है। मस्तिष्क विज्ञानी तो यह भी कहते हैं कि मस्तिष्क की शक्तियों का केवल चार या पांच प्रतिशत उपयोग आदमी करता है, शेष शक्तियां सुप्त पड़ी रहती है। चाहे कर्म का क्षेत्र हो या धर्म का क्षेत्र हो, दोनों में हम पिछड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारी जानकारी मस्तिष्क विद्या के बारे में होनी चाहिए। योग विद्या भारत की सबसे प्राचीन विद्या है। इसी भारतीय योग एवं ध्यान के माध्यम से भारत दुनिया में गुरु का दर्जा एवं एक अनूठी पहचान हासिल करने में सफल हो रहा है। इसीलिये समूची दुनिया के लिये अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वीकार्य हुआ है। हमारे मस्तिष्क में एक पर्त है एनीमल ब्रेन की। वह पर्त सक्रिय होती है तो आदमी का व्यवहार पशुवत हो जाता है। जितने भी हिंसक और नकारात्मक भाव हैं, वे इसी एनीमल ब्रेन की सक्रियता का परिणाम है। इसे संतुलित करने का माध्यम योग है। शारीरिक, मानसिक और अध्यात्मिक शांति एवं स्वस्थ्यता के लिये योग की एकमात्र रास्ता है। लेकिन भोगवादी युग में योग का इतिहास समय की अनंत गहराइयों में छुप गया है। वैसे कुछ लोग यह भी मानते हैं कि योग विज्ञान वेदों से भी प्राचीन है। दुनिया में भारतीय योग को परचम फहराने वाले स्वामी विवेकानंद कहते हैं-ह्यह्यनिर्मल हृदय ही सत्य के प्रतिबिम्ब के लिए सर्वोत्तम दर्पण है। इसलिए सारी साधना हृदय को निर्मल करने के लिए ही है। जब वह निर्मल हो जाता है तो सारे सत्य उसी क्षण उसमें प्रतिबिम्बित हो जाते हैं।...पावित्र्य के बिना आध्यात्मिक शक्ति नहीं आ सकती। अपवित्र कल्पना उतनी ही बुरी है, जितना अपवित्र कार्य। आज विश्व में जो आतंकवाद, हिंसा, युद्ध, साम्प्रदायिक विद्धेष की ज्वलंत समस्याएं खड़ी है, उसका कारण भी योग का अभाव ही है। हम अपनी समस्या को समझें और अपना समाधान खोजें। समस्याएं परेशान करती हैं। जरूरत खुद को काबू में रखने की होती है, हम दूसरों को काबू में करने में जुटे रहते हैं। विज्ञान ने यह प्रमाणित कर दिया है- जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, उसे योग को अपनाना होगा। बार-बार क्रोध करना, चिड़चिड़ापन आना, मूड का बिगड़ते रहना- ये सारे भाव हमारी समस्याओं से लडने की शक्ति को प्रतिहत करते हैं। इनसे ग्रस्त व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है। हमें अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को किसी दायरे में बांधने से बचना होगा। ऐसा तब होगा, जब हम योग को अपनी जीवनशैली बनायेंगे। हम जितना ध्यान रोगों को ठीक करने में देते हैं, उतना उनसे बचने में नहीं देते। दवा पर जितना भरोसा रखते हैं, उतना भोजन पर नहीं रखते। यही कारण है रोग पीछा नहीं छोड़ते। हमें यह पता होता है कि कार के लिए कौन सा ईंधन सही है, पर हम ये नहीं जानते कि शरीर को ठीक रखने के लिए कौन से ईंधन की जरूरत है? हमें कैसा भोजन करना चाहिए? कैसी सोच चाहिए? कैसी जीवनशैली चाहिए?

योग एवं ध्यान एक ऐसी विधा है जो हमें भीड़ से हटाकर स्वयं की श्रेष्ठताओं से पहचान कराती है। हममें स्वयं पुरुषार्थ करने का जज्बा जगाती है। स्वयं की कमियों से रू-ब-रू होने को प्रेरित करती है। स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार कराती है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हमारे भीतर से न मिले। भगवान महावीर का यह संदेश जन-जन के लिये सीख बने- ह्यपुरुष! तू स्वयं अपना भाग्यविधाता है। औरों के सहारे मुकाम तक पहुंच भी गए तो क्या? इस तरह की मंजिलें स्थायी नहीं होती और न इस तरह का समाधान कारगर होता है। हमारे भीतर ऐसी शक्तियां हैं, जो हमें बचा सकती हैं। योग, संकल्प एवं संयम की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। अनावश्यक कल्पना मानसिक बल को नष्ट करती है। लोग अनावश्यक कल्पना बहुत करते हैं। यदि उस कल्पना को योग में बदल दिया जाए तो वह एक महान शक्ति बन सकती है।

भवन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की कहानी है बिहार में पुलों का गिरना!

अशोक भाटिया

बिहार के अररिया जिले में एक बार फिर बकरा नदी पर बना पुल भरभराकर गिर गया। 12 करोड़ से निर्मित इस पुल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था। हालांकि, बिहार में पुल गिरने की बात नई नहीं है। बीते 10 सालों से बिहार के कई जिलों में पुल गिरे, भ्रष्टाचार को लेकर सिस्टम पर सवाल भी खड़े हुए। लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिला दरअसल, पुल गिरने की घटना भवन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता है। पुल गिरने की घटना, निर्माण कार्य में खराब गुणवत्ता वाला मेटेरियल का उपयोग और भूमि जांच में गड़बडी की बात को उजागर करता है और इस तरह की घटना बिहार के सरकारी सिस्टम पर सवालिया निशाना है। ज्ञात हो कि बिहार के अररिया जिले में मंगलवार को बकरा नदी पर बना पुल भरभराकर गिर गया। 12 करोड़ से निर्मित इस पुल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था। सिकटी प्रखंड स्थित बकरा नदी के पड़रिया घाट पर 12 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया गया था।

बताया जाता है कि नेपाल में हुई बारिश के कारण अचानक आए नदी में तेज बहाव ने पुल को अपने साथ बहा लिया। पुल का कार्य पूरा हो गया होता तो इससे सिकटी और कुर्साकांटा प्रखंड जुड़ जाता। यह दुखद बात है कि सरकार ने इस पुल पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए थे लेकिन सब पानी में चला गया। अच्छा हुआ यु आवागमन के लिए चालू नहीं हुआ था नहीं तो लाशो का ढेर बिछ जाता। वैसे पिछले 5 साल में दूसरी बार नदी ने बदला रास्ता : इस बहाव में परडिया घाट पर बने पुल का तीन पाया भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गये। इसके ऊपर बना गार्डर भी नदी में समा गया है। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष है। इतना घटिया निर्माण किए जाने से इस पुल की यह दशा हुई है।

बिहार में यह एक ऐसी नदी है जिसकी वजह से सरकार भी परेशान है और लोग भी। जब इस नदी पर पहली बार पुल बना तो स्थानीय लोगों को लगा कि पुल निर्माण के बाद उनके इलाके की सूरत बदल जाएगी। लेकिन बकरा नदी ने यहां के लोगों को ऐसा गच्चा दिया कि सरकार के बड़े से बड़ा इंजीनियर भी फेल हो गया। हुआ ये कि, अररिया के सिकटी में बकरा नदी पर साल 2012 में पुल बना। जितनी नदी की चौड़ाई थी उसके मुताबिक पुल 2019 में बनकर तैयार भी हो गया। जैसे ही पुल बनकर तैयार हुआ नदी ने अपना रुख मोड़ लिया और नदी पूरब की ओर खिसक कर बहने लगी। सरकार भी हार मानने वाली नहीं थी। उसने दूसरी बार 11 करोड़ खर्च करके 200 मीटर तक पुल का निर्माण किया। फिर स्थानीय लोगों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। कुछ दिन की समस्या मानकर, लोगों ने पुल बनते ही सारे दुख दूर होने की उम्मीद जग गई। लेकिन सभी के अरमानों को रौंदकर बकरा नदी ने फिर रास्ता बदल दिया। नदी इस बार इस पुल के पश्चिम में बहने लगी। पुल के दोनों ओर बहती नदी के बीच ग्रामीण चचरी पुल बनाकर आर-पार होते हैं। पुल के दोनों हिस्से अब सूखे में खड़े हैं। हर कोई बिहार के इंजीनियर की इंजीनियरिंग की दाद दे रहा है। इधर बकरा नदी है कि इंजीनियरों की 'औकात' से बाहर हो चुकी है। गांव वाले बता रहे हैं कि बकरा नदी हर बार फिर अपना रास्ता बदल रही है। बार-बार मार्ग बदले जाने की वजह से 31 करोड़ की लागत से तैयार खड़ा पुल अब किसी काम का नहीं रहा। लोगों के अरमान फिर एक बार नदी की धारा में गुम हो गए हैं। अगर ये पुल निर्माण पूरा हो जाता तो इस रास्ते से कुर्साकांटा और सिकटी प्रखंड से लेकर नेपाल सीमा तक के लाखों लोगों को इसका फायदा मिलता। नदी का मार्ग बदलने से कई घरों की जल समाधि हो चुकी है। स्थानीय ग्रामीण ने बताते है कि बकरा नदी के धारा बदलने से सिर्फ पुल का ही नहीं बल्कि कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इसकी धारा में कई घर विलीन हो गए। एक पूरी की पूरी बस्ती बकरा नदी के बदले रास्ते में आ गई। लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है।

बता दें कि इस पुल का उद्घाटन होने वाला था। लेकिन उद्घाटन से पहले ही करोड़ों की लागत से बनने वाला पुल ध्वस्त हो गया। बिहार में एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं। कोई आंधी से तो कोई बिना आंधी और पानी के। ये हाल तब है जब प्रदेश में बारिश नहीं हुई।

पुल की गुणवत्ता पर सवाल : पुल कैसे गिरा, क्या गुणवत्ता में कोई कमी की वजह से ये हादसा हुआ ये कह पाना मुश्किल है। फिलहाल इस बार भी पुल गिरने पर जांच का मुलम्मा चढ़ाया जाएगा। देखना है कि संबंधित जिम्मेदार पुल के गिरने की क्या वजह बताते हैं।

वैसे बिहार में पुल का गिरना पहली घटना नहीं है। पुलों के गिरने की लम्बी सूची है। बीते 10 सालों से बिहार के कई जिलों में पुल गिरे, 19 मार्च 2023 को बिहार के सारण जिले में एक पुल गिर गया था। बताया जाता है कि यह पुल अंग्रेजों के जमाने का था। बाढ़ से बाद पुल जर्जर हो गया था और कई जगहों पर दरारें आ रही थी। विभाग के लापरवाही के कारण यह पुर गिर गया। लेकिन जर्जर पुल को लेकर विभाग की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं किया गया था। 4 जून 2023 को सुल्तानगंज से खगड़िया के अगुवानी गंगा घाट पर निर्माणाधीन पुल के पिलर नंबर 10, 11 और 12 अचानक गिरकर नदी में बह गए थे। पुल गिरने की घटना से बिहार में सियासी बवाल खड़ा कर दिया था। पक्ष-विपक्ष के नेताओं ने एक दूसरे पर सवाल खड़े किए थे। 19 फरवरी 2023 को पटना के बिहटा में सरमेरा में फोन लेन पर गिर गया था। वहीं बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान में कमला बलान नदी के सबोहल घाट पर ओवरलोड ट्रक की चपेट में आने से पुल गिर गया था। 15 मई 2023 को पूर्णिया में एक बड़ा हादसा हुआ था। यहां एक पुल का एक बॉक्स ढलाई के दौरान गिर गया था। जुलाई 2022 में बिहार के कटिहार जिले में भी एक निर्माणाधीन पुल गिर गया था और पुल गिरने से 10 मजदूर घायल हो गए थे। 18 नवंबर 2022 को बिहार के नालंदा जिले में एक निर्माणधीन पुल गिर गया था। पुल गिरने से 1 की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि यह पुल घटिया निर्माण के कारण गिर गया था।

9 जून 2022 को बिहार के सहरसा में एक पुल गिरने से कई मजदूर घायल हो गए। बख्तियारपुर के कंडुमेर गांव में पुल गिरने से कई लोग दब गए थे। मजदूर पुल पर काम कर था। इसी दौरान पुल गिर गया और मजदूर मलबा में दब गया। हालांकि, बाद में उसे बचा लिया गया। पटना के फतुहा में 20 मई 2022 को अधिर बारिश के कारण एक पुल गिर गया था। यह पुल 1984 में बना था। वहीं, 30 अप्रैल 2022 को भागलपुर-खगड़िया में एक सड़क पुल गिर गया था।

क्रिकेट का सट्टा युवाओं के भविष्य से खिलवाड़

-नरेंद्र तिवारी 'पत्रकार'

ड्रीम इलेवन, माय इलेवन, हाउजेट ने दिया सट्टे को वैधानिक रूप

सरकार मानव के उत्थान के लिए कार्य करती है। सरकार को सामाजिक विकास के साथ मानवीय उत्थान की गति भी बढ़ना चाहिए। हरदम आदर्श समाज की स्थापना का प्रयास करते रहना चाहिए। भारत जैसे देश में जहां मानवीय मूल्य और गरिमा का बहुत अधिक महत्व है। वहां प्रजातांत्रिक सरकार का दायित्व है की वह नागरिकों के लिए मूल्य युक्त समाज और आदर्श समाज की स्थापना के प्रयास करें सिर्फ प्रयास ही नहीं करें उन्हें मूर्तरूप भी प्रदान करें। यह देखकर बढ़ा अंचम्भा होता है की जिस सरकार को आदेश समाज की स्थापना का कार्य करना चाहिए, वह क्रिकेट जैसे खेल को जुएं में परिणित कर समाज में खुले आम सट्टे की प्रवृति को बढ़ा रही है। एक और पुलिस एवं सरकार की आंखों में धूल झोंककर अपराधी वर्ग आनलाइन सट्टे का खेल खिला रहा है। उज्जैन में पकड़ाया करोड़ों का आनलाइन सट्टा इसी प्रकार के अपराधियों की करतूत है। यह सच है की क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल है। यह खेल दो टीम मैदान में खेलती है। क्रिकेट शारारीक प्रदर्शन की मांग करता है। यह मनुष्य को खिलाड़ी भावना, एक दूसरे के सम्मान तथा अंपायर के निर्णय को सर्वमान्य मानने की सीख भी देता है। क्रिकेट के मैच में दो टीम खेलेगी तो एक टीम जीतेगी दूसरी की हार होगी। जब क्रिकेट का मैच दो देशों की टीमों के मध्य होता है, तब नागरिकों की भावनाएं अपने देश के प्रति होती है। हार जीत का देश के नागरिकों पर भावनात्मक असर होता है। किंतु क्रिकेट के विषय में यह बात अब पुरानी हो गई है। जितना मैच और खेल मैदान में नही होता उससे अधिक सट्टा मोबाइलों की स्क्रीन पर चलता है। आनलाइन सट्टे के कारोबार से जुड़े कारोबारियों और क्रिकेट के सट्टे में रुचि लेने वाले सट्टेबाजों के मन मतिष्क में चलता है। एक एक गेंद पर सट्टा लगता है। क्रिकेट के सट्टे में आनलाइन तकनीकी का उपयोग होता है। मोबाइल के एप इस खेल में रुचि रखने वालो को एक गेंद पूर्व की स्थिति से अवगत कराते है। याने आप जो मैच टीवी पर देख रहे है। उसका हाल सट्टेबाजो को अपने एप के सहारे आपसे दो गेंद पहले पता चल जाता है। आनलाइन सट्टा सेंटर से कमेंट्री भी प्रसारित होती है। फटाफट क्रिकेट ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। यह कहने में बुरा लगता है की क्रिकेट अब सट्टे का पर्याय हो गया है। मध्यप्रदेश के उज्जैन में पकड़ा गया आनलाइन सट्टे का बड़ा कारोबार मध्यप्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में सरकार की नाक के नीचे चल रहे अपराध का नमूना है। इतने बड़े रूप में चल रहा क्रिकेट का सट्टा कबसे चल रहा है। मध्यप्रदेश की तकनीकी रूप से सक्षम पुलिस से यह पूछा जाना चाहिए की इतने बड़े रूप में क्रिकेट का सट्टा कब से चल रहा है? सरकार को इसकी भनक क्यों नही लग पाई? यह भी पता लगाना चाहिए की इतना बड़ा अवैध कारोबार किस नेता, अधिकारी के सरंक्षण में चल रहा था? आए दिन देश में आनलाइन सट्टे से जुड़े अपराधियों को पकड़ने का सिलसिला जारी है। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर भी इससे अछूता नहीं है। इंदौर में सट्टे के बड़े कारोबारी पूरे मध्यप्रदेश में क्रिकेट के सट्टे का बड़ा नेटवर्क संचालित करते है। गांवझगांव से इनके कनेक्शन है। यह कहने और लिखने में कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए की क्रिकेट से जुड़ा यह आपराधिक वर्ग राजनीति और पुलिस के गठजोड़ से फलफूल रहा है। एक और अपराधियों द्वारा संचालित आनलाइन सट्टा देश की युवा पीढ़ी को अंधेरे कुएं में धकेल रहा है। दूसरी ओर ड्रीम इलेवन सर्कल, माय इलेवन सर्कल, हाउजेट जैसे एप ने क्रिकेट के सट्टे को नया रूप दिया है। सरकार द्वारा पोषित सट्टे का यह रूप भी समाज के लिए नुकसानकारी है। समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को बर्बाद कर रहा है। युवा पीढ़ी के भड़काव का कारण बन चुका है। यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है की क्रिकेट की दुनियां से बड़े चेहरे जो समाज का मार्गदर्शन करते है। जिनकी महती जवाबदेही आदर्श समाज निर्माण की होना चाहिए। वें क्रिकेट के सरकार पोषित सट्टे के एप का प्रचार कर रहे है। एमपी के उज्जैन में पुलिस द्वारा नील गंगा थाना क्षेत्र में तिरुपति ड्रीम्स कालोनी में रहने वाले पियूष चोपड़ा के ठिकानों पर दबिश दी तो 15 करोड़ रुपए की राशि और भारी मात्रा में विदेशी करेंसी भी बरामद की गई। आई जी संतोष कुमार सिंह के अनुसार आनलाइन सट्टे की यह मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी कार्यवाही है। जूम मीटिंग एप का उपयोग कर सट्टे का कारोबार पूरे मैच के दौरान बुकीज और पंटर जूम मीटिंग एप सिमटोडो एप का उपयोग करते लाइव कम्युनिकेशन में रहते। इसी दौरान अवैध धंधा होता एक बार में 50 हजार से 25 लाख रुपए का इस पार से उस पार होता। धंधा कितना करना है, यह पियूष चोपड़ा बताता इसके बाद पंटर बुकीज को धंधा उतारते। इस तरह एक मैच में करोड़ों की हार जीत हो जाती। पुलिस ने दस्तावेज भी बड़ी मात्रा में जप्त किए है। आईपीएल 2024 के मैच के दौरान इंदौर क्राइम ब्रांच ने लसूडिया क्षेत्र के स्कीम 136 स्थित फ्लैट में छापामार कर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 22 मोबाइल, 17 चैकबुक, , 5 लैपटाप, 31 एटीएम 21 सीम कार्ड, नगदी और आनलाइन सट्टे के हिसाब का करोड़ों रुपए का लेखा जोखा जप्त किया था। आरोपी लोटस 365 वेबसाइट के जरिए ग्राहकों की आईडी बनाकर आईपीएल मैचों में सट्टा खिलवाते थे। एक नहीं देश में अनेकों प्रकरणों में तकनीकी के दुरुपयोग से सट्टा खिलाने के मामले उजागर हुए है। मोबाइल युग के पदार्पण के बाद चिट्ठी वाले सट्टे का स्थान आनलाइन सट्टे ने ले लिया है। इस सट्टे ने हजारों लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है। लाखो लोग कर्ज के दलदल में डूब चुके है। आनलाइन सट्टे के जैसा ही ड्रीम इलेवन, माय इलेवन सर्कल और हाउजैट जैसे एप है। इन साइटों के प्रचलन के बाद समाज का एक बड़ा वर्ग अपने भाग्य को आजमाने के चक्कर में मोबाइल पर ध्यान लगाए हुए है। हजारों लाखों लोग इन एपो के माध्यम से करोड़पति बनने का सपना संजोए हुए है। अब तो टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल अन्य प्रचार माध्यम भी इनके विज्ञापन करने लगे है। सरकार ने क्रिकेट के साइटों को वैधानिकता प्रदान कर दी है। क्रिकेट जेंटलमैन गेम कहा जाता है। इस खेल से टीम भावना, एक दूसरे का सम्मान करना, अंपायर के निर्णय का सम्मान करना जैसे महत्वपूर्ण गुण सीखें जा सकते है। फटाफट क्रिकेट ने इस खेल में चकाचौंध पैदा की है। क्रिकेट में सट्टे की प्रवृति को बढ़ाने के जतन किए जा रहे है। क्रिकेट का मैच अब दो टीमों या दो देशों का नहीं रहा यह करोड़ों दिमागों में दौड़ रहा है। क्रिकेट के सट्टे का नशा देश के युवाओं को अपना गुलाम बना रहा है। क्रिकेट में पनप रही सट्टे की प्रवृति भारतीय समाज के युवाओं के लिए घातक है। आनलाइन सट्टे के खिलाफ तो सख्ती होना ही चाहिए। सरकार द्वारा पोषित क्रिकेट के विभिन्न एप ड्रीम इलेवन, माय इलेवन सर्कल, हाउजैट जैसे सट्टेबाजी की प्रवृति को बढ़ाने वाले एपो को भी प्रतिबंधित करना चाहिए। सरकार का कार्य समाज में आदर्श स्थापना का होना चाहिए। क्रिकेट का सट्टा समाज को पतन की राह पर ले जा रहा है। सरकारों को इस दिशा में गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। देश को गर्त में ले जाने वाले तथाकथित एप मीडिया के विज्ञापन का प्रमुख मसाला हो जाए। तब मीडिया की समाज निर्माण में भूमिका भी प्रश्नों के घेरों में दिखाई पड़ती है।

योग की अद्भुत माया, स्वस्थ निरोगी काया

संजीव ठाकुर

(21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस)

योग स्वयं के माध्यम से स्वयं की यात्रा है। अवार्चीन भारतीय दर्शन शास्त्र की पाठशाला में एक महत्वपूर्ण एवं अद्भुत पाठशाला योग भी है' योग शब्द मूलतः संस्कृत की भाषा से उपजा शब्द है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द 'युज,से हुई है इसके दो अर्थ है पहला अर्थ जोड़ना तथा दूसरा बहुत ही वृहद व्यापक शब्द अनुशासन है। योग से उसके अभ्यास के कारण शरीर तथा मस्तिष्क में एक सामंजस्य और संबंध बन जाता है, जिससे मस्तिष्क शांत तथा अनुशासित रहता हैं। यह व्यायाम का ही एक अंग है,जिससे शरीर तथा मन नियंत्रित रह कर जीवन को परिस्थितियों के अनुकूल एवं सफल बनाता है। योग स्वस्थ जीवन जीने का एक विज्ञान है। यह एक प्रकार की यौगिक औषधि है, वह हमारे शरीर के काम करने के तरीकों को धीरे-धीरे बेहतर कर शिथिल अंगों को स्वयं हल्के हल्के ठीक कर देता है।

निरोगी काया श्रेष्ठ जीवन का वरदान होती है। यदि आप निरोगी और स्वस्थ हैं तो आप सफलतम व्यक्ति बन सकते हैं धन लिप्सा आकांक्षा लालच से योग मुक्त कर एक खुशनुमा जीवन जीने की जीजिविषा तथा जुजुस्ता पैदा करता है। योग जीवन की एक कला है जो वर्तमान परिवेश में और भौतिक जगत में अत्यंत प्रासंगिक भी है। योग हमें शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रखने का एक सशक्त माध्यम है हम सबको, आपको लगता है कि आज के आधुनिक जीवन में हमें एक बहुत अस्त व्यस्त तथा मानसिक असंतुलन वाली जीवन शैली मिली है। यह सभी अनियमित भोजन की आदतों, अभाव या अनुचित नींद या लंबे समय तक कठोर श्रम करने के कारण प्राप्त हुई है। नई पीढ़ी के बच्चे, युवा स्वस्थ जीवन शक्ति सार्वजनिक लचीलापन ऊर्जा और रोगों के लिए प्रतिरोधात्मक क्षमता की खोज में लगे हुए है,और सही सहीं माना जाए तो इन सब का जवाब योग अभ्यास में ही है।

योग के आसन प्राणायाम और ध्यान से संयमित शरीर और आत्मा के साथ संतुलित जीवन शैली को प्राप्त किया जा सकता है। और इस जीवन में हम अपने को शक्तिवान,ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। योगाभ्यास के जरिए न केवल बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है बल्कि स्वयं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी किया जा सकता है। अपने बेडौल शरीर को भी योग अभ्यास के जरिए सही आकार में लाने का यह सर्वाधिक सुरक्षित आसान और कारगर तथा लागत विहीन जरिया है। योग्य के वैसे तो कर्म योग, भक्ति योग,ज्ञान योग, राजयोग और हठयोग भी अलग-अलग विभेद हैं, पर सभी पांचों योगों के अलग-अलग तरीके तथा अलग-अलग फायदे हैं।

कर्म योग सदैव दूसरों की सेवा के लिए प्रेरित करता है। और इसका मूल्य देश सामाजिक कल्याण यह समाज सेवा ही है। भक्ति योग हमें ईश्वर की साधना कैसे की जाए, यह पाठ पढ़ाता है ।भक्ति योग मनुष्य के अंदर हृदय तथा मस्तिष्क को संतुलित कर एक सकारात्मक ऊर्जा की ओर प्रेरित करता है ।भक्ति योग एक प्रकार का मानसिक योग है जिससे मन शांत रहकर सहिष्णुता की उत्पत्ति होती है, यह अहिंसक मार्ग की ओर प्रेरित करता है। ज्ञान योग बुद्धि के विकास एकाग्रता बढ़ाने तथा समाजिक ज्ञान विज्ञान की प्रेरणा देते एवं अध्ययन मनन में मनुष्य की सहायता करता है। राजयोग सर्वाधिक प्रचलित कथा लोकप्रिय योग है। यह योग की सबसे महत्वपूर्ण विधा है इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम,प्रत्याहार धारणा और ध्यान या समाधि इसमें परम आनंद की प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति की विधाओं के बारे में विस्तृत वर्णन है।

योग का इतिहास पांच सौ साल पुराना है। पश्चिमी देशों के लोगों का परिचय योग से तब हुआ जब स्वामी विवेकानंद ने अपने शिकागो की यात्रा के समय लोगों को योग के महत्व के बारे में व्यापक रूप से बताया था। इसके बाद पूरे विश्व में योग के प्रचार प्रसार के लिए कई योग गुरु ने अनथक प्रयास कर योग को विश्वव्यापी फलक पर विराजमान किया। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी पहल कर 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में अपने भाषण में उल्लेख कर इसे प्रतिपादित किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि योग शारीरिक तथा मानसिक सामंजस्य का अद्भुत सहयोग तथा तरीका है। यह मनुष्य तथा प्रकृति के बीच का एक सामंजस्य स्थापित करने वाला अद्भुत से सेतु है। और तब 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की सहमति देकर इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की थी। इस प्रस्ताव को बहुत ही कम समय में मंजूरी प्रदान कर दी गई, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास की सबसे कम समय में दी गई मंजूरी थी।

योग के वैसे तो अनगिनत फायदे हैं। और हम यह कह सकते हैं कि योगाभ्यास ईश्वर द्वारा मानव सभ्यता को दिया गया अप्रतिम उपहार है। योग किसी चमत्कार से कम नहीं।जिन असाध्य बीमारियों का वर्तमान चिकित्सा पद्धति से इलाज नहीं हो पाता,योग उन बीमारियों को शनै शनै उपचार कर ठीक कर देता है। यह शारीरिक मानसिक शांति ऊर्जा शक्ति तो देता ही है, साथ में हमें आत्म संयम, आत्मबल तथा आत्मज्ञान से भी रूबरू कराता है। योग बहुत ही आसान व्यायाम है,यह दैनिक क्रियाओं के साथ स्वस्थ शरीर और मन की क्रिया है। नाड़ी शोधन, कपालभाति, शीतली, अनुलोम विलोम जैसी क्रियाओं से शरीर में प्राण वायु की संतुलित मात्रा बढ़ती है, एवं स्नायु तंत्र मजबूत होता है। कोरोना संक्रमण काल मे कपालभाति, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के कारगर उपायों में गिना जाता रहा है, और इसने मरीजों की बहुत मदद भी की है। योग से रोगों की तीव्रता कम हो जाती है, तथा कई रोगों से छुटकारा भी मिल जाता है।अतः आप सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं स्वस्थ रहें मस्त रहें निरोगी रहें।

नेताओं के नेतृत्व की जरूरत

जो कोई व्यक्ति सामाजिक प्रभाव के द्वारा अन्य लोगों की सहायता लेते हुए सर्वनिष्ट कार्य सिद्ध करता है वह नेता है. जटिल समस्यायों से भटका कर जो नेतृत्व करे वह नेता है. जिसमें गुणों और क्षमताओं का एक समूह होता है जो उन्हें सामान्य उद्देश्य के लिए लोगों को प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन करे वह नेता है. होंठों पर हंसी, आँखों में नमी, और दिल के अंदर जहर रखता हो और कुछ लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मौवालियों को पाल रखते हैं, जो चिताओं पर भी रोटियाँ सेंक लेते हैं वह अगुवा, नायक, सरदार नेता है. यह सभी गुण आज के नेताओं में बड़ी आसानी से देखने को मिल जायेंगे. हमारे देश में हजारों पार्टियाँ हैं. हजारों प्रकार के अलग अलग नेता हैं. हर नेता लोगों का अलग अलग ढ़ंग से नेतृत्व करता है. हर नेता को चाहने वाले समाज में सैकडो.हजारों और लाखों हैं. सबकी दुकाने लेगों के द्वारा चलाई जाती है. किसी का कम तो किसी का अधिक से अधिक. कोई थोड़ा खुश है तो थोड़ा ज्यादा खुश है. हर नुक्कड़ गली चौराहे पर लोग बैठ कर अपने अपने नेता की बड़ाई करते हुए आपको नजर आयेंगे. कही भूल से अगर आप वहाँ बैठ गये और उनकी हां में हां मिलाना शुरू किए तो बखान करने वाले के मुख से गालियां निकलनी शुरू हो जायेगी. बात तू तू मैं मैं पर पहुँच कर मार पीट तक पहुँच जाया करती है. आपस का माहौल खराब हो जाता है. आपसी प्रेम में खटास आजाता है. वहाँ पर नेता नही होता है. वहाँ पर केवल नेताओं की शान और गरिमा होती है. कोई भी आदमी अपने नेता की तोहीन होते बर्दाश्त नही कर सकता है. नेतृत्व करने वाले नेताओं का प्रभाव लोगों पर दृढ़ विश्वास लिए हृदय में बैठ जाता है और वह अपने नेता की बुराई सुनना पसंद नही करता है. चाहे कोई पक्ष का नेता हो या विपक्ष का, समाज में सबका रुतबा रहता है. हर नेता जनता का हीरो है. जैसे परदे पर काम करने वाला कलाकार हीरो कहलाता है, वैसे ही समाज का नेतृत्व करने वाला नेता जनता का हीरो कहलाता है. चुनाव खत्म होते ही जनता के बीच कम और ज्यादा वोट पाने वालों पर बहस होती रहती है. जो बंद होने का नाम नही लेती है. जहाँ दो चार आदमी बैठे या खड़े होकर बातें कर रहें हैं वहाँ पर नेताओं की बातें शुरू हो जाती है. जनता कभी अपना मुख बंद नही करती है, उनकों इन सब बातों में बड़ा आनंद आता है. मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं बेकार की बातों में लोग उलझ जाते हैं. पढ़ाई लिखाई, मंहगाई, नौकरी पेशे, रोजगार की बातें छोड़ कर लोग नेताओं की बातें करते हुए नजर आयेंगे मगर मुद्दे की बात नही करेंगें. समाज को संगठित करने के लिए नेताओं के नेतृत्व की सदा जरूरत है. समाज में नेताओं का होना बहुत ही जरूरी है. एक नेता ही समाज को संगठित कर सकता है, और समाजिक बुराइयों और कठिनाइयों से समाज को बचा सकता है. सरकार चला सकता है देश-विदेश से मैत्री पूर्ण संबंध बना सकता है. सीमाओं की रचनात्मक सुरक्षा करवा सकता है. देश को नई दिशा और आगे बढ़ा सकता है. लेकिन जनता के मुख को बंद नही करवा सकता है. चुनाव खत्म हुआ, हारने जीतने वाले पक्ष और विपक्ष के नेतागण अपने अपने काम पर लग गये हैं. मगर जनता के बीच अभी भी बहस जारी है और निरंतर जारी रहेगी. आपसी विवाद बंद नही होंगे और विवाद तो होते रहेंगे.

-विक्रम दयाल

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

सेवा भाव विलुप्त स्वार्थ भाव बलवती!

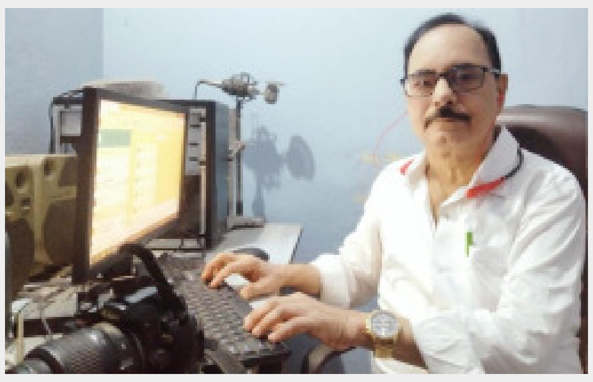

लोकतंत्र में देश और समाज की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए राजनीति को एक ऐसा माध्यम बनाया गया है, जिसमें शामिल होने वाले लोगों को राजनीतिज्ञ कहा जाता है और यह राजनीतिज्ञ कहलाने वाले लोग ही जनप्रतिनिधि के रूप में सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं। सामाजिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने और आमजन को राहत पहुंचाने का कार्य इनके जिम्मे होता है। यह सेवा कार्य कहलाता है, लेकिन इन दिनो राजनीतिज्ञों में अब सेवा भाव का विलुप्त हो चुका है और स्वार्थ भाव बलवती हो चुकी है। काम, क्रोध, लोभ, घृणा तृष्णा अहंकार, द्वेषभावना आज दरख्त की तरह फैल सा गया है, जगत में, प्रेम, अपनत्व, सद्भाव का अभाव हो गया है, संसार में और यही कारण है कि आज लोग दुख में ज्यादा पड़े रहते हैं, सुख की चाह में, पर यह सुख कहां से आएगा जब कोई किसी के काम ही नहीं आएगा। यह तो दुनिया है और इस दुनिया में जो भी आया है, वह उस परमात्मा की देन है और वह परमात्मा कोई और नहीं जिसे आप भगवान मानते हैं।वह तो हर किसी मानुष तन में विराजमान है। मानव जीवन ही एक ऐसा जीवन है, जिसमें सुख दुख का पल पल अनुभव होता है। कभी सुख से लोग खुश होते हैं, तो दुख में लोग द्रवित होते हैं। यही दुख सुख तो जीवन जीने की प्रेरणा देती है और जीवन को अनुभव वान बनाती है।इसी दुख सुख के अनुभव के सहारे लोग जीवन का बेड़ा पार लगाते हैं। लोग कहते हैं कि दुनिया जीने लायक नहीं रही सामाजिक पारिवारिक और राजनीतिक स्थितियां इस कदर दुविधाओं से भरी पड़ी है, कि लगता है कि अब यह दुनिया और यहां के लोग बस जी रहे मर मर कर, जीवन के संघर्षों के बीच, बस जीने की जो मजबूरियां है, वहीं लोगों को भगवान भरोसे जिलाए जा रही है, जीना इसी का नाम है।यहां जीने बालो को अपने दम खम पर जीना पडता है, जीने की उलझन पग पग पर डेरा डेरा डाले हुए हैं, इसके बीच हर आदमी की बस यही चाहत बनती है, कि वह इस दुनिया में सुख से जीये, पर सवाल उठता है कि लोगों का यह कहना की दुनिया जीने लायक नहीं है, तो यह तो निराशा भरी बाते हैं, इस निराशा का कारण जो कुछ धरातल पर दिखता है, वह तो यही दिखता है कि आज समाज के लोग अपने स्वार्थ में ही जीना, सबसे माकूल समझते हैं, दूसरों के काम आने वाली बातें, अब रही नहीं, दुनिया के लोग अब अपने अपने काम से मतलब रखने में ही ज्यादा सुकून महसूस करने लगे हैं, समाजिक परिवेश आज आदमी के व्यक्तिगत स्वार्थ में ही निहित दिखता है। आदमी आदमी के काम आए ऐसा कुछ है नहीं, संस्कार तो विलुपति के कागार पर ही है, विलुपति चीज ही ऐसी कि जहां यह दिखता ही नहीं कि समाज के लोग एक दूसरे के लिए कहीं खड़े नजर आते हो, हर कोई को अपने से मतलब सा रह गया है। सामाजिक परिवेश इस कदर बदल गया है, कि किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं रह गया।हर किसी को बस अपने काम से काम का मतलब भर आ गया है, पहले की बातें कुछ और हुआ करती थी, पहले सामाजिक व्यवस्था में लोग जीने में सुकून महसूस करते थे, पर अब ऐसा कुछ नहीं दिखता बस दिखता है, तो लोगों को अपना स्वार्थ और स्वार्थ भी ऐसा की अपने से ही मतलब रह गया है। कोई किसी के दुख सुख का भागी भी बस अपने स्वार्थ और मतलब से ही रखना ज्यादा बेहतर समझते चल रहे हैं। व्यक्ति जी रहा है, यहां हर किसी के लिये जीने की सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं, इस महंगाई में खाने के लाले पड़े हो तो फिर जीना कैसा आज हर तरफ हर चीज में प्रदूषण की जो पैठ कमाई के फेरे में सब में समाहित हो गई है, वह हर किसी को खराब बनाता चल रहा है, चाहे मनुष्य का जीवन हो या फिर पशुओं का सामाजिक व्यवस्था की खामियाँ या आदमी के कार्यो की दक्षता व्यवस्था, सब कुछ प्रदूषण की चपेट में आ चुकी है, लोगो की चाल से हवाएं दूषित हो गई है, लोगों का मन भी, हर तरफ से दूषित ही दिखता है। जहां तक बात की जाये राजनीतिक व्यवस्थाओं का तो, जिस पर देश में रहने वाले लोगों को जीने खाने और रहने की व्यवस्था का दायित्व डाला हुआ है, वह राजनीतिक व्यवस्था भी इस कदर स्वार्थ में डूब चुका है कि राजनीतिज्ञों को बस अपने से और अपने लोगों से ही मतलब दिखता है, दूसरे लोगों को वह देखना भी नहीं चाहता। राजनीतिक व्यवस्था स्वार्थ में तब्दील हो चुकी है, व्यवस्था ऐसी भी कि जीने खाने के लिये रोजगार नहीं, जीने वालों के लिए रोटी की व्यवस्था नहीं और घर भी नहीं, यानी स्वार्थ कि जो धार मानव मन में पनपा हैं उससे आज हर कोई इस बात के लिए चिंतित है कि उसका स्वार्थ पुरा हो। इसमें दूसरो के लिए जगह हैं कहां इस देश की अपनी व्यवस्था है, देश के लोग बस राजनीति को इस रूप में देखते हैं, कि देश चल रहा है, देश की व्यवस्थाएं जैसे भी हो, आदमी तो जी रहा है, आदमी के जीने की कोई सुकून भरी व्यवस्थाएं तो दिखते ही नहीं राजनीति में। आज लोगों की दिलचस्पी इस कदर बढी है कि हर कोई नेता बनकर ही इस दुनिया में जीना चाहता है। हर कोई बहस करता है, हर कोई चिंतन करता है और बस यही कहता है कि दुनिया जीने लायक नहीं रही दुनिया के लोग स्वार्थ से वशीभूत हैं और दुनिया के लोगों में राजनीति की जो चाहत बनी है वह सुख सुविधाओं से लैस दिखती है, राजनीतिज्ञो को सुविधाएं प्राप्त हो रही है, आम आदमी को नहीं मिलता। महंगाई बेरोजगारी समेत अनेक तरह की समस्याएं आम आदमी को घेरे हुए है, परिवार में भी परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही है, परिवार में आज कोई एक दूसरे भाई बंधु सगे संबंधियों को देखकर उनके दुखों को देखकर दुख नहीं होता, उनके सुखों को लेकर भले ही दुखित हो ले, सुख की चाहत दूसरे में देखना है नहीं, आज परिवार में बाप बेटी की जो स्थिति हो गई है, वह इस कदर संस्कार हीन दिखता है कि जिस बेटे को बाप ने इस धरा पर अवतरित किया, वह बेटा जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, तो समझने लगता है कि उसे भगवान ने इस दुनिया में लाया है और दुख सुख जो भी भगवान दे रहे हैं, मिल रहा है, वह तो बस उनकी ही देन, यानी भगवान की ही देन है, बाप लाख बेटे के दुख में दुखी हो, लेकिन बेटा आज बाप के दुख में शामिल होना नहीं चाहता, हर परिवार में हर किसी के साथ कमोवेस यही स्थिति दिखती है, पारिवारिक परिस्थितियां बद से बदतर हो चली है, सामाजिक व्यवस्थाएं भी स्वार्थ के घेरे में इस तरह फलीभूत हो रहा है कि हर आदमी अपने आप में खो सा गया है। हर बाप अपने बेटे को सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर तरह की कोशिशें मेहनत और दुआएं के लिए लगा रहता है, पर बेटा को इसकी कोई कदर नहीं होती बेटा तो बस कभी जब बाप बनेगा तभी उसके समझ में इन बातों की पैठ होगी, यह बातें उन्हें तभी समझ में आएगी, जब बेटा बाप बन जाएगा। आज की स्थिति में जीना मुहाल हो गया है, हर तरफ संघर्षों की एक लंबी फेहरिस्त चलती चली जा रही है, हर कोई बस जीने की ललक में समाये मजबूरियों में ही, बस जिए जा रहा है।राजनीतिक सामाजिक और पारिवारिक यह तीनों व्यवस्थाएं आज धूल थुसरीत हो चुकी है। यह लोग कहते हैं और लोगों को कहना भी धरातल पर ही दिखता है । हर किसी को अपने से मतलब सा रह गया है और रहे भी क्यो नहीं, क्योकि जीना तो अपने को ही हैं न सुख दुख में है जीवन सारा। इसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हर एक व्यक्ति को क्योंकि जीवन जो मिला है वह दुख सुख का एक ऐसा दरिया है।

प्रभात वर्मा

ज्ञान पीठ पुरस्कार से सम्मानित

राष्ट्रीयता और ओज के कवि रामधारी सिंह दिनकर

महान कवि दिनकर ने, अपनी काव्य रचना से जनमानस को झकझोर कर रख दिया है। राष्ट्रीयता की ओज वाणी में धरती पुत्र को जागरण का संदेश दिया है। सत्य कहा जाय तो राष्ट्रीयता का स्वर दिनकर की पहचान बन गई है। दिनकर के व्यक्तित्व का निरूपण करते हुए डा.सावित्री सिंहा ने कहा है " दिनकर के व्यक्तित्व में धरती पुत्र का आत्मविश्वास और दृढ़ता साहित्यकार की अनुभूति प्रवणता दार्शनिकता का तत्व चिन्तन तथा राजपुरूष का ओज और तेज है। " हिन्दी साहित्य में चाहे वह अपभ्रंश का काल हो, वीर गाथा काल हो, भक्ति काल हो, रीति काल हो या आधुनिक काल हो सर्वत्र किसी न किसी रूप में राष्ट्रीयता का स्वरूप मुखरित होता है।

इसमें राष्ट्रीयता के नायक दिनकर का नाम अमर है। "उस राष्ट्रकवि के अग्नि तेज को, है मेरा सादर शतशः प्रणाम। जिसकी कविता है धधक रही, लेकर अमर ज्योति ललाम।" दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। बिहार के बेगुसराय जिले के सिमरिया गांव में एक भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास, राजनीति विज्ञान में स्नातक किया। उन्होंने 1934से1947 तक बिहार सरकार में रजिस्टार के पद पर कार्य किया। "हिन्दी नभ वह उदित हुआ, क्षितिज का चमका प्राच्य छोर, जिस ओर चरण वह डाल दिया, दब गया वहीं अंबर भूगोल।" दिनकर की राष्ट्रीयता स्फूर्त नहीं है, बल्कि बाहर से आरोपित है इस संदर्भ में वे दिनकर की उक्ति को ही जिसे उन्होंने चक्रवाल की भूमिका में लिखा है " संस्कारों से मैं कला के सामाजिक पक्ष का प्रेमी अवश्य बन गया था, किंतु मेरा भी मन चाहता था कि गर्जन तर्जन से दूर रहूं, और केवल ऐसी ही कविताएं लिखूं जिनमें कोमलता और कल्पना का उभार हो, राष्ट्रीय और क्रांतिकारी होने का सुयश तो मुझे हुंकार से ही मिला किन्तु आत्मा मेरी अब भी रसबंती में बसती है। राष्ट्रीयता मेरे भीतर से नही जन्मी, उसने बाहर से आकर मुझे आक्रांत किया है ?।" सकंट के समय मनुष्य बुद्धि नहीं भावना के अधीन हो जाता है। रेणुका दिनकर जी की प्रथम कविता संग्रह है जिसका संस्करण 1935 में प्रकाशित हुआ था। इसकी पहली रचना तांडव मे ही जिस क्रांति परक भावना का उद्रेक हुआ है वह कवि के व्यक्तित्व में छिपे अंगार को रूपायित करता है। " नाचो अग्नि खंडभर स्वर में, ।फूंक फूंक ज्वाला अम्बर में अनिल कोश द्रुम दल जल थल में, अभय विश्व के ऊर अंतर में, गिरे बिभव का दर्प चूर्ण हों लगे आग इस आडंबर में। " 1950 से 1952 तक लंगट सिंह कालेज मुज्जफरपुर में हिन्दी के विभागाध्यक्ष रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति के पद पर 163 से 1965 के बीच कार्य किया। उसके बाद भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। दिनकर जी की प्रसिद्धि 1933में हिमालय के प्रति नामक कविता में कवि ने हिमालय से कहा है – " रे! रोक युद्धिष्ठर को न यहां, जाने दो उसको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडिव गदा

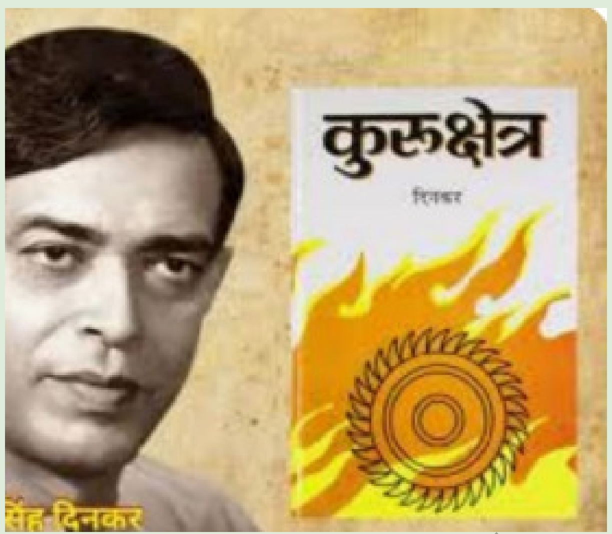

लौटा दे अर्जून, भीम वीर।" हुंकार में स्वयं अपना परिचय कवि देते हैं – " सुनूं क्या सिंधु ! मैं गर्जन तुम्हारा स्वयं युग धर्म का हुंकार हूं मैं, कठीन निर्घोष हूं भीषण अग्नि का प्रलय गांडीव की टंकार हूं मैं।" दिनकर जी को पद्म विभूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। उनकी पुस्तक_संस्कृति के चार अध्याय 'के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा, 'उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द्वापर युग की ऐतिहासिक घटना महाभारत पर आधारित उनके प्रबंध काव्य कुरूक्षेत्र को विश्व के सौ सर्व श्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया। राष्ट्र कवि दिनकर की कविता में केवल क्रांति और विस्फोट ही नहीं उसमें जीवन दर्शन का उदात्त स्वरूप भी है। जिसकी झलक कुरूक्षेत्र में विशेष रूप से देखने को मिलता है जो न्याय को चुराकर अन्याय का समर्थन करता है वास्तव में वह युद्ध के लिए वही उत्तरदाई है कुरूक्षेत्र में यह दर्शन उभरकर सामने आता है – " चुराता न्याय जो, रण को बुलाता भी वही है, युधिष्ठिर ! सत्य की अन्वेषणा पातक नहीं है ।

नरक उनके लिए पाप को स्वीकार ते हैं, न उनके हेतु जो रण में उसे ललकारते हैं।" कवि का दृष्टिकोण मानवताबादी होते हुए भी व्यक्ति केइ अंदर छिपी शक्ति को जगाने की प्रेरणा देता है जिसमें पुरुषार्थ का आह्वान है– " मुसीबत को नहीं जो झेल सकता, निराशा से नहीं जो खेल सकता, पुरूष क्या जोग श्रृंखला कोई तोड़ कर, चले आगे नहीं जो जोर करके। देश की आजादी के बाद दिनकर को जिस भारत की आशा बनी थी उनका वह उत्साह भंग होने लगा तो कवि की वाणी एक बार फिर किसी विप्लवी विस्फोट की अभिव्यक्ति बनने लगी। " वज्र की दीवार जब टूटती है, नींव की यह वेदना विकराल बनकर छूटती है, दौड़ता है दर्द की तलवार बनकर, पत्थरों की पेट से नरसिंह लेइ अवतार ।" यही नहीं बल्कि जिस गांधी ने सत्य और अहिंसा से स्वतंत्रता लाई उसी के संबंध में कवि एक विस्फोट संदेश देता है हठी तुम्हारे पापों से फिर एक प्रलय छाने वाला है, गांधी ने भूकंप किया तूफान वहीं लाने वाला है। स्वराज प्राप्ति के पूर्व दिनकर राष्ट्रीयता से बंधे नजर आते हैं लेकिन देश की आजादी के बाद उनका मानवतावादी और भारतीय संस्कृति के गुणों से ओतप्रोत दिखलाई पड़ता है जिसमें युद्ध की नहीं बल्कि शांति की गुहार है। कवि की यह यात्रा शायद और लंबी होती मगर देश पर चीनी आक्रमण के समय उत्पन्न जनता की क्रोध की ज्वाला को पीना क्रांतिकारी कवि के लिए असह्य हो उठा। उस जनाक्रोश की आग को दिनकर ने कविता में बांध कर एक बार फिर राष्ट्रीयता की गुहार का प्रबल वेग से 'परशुराम की प्रतिक्षा में हुंकार किया। भारत का जन मन जिस पराजय की पीड़ा से फुफकार उठा था और उसकी भावनाएं जिस प्रकार आहत हुई थी उसे कविता में बांधना दिनकर जैसे राष्ट्रीय कवि की ही वश की बात थी ? एक बार फिर दिनकर की कविताओं में क्रांति का स्वर प्रधान हो उठा। "गर्दन पर किसका भार तुम ढोते हो, शोणित से तुम किसका कलंक धोते हो, और इस प्रश्न का उत्तर भी ज्वालामुखी के लावे की तरह फूट पड़ता है और सीमा पर हारा हुआ सिपाही इस दास्तान को कारूणिक भाव से मगर रोष पूर्वक प्रकट करता है। " गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं, शीतल करते हैं अनल प्रबुद्ध प्रजा का, शेरों को सिखलाते धर्म अजा का। सारी बसुंधरा में गुरु पद पाने को, प्यासी धरती के लिए अमृत लाने को, जो संत लोग सीधा पाताल चले थे, अच्छे हैं अब भी, पहले भी बहुत भले थे, हम उस धर्म की लाश यहां ढोते हैं शोणित से संतों का कलंक धोते हैं। " तो इस तरह के कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर की कविताओं में राष्ट्र बंदना का स्वर है, अतित का गौरव गान है, नव निर्माण का आह्वान है, क्रांति का उद्बोधन है, प्रगति की कामना है, आदर्शों के प्रति सजगता है और युग चेतना का संख नाद है ।इस महान कवि की मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हो गया, फिर कभी भारत वर्ष में ऐसे कवि का उदय नहीं हुआ। "जिनकी कविता द्यूति दीपक से, है दीप्त राष्ट्र का हृदय प्राण, उस राष्ट्रकवि के अग्नि तेज को है मेरा सादर शतशः प्रणाम।

दस्तक प्रभात/कौशल किशोर

कृषि प्रधान देश मे किसान ....

मैं और मेरी श्रीमती जी घर के बाहर गार्डन मे अखबार के साथ चाय की चुस्कियों का आंनद ले रहे थे, क्योंकि चाय के साथ अखबार मिल जाए तो आनंद मे चार चाँद लग जाते है तभी मेने एक खबर देखी जिसमें फसल बर्बाद होने और उसका उचित मुआवजा ना मिलने के कारण किसानों के द्वारा की गयी आत्म हत्या के वारे मे लिखा था, जिसे पड़कर मेरा मन बहुत व्याकुल हो उठा ' मानो इस खबर ने तो मुझे झकझोर ही दिया और मेरे मन मे प्रश्नो का गुबार उठने लगा ' "क्यों आज भी हमारे देश मे किसानो को आत्म हत्या जैसे कदम उठाने पड रहे है? क्यों आज भी किसान दो वक्त का खाना ठीक से नहीं जुटा पाते? क्यों आज भी कृषि प्रधान देश मे किसानों को आत्म दाह करना पड रहा है ?, क्यों आज भी नयी तकनीकें किसानो की पहुँच से दूर है " मैं खुद से ही प्रश्नो के मायाजाल मे फस सा गया था तभी मुझे आवाज आती है – "गुड मार्निंग भाई साहब " मेने भी बिना देखे औपचारिकता पूर्ण – "गुड मार्निंग" पर आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी ' मेने पीछे घूमकर

देखा ' "तो शीतल थी "शीतल जो कि मेरी बहन है, गाँव मे माँ के साथ रहती है और खेती मे माँ का हाथ बॅटाती है आओ शीतल, बैठो, सही समय पर आयी हो, अरे भाग्यवान! सुनती हो "शीतल के लिए चाय लेके आना " इसके साथ ही श्रीमती जी चाय बनाने चली जाती है मैं – कैसे आना हुआ, आज ? शीतल– कुछ नहीं भाई साहब, खेत मे फसल कट गयी और कुछ भी नहीं था खेतों मे। तो सोचा आपसे ही मिल लू। मैं – ये तो तुमने बहुत अच्छा किया ', माँ केसी है ? शीतल– माँ अच्छी है, बस आपको ही याद करती है मैं– इस बार छुट्टियों मे माँ से मिलने आउगा' और बताओ, इस बार फसल केसी हुयी ? शीतल– ज्यादा कुछ खास नहीं, हाँ, पर काम चल जाता है मैं– क्यों शीतल क्या हुआ? उधर किसान आत्म हत्या जेसे कदम उठा रहे है और इधर तुम भी एसा ही बोल रहीं हों ' शीतल– हाँ भाई साहब, मँहगाई के हिसाब से मुनाफा ही कहा होता है फसल से मैं– क्यों? शीतल– एक खेतों मे काम बहुत होता है, जिसके लिए मुझे और माँ को जल्दी 4 बजे उठना पड़ता है, फिर माँ खाना बनाती है और. मैं घर की साफ सफाई करते है 7 बजे के लगभग मैं और माँ खेत की और निकल पड़ते है, जहा पर हमे काम करना होता है.......दो मिनट बैठने तक का भी समय नहीं होता ' फिर भी जेसे तेसे समय निकाल कर खाना खाते है, और फिर से करने लग जाते है ' सूरज ढलने के बाद हम भी घर की और चल पड़ते है। घर पर आने के बाद भी चेन की साँस कहा मिलती है, मैं– वाह! शीतल तुम कितना काम करते हो? शीतल– काम का सिलसिला अभी कहा खत्म होता है, भाई साहब! यही पूरे साल भर चलता है, फिर आता है फसल कटाई का समय.... भाई साहब! इतनी

सब मेहनत भी हो जाती है, क्योंकि आशा होती है ना एक अच्छी फसल और मुनाफे की ' यही आशा निराशा मे, तब बदल जाती है, जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए. और उसमे भी किसान को उचित मुआवजा ना मिले .....तो फसल बर्बाद होने और उचित मुआवजा ना मिलने के कारण किसान टूट सा जाता है। या फिर उस किसान की फसल का उचित मुनाफा ना मिले, क्योंकि छोटे व्यापारी किसान की फसल को कोड़ियों के दाम खरीद कर अच्छे दाम मे आगे अनाज मंडियों मे बेचते है, इससे वो खुद तो अच्छा पेसा बना लेते है पर किसान के हाथ कुछ नहीं लगा पाता। हम लोग यह क्यों नहीं सोचते कि किसान का भी परिवार है, उसको भी अपना परिवार का पालन पोषण करना होता है हम लोग अपने चंद पैसो के लाभ मे इतना अंधे कब हो गए, हमे खुद को भी पता नहीं किसानो की समस्या को आपको बताने का, एक तुच्छ सा प्रयास किया है ' आशा करता हू आपको अच्छा लगा होगा । अभी के लिए इतना ही, मिलते है फिर से, एक नयी कहानी के साथ

दस्तक प्रभात/विशाल शर्मा

जयंती पर विशेष

तिलस्मी साहित्य के जनक बाबू देवकी नन्दन खत्री

तिलस्मी साहित्य के जनक बाबू देवकी नन्दन खत्री जी का जन्म आषाढ़ कृष्ण सप्तमी संवत 1918, तदनुसार 18 जून सन 1861 ई. को पूसा, मुजफ्फरपुर (बिहार) में 'धवन पंजाबी खत्री' परिवार में हुआ था। इनके पूर्वज पंजाब के निवासी थे। जब वहां अराजकता फैली तब इनके पिता लाला.ईश्वरदास लाहौर छोड़कर काशी में जा बसे थे। इनकी माता पूसा के रईस जीवन लाल महथा की सुपुत्री थी। खत्री जी का बचपन ननिहाल में ही व्यतीत हुआ। ये बचपन से ही मस्त, सैर के शौकीन, पतंग उड़ाने के शौकीन, मजाकिया व तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति थे। इनकी शिक्षा हिन्दी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में हुई थी। गया जिले के टेकारी स्थल से बाबू देवकी नन्दन जी के पिता ईश्वर दास जी का व्यवसायिक संबंध था। अतः उन्होंने गया में ही कारोबार प्रारम्भ किया। वहां एक कोठी भी बनवायी थी। जब टिकारी अव्यवस्था के कारण सरकारी प्रबंध में चला गया तो पिता ईश्वर दास जी काशी चले गये। टिकारी में काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह की बहन का ब्याह हुआ था इसलिए बनारस में भी इनके पिता की अच्छी पैठ हो गयी। इन्हें राज सम्पर्क की सहज सुविधा का लाभ मिला और चकिया तथा नौगढ़ के जंगलों में घूमने के क्रम में एक घटना विशेष ने इनके जीवन की दिशा बदल दी और इनको 'चन्द्रकान्ता' लिखने के लिए प्रेरित किया। थोड़े समय में ही इन्होंने चन्द्रकान्ता का पहला भाग पूरा कर लिया जो हरि प्रकाश प्रेस से सन 1888 ई. में प्रकाशित हुआ। चन्द्रकान्ता की अभूतपूर्व और आश्चर्यजनक लोकप्रियता को देखते हुए जल्द ही खत्री जी ने इसके तीन भाग 1888-1889 और लिखे। इसको पढ़ने के लिए बहुतों ने हिन्दी सीखी थी। 'चन्द्रकान्ता' साहित्य की संक्षिप्त कथा इस प्रकार है नौगढ़ के राजा सुरेन्द्र सिंह के पुत्र राजकुमार वीरेन्द्र सिंह और विजयगढ़ के राजा जयसिंह की पुत्री राजकुमारी चन्द्रकान्ता में प्रेम हो गया। विजयगढ़ के दीवान का बेटा क्रूर सिंह खुद चन्द्रकान्ता को प्राप्त करना चाहता था। वह भी प्रेम नहीं हिंसा और क्रूरता से। क्रूर सिंह के ही बहकावे में आकर चुनार का राजा शिवदत्त भी वीरेन्द्र सिंह के विरूद्ध षड्यन्त्र करने लगा और अन्त में वीरेन्द्र सिंह की विजय होती है। सारे विरोधी और षड्यन्त्रकारी मारे जाते हैं, कुछ गिरफ्तार कर लिये जाते हैं। अन्त में चन्द्रकान्ता की शादी वीरेन्द्र सिंह से हो जाती है। वीरेन्द्र सिंह और क्रूर सिंह दोनों के साथ ऐयार है, जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चन्द्रकान्ता के साथ भी कई ऐयारा है। कहानी में ऐयार-ऐयाराओं के द्वारा विरोध का जाल

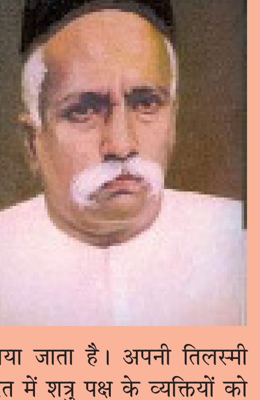

फैलाया जाता है। अपनी तिलस्मी ईमारत में शत्रु पक्ष के व्यक्तियों को फंसाया जाता है। दूसरे पक्ष द्वारा अपने व्यक्तियों को तिलस्म से छुड़ाने के लिए ऐयार-ऐयारा अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। इस प्रकार पूरे उपन्यास में ऐयारों के हौसले भरे हैरत अंगेज कारनामे है। ऐसी तिलस्मी और रोचक कथा है कि पढ़ने वाले इसमें पूरी तरह रम जाते हैं। 'चन्द्रकान्ता' के प्रकाशन से देवकी बाबू को सदैव प्रोत्साहन और स्नेह मिलता गया। इसके बाद (1894 - 1905) चन्द्रकान्ता सन्तति (रानी चन्द्रकान्ता और राजा वीरेन्द्र सिंह की सन्तानों की कहानी) को चौबीस भागों में पूर्ण किया। इसके अलावा सन 1893 ई. में 'नरेन्द्र मोहनी' मुजफ्फरपुर से एवं काशी नगरी प्रचारिणी सभा से सन 1896 ई. में 'वीरेन्द्र वीर' अर्थात 'कटोरा भरा खून' नामक उपन्यास प्रकाशित हुए। इनके उपन्यासों के कई संस्करण प्रकाशित हुए। सन 1898 ई. के सितम्बर माह में इन्होंने अपना लहरी प्रेस खोला। लहरी प्रेस से इनके 'कुसुम कुमारी' सन 1899 ई. में 'काजर की कोठरी' सन 1902 ई. में तथा 'गुप्त गोदान' प्रथम भाग सन 1906 तथा 'लैला मजनू' सभी कृतियां प्रकाशित हुई। गुप्त गोदान, लैला मजनू और मृत्यु किरण वर्षो से अप्राप्य है। इनके नौलखा हार तथा अनूठी बेगम नामक दो उपन्यास क्रमशः कचौड़ी गली वाराणसी तथा फ्रेण्डस एण्ड कम्पनी मथुरा में छपे। पिछले उपन्यास के एक मुख्य ऐयार पात्र भूतनाथ को आधार बनाकर इन्होंने 'भूतनाथ' (1906 - 1912) उपन्यास शुरू की थी जिसे कई भागों में लिखना था, किन्तु 01 अगस्त 1913 ई. को अपनी असामयिक मृत्यु से उसके सिर्फ छः भाग ही लिख सके थे। शेष पन्द्रह भाग इनके सुपुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री (धवन) ने पूरे किये। इसका प्रकाशन भी लहरी प्रेस से हुआ था। इन्होंने 'उपन्यास लहरी' नामक मासिक पत्रिका निकाली थी। जिसमें चन्द्रकान्ता सन्तति तथा भूतनी धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुए थे। माधव प्रसाद मिश्र के सम्पादन में निकलने वाली साहित्यिक पत्रिका 'सुदर्शन' भी इन्हीं की देख-रेख में इनके द्वारा ही प्रकाशित होता था जो दो वर्ष तक ही चल सका।एक ओर खत्री जी के उपन्यास का अभूतपूर्व स्वागत तो दूसरी ओर श्री वेंकटेश्वर समाचार (बम्बई) समालोचक (जयपुर) बिहार बन्धु (पटना) एवं सरस्वती पत्रिका ने तीखें स्वर में इनका गहरा विरोध किया। इन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों ने वस्तुतः इनके मार्ग का विकास किया। ब्रिटिश सरकार की भाषा नीति, आर्थिक व सांस्कृतिक शोषण ने भी हिन्दी में प्रकाशित इस नव विकसित विद्या (उपन्यास) को गहरा प्रभावित किया । खत्री जी के चन्द्रकान्ता लिखने का उद्देश्य केवल अपना और पाठक वर्ग का मनोरंजन करना था। उनके उपन्यास में उनकी अपनी सोच और परिस्थितियों ने काम किया है। वहीं यह भी कहा जाता है कि तिलस्मी ऐयारी उपन्यास के जिस रूप की परिकल्पना इन्होंने की उसकी प्रेरणा इन्हें फौजी के 'तिलस्म-इ-होशरूबा' नामक उर्दू रचना को पढ़कर मिली थी और उसमें इन्होंने 'बोस्तन-इ-ख्याल' तथा 'दास्तान-इ-अमीर हम्जा' जैसी रचनाओं का अनुकरण किया था। उर्दू के उपन्यास जहां वासना परक थे वहीं खत्री जी ने अपनी सभी कृतियों को उससे दूर रखा। खत्री जी की कल्पना शक्ति उर्वर थी। दुर्गा उपासक होने से इन्हें सदैव शारीरिक एवं मानसिक बल मिलता रहा। तिलस्मी एवं ऐयारी के उपन्यासों का प्रचलन करने का इन्हें श्रेय तो मिला ही साथ ही यह जन साधारण को हिन्दी के प्रति उन्मुख करने में भी काफी सफल हुई। इनकी रचनाओं में जो रहस्य और रोमांच है वह आलौकिक चमत्कार न होकर सिर्फ मानवीय बुद्धि और कौशल का परिणाम है, जो मनुष्य को भटकाव के पथ से रोकता है। आज जरूरत है इनके साहित्य को ज्यादा से ज्यादा प्रकाश में लाकर उसके मूल्यांकन और पठन-पाठन की। मेरा सौभाग्य है मैं देवकी बाबू के करीब का हूँ। आज इनके वंशज वाराणसी के महमुर गंज एवं पटना में रह रहे हैं।

दस्तक प्रभात/प्रभात कुमार धवन

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जल संकट से परेशान दिल्ली

भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के लोगों को पानी की कटौती का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा पानी देने में कोताही कर रहा है। हालत यह है कि दिल्ली जल संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गया है। हालांकि शीर्ष अदालत का यह कहना बिल्कुल सही है कि उसके पास पानी के बंटवारे का फॉम्युर्ला तय करने की विशेषज्ञता नहीं। वैसे भी अभी यह समय फॉम्युर्ला निकालने का नहीं है। अभी दिल्ली को पानी चाहिए, जल्द से जल्द। पानी को लेकर हिमाचल, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली के बीच 1994 में एक एमओयू साइन हुआ था। हालांकि इस बात को तीन दशक बीत चुके हैं और इस दौरान दिल्ली की आबादी, उसकी जरूरतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इसलिए पुराने समझौते में बदले हुए हालात के मुताबिक बदलाव करना बेहतर होगा। पानी की समस्या केवल दिल्ली की नहीं, देश के लगभग सभी बड़े शहर इससे जूझ रहे हैं। कुछ अरसा पहले बेंगलुरु से ऐसी खबरें आ रही थीं। मुंबई में भी इस साल बीएमसी को पानी में कटौती करनी पड़ी। यह साफ इशारा है कि हमारा जल प्रबंधन ठीक नहीं। अभी तक जो भी इंतजाम किए हैं हमने, वे कारगर नहीं हो पा रहे हैं। वक्त है कि उनकी फिर से समीक्षा की जाए। हमारे शहर जिस संकट का सामना कर रहे हैं, वह केवल इस साल की कहानी नहीं है। जलवायु परिवर्तन का असर गहराने के साथ यह संकट भी बढ़ता जाएगा। इससे बचने के लिए प्रभावी और दूरगामी कदम उठाने होंगे। हमारी नदियों में पानी की गुणवत्ता और खराब होती जा रही है। तमाम नदियों का पानी तो अब जानवरों के पीने लायक भी नहीं बचा है। यही हाल तालाब, कुओं और दूसरे जलाशयों का भी है। कई जगह अतिक्रमण हो चुका है। इस पर सख्त एक्शन लेना होगा। दिल्ली में जब संकट गहराया है तो टैंकर माफिया की बात चल निकली है। लेकिन, सोचने वाली बात है कि ये माफिया एकाएक तो इतने मजबूत हुए नहीं होंगे। इन पर पहले एक्शन क्यों नहीं हुआ? और इन्हें किनकी शह मिल रही है? इसी तरह वॉटर रीसाइक्लिंग और ग्राउंड वॉटर रिचार्ज पर कितना काम हो रहा, इसे भी चेक किया जाना चाहिए। पानी जैसी बुनियादी जरूरत की किल्लत सबसे ज्यादा मार करती है गरीबों पर। अमीर तबका पानी खरीदकर अपनी प्यास बुझा सकता है, लेकिन टैंकर के पीछे दौड़ने और सार्वजनिक नलों पर धूप में लंबी लाइन लगाने वाली आम जनता कहां जाए? किसी भी पॉलिसी में इनका ध्यान रखना चाहिए। यह मसला अब राजनीति का नहीं रह गया है। जो स्थिति है उससे यह स्पष्ट है कि आनेवाले समय में जल संकट वाले क्षेत्रों का दायरा बढ़ेगा, और हाहाकार मचेगा। इसके लिए तू -तू, मैं -मैं के फेरे में पड़े बिना इस समस्या का स्थायी हल ढूंढने की जरूरत है। जल के नए स्रोत विकसित करने होंगे। पानी की बर्बादी रोकनी होगी। तभी इस संकट से छुटकारा पाया जा सकता है।

पत्थर में भगवान और पत्थर दिल इंसान!

महेश खरे

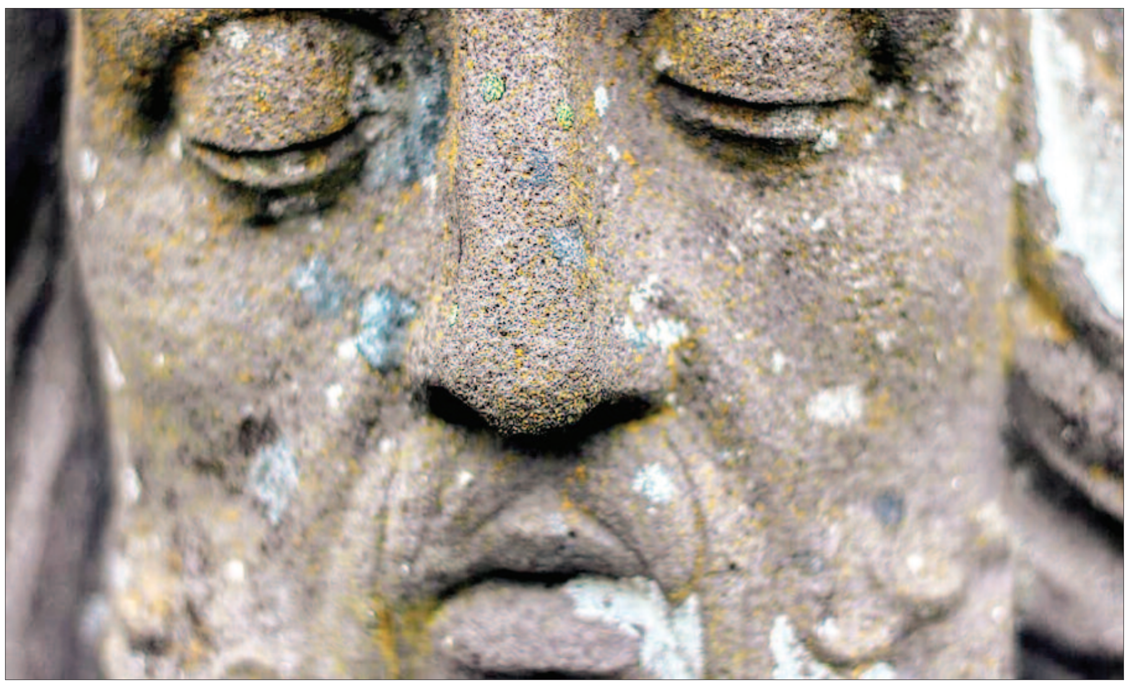

विकास में प्रवाह होता है और प्रवाह से परिवेश बदलता है.. इंसान भी बदलता है और इंसानियत के मायने भी...शहर भी, गांव भी...आचार भी, व्यवहार भी। बदलेंगे नहीं तो जहां थे वहीं बने रहेंगे। जीवन है तो हलचल है। वरना तो सब नश्वर है। विकास अनिवार्य प्रक्रिया है। सतत है। तभी तो गांव बदल रहे हैं। शहर बदल रहे हैं। रेल पटरियां बिछेंगी तो बस्तियों को रास्ता देना ही होगा। मतलब कुछ नया बसाया जाता है तो कुछ उजड़ता जरूर है। विकास के साथ सभी को चलना है। हमें भी और आपको भी। अमीर को भी और गरीब को भी।

अयोध्या में भगवान राम 500 साल की प्रतीक्षा के बाद बिराज पाए। भगवान अमीर और गरीब में भेद नहीं करते। यह इंसान के ही स्वभाव में है। पर संयोग यह रहा कि अयोध्या के सौंदर्यीकरण में उजड़ने वाले ज्यादातर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार थे। सौंदर्यीकरण के लिए ऐसा क्यों होता है? धर्म और आस्था की नगरी अयोध्या में ऐसा हुआ। मुआवजा भी दिया गया। यह भी सच है पीड़ित मुआवजे से कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। हमने स्वयं स्थल मुआयना तो नहीं किया... जो मीडिया में छप रहा है... अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं...उसने आक्रोश उपजाया। इसका असर लोकसभा चुनाव में भी दिखा। चुनाव में वोटर ने अपना गुस्सा उतारा तो महंगाई ने चुनाव में हुए भारी-भरकम खर्च की बढ़-चढ़कर गवाही दी। मई के आंकड़े आ गए। जून, जुलाई के भी आएंगे। अर्थशास्त्री बताते हैं कि अभी तो यह झांकी है...असली तस्वीर बाकी है। यानी आने वाले महीनों में महंगाई और अधिक गर्मी दिखाएगी... होई है सोई जो राम रचि राखा...को करि तर्क बढ़ावहिं शाखा। लोकतंत्र में चुनाव अपरिहार्य हैं और उसका बोझ जनता पर पड़ना स्वाभाविक है... लोकतंत्र की असली खूबसूरती शायद यही है।

सोशल मीडिया में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक वीडियो खूब देखा जा रहा है। वे बता रहे हैं कि हाईवे के लिए उन्होंने कैसे दिल पर पत्थर रखकर अपने श्वसुर का मकान तुड़वा दिया था। मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने यह भी बताया कि अपना घर भी सौंदर्यीकरण के आड़े आ रहा था...तो वह भी टूटने दिया। सबके लिए...समाज के लिए स्व को कुर्बान होना ही पड़ता है। ध्यान केवल इतना रखना चाहिए कि उजड़ने वाले कहीं बसा भी दिए जाएं। जो बस नहीं पाएं उन्हें पर्याप्त ही नहीं मूल्य से अधिक मुआवजा मिल जाए। विरासत ढ़हने...उजड़ने के दर्द की क्या कीमत लगाई जा सकती है? लेकिन, जितना संभव हो उतना अधिक से अधिक मिलना ही चाहिए। दुर्भाग्यवश कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता...अथवा दिया जाता है तो उम्मीद से बहुत कम। नतीजतन रोष उपजता है...विवश आंखें नम हो जाती हैं। सक्षम तो अपने धन बल से बच या सह जाता है। पर, अक्षम क्या करें? भेद हो या भाव साफ साफ दिखाई देता है।

अयोध्या में भगवान राम 500 साल की प्रतीक्षा के बाद बिराज पाए। भगवान अमीर और गरीब में भेद नहीं करते। यह इंसान के ही स्वभाव में है। पर संयोग यह रहा कि अयोध्या के सौंदर्यीकरण में उजड़ने वाले ज्यादातर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार थे। सौंदर्यीकरण के लिए ऐसा क्यों होता है? धर्म और आस्था की नगरी अयोध्या में ऐसा हुआ। मुआवजा भी दिया गया। यह भी सच है पीड़ित मुआवजे से कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। हमने स्वयं स्थल मुआयना तो नहीं किया... जो मीडिया में छप रहा है... अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं...उसने आक्रोश उपजाया। इसका असर लोकसभा चुनाव में भी दिखा। चुनाव में वोटर ने अपना गुस्सा उतारा तो महंगाई ने चुनाव में हुए भारी-भरकम खर्च की बढ़-चढ़कर गवाही दी। मई के आंकड़े आ गए। जून, जुलाई के भी आएंगे। अर्थशास्त्री बताते हैं कि अभी तो यह झांकी है...असली तस्वीर बाकी है। यानी आने वाले महीनों में महंगाई और अधिक गर्मी दिखाएगी... होई है सोई जो राम रचि राखा...को करि तर्क बढ़ावहिं शाखा। लोकतंत्र में चुनाव अपरिहार्य हैं और उसका बोझ जनता पर पड़ना स्वाभाविक है... लोकतंत्र की असली खूबसूरती शायद यही है।

पत्थरों से इंसान का बड़ा लगाव रहा है। परंपरा का निर्वाह फिल्मों ने भी किया... खूब निभाया। पत्थर के सनम की थीम पर फिल्में भी बनीं और गीत भी रचे गए। कहते हैं दीवारों की नींव में भी पत्थर मजबूती की गारंटी होते हैं। बिहार के दशरथ माँझी पत्नी प्रेम में पहाड़ काट कर 'माउंटेन मैन' कहलाए। दशरथ ना पहाड़ काटते और ना उनका यह नामकरण होता। सच ही कहा है इंसान ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। पत्थर, प्रेम और चोट का गहरा नाता है। दिल चोट खाकर पथरा जाए तो चट्टान से भी मजबूत हो जाता है। दशरथ की पत्नी फाल्गुनी के इलाज में पहाड़ बाधक बना और वह असमय चल बसी।

पत्नी की मौत का बदला उन्होंने पहाड़ से लिया। बिहार में गया के करीब गहलौर गांव के इस गरीब लेकिन जुनूनी मजदूर ने केवल एक हथौड़ा और छेनी लेकर अकेले ही 360 फुट लंबे 30 फुट चौड़े और 25 फुट ऊँचे पहाड़ को काट कर एक सड़क बना डाली। लोग दशरथ को पागल कहते रहे लेकिन वे छैनी से पहाड़ का सीना चीरते रहे। कहते हैं 22 साल लगे लेकिन दशरथ रास्ता बनाकर ही माने और माउंटेन मैन के नाम से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। कवि और शायरों की कल्पनाओं में भी पत्थरों का अपना खास महत्व है। दुष्यंत कुमार अपनी गजल के नामचीन शेर में पत्थर का महत्व बता गए। 'कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता...एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो।'

चलते-चलते बताते चलें कि संसद भवन में स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां शिफ्ट करने के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच 'संग्राम' चल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने जानबूझकर मूर्तियों को किनारे पर शिफ्ट कर दिया है। ताकि, विपक्षी सांसद समय-समय पर मूर्तियों के सामने एकजुट होकर विरोध-प्रदर्शन ना कर सकें। जैसी भूमिका वैसी सुविधा की दरकार होती है। हालांकि, इस पर पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कहना है कि मूर्तियों को हटाया नहीं गया। संविधान भवन के सामने 'प्रेरणा स्थल' पर शिफ्ट किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही जगह पर सभी प्रतिमाएं होने से लोगों को देश की महान शख्सियतों के बारे में जानने में आसानी होगी। लोग अपने ऐतिहासिक नायकों की गाथाओं से एक ही स्थान पर अवगत हो सकेंगे। पहले अलग अलग होने के कारण सभी प्रतिमाओं को विजिटर्स देख भी नहीं पाते थे।

समर्थकों की भीड़ के बावजूद तन्हा हैं राहुल गांधी

फिरदौस खान

राहुल गांधी छल और फरेब की राजनीति नहीं करते। वे कहते हैं- 'मैं गांधीजी की सोच से राजनीति करता हूं। अगर कोई मुझसे कहे कि आप झूठ बोल कर राजनीति करो, तो मैं यह नहीं कर सकता। मेरे अंदर ये है ही नहीं। इससे मुझे नुकसान भी होता है। मैं झूठे वादे नहीं करता। सत्ता और सच्चाई में फर्क होता है। जरूरी नहीं है, जिसके पास सत्ता है उसके पास सच्चाई है। जब भी मैं किसी देशवासी से मिलता हूं। मुझे सिर्फ.उसकी भारतीयता दिखाई देती है।

राहुल गांधी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वे देश और राज्यों में सबसे लम्बे अरसे तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। हाल के लोकसभा चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश के रायबरेली और केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से लाखों मतों से जीत हासिल कर इतिहास रचा है। उन्होंने अपने पुराने लोकसभा क्षेत्र वायनाड छोड़कर रायबरेली से सांसद रहने का फैसला किया है। बहरहाल, उनकी जिन्दगी कोई आसान नहीं है। इसमें जितने फूल हैं, उससे कहीं ज्यादा खार हैं जिनकी चुभन उन्हें हमेशा महसूस होती रहती है।

राहुल गांधी एक ऐसे खानदान के वारिस हैं, जिसने देश के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दीं। उनके भारत ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में लाखों-करोड़ों चाहने वाले हैं, लेकिन इस सबके बावजूद वे अकेले खड़े नजर आते हैं। उनके चारों तरफ एक ऐसा अनदेखा दायरा है, जिससे वे चाहकर भी बाहर नहीं आ पाते। एक ऐसी दीवार है, जिसे वे तोड़ नहीं पा रहे हैं। वे अपने आसपास बने खोल में घुटन तो महसूस करते हैं, लेकिन उससे निकलने की कोई राह, कोई तरकीब उन्हें नजर नहीं आती।

बचपन से ही उन्हें ऐसा माहौल मिला, जहां अपने-पराये और दोस्त-दुश्मन की पहचान करना बड़ा मुश्किल हो गया था। उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके पिता राजीव गांधी का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इन हादसों ने उन्हें वह दर्द दिया, जिसकी जरा-सी भी याद उनकी आंखें भिगो देती है। उन्होंने कहा था उनकी दादी को उन सुरक्षा गार्डों ने मारा, जिनके साथ वे बैडमिंटन खेला करते थे। वैसे राहुल गांधी के दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं है। कभी उन्हें जान से मार देने की धमकियां मिलती हैं, तो कभी उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके जाते है। अप्रैल 2018 में उनका जहाज क्रैश होते-होते बचा। कर्नाटक के हुबली में उड़ान के दौरान 41 हजार फुट की ऊंचाई पर जहाज में तकनीकी खराबी आ गई और वह आठ हजार फुट तक नीचे आ गया। उस वक़्त उन्हें लगा कि जहाज गिर जाएगा और उनकी जान नहीं बचेगी। लेकिन न जाने किनकी दुआएं ढाल बनकर खड़ी हो गईं और हादसा टल गया। कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया था।

किसी अनहोनी की आशंका की वजह से ही राहुल गांधी हमेशा सुरक्षाकर्मियों से घिरे रहे हैं, इसलिए उन्हें वह जिन्दगी नहीं मिल पाई, जिसे कोई आम इंसान जीता है। बचपन में भी उन्हें गार्डन के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने की इजाजत नहीं थी। खेलते वक़्त भी सुरक्षाकर्मी किसी साये की तरह उनके साथ ही रहा करते थे। वे अपनी जिन्दगी जीना चाहते थे, एक आम इंसान की जिन्दगी। राहुल गांधी ने एक बार कहा था- अमेरिका में पढ़ाई के बाद मैंने जोखिम उठाया और अपने सुरक्षा गार्डों से निजात पा ली, ताकि इंग्लैंड में आम ज़िन्दगी जी सकूं। लेकिन ऐसा ज्यादा वक़्त तक नहीं हो पाया और वे फिर से सुरक्षाकर्मियों के घेरे में कैद होकर रह गए।

हर वक़्त कड़ी सुरक्षा में रहना, किसी भी इंसान को असहज कर देगा, लेकिन उन्होंने इसी माहौल में जीने की आदत डाल ली। खौफ के साये में रहने के बावजूद उनका दिल मुहब्बत से सराबोर है। वे एक ऐसे शख़्स हैं, जो अपने दुश्मनों के लिए भी दिल में नफरत नहीं रखते। वे कहते हैं- ह्लमेरे पिता ने मुझे सिखाया कि नफरत पालने वालों के लिए यह जेल होती है। मैं उनका आभार जताता हूं कि उन्होंने मुझे सभी को प्यार और सम्मान करना सिखाया। अपने पिता की सीख को उन्होंने अपनी जिन्दगी में ढाला, इसीलिए उन्होंने अपने पिता के कातिलों तक को माफ कर दिया। उनका कहना है- वजह जो भी हो, मुझे किसी भी तरह की हिंसा पसंद नहीं है। मुझे पता है कि दूसरी तरफ होने का मतलब क्या होता है, ऐसे में जब मैं हिंसा देखता हूं चाहे वो किसी के भी साथ हो रही हो, मुझे पता होता है कि इसके पीछे एक इंसान, उसका परिवार और रोते हुए बच्चे हैं। मैं ये समझने के लिए काफी दर्द से होकर गुजरा हूं। मुझे सच में किसी से नफरत करना बेहद मुश्किल लगता है।

उन्होंने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (लिट्टे) के प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरण का जिक्र करते हुए कहा था- मुझे याद है जब मैंने टीवी पर प्रभाकरण के मुर्दा जिस्म को जमीन पर पड़ा देखा। ये देखकर मेरे मन में दो जज्बे पैदा हुए। पहला ये कि ये लोग इनकी लाश का इस तरह अपमान क्यों कर रहे हैं और दूसरा मुझे प्रभाकरण और उनके परिवार के लिए बुरा महसूस हुआ। राहुल गांधी एक ऐसी शख़्सियत के मालिक हैं, जिनसे कोई भी मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकता। देश के प्रभावशाली राज घराने से होने के बावजूद उनमें जर्रा भर भी गुरूर नहीं है। उनकी भाषा में मिठास और अपनापन है, जो सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। वे विनम्र इतने हैं कि अपने विरोधियों के साथ भी सम्मान से पेश आते हैं, भले ही उनके विरोधी उनके लिए कितनी ही तल्ख भाषा का इस्तेमाल क्यों न करते रहें. किसी भी हाल में वे अपनी तहजीब से पीछे नहीं हटते।

उनके कट्टर विरोधी भी कहते हैं कि राहुल गांधी का विरोध करना उनकी पार्टी की नीति का एक अहम हिस्सा है, लेकिन जाती तौर पर वे राहुल गांधी को बहुत पसंद करते हैं। वे खुशमिजाज, ईमानदार, मेहनती, क्षमाशील और सकारात्मक सोच वाले हैं। बुजुर्ग उन्हें स्नेह करते हैं, उनके सर पर शफकत का हाथ रखते हैं, उन्हें दुआएं देते हैं। वे युवाओं के चहेते हैं। राहुल गांधी अपने विरोधियों का नाम भी सम्मान के साथ लेते हैं, उनके नाम के साथ जी लगाते हैं। सच है कि संस्कार विरासत में मिलते हैं, संस्कार घर से मिला करते हैं। अपने से बड़ों के लिए उनके दिल में सम्मान है, तो बच्चों के लिए प्यार-दुलार है। वे इंसानियत को सर्वोपरि मानते हैं। अपने पिता की ही तरह अपने कट्टर विरोधियों की मदद करने में भी पीछे नहीं रहते।

राहुल गांधी छल और फरेब की राजनीति नहीं करते। वे कहते हैं- 'मैं गांधीजी की सोच से राजनीति करता हूं। अगर कोई मुझसे कहे कि आप झूठ बोल कर राजनीति करो, तो मैं यह नहीं कर सकता। मेरे अंदर ये है ही नहीं। इससे मुझे नुकसान भी होता है। मैं झूठे वादे नहीं करता। सत्ता और सच्चाई में फर्क होता है। जरूरी नहीं है, जिसके पास सत्ता है उसके पास सच्चाई है। जब भी मैं किसी देशवासी से मिलता हूं। मुझे सिर्फ.उसकी भारतीयता दिखाई देती है। मेरे लिए उसकी यही पहचान है। अपने देशवासियों के बीच न मुझे धर्म, ना वर्ग, ना कोई और अंतर दिखता है। कहते हैं कि सच के रास्ते में मुश्किलें ज्यादा आती हैं और राहुल गांधी को भी बेहिसाब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बचपन से ही उनके विरोधियों ने उनके खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी थीं। उन पर लगातार जाती हमले किए जाते हैं। इस बात को राहुल गांधी भी बखूबी समझते हैं, तभी तो एक बार विदेश जाने से पहले उन्होंने एक्स पर अपने विरोधियों को सम्बोधित करते हुए लिखा था- कुछ दिन के लिए देश से बाहर रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सोशल मीडिया ट्रोल आर्मी के दोस्तों, ज्यादा परेशान मत होना. मैं जल्द ही वापस लौटूंगा।

राहुल गांधी पर हर तरफ से हमले होते ही रहते हैं। उनके खिलाफ देशभर में इतने मामले दर्ज हैं कि वे आए दिन किसी न किसी अदालत में पेश होते रहते हैं। मोदी सरनेम वाले मामले में सूरत की अदालत से दो साल की सजा मिलने के बाद 23 मार्च 2023 से उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इस पर उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। अदालत ने 4 अगस्त को उन्हें दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद 7 अगस्त को लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी।

राहुल गांधी एक नेता हैं, जो पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी को हुकूमत में लाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वह कामयाबी नहीं मिल पा रही है, जो उन्हें मिलनी चाहिए या ये कहें कि जिसके वे हकदार हैं। शायद वे सियासत के लिए बने ही नहीं हैं। उन्हें तो सियासत में धकेला गया है।

बहरहाल वे तमाम अफवाहों और अपने खिलाफ रची जाने वाली तमाम साजिशों से अकेले ही जूझ रहे है और मुस्कराकर उनका सामना कर रहे हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नालन्दा फिर जीवन्त

पूरे विश्वमें शिक्षाके प्रमुख केन्द्रके रूपमें प्रतिष्ठित बिहारके राजगीरके निकट स्थित नालन्दा विश्वविद्यालय आठ सौ वर्षोंके बाद पुन: जीवन्त हो उठा है। १७ देशोंके सहयोगसे भारत सरकारने नालन्दा विश्वविद्यालयके नये परिवारका निर्माण कराया है, जिसका प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीने बुधवारको एक भव्य समारोहमें लोकार्पण कर पूरी दुनियाको नया सन्देश भी दिया है। नालन्दा विश्वविद्यालयका नया परिसर अनेक विशिष्टताओंसे सुसज्जित है। प्रधान मंत्री मोदीने इसके निर्माणमें सभी सहयोगी देशोंका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नालन्दा सिर्फ भारतका पुनर्जागरण नहीं है अपितु इससे कई देशोंकी विरासत भी जुड़ी हुई है। नालन्दाके ध्वंसको याद करते हुए प्रधान मंत्री मोदीका यह कथन भी विशेष रूपसे महत्वपूर्ण है कि आगकी लपटें ज्ञान नहीं मिटा सकती हैं। नालन्दा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालन्दा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालन्दा उद्घोष है इस सत्यका कि आगकी लपटोंमें पुस्तकें भले जल जायें लेकिन आगकी लपटें ज्ञानको कदापि नहीं मिटा सकती हैं। उन्होंने कहा कि अपने प्राचीन अवशेषोंके समीप नालन्दाका नवजागरण विश्वको भारतके सामर्थ्यका परिचय देगा। नालन्दा यह भी बतायेगा कि जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्योंपर खड़े होते हैं, वह राष्ट्र इतिहासको पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्यकी नींव रखना जानते हैं। विश्वके कई देशोंके विद्यार्थी यहां आने लगे हैं। यह वसुधैव कुटुम्बकम्‌की भावनाका सुन्दर प्रतीक है। नालन्दा विश्वविद्यालयका नया परिसर १७४९ करोड़की लागतसे बना है। नालन्दा विश्वविद्यालयका समृद्ध इतिहास है और शिक्षाके क्षेत्रमें छह सौ वर्षोंतक इसका डंका बजता रहा लेकिन १३वीं सदीमें तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजीने आक्रमण कर इस विश्वविद्यालयको बर्बाद कर दिया। इस परिसरकी सबसे बड़ी पहचान इसका विशाल पुस्तकालय था। नौ मंजिले पुस्तकालयमें करीब तीन लाखसे अधिक पुस्तकें थीं। इन पुस्तकोंको आगके हवाले कर दिया गया था। लेकिन यह अत्यन्त ही संतोष और गर्वका विषय है कि भारत सरकार और १७ देशोंके सहयोगसे प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालय फिरसे जीवित हो उठा है। ऐसा विश्वास है कि नया परिसर पुन: अपने प्राचीन गौरवको प्राप्त करेगा। इसमें सभीका सहयोग भी अपेक्षित है।

पदोन्नति और सम्पत्ति

मानव सम्पदा पोर्टलपर सम्पत्तिका ब्योरा नहीं देनेवाले शिक्षकोंके प्रति उत्तर प्रदेश सरकारने कड़ा रुख अपनाया है। इसके तहत अब सम्पत्तिका ब्योरा देनेपर ही शिक्षकोंकी पदोन्नति होगी। इस बारेमें माध्यमिक शिक्षा विभागने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ३० जूनतक सभी शिक्षक अपनी चल-अचल सम्पत्तिका ब्योरा मानव सम्पदा पोर्टलपर दर्ज करा दें, तभी उन्हें प्रोन्नति एवं अन्य लाभ मिल सकेगा। साथ ही यह चेतावनी भी दी गयी है कि तय तिथिके भीतर यदि पोर्टलपर सम्पत्तियोंका विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया तो इसे प्रतिकूल तथ्यके रूपमें लिया जायगा। ऐसे शिक्षकोंकी सत्यनिष्ठाको प्रमाणित न मानते हुए उनके पदोन्नति प्रकरणपर कतई विचार नहीं किया जायगा। यह लापरवाह शिक्षकोंके प्रति शासनका कड़ा कदम है। दरअसल पिछले वर्ष ३१ दिसम्बरको सभी शिक्षकोंको पोर्टलपर अपनी सम्पत्तिका ब्योरा दर्ज करानेका निर्देश दिया गया था लेकिन १४ जूनतक प्रदेशभरके लगभग १८ लाख शिक्षक कर्मियोंमेंसे मात्र १८,६०० शिक्षकोंने ही अपनी सम्पत्तिका ब्योरा दर्ज कराया यह शासनादेशकी पूरी तरह अनदेखी है, जो क्षम्य नहीं है। पूर्वमें आईएएस-पीसीएसको ही अपनी सम्पत्तिका ब्योरा देना अनिवार्य किया गया था लेकिन दो वर्ष पूर्व सरकारने सभी संवर्गके कर्मचारियोंके लिए भी इसे अनिवार्य कर दिया। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली १९५६ में संशोधन कर उसमें नियम २४ जोड़ दिया गया। सरकारकी ओरसे जारी की गयी ३० जूनतककी समय-सीमातक सम्पत्तियोंका ब्योरा दर्ज करना अनिर्वाय है अन्यथा ऐसे शिक्षकोंकी प्रोन्नतिपर विचार नहीं होगा। साथ ही उनके विरुद्ध अनुशासनिक काररवाई भी होगी। सरकारका यह कड़ा कदम उन कर्मचारियोंके लिए सबक है जो शासनादेशकी अवहेलना करते हैं और अनावश्यक रूपसे सरकारपर दबाव बनानेका प्रयास करते हैं। सरकारका यह कठोर कदम स्वागतयोग्य है। इससे सरकारी कर्मियोंके मनमानीपर अंकुश लगेगा और वे अनुशासित तरीकेसे कार्य भी करेंगे।

लोक संवाद

लापरवाहीका मामला

महोदय,-भारतीय रेलवे एशियाका दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। सार्वजनिक परिवहन होनेके नाते इसके सस्ता और सुरक्षित होनेकी अपेक्षा की जाती है परन्तु लगातार किराये बढ़ानेके बावजूद सुविधाओं और सुरक्षाके मामलेमें अकसर रेलवेमें लापरवाहीके मामले सामने आते रहते हैं। पिछले एक वर्षमें देशमें दर्जनों रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें ३३० के लगभग यात्रियोंकी मौत तथा १५०० के लगभग घायल हुए हैं। यहां प्रस्तुत हैं पिछले एक वर्षके दौरान हुई चंद बड़ी रेल दुर्घटनाएं-२ जून, २०२३ को ओडिशाके बालासोरमें चेन्नईसे हावड़ा जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेसके एक मालगाड़ी तथा एक अन्य यात्री गाड़ीसे टकरा जानेसे २९६ लोगोंकी मौत एवं १२०० से अधिक लोग घायल हो गये। ११ अक्तूबर, २०२३ को नयी दिल्लीसे कामाख्या जा रही नार्थ एक्सप्रेसके बक्सर स्टेशनके निकट दुर्घटनाग्रस्त होनेसे चार लोगोंकी मौत हो गयी। २९ अक्तूबर, २०२३ को आंध्र प्रदेशमें विजयनगरम जिलेके कंटाकापल्लीमें रायगढ़ा पैसेंजर ट्रेनने पीछेसे आकर विशाखापत्तनम पलासा ट्रेनको टक्कर मार दी, जिससे १४ यात्रियोंकी मौत एवं ५० यात्री घायल हो गये। २ जून, २०२४ को पंजाबमें सरहिंदके माधोपुरके निकट दो मालगाड़ियोंके आपसमें टकरा जानेसे दो ड्राइवर घायल हो गये। ७ जून, २०२४ को राजस्थानके जयपुरमें खातीपुरा तथा जगतपुरा रेलवे स्टेशनोंके बीच दौलतपुर-साबरमती एक्सप्रेसके थर्ड एसी कोचमें आग लग गयी। १० जून, २०२४ को दिल्लीके सराय रोहिलासे जम्मूतवी जा रही दुरंतो एक्सप्रेसके इंजनमें शाहाबाद रेलवे स्टेशनपर शार्ट सर्किटसे आग लग गयी। १६ जून, २०२४ को वैष्णो देवी जा रही मालवा एक्सप्रेस ट्रेनके इंजनकी पावर फगवाड़ा तथा गोरायाके बीच तथा जम्मूतवी-गांधी नगर कैपीटोलकी पावर दसूहाके निकट फेल हो जानेसे यात्रियोंको भारी परेशानी हुई। अब १७ जून, २०२४ को सुबहके समय पश्चिम बंगालके सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेसको दार्जीलिंग जिलेमें एक मालगाड़ी द्वारा पीछेसे टक्कर मार देनेसे मालगाड़ीके पायलट तथा सह.पायलट सहित १५ लोगोंकी मौत तथा ६० घायल हो गये। रेलवेके सूत्रोंके अनुसार रानीपात्रा रेलवे स्टेशन तथा छत्तरहाट जंक्शनके बीच आटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम सुबह ५.५० बजेसे ही खराब था। रेल मंत्रालय करोड़ों रुपये खर्च करके रेलवे स्टेशनोंके नवीकरण तथा तेज रफ्तार गाड़ियां चलानेपर तो जोर दे रहा है, परन्तु रेलवेमें सुरक्षित परिचालनके लिए जरूरी रिक्त पद भरनेकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जून, २०२३ तक रेलवेमें ग्रुप सी में सेफ्टी कैटेगरीके १.७ लाख पदों सहित २,७४,५८० पद खाली थे जिस कारण स्टाफको ओवरटाइम काम करना पड़ रहा है तथा रेल दुर्घटनाओंका एक कारण परिचालन स्टाफकी थकान और नजरका कमजोर होना भी शामिल है। लोको पायलटोंकी नजर काफी दूरतक स्पष्ट देखनेमें सक्षम होनी चाहिए परन्तु कई मामलोंमें वे अधिक दूरतक स्पष्ट नहीं देख पाते। फिटनैस सर्टीफिकेट लेनेके लिए कथित रूपसे रिश्वतका सहारा लिया जाता है। एक ओर विश्वके विकासशील देशोंके साथ कदमसे कदम मिलाकर भारतीय रेल मंत्रालय नयी तेज रफ्तार गाड़ियां चला रहा है तो दूसरी ओर प्रश्नचिह्न लगाती उक्त रेल दुर्घटनाएं प्रमाण हैं कि भारतीय रेलें किस कदर दुर्घटनाओंके जोखिमपर हैं। ऐसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए भारतीय रेलोंकी कार्यशैली और रख-रखावमें तुरंत बहुआयामी सुधार लाने तथा रेलगाड़ियोंके परिचालन जैसी महत्वपूर्ण ड्यूटीपर तैनात होनेके बावजूद लापरवाही बरतनेवाले कर्मचारियोंके विरुद्ध कठोरतम काररवाई करनेकी जरूरत है। इसके साथ ही रेलों तथा आवागमनके अन्य सार्वजनिक माध्यमोंके चालकोंके चयनके मापदंड कड़े तथा निष्पक्ष होने चाहिए। **-विजयस वाया ईमेल।**

मोदीके समक्ष वैश्विक चुनौतियां

कुछ आलोचकोंका स्वभाव है भारतकी आर्थिक नीतियोंपर नुक्ताचीनी करना, लेकिन अंतरराष्ट्रीय तौरपर भारतकी आर्थिक वृद्धि दर तेजीसे बढ़ रही है। दुनिया भी मानती है कि भारत विश्वकी सबसे तेजीसे तरक्की करती अर्थव्यवस्था है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोषका आकलन है कि इस साल भारतकी आर्थिक वृद्धि दर ६.६ फीसदी रहेगी।

❐ जी.पार्थसारथी

भारत उच्च आर्थिक विकास दर पानेकी ओर अग्रसर है किन्तु यह बात ध्यानमें रखनी होगी कि विश्वमें इसका रुतबा और प्रभामंडल अधिकांशत: मजबूत आर्थिकी एवं तकनीकी तरक्कीसे ही तय होगा। इस जरूरी आवश्यकताके चलते, एकदम साथ लगते पड़ोसियोंसे संबंध सुदृढ़ करनेके अलावा भारतके समक्ष विकल्प कम ही हैं। इस ढंगके, जिनसे सुरक्षा एवं शांति सुनिश्चित हो, पश्चिममें लाल सागर-फारसकी खाड़ीसे लेकर पूरबमें मलक्काकी खाड़ीतकके इलाकेमें। अब यह व्यापक तौरपर मान्य है कि जो मुख्य चुनौतियां भारतके सामने अपनी सीमाओंपर और उनसे पार हैं, वे चीनकी विस्तारवादी महत्वाकांक्षा और नीतियोंसे उपजी हैं। लम्बे समयतक भारत तेल संपन्न खाड़ी क्षेत्रसे नजदीकी रिश्ते बनानेकी आकांक्षा रखता आया है, जहांपर लगभग ६० लाख भारतीय कामगार रोजी-रोटी कमा रहे हैं। एक ओर भारतने सऊदी अरबके साथ नजदीकी संबंध स्थापित कर लिये हैं, वहीं दूसरी तरफ यूएईके साथ पहलेसे अच्छे संबंधोंको और प्रगाढ़ किया जा रहा है। अमेरिका और सऊदी अरबके बीच रिश्ते पुन: मधुर बनानेमें भारतकी भूमिका अहम रही, जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा सऊदी अरबके राजपरिवारको लेकर की गयी नागवार टिप्पणीके बाद, सऊदी अरबकी पलटवार बयानबाजीके बाद इनके संबंध तल्ख हो गये थे। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक स्लिवन और सऊदी अरबके युवराज मोहम्मद बिन सलमानके बीच हुई वार्तामें यूएईके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शेख तहनून बिन जायद अल नाहयान भी उपस्थित थे। इन वार्ताओंके एक सूत्रधार भारतके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल थे। यूएई, अमेरिका और भारतके बीच सहयोग बढ़ानेके वास्ते एक समझौता हुआ और जल्द ही अंतिम प्रारूपपर दस्तखत किये गये। अब पड़ोसके छह अरब राष्ट्रों सहित हिंद महासागर क्षेत्रके पश्चिमी किनारेतकके इलाकेमें उत्तरोतर सकारात्मक एवं सहयोगात्मक भूमिका निभानेके लिए भारतका मंच तैयार है।

ईरानके साथ भारतके बढ़ते रिश्तोंपर अमेरिकाने पहले एतराज जताया था लेकिन अब उसे ईरानसे होकर अफगानिस्तानके साथ जोड़ता भारतका परिवहन गलियारा बनाना स्वीकार्य है। उम्मीदके मुताबिक पाकिस्तान इस परिवहन गलियारेसे खुश नहीं है क्योंकि इससे रावलपिंडीके सेना मुख्यालयमें बैठे पाकिस्तानी जनरलोंको भारतकी ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशियातक बनती पहुंचमें रोड़े अटकानेका मौका नहीं मिलता। आगे चलकर यह गलियारा अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारेसे जुड़नेमें भारतका अहम आवागमन द्वार बन जायेगा।

भारत-अमेरिकी संबंध तबसे अधिक प्रगाढ़ होते गये जब अमेरिकी राष्ट्रपतिने तय किया कि हिंद महासागर क्षेत्रमें चीनकी बढ़ती ताकतसे संतुलन बैठाना भारतके बसकी बात है और वह यह करना भी चाहेगा। दोस्तीके नाटकके बावजूद चीनकी नीतियां भारतके प्रभावको सीमित करनेसे बंधी हुई हैं। चीन पाकिस्तानके मिसाइल एवं परमाणु क्षमताओंको मजबूती देनेका काम जारी रखे हुए है। भारतकी अफगानिस्तानकी तरफ लगती पश्चिमी सीमाके साथ और परे, चीन पाकिस्तानके साथ निकट सहयोग बनाकर काम कर रहा है। ईरानके साथ रिश्ते मजबूत करनेके भारतके हालिया प्रयास, जिसमें सामरिक रूपसे अहम चाबहार बंदरगाहका विकास कार्य शामिल है, इससे जहां भारतको मध्य एशियातक और अधिक आर्थिक एवं नौवहनीय पहुंच बनानेमें मदद मिलेगी, वहीं अफगानिस्तानतक भारतकी पहुंचको अड़ंगे लगानेके पाकिस्तानी प्रयासोंकी गुजाइश कम बचेगी। ईरानके साथ भारतके बढ़ते रिश्तोंपर अमेरिकाने पहले एतराज जताया था, लेकिन अब लगता है कि बादमें विचार करनेपर, उसे ईरानसे होकर, अफगानिस्तानके साथ जोड़ता भारतका परिवहन गलियारा बनाना स्वीकार्य है। उम्मीदके मुताबिक पाकिस्तान इस परिवहन गलियारेसे खुश नहीं है, क्योंकि इससे रावलपिंडीके सेना मुख्यालयमें बैठे पाकिस्तानी जनरलोंको भारतकी ईरान, अफगानिस्तान और आगे मध्य एशियातक बनती पहुंचमें रोड़े अटकानेका मौका नहीं मिलता। आगे चलकर यह गलियारा अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारेसे जुड़नेमें भारतका एक अहम आवाजाही द्वार बन जायगा, इसके होकर भारत पहले मध्य एशिया और रूससे जुड़ेगा तो अंतिम छोरमें, यूरोपतक समुद्री, रेल और सड़क मार्गसे जुड़ जायगा।

भारत-अमेरिका संबंधोंपर जिस अहम कारककी छाया पड़ी है, वह है अमेरिकी मीडिया द्वारा भारतमें लोकतांत्रिक आजादीपर कथित कुठाराघातको लेकर हो रही निरंतर आलोचना। आम तौरपर महसूस किया जाता है कि इस मीडिया आलोचनाको राष्ट्रपति बाइडेनका समर्थन हासिल है। यह भी माना जा रहा है कि यदि सालके अंतमें होनेवाले राष्ट्रपति चुनावमें भारतके प्रति दोस्ताना रखनेवाले ट्रम्प विजयी हुए तो इस किस्मकी आलोचनाएं बंद हो जायंगी। हो सकता है भारत उन कुछ देशोंमें एक हो, जिसके नेतृत्व और लोगोंको राष्ट्रपति ट्रम्प मित्रवत और बेबाक लगें, जब वे भारत आये थे। चीनको लेकर ट्रम्पमें न तो कोई भ्रम है न ही उम्मीदें और पाकिस्तानके बारेमें सोचनेकी तरफ भी उनका झुकाव कम ही रहा है। बाइडेन प्रशासनकी रीतिके विपरीत पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प भारतके लोकतंत्रके बारेमें कोई उपदेश नहीं देते। तथापि अमेरिकाके साथ हमारे संबंध लगातार निकट बनते गये, जिसमें भारत-अमेरिकामें नौवहनीय सम्पर्कसे सुदृढ़ता लाने हेतु सहयोग काफी बढ़ा। हिंद महासागरमें बीच समुद्र जलपोतोंपर हमला या लूटकी वारदातोंसे पैदा हुए तनावके बाद यह घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण है, ठीक इसी वक्त गाजापर इसराइली कब्जा अभियान जारी था। होरमुजकी खाड़ीसे लेकर मलक्काकी खाड़ीतक फैले हिंद-प्रशांत क्षेत्रमें चीनके बढ़ते दबदबेके मद्देनजर अमेरिका भारतको बतौर एक महत्वपूर्ण सामरिक भागीदार मानना जारी रखे हुए है।

चीन और पाकिस्तानके साथ अपनी सीमाओंपर भारतकी समस्याएं और तनाव आगे भी जारी रहेंगे। लगभग दिवालिया होनेके बावजूद भी, लगता है पाकिस्तान भारतमें आतंकवादको हवा देना जारी रखे हुए है। जहां शरीफ-बंधु और उनकी सिविलियन सरकारने पाकिस्तानको दिवालिया होनेके कगारपर धकेल दिया है, भारतका पाला गोली-चलानेको सदा तत्पर रुखवाले पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष असीम मुनीरसे पड़ा है, जिनके हाथमें राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों बाबत शक्ति है। अपने गुरु और पूर्ववर्ती जनरल बाजवाके बरअक्स, जिन्हें समझ थी कि भारतके साथ तनावका असर पाकिस्तानकी आर्थिक एवं कूटनीतिपर क्या होगा, लगता है गर्ममिजाज जनरल मुनीर भारतपर आतंकवाद थोपनेपर उतारू हैं, विशेषकर जम्मू-कश्मीरमें। जनरल मुनीर द्वारा प्रायोजित आतंकवादका उत्तर देनेको भारतको राजनयिक एवं सैन्य रूपसे प्रतिक्रिया देनेकी जरूरत है।

बेशक पाकिस्तानकी सिविलियन और राजनीतिक संस्थाओंका नियंत्रण शरीफ बंधुओंके हाथ है, मुनीर द्वारा भारतके खिलाफ प्रायोजित आतंकवादपर उनका प्रभाव बहुत कम है, जो पहले की भांति जम्मू-कश्मीर एवं अन्य जगहोंपर जारी है। अतएव भारतको जम्मू-कश्मीर ही नहीं इससे परेके इलाकेमें मुनीर द्वारा पोषित आतंकी कृत्योंपर नजदीकी नजर बनाये रखनेकी जरूरत है। इसी बीच भारत और ईरानने अफगानिस्तानके साथ अच्छे रिश्ते कायम कर लिये हैं, जिसमें भारतके ध्यानका मुख्य केंद्र आर्थिक सहयोगपर है। जो भी है, अहम होगा कि पाकिस्तानके साथ राब्ता और संबंधके लिए विगतकी भांति पर्देके पीछे वार्ता चैनल खुला रखा जाय। जिससे कि वह प्रत्येक बैठकको भारत विरोधी प्रचारका जरिया न बनाने पाये। वहीं आतंकवादको बढ़ावा देनेपर भारत भी जवाबी काररवाई करनेमें परहेज न करे।

जंगलोंको बचानेकी जरूरत

वैश्विक स्तरपर हाहाकार मचानेवाली गर्मीने लोगोंका जीना दूभर कर दिया। पिछले दिनों जब लोग लोकसभा चुनावमें व्यस्त थे तब जंगल भी दावानलकी चपेटमें थे। उसका असर प्रकृतिपर पड़ा और धरती गर्म होने लगी।

❐ प्रताप सिंह

पूरे ब्रह्मांडमें प्राकृतिक दुनियाकी सबसे बेशकीमती एवं खूबसूरत संपदा पेड़-पौधोंसे लबरेज वन हैं। प्राचीन कालसे वन्य क्षेत्र जंगली जानवरों एवं मानवताके लिए अनमोल प्राकृतिक संसाधन रहे हैं। देशकी सियासत एवं तमाम इंतजामिया हालमें संपन्न हुए लोकसभा चुनावोंमें मशगूल थे, परन्तु हिमाचल सहित कई अन्य राज्योंमें जंगल दावानलकी चपेटमें आ चुके थे। नब्बे प्रतिशतसे अधिक जैव विविधता जंगलोंमें ही पायी जाती है। लोगोंको प्राकृतिक संसाधनोंके दोहनके प्रति जागरूकता तथा पर्यावरणकी अहमियतको समझानेके लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तरपर हर वर्ष पर्यावरण दिवस एवं पृथ्वी दिवस मनाये जाते हैं। जंगली जीवोंके संरक्षणकी आवश्यकताको देखते हुए विश्व वन्य जीव दिवस भी मनाया जाता है। जंगलों एवं पेड़ोंके महत्वके मद्देनजर सन् १९५० से वन महोत्सव तथा वन संरक्षणसे संबधित अतरराष्ट्रीय वन दिवस भी मनाया जाता है। पर्यावरण एवं वन संरक्षणके लिए देशकी अदालतोंमें एक बड़ा कानूनी मसौदा मौजूद है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एवं प्रशासन जैसी व्यवस्थाओंके दफ्तरोंमें अंग्रेजी झाड़नेवाली अफसरशाही तथा सैकड़ों अहलकार विराजमान हैं। राज्योंसे लेकर मरकजी हुकूमततक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मौजूद हैं। लेकिन इसे इत्तेफाक कहें या व्यवस्थाओंकी नाकामी, हर वर्ष जंगलोंमें लगनेवाली भयंकर आगसे निबटनेके लिए कोई भी हिकमत-ए-अमली कारगर साबित नहीं हुई, बल्कि वनाग्निकी घटनाओंमें हर वर्ष इजाफा हो रहा है।

चुनावी दौरमें मुल्ककी आवाम गुरबत, जाति, मजहब, मुफ्तखोरीकी खैरात, नौकरियां एवं विकास जैसे मुद्दे उठानेके प्रति जागरूक है। परन्तु पर्यावरण संरक्षण एवं जंगलोंकी भयंकर आग जैसे संवेदनशील मसलेपर आवाज कभी बुलंद नहीं होती। लोकसभा चुनावोंके दौरान सियासी दलोंने महंगी एवं बेरोजगारी जैसे मुद्दोंको जोर-शोरसे उठाया। लेकिन पर्यावरण संरक्षण एवं जलते जंगलोंका जिक्र किसी भी सियासी मंचसे नहीं हुआ। पर्यावरण संरक्षणका मुद्दा कभी चुनावी घोषणापत्रोंमें भी शामिल नहीं हुआ। वनाग्निके मसलेपर सियासी तौरपर भी कभी चर्चा नहीं हुई। भारतमें राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) को पर्यावरण अदालत कहा जाता है। एनजीटीको उच्च न्यायालयके बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। सन् २०१० में एनजीटीकी स्थापनाका मकसद पर्यावरणीय क्षति एवं वन संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनोंसे संबंधित मुद्दोंको शीघ्रतासे हल करनेसे है। आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंडके बाद पर्यावरण न्यायाधिकरणकी स्थापना करनेमें भारत विश्वमें तीसरा देश है। दुनियाके सबसे बड़े वन क्षेत्रोंवाले दस देशोंमें भारत भी शामिल है, परन्तु दावानलकी भयंकर चपेटमें आनेसे जंगल, पर्यावरण एवं जैव विविधता जिस कदर सिसकियां भर रहे हैं, उस सूरत-ए-हालको लफ्जोंमें बयान नहीं किया जा सकता। जंगल आगकी चपेटमें आ रहे हैं। देशमें हजारों उद्योग एवं फैक्टरियां लगातार प्रदूषण उगल रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों एवं शहरोंमें ज्यादातर लोग प्रदूषणकी जदमें जीवनयापन करनेको मजबूर हैं।

हिमाचल प्रदेशका नाम सुनते ही जहनमें पहाड़ों एवं वनोंकी तस्वीर उभरती है। पर्वतीय राज्य हिमाचलमें पर्यटन उद्योग युवावर्गके लिए रोजगारका महत्वपूर्ण साधन है। मैदानी क्षेत्रों एवं शहरोंसे हजारोंकी तादादमें लोग भीषण गर्मीसे निजात पानेके लिए तथा सुकूनके कुछ पल बितानेके लिए पहाड़ोंका रुख करते हैं। प्रकृतिसे सराबोर जंगल पर्यटन उद्योगके आकर्षणका मुख्य केन्द्र हैं। परन्तु बरसातके मौसममें प्रकृतिके प्रकोपसे पहाड़ दरक रहे हैं। गर्मियोंमें जंगल भीषण आगसे जल रहे हैं। कई जंगली जीवों एवं पक्षियोंकी दुर्लभ प्रजातियोंका प्रजनन काल गर्मीके मौसममें होता है, परन्तु प्रतिवर्ष असंख्य वन्य जीव एवं जंगली जानवर वनोंकी भयानक आगमें जलकर राख हो जाते हैं। वनोंमें आगजनीकी बढ़ती घटनाओंसे वन्य जीवों एवं पक्षियोंकी कई दुर्लभ प्रजातियोंका वजूद मिट चुका है। औषधीय वनस्पतिसे लबरेज वनोंका आयुर्वेदिक पद्धतिमें भी अत्यधिक महत्व रहा है, परन्तु वनाग्निसे कई किस्मकी औषधीय वनस्पतिका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। यदि अमूल्य वन संपदा वनाग्निकी भेंट चढ़ जायगी तो पर्यावरणके साथ पर्यटन उद्योग भी मुतासिर होगा। वायु प्रदूषणके बढ़ते स्तरपर काबू पानेका मुफीद विकल्प पेड़ोंसे लबरेज वन्य क्षेत्र हैं। वन्य क्षेत्रके बिना स्वच्छ पर्यावरण, जैव विविधता एवं जंगली जीवोंके वजूदकी कल्पना नहीं की जा सकती। वनोंमें आग लगनेकी घटनाओंपर देशके न्यायालय, पर्यावरणकर्ता एवं सरकारें चिन्ता जरूर व्यक्त करती हैं, जबकि प्रकृतिको सबसे अधिक नुकसान मानवीय गतिविधियोंसे ही पहुंचता है। जंगलोंमें आग लगनेके ज्यादातर कारण मानवीय लापरवाहीके हैं। भयंकर दावानलपर काबू पाना लगभग नामुमकिन है। अलबत्ता सामाजिक तौरपर जागरूकता बढ़ानेकी जरूरत है, ताकि जंगलोंमें आग न लगायी जाय। वनोंके लगातार जलनेसे इस धरापर समस्त प्राणियोंका जीवन असम्भव हो जायगा। वनाग्निसे अमूल्य वन सम्पदा एवं जंगली जीवों तथा पक्षियोंके जलनेका दर्द समझना होगा।

प्राचीन भारतके अनुसंधानका केन्द्र रहे वन्य क्षेत्र मानवीय स्वास्थ्यका सबसे बड़ा रक्षा कवच हैं। भारतीय संस्कृतिमें अनादिकालसे वनोंका आध्यात्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व रहा है। वैदिक साहित्यके रचयिता हमारे मनीषियोंके चिंतन, ध्यान साधना, अध्यात्म, दर्शन एवं शोधका केन्द्र वन्य क्षेत्र ही रहे हैं। आधुनिक दौरके पर्यावरण संरक्षणके आयोजनों एवं मंत्रालयोंके बिना प्रकृतिको सहेजनेके कई उत्सव एवं संस्कार प्राचीन भारतकी वैदिक संस्कृति एवं सामाजिक परिवेशमें मौजूद थे। उन महान संस्कारोंको अपनानेकी जरूरत है। फिलहाल यदि कायनातकी खूबसूरत वन संपदाका दिलशाद चेहरा दावानलसे खाक होता रहेगा तो प्रकृति एवं पर्यावरणकी तबीयत नासाज हो जायगी। अत: प्रकृतिका संतुलन बरकरार रखनेके लिए जंगलोंको आगसे महफूज रखनेके हरसंभव प्रयास होने चाहिए। वनोंको दावानलसे हर कीमतपर बचाना होगा।

आत्मबोध

आध्यात्मिकताका लक्ष्य

❐ श्रीश्री रविशंकर

आध्यात्मिकता और राजनीति दोनोंका ही मानवता एवं मानवके साथ गहरा संबंध है। राजनीतिका उद्देश्य सुशासन लाना और भौतिक एवं भावानात्मक सुविधाओंको जनतातक पहुंचाना है। वहीं आध्यात्मिकताका लक्ष्य नैतिकता एवं मानवीय मूल्योंको बढ़ाना है। किसी भी देशकी समृद्धि एवं विकासके लिए राजनीति एवं आध्यात्मिकताका एक साथ चलना अति आवश्यक है। सुशासन एवं अच्छे प्रजातंत्रके लिए आध्यात्मिकताका होना अनिवार्य है। केवल आध्यात्मिकता ही प्रतिबद्धता, दायित्व एवं आत्मविश्वासका आह्वान कर उन्हें मानवमें स्थापित कर सकती है। बिना आध्यात्मिकताके राजनीतिमें अनैतिकताका वातावरण बनता है और इस कारण भ्रष्टाचार, अपराध एवं अराजकताको बढ़ावा मिलता है। भारतीय आध्यात्मिकताने पूरे संसारको धर्मनिरपेक्षतासे अवगत करवाया है। यदि हम अपने प्राचीन इतिहासको देखें तो हम पायंगे कि आध्यात्मिकता भारतीय राजनीतिमें बहुत गहरी जड़ोंतक स्थित है। प्राचीन कालमें राजगुरु द्वारा राजाको सलाह दी जाती थी एवं उनका मार्ग प्रशस्त किया जाता था। जब आध्यामिकता एवं राजनीति एक दूसरेके साथ-साथ नहीं चलते तब हमें राजनीतिमें भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट नेता देखनेको मिलते हैं। आध्यात्मिक लोग मूल्योंपर आधारित जीवन जीते हैं जो कि सुशासनके लिए अति आवश्यक है। एक नेताका समदर्शी होना अति आवश्यक है ताकि वह प्रत्येक व्यक्तिके साथ समानताका व्यवहार कर सके। एक नेताका दूरदर्शी होना भी अति आवश्यक है, खुले विचारों एवं समाजके हितमें अपने सपनोंको साकार करते हुए वह मानवताकी भलाई कर सकता है। आजके समयकी आवश्यकता ऐसी राजनीति कार्य प्रणाली है जो कि पूर्वागृहोंसे मुक्त हो। आम सहमति केवल तभी उभर सकती है जब राजनेता धर्म, जाति एवं लिंगके आधारपर पूर्वागृहोंको छोड़कर आगे बढ़ें। पूर्वागृहकी भावनाका त्याग करनेके लिए राजनेतामें अपनेपनकी भावना एवं खुले विचारोंका होना अति आवश्यक है। आध्यात्मिकता लोगोंको ईमानदार एवं प्रतिबद्ध बनाती है जो कि किसी भी अपराध रहित समाजके लिए बेहद आवश्यक है। परन्तु आधिकारिक संरक्षणके बिना आध्यात्मिकताका विकसित होना बहुत मुश्किल है।

अरुंधति रायपर राजद्रोहका मामला

❐ विष्णुगुप्त

अरूंधति रॉयपर राजद्रोह सहित कई संहिताओंके अधीन मुकदमें दर्ज हो चुके हैं। उनपर गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम भी लगाया गया है। गैर-कानूनी गतिविधियां यानी यूएपीए लगनेपर आरोपीको जमानत मिलनेमें कठिनाई होती है। दिल्लीके उपराज्यपालने अरूंधति रॉयपर मुकदमा चलानेकी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली पुलिसके पास करीब १४ सालसे यह प्रकरण लंबित था। यह प्रकरण कोई आजका नहीं है, बल्कि २०१० का है। २०१० में देशमें मनमोहन सिंहका शासन था। देशके खिलाफ बोलने और देशका संहार करनेकी मानसिकता रखनेवाले लोग कांग्रेसके प्रिय कैसे हो सकते हैं? २१ अक्तूबर २०१० को दिल्लीमें भारत विरोधियोंने एक सेमिनारका आयोजन किया था। सेमिनारका नाम था आजादी द ओनली। इस सेमिनारका इस्तेमाल भारतके खिलाफ विषवमनके लिए किया गया था।

अरूंधति रॉयके साथ सैयद अली शाह गिलानी, शेख शौकत हुसैन भी थे। इस सेमिनारमें अरूंधति रॉयने सरेआम कहा था कि कश्मीर भारतका अभिन्न अंग नहीं है, कश्मीरका आन्दोलन आजादीका आन्दोलन है, कश्मीरके आन्दोलनको आतंकवाद और हिंसा नहीं कहा जा सकता है? भारतने सात लाख सैनिकोंको खड़ा कर कश्मीरपर कब्जा कर रखा है। अरूंधति रॉयको कश्मीरसे भगाये गये पांच लाखसे अधिक कश्मीरी पंडित परिवारों और सैकड़ों कश्मीरी पंडितोंकी हुई हत्याएं याद ही नहीं आयी थी। अरूंधति रॉय राजद्रोहके मुकदमें जो फंसी है उसके पीछे कश्मीर पीड़ित सुशील पंडितका संघर्ष है। सुशील पंड़ित कई सालोंसे कश्मीरमें पंड़ितोंके साथ हुई कत्लेआमकी घटनाको लेकर संघर्षरत हैं। दिल्ली पुलिसमें सुशील पंड़ित ही एफआईआर दर्ज करायी थी। अरूंधति रॉय जैसे देशमें सैकड़ों बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो भारतमें रहकर और भारतकी उदार राज व्यवस्थाका लाभ उठाकर भारतकी ही छविको खराब करते हैं। यहांपर गुलाम फईका प्रसंग जोड़ना प्रासंगिक होगा। गुलाम फई भारतीय मूलके अमेरिकी नागरिक हैं। नवलखा जैसे भारतीय बुद्धिजीवी गुलाम फईके मोहरे बन कर अमेरिका जाते और पाकिस्तानका गुणगान करते, भारतको हानि पहुंचाते। प्रसंग उजागर होनेके बाद गुलाम फईको अमेरिकाने जेलोंमें डाला। गुलाम फईको अमेरिकाने सजा दे दी परन्तु गुलाम फई और पाकिस्तानके मोहरे भारतीय बुद्धिजीवियोंपर कोई काररवाई नहीं हुई, वे आज भी भारतके खिलाफ खुलेआम बोलते हैं।

अरूंधति रायके वक्तव्य भारतकी एकता और अखंडताका संहार करनेवाला है, एक सजग नागरिक होनेके कर्तव्यका घोर उल्लंधन है, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसकी सक्रियतासे ऐसा लगता है कि वह भारतीय नागरिक ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी नागरिक है, भारतके विकास और समृद्धिसे नफरत करनेवाली है, भारतके लोकतंत्रको वह गैर-जरूरी मानने वाली है। कश्मीरके आतंकवादको वह आजादीकी लड़ाई माननेवाली है। वह कहती है कि कश्मीर भारतका अंग कभी नहीं रहा है। यह सरासर गलत है। यह लाइन पाकिस्तान पोषित आतंकवादका है। अरूंधति रायकी यह मानसिकता सचसे परे यानी कि झूठ है, पाकिस्तानी मानसिकता है। कश्मीर भारतका अभिन्न अंग रहा है। अंग्रेजोंने भारत छोड़नेके पूर्व राजवाड़ोंको इच्छाका विकल्प दिया था। राजवाड़े किसी भी तरफ शामिल हो सकते थे। राजा हरि सिंहने भारतको विकल्प चुना था और उसने अपने राज्यका भारतमें विलय किया था। राजा हरि सिंहका विलय पत्रपर हस्ताक्षर करनेके साथ ही साथ कश्मीर भारतका अभिन्न अंग बन चुका था। इसलिए अरूंधतिके तर्कको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, अरूंधति सिर्फ अफवाह फैलाती है और भारत विरोधकी मानसिकताका सरेआम प्रदर्शन करती है।

कश्मीरी आतंकवादियोंके साथ अरूंधतिके रिश्ते जगजाहिर है। हुर्रियतकी वह एक तरहसे समर्थक है। क्योंकि हुर्रियतका जो रूख है वही रूख उसकी भी रहा है। हुर्रियत नेता खुद यह स्वीकार कर चुके हैं कि वे कभी न कभी आतंकवादके रास्तेपर थे। हुर्रियतके कई नेता अब भी जेलोंमें बंद जिनके खिलाफ खून और कत्लेआमके घिनौने आरोप हैं। ऐसे आतंकवादियों और अपराधियोंका साथ देना कानूनी रूपसे सही नहीं है। वह मानवतावादी होनेका ढोंग रचती है। यदि वह मानवतावादी होती तो निश्चित तौरपर कश्मीरी पंड़ितोंकी पीड़ा भी उनके विमर्शमें शामिल होता और कश्मीरी पंड़ितोंकी हुई हत्याएं भी उन्हें विचलित करता। लेकिन उन्होंने एक बार भी कश्मीरी पंड़ितोंकी हुई हत्याओंके लिए कश्मीरी आतंकवादियोंकी करतूतकी आलोचना नहीं की है। राष्ट्रकी कब्र खोदनेवालों और राष्ट्रकी एकता-अखंडताका संहार करनेकी मानसिकता रखनेवालोंको कभी भी न तो बढ़ावा दिया जाना चाहिए और न ही कानून उनपर खामोश रहना चाहिए। कानूनके खामोश रहनेपर ही अरूंधति रॉय जैसोंकी दुकानदारी चलती है, भारतके खिलाफ बोलनेपर ही इनकी दुकानदारी समृद्ध होती है। पाकिस्तान, यूरोप एवं अमेरिकासे पैसे मिलते हैं। टूर पैकेज मिलते हैं, फेलोशिप मिलते हैं, पुरस्कार मिलते हैं। यदि विदेशी सहायताएं रोक दी जाय तो फिर अरूंधति रॉय जैसोंकी भारत विरोधी मानसिकताएं खुद-ब-खुद दम तोड़ देंगी।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

कांग्रेसी रणनीति

वायनाड से प्रियंका

कांग्रेस ने रणनीति के तहत वायनाड से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है, जबकि राहुल गांधी रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे। आधिकारिक घोषणा के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को केरल के वायनाड चुनाव क्षेत्र से लोकसभा उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया गया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है कि उनके भाई राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट अपने पास रखेंगे। वायनाड से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी कांग्रेस द्वारा उठाई जा रही जोखिम है जिसके माध्यम से वह उत्तर भारत में अपनी पकड़ बनाए रखते हुए दक्षिण भारत में पहुंच बढ़ाना चाहती है। अपनी उच्च शिक्षा दर तथा विविधतापूर्ण जनसंख्या संरचना के कारण वायनाड को कांग्रेस के लिए तुलनात्मक रूप से सुरक्षित माना जाता है। राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में उपस्थिति बनाए रखने से वे उत्तर प्रदेश पर ध्यान दे सकेंगे। इससे पार्टी के लिए एक सीट पर निरंतरता व स्थायित्व सुनिश्चित होगा जो 'गांधी परिवार' के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। प्रियंका गांधी को वायनाड से उतार कर पार्टी केरल के नौजवानों व महिला मतदाताओं में अपना आकर्षण बढ़ाना चाहती है। इस राज्य में खासकर क्षेत्रीय पार्टियों तथा वाम लोकतांत्रिक मोर्चा-एलडीएफ के उभार के बाद राजनीतिक प्रतियोगिता बहुत कठोर हो गई है। सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद संसद में कांग्रेस के तीन सदस्य कांग्रेस विरोधियों को उस पर वंशवाद का आरोप लगाने का अवसर दे देते हैं, लेकिन कांग्रेस वर्तमान समय में संभवत: चुनावी गणित पर ज्यादा ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का खराब प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के साथ इस महत्वपूर्ण राज्य में कांग्रेस

गठबंधन का कारण स्पष्ट करता है। रायबरेली से राहुल की उपस्थिति सीधे उनको इस राज्य से जोड़ेगी, जबकि दक्षिण भारत में प्रियंका की उपस्थिति उनको इस क्षेत्र में स्थान दिलाएगी। प्रियंका का चुनावी राजनीति में प्रवेश स्पष्ट करता है कि वे ज्यादा से ज्यादा सक्रिय राजनीति में रहना चाहती हैं। इससे संकेत मिलता है कि वे प्रमुख निर्णयकर्ताओं में शामिल होना चाहती हैं और स्वयं को केवल चुनाव प्रचार तथा अपने भाई राहुल की सहायता तक सीमित नहीं रखेंगी।

लेकिन उत्तर प्रदेश तथा इस प्रकार कांग्रेस की खोई हुई गरिमा प्राप्त करना अभी बहुत दूर का सपना है क्योंकि कांग्रेस के अधिकांश वोटबैंक पर क्षेत्रीय पार्टियों ने कब्जा कर लिया है और इससे वे मजबूत हुई हैं। यह कदम प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा प्रमुख भूमिका मिलने का संकेत करता है। इससे संभवत: वे पार्टी के भीतर ज्यादा जिम्मेदारियां संभालने का मंच बनाना चाहती हैं। हालांकि, ये कदम रणनीतिक दिखते हैं, पर कांग्रेस को अब भी कठिन चुनौतियों का सामना करना है। भाजपा की जीवन्त संगठनात्मक मशीनरी और संसाधन उसे मजबूत विपक्ष बनाते हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय पार्टियां लगातार चुनौती बनी हुई हैं और वे प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में वोट बंटवारे का कारण बनती हैं। इसके साथ ही कांग्रेस को आंतरिक विरोध का सामना करते हुए चुनावी संभावनाओं को अधिकतम बनाने के लिए एक संयुक्त मोर्चा बनाना होगा। उसके सामने असली चुनौती एक सुसंगत एवं आकर्षक दृष्टिकोण रखना है जो उसे विविध जनसंख्या संरचनाओं में समर्थन दिला कर कार्यकर्ताओं को ऊर्जान्वित कर सके। इस दिशा में संगठनात्मक स्तर पर बहुत कुछ करने की आवश्कता है क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता लंबे समय से निराश हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले चुनाव नई कांग्रेसी रणनीतियों और उनके क्रियान्वयन की परीक्षा लेंगे।

लू का अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव

वर्तमान समय में जारी भयानक गर्मी का आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ता है। इससे निपटने के लिए जलवायु-संवेदी कार्रवाई तथा जनता व उत्पादकता को सुरक्षित रखने के उपाय जरूरी हैं।

ए.एस. मित्तल
(लेखक, उद्योग जगत से संबद्ध हैं)

हम में से बहुत से लोगों के लिए 'भयानक गर्मी' इस वर्ष के सर्वाधिक गर्म महीनों में पैदा असुविधा का कारण हैं। देश भर में व खासकर उत्तर भारत में भयानक गर्मी और लू से दिल्ली और राजस्थान में अधिकतम तापमान 52 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। गर्मी के कारण पैदा बीमारियों से अनेक लोगों की मौत हुई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी लू चल रही है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि स्थिति और खराब होगी क्योंकि उत्तर-पश्चिमी भारत में भी तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इससे खेती, निर्माण तथा औद्योगिक गतिविधियों में लगे लाखों कामगारों के लिए खतरा बढ़ गया है।

अनेक अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह उत्पादकता हेतु गंभीर खतरा बन गई है। इसलिए तत्काल जलवायु-संवेदी कार्ययोजना बनाना जरूरी हो गया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है जिससे देश को हर साल उच्च तापमान का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2030 तक देश में हर साल 160-200 मिलियन लोगों को हर साल भयानक लू का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही भारत में लगभग 34 मिलियन लोगों को गर्मी के कारण पैदा तनाव तथा उत्पादकता में आई कमी से नौकरियों और रोजगार से वंचित होना पड़ सकता है। औसत तापमान में वृद्धि का प्रभाव विभिन्न पेशों तथा रोजगार देने वाले क्षेत्रों के लिए अलग-अलग होता है। अत्यधिक शारीरिक परिश्रम वाले कामों तथा लगातार लंबे समय तक बाहर काम करने वाले रोजगारों पर बढ़ती गर्मी का खासतौर से प्रभाव पड़ता है। खासकर कृषि व निर्माण कार्य, स्टील प्लांटों व ईंट भट्ठों में काम करने वाले लोगों पर इसका प्रभाव सर्वाधिक होता है।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन-आईएलओ द्वारा 1995 में किए एक अध्ययन के अनुसार भारत में अत्यधिक गर्मी के कारण नुकसान होने वाले कार्यदिवसों का प्रतिशत कृषि और निर्माण में 5.87 प्रतिशत, उद्योग में 2.97 प्रतिशत तथा सेवाओं में 0.63 प्रतिशत था। इन आंकड़ों में 2030 तक कृषि और निर्माण में 9.04 प्रतिशत, उद्योग में 5.29 प्रतिशत तथा सेवाओं में 1.48 प्रतिशत वृद्धि हो सकती है। गर्मी के कारण बढ़ने वाला तनाव आर्थिक गतिविधि में एक बाधा बनता जा रहा है। इससे बिजनेसों को सबसे गर्म घंटों में काम करने में बाधा आती है, तापमान बढ़ने से श्रम उत्पादकता में और कमी आती है, कुछ कृषि क्षेत्र अनुत्पादक हो जाते हैं तथा बड़ी संख्या में खेतिहर मजदूर विस्थापित होते हैं।

1995 में वैश्विक आर्थिक नुकसान 280 बिलियन डालर था और इस आंकड़े के 2030 तक बढ़ कर 2,400 बिलियन डालर होने की आशंका है। वर्तमान समय में बढ़ती गर्मी के कारण परिवहन के दौरान वार्षिक खाद्य पदार्थों का नुकसान लगभग 13 बिलियन डालर होता है। 2030 तक शीतलन की मांग वर्तमान समय के मुकाबले आठ गुना बढ़ने की आशंका है। इसका अर्थ है कि हर 15 सेकेंड पर नए एयरकंडीशनर की मांग होगी जिससे वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन अगले दो दशकों में 435 प्रतिशत बढ़ सकता है। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए भारत को लोगों को बढ़ते तापमान के अनुकूल बनाने में सहायता के लिए नए रणनीतिक टिकाऊ समाधान जरूरी होंगे। विश्व बैंक के अध्ययन 'क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपारचुनिटीज़ इन इंडियाज़ कूलिंग सेक्टर' से स्पष्ट संकेत मिलता है कि लू के संकट से मुकाबला करने के लिए वैकल्पिक व खोजी ऊर्जा-सक्षम तकनीकों की आवश्यकता होगी। यह दृष्टिकोण 2040 तक भारत में 1.6 ट्रिलियन डालर निवेश की संभावनायें खोलता है ताकि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में काफी कमी लाई जा सके।

इससे लगभग 3.7 मिलियन रोजगारों का सृजन होगा। इस अध्ययन के अनुसार ऊर्जा-सक्षम मार्ग से कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन में अगले दो दशकों में काफी कमी लाई जा सकती है। भारत की शीतलन रणनीति जीवनों और आजीविकाओं को बचा सकती है, कार्बन उत्सर्जन घटा सकती है तथा भारत को ग्रीन-शीतलन विनिर्माण का महत्वपूर्ण वैश्विक केन्द्र बना सकती है। इस रिपोर्ट में शीतलन का प्रभावी टिकाऊ रोडमैप पेश किया गया है जिससे 2040 तक कार्बन डाईआक्साइड उत्सर्जन में 300 मिलियन टन की कमी आ सकती है।

2019 में इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान-आईकैप शुरू किया गया था ताकि विभिन्न क्षेत्रों में निर्णायक व टिकाऊ शीतलन उपाय किए जा सकें। इन उपायों में इमारतों में भीतरी शीतलन, कृषि एवं फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में कोल्ड चेन सोलर रेफ्रीजरेशन तथा यात्री परिवहन में एयरकंडीशनिंग शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य 2037-38 तक बिजली-संचालित शीतलन की मांग में 25 प्रतिशत कमी लाना, प्रशिक्षित तकनीशियनों के 2 मिलियन रोजगारों का सृजन करना तथा अगले दो दशकों में रेफ्रीजरेंट्स की मांग में लगभग 31 प्रतिशत कमी लाना शामिल है। जलवायु-संवेदी शीतलन तकनीकों के प्रयोग के लिएआवश्यक है कि निजी और सरकारी- फंडिंग वाले निर्माण कार्यों में जलवायु-संवेदी शीतलन तकनीकों का प्रयोग किया जाए।

इससे यह सुनिश्चित होगा कि आर्थिक सीढ़ी के सबसे निचले स्तर पर रहने वाले लोगों पर बढ़ते तापमान का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़े। इस रिपोर्ट में भारत में सस्ती आवास परियोजनाओं में इन परिवर्तनों की व्यापक रूप से स्वीकार्यता पर जोर दिया गया है। इससे उन 11 मिलियन शहरी आवासों तथा 29 मिलियन से अधिक ग्रामीण आवासों को लाभ होगा जिनका निर्माण सरकार करवाना चाहती है। जिला स्तर पर शीतलन तकनीकों के लिए सार्वजनिक-निजी निवेश आवश्यक है। इन अद्यतन तकनीकों का प्रयोग एक सेंट्रल प्लांट में ठंडा पानी तैयार करने में होगा जिसे बाद में अंडरग्राउंड इन्सुलेटेड पाइपों के माध्यम से अनेक इमारतों में फैलाया जा सकेगा। इससे अलग-अलग इमारतों को ठंडा करने के खर्च में भारी कमी आएगी तथा सर्वाधिक सक्षम परंपरागत शीतलन समाधानों की तुलना में बिजली बिलों में 20-30 प्रतिशत कमी आएगी। चंडीगढ़ में पंजाब इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी-पीडा कार्यालय इस जलवायु-संवेदी इमारत का प्रमुख उदाहरण है। इससे गर्मी के महीनों में शीतलन तथा जाड़े में गर्मी पैदा करने का काम होता है। इस उदाहरण का अनुसरण भविष्य में हरित इमारतों के निर्माण में किया जा सकता है।

उच्च तापमान के कारण खाद्य पदार्थों व दवाओं के परिवहन के दौरान बढ़ते नुकसान से बचने के लिए विश्व बैंक रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से कोल्ड चेन वितरण नेटवर्कों में कमियां संबोधित करने पर जोर दिया है। प्री-कूलिंग तथा रेफ्रिजरेटेड परिवहन से खाद्य पदार्थों के नुकसान में 76 प्रतिशत की कमी लाई जा सकती है और कार्बन उत्सर्जन भी 16 प्रतिशत घट सकता है। भारत ओजोन-क्षरण का कारण बनने वाले हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बनों के उत्पादन और प्रयोग को हतोत्साहित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है जिनका प्रयोग एयरकंडीशनरों और रेफ्रिजरेटरों में कूलेंट के रूप में होता है। इस रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि सेवाओं, रखरखाव तथा ऐसे उपकरणों के डिस्पोजल में सुधार की जरूरत है जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बनों का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही ग्लोबल वार्मिंग फुटप्रिंट घटाने के लिए वैकल्पिक उपायों का तेजी से प्रयोग जरूरी है।

कार्यस्थलों पर खासकर सर्वाधिक प्रभावित व संकटग्रस्त क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव समझना जरूरी है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से ढांचागत परिवर्तन की पैरवी की गई है। इसके लिए जिम्मेदार और टिकाऊ 'हरित' बिजनेसों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे खेतिहर मजदूरों को उच्च तापमान से बचाने तथा उनके शारीरिक श्रम में कमी लाने में सहायता मिलेगी। जलवायु संकट से निपटने के अन्य नीतिगत उपायों में कौशल विकास, टिकाऊ उद्यमों के लिए उपयुक्त परिवेश बनाने तथा ढांचागत संरचनाओं में समुचित सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है।

वाणिज्यिक सफलता के लिए पहल करें स्टार्ट अप्स

सुभाकर अलापती
(लेखक, स्तम्भकार हैं)

भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम ने पिछले दशक में महत्वपूर्ण प्रगति की है, हालांकि यह अभी भी वैश्विक बेंचमार्क से पीछे है। विकास की संभावना बहुत अधिक है, जिसे कर छूट और वित्तीय सब्सिडी जैसी सहायक सरकारी पहलों से बल मिला है। कई फंडर भारत के युवाओं को पोषित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इन अनुकूल नीतियों और हमारे समर्पित प्रयासों के कारण अगले दशक में स्टार्टअप की संख्या में उछाल की उम्मीद करते हैं। कई स्टार्टअप लड़खड़ा जाते हैं क्योंकि युवा उद्यमी, आशाजनक विचारों से भरे होते हैं, लेकिन संचालन, वित्तीय प्रबंधन और संसाधन उपयोग में आवश्यक ज्ञान की कमी होती है। कॉलेज से निकले नए-नए लोग बदलाव लाने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन अक्सर सफलता के लिए महत्वपूर्ण कौशल की कमी होती है। अपने 12 से अधिक वर्षों के अनुभव और एक मजबूत नेटवर्क से, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि युवा भारतीय उद्यमियों में सफल होने की क्षमता है, उन्हें बस विधि की आवश्यकता है। उन्हें न केवल फंडिंग पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, बल्कि महत्वपूर्ण ज्ञान अंतराल को पाटने और विकास को बढ़ावा देने के लिए वित्त, संचालन और समग्र व्यवसाय प्रबंधन में विशेषज्ञता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। प्राथमिक चुनौती युवा उद्यमियों में परिचालन और वित्तीय प्रबंधन कौशल की कमी है, जो अपने अभिनव विचारों को क्रियान्वित करने में संघर्ष करते हैं।

मैं चाहूंगा कि वे इस कमी को पूरा करें। यहीं पर वाईइए जैसे फंडर्स वित्तीय सहायता के साथ-साथ व्यापक सलाह देकर आगे आते हैं। मेंटर्स को परिचालन दक्षता बढ़ाने, वित्त का प्रबंधन करने और सरकारी प्रोत्साहनों का लाभ उठाने में स्टार्टअप का मार्गदर्शन करना चाहिए, जिससे उनकी सफलता की संभावनाएँ बढ़ें। आज, भारत में कई स्टार्टअप युवा उद्यमियों द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जिनके पास कंपनी प्रबंधन और संचालन में अनुभव की कमी है। हमारे जैसे फंडर्स इन व्यक्तियों को विस्तृत परिचालन योजनाएँ देने को प्राथमिकता देते हैं, जिनके पास बेहतरीन विचार होते हैं, लेकिन उन्हें क्रियान्वयन में मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उन्हें लागत की गतिशीलता को समझने, दक्षता के लिए संचालन को अनुकूलित करने और हमारे निवेश का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए संसाधनों तक पहुँचने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, फंडर्स वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता प्रदान करते हैं और उन्हें कर छूट जैसी सरकारी नीतियों के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। जैसे-जैसे विभिन्न चरणों में फंडिंग की ज़रूरतें विकसित होती हैं, हमारा व्यापक नेटवर्क हमें बाहरी निवेशकों से अतिरिक्त फंड हासिल करने में सक्षम बनाता है, जिससे निरंतर सफलता सुनिश्चित होती है। ड्डश्च जैसे अधिकांश फंडर्स उद्योगों में बदलाव लाने में सक्षम अभिनव विचारों की तलाश करते हैं, न कि मौजूदा मॉडलों की नकल। हमारी कठोर चयन प्रक्रिया में विस्तृत प्रस्ताव, प्रश्नावली और प्रस्तुतियाँ सहित सावधानीपूर्वक जाँच शामिल है। एक बार चुने जाने के बाद, स्टार्टअप व्यक्तिगत सलाह से लाभान्वित होते हैं और विशेषज्ञों और संसाधनों के नेटवर्क तक पहुँच प्राप्त करते हैं। इस व्यापक समर्थन का उद्देश्य स्थायी विकास और अंतत: सफलता को बढ़ावा देना है। हम फंडर्स उद्यमिता में वास्तविक नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हैं। हमारे कड़े चयन मानदंड वास्तव में अभूतपूर्व विचारों की पहचान करने के लिए कई अनुप्रयोगों को छानते हैं। हम अक्सर ऐसे अनुप्रयोगों का सामना करते हैं जो पर्याप्त विभेदन की कमी वाले सामान्य अवधारणाओं का प्रस्ताव करते हैं, जिन्हें हमें खेद के साथ अस्वीकार करना पड़ता है। हमारा ध्यान अगले गूगल या फेसबुक बनने की क्षमता वाले स्टार्टअप को पोषित करने पर रहता है - अद्वितीय प्रस्तावों और स्केलेबल मॉडल वाले उद्यम।

उद्यमिता जुनून से अधिक की मांग करती है; इसके लिए सावधानीपूर्वक योजना, लचीलापन और धैर्य की आवश्यकता होती है। सफलता तात्कालिक नहीं है, बल्कि पुनरावृत्त शोधन और अनुकूलन के माध्यम से विकसित होती है। उद्यमियों को अपनी दृष्टि में दृढ़ रहना चाहिए, लगातार सीखना और अनुकूलन करना चाहिए, और चुनौतियों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए सलाह लेनी चाहिए।

नए और अनुभवी दोनों तरह के महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए, मैं इस बात पर ज़ोर देता हूँ कि जहां रुचि और इरादा सराहनीय है, वहीं किसी कंपनी को लॉन्च करना और उसे बनाए रखना इससे कहीं ज़्यादा की मांग करता है। इसके लिए सोच-समझकर योजना बनाना, पहली पीढ़ी के उद्यमी के रूप में अपनी यात्रा से प्रेरणा लेते हुए समय के साथ अटूट प्रतिबद्धता और फंडिंग में रुकावट या विचार विकास जैसी चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन ज़रूरी है।

आज के स्टार्टअप अक्सर तेज़ी से मल्टी मिलियन या बिलियन डॉलर की सफलता का लक्ष्य रखते हैं, फिर भी ऐसी उपलब्धियां शायद ही कभी तुरंत मिलती हैं। अधिक से अधिक व्यक्तियों को उद्यमिता को अपनाते हुए देखना उत्साहजनक है, फिर भी सच्ची सफलता निरंतर प्रतिबद्धता, फ़ोकस और दृढ़ता पर निर्भर करती है। फंडिंग हासिल करना उद्यमी की यात्रा की शुरुआत भर है, उसका अंत नहीं। उद्यमियों को यह पहचानना चाहिए कि एक संपन्न उद्यम बनाने के लिए खुद को, निवेशकों, ग्राहकों और हितधारकों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है।

आप की बात

जल संकट से सबक

भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के लोगों को पानी की कटौती का भी सामना करना पड़ रहा है। अकेली दिल्ली ही नहीं, बैंगलोर व मुंबई सहित देश के सभी बड़े शहर गर्मियों में पानी की भारी कमी से जूझ रहे हैं। पड़ोसी राज्यों से नए जल समझौते करने की कोशिश की जा रही है, मगर उनके पास भी एक्स्ट्रा जल होगा तभी तो वह सप्लाई कर सकेगा। जल समस्या का असली निदान केवल राज्यों के बीच जल बंटवारे का उचित समझौता नहीं है। जल संचय के लिए मानसून में देशभर में महा-अभियान चलाना होगा। वर्षा की प्रत्येक बूंद को सहेजना होगा। बोतल में पानी बेचने वालों, कोल्ड ड्रिंक बनाने वालों तथा व्हीकल वॉशिंग सेंटरों पर नियंत्रण लगाना होगा। अधिकाधिक वृक्षारोपण करना होगा। इसमें प्रमुख भूमिका जनता को ही निभानी है। सरकार को इसके लिए आवश्यक संसाधन और मार्गदर्शन देना होगा। देश भर में हर जल स्त्रोत को पुनर्जीवित करना होगा तथा जल भराव के रास्तों में बनाए गए निर्माण में जल रोकने वाले हिस्से को हटाकर जलाशयों को पूरा भरने के इंतजाम करने होंगे। हर गर्मी में पानी की कमी का कष्ट भुगतने के बावजूद 99 प्रतिशत जनता जल संचय व वृक्षारोपण के प्रति कतई रुचि नहीं रखती है। इस स्थिति में भावी पीढ़ी को और अधिक जल संकट का सामना करना होगा।

-**सुभाष बुड़ावन वाला,** रतलाम

ईवीएम का जिन्न

स्वतन्त्र भारत के इतिहास में सत्ता के लिए ऐसी तड़प शायद ही कभी देखने को मिली हो जैसी गत लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद विपक्षी दलों की देखने को मिल रही है। हर चुनाव से पहले विपक्षी दल ईवीएम का रोना रोते हैं, जिससे विपरीत परिणाम आने पर वे हार का ठीकरा ईवीएम और चुनाव आयोग पर फोड़ सकें। अनुकूल परिणाम आने पर ईवीएम का जिन्न फिर बोतल में बंद हो जाता है या फिर ईवीएम ठीक हो जाती है। इस बार भी तीन जून तक विपक्षी दलों ने ईवीएम मुद्दा जीवित रखा, पर परिणाम आते ही ईवीएम मुद्दा गायब हो गया और चुनाव आयोग ने भी राहत की सांस ली। किन्तु एलन मस्क के बयान से ईवीएम का जिन्न फिर बोतल से बाहर आ गया। उनका बयान अमेरिका की ईवीएम के संदर्भ में था किन्तु भारत के विपक्षी दलों के लिए तो यह मानो संजीवनी बन गया। अमेरिकी और भारतीय ईवीएम में तकनीकी अन्तर यह है कि भारतीय ईवीएम इन्टरनेट से कनेक्ट नहीं हैं। जिससे उसमें कोई धांधली नहीं हो सकती है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष को अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और इंजीनियरों से अधिक विदेशियों पर अधिक विश्वास है। यह देश का अपमान है।

- **नरेन्द्र टोंक,** मेरठ

भारत और इंडिया

आजकल यह बेतुकी बहस सुनने को मिलती रहती है कि हमें अब भारत शब्द का ही उपयोग करना चाहिए एवं इंडिया को भुला देना चाहिए। लेकिन हजारों साल से भारतवर्ष को इंडिया शब्द कहा जाता रहा है और संविधान भी इसका प्रयोग करता है। अत: भारत बनाम इंडिया को बहस का मुद्दा बनाना निरर्थक है। हमारे इतिहास की पुस्तकों में भी भारत को इंडिया कहा गया था। एनसीईआरटी के निदेशक का कहना है चूंकि इंडिया शब्द का उपयोग हमारे प्राचीन काल से चला आ रहा है, अत: इसे देखते हुए एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में भी भारत एवं इंडिया, दोनों शब्दों का परस्पर प्रयोग किया जाता रहा है। इसे आगे भी बदला नहीं जाएगा एवं पूर्व की तरह दोनों शब्दों का प्रयोग जारी रहेगा। वैसे धीरे-धीरे इंडिया के स्थान पर भारत प्रचलन में आ सकता है और देशवासियों के साथ विदेशी भी इसके अभ्यस्त हो सकते हैं। यह भारत के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय कद तथा खासकर उसकी आर्थिक शक्ति पर भी निर्भर करता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में सरकार बनने के बाद से ही अनेक स्थानों पर भारत के प्रयोग को बढ़ावा दिया है। भारत और इंडिया, दोनों ही हमारी राष्ट्रीय शक्ति, संपन्नता और वैश्विक बिरादरी में सम्मान के प्रतीक हैं।

-**मनमोहन राजावत,** शाजापुर

ट्रेन दुर्घटनायें

कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन में पीछे से मालगाड़ी की टक्कर से नौ से अधिक यात्रियों की मौत हो गई व 40 से अधिक घायल हो गए। 2 जून, 2023 को उड़ीसा में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे में 300 से अधिक यात्री असमय मौत का शिकार हुए थे और लगभग 900 से अधिक घायल हुए थे। दुनिया में भारतीय रेलवे का नेटवर्क चौथे स्थान पर है। 64 हजार किलोमीटर के दायरे में पटरियां बिछीं है, जिस पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री व मालगाड़ियां फेरे लगातीं हैं। रेलवे को प्राकृतिक घटनाओं, जैसे, बारिश, भूस्खलन, धुंध, आदि कारणों से होने वाले हादसों के साथ मानवीय लापरवाहियों के चलते होने वाले हादसों पर लगाम लगाने हेतु विशेष ध्यान देना चाहिए। ट्रेनों में दुर्घटनायें रोकने को प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। ट्रेन दुर्घटनायें रोकने में तकनीकी उपकरण सहायक हो सकते हैं और प्रमुख भूमिका भी निभा सकते हैं। लेकिन रेलवे में सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी और जवाबदेही वाले इंजीनियरों व दक्ष श्रमिकों की आवश्यक भर्ती भी जरूरी है। कर्मियों द्वारा नियम तोड़ने पर कठोर सजा मिलनी चाहिए।

- **हेमा हरि उपाध्याय,** उज्जैन

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

कल्पमेधा

जिस विद्या में कर्म की शक्ति नहीं, स्वतंत्र रूप से सोचने की बुद्धि नहीं, खतरा उठाने की प्रवृत्ति नहीं, वह विद्या निस्तेज है।

– विनोबा भावे

आतंक का सम्मान

यह समझना मुश्किल है कि कनाडा आखिर भारत के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहता है। इटली में आयोजित जी-7 के शिखर सम्मेलन में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारतीय प्रधानमंत्री से मिले तो कहा कि भारत के साथ कनाडा का कई मामलों में बेहतर तालमेल है और नई सरकार के साथ बातचीत आगे बढ़ाने का अवसर दिखाई दे रहा है। मगर वहां से लौटते ही उनका रुख बदल गया। खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की बरसी पर वहां की संसद में एक मिनट का मौन रखा गया। पिछले वर्ष कनाडा में निज्जर की हत्या कर दी गई थी। तब कनाडा सरकार ने आरोप लगाया था कि उसकी हत्या में भारतीय अधिकारी शामिल थे। हालांकि वह अभी तक इसका कोई सबूत नहीं पेश कर सका है। उसके बाद से कई जगहों पर खालिस्तानी अलगाववादियों ने भारत के खिलाफ उकसाने वाली गतिविधियां चलाईं, भारत की तरफ से उन पर सख्त कदम उठाने की अपील की गई, मगर कनाडा सरकार उन पर चुप्पी साधे रही। अब निज्जर की बरसी पर संसद में मौन रखने का प्रकरण एक तरह से भारत को उकसाने का नया प्रयास है।

यह हैरानी की बात है कि निज्जर आखिर कनाडा सरकार को इतना प्रिय क्यों हो गया। आमतौर पर किसी देश की संसद में राष्ट्र के किसी सम्मानित व्यक्ति, किसी हादसे, जनसंहार या युद्ध में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि निज्जर की गतिविधियों को लेकर कनाडा सरकार अनजान हो। भारत ने उसे आतंकवादियों की सूची में डाल रखा था। आतंकवाद के खिलाफ भारत की कटिबद्धता भी कनाडा से छिपी नहीं है। फिर भी कनाडा सरकार निज्जर की हत्या को इतना तूल दे रही है, तो इससे यही जाहिर होता है कि न तो वह आतंकवाद पर अंकुश लगाने को लेकर गंभीर है और न भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाने को लेकर। अगर ट्रूडो सरकार भारत के साथ बातचीत आगे बढ़ाने की इच्छुक होती, तो निज्जर को इतना महत्त्व न देती कि संसद में उसे श्रद्धांजलि दी जाती। यह तो स्पष्ट है कि इस तरह निज्जर को महत्त्व देकर ट्रूडो वहां रह रहे सिख समुदाय का जनाधार अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कुछ लाभ शायद इस चुनाव में उनकी पार्टी को मिल भी जाए, मगर इससे भारत के साथ जो रिश्ते खराब हो रहे हैं, उसकी भरपाई आसान नहीं होगी।

अलग खालिस्तान की मांग को लेकर चलाई जा रही हिंसक मुहिम से कनाडा सरकार अनजान नहीं है और न वह इस बात से बेखबर है कि किसी भी देश में चलाई जाने वाली कोई भी अलगाववादी गतिविधि दहशतगर्दी के दायरे में आती है। पंजाब के लोग खुद अलग राज्य का मुद्दा नहीं उठाते, मगर कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया आदि देशों में जाकर बस गए और वहां की नागरिकता ले चुके कुछ लोग इसे लेकर उपद्रव करते देखे जाते हैं, तो उन पर अंकुश लगाने में मदद करने के बजाय अगर वहां की सरकारें उन्हें प्रश्रय देती हैं, तो इसे किसी भी रूप में स्वस्थ कूटनीति नहीं कहा जा सकता। इससे आतंकवादियों का मनोबल बढ़ता है और आखिरकार इसका खमियाजा किसी एक देश को नहीं, सारी दुनिया को भुगतना पड़ता है। कनाडा सरकार के जवाब में भारत ने कनिष्क विमान हादसे की बरसी मनाने का फैसला किया है। ऐसे तनातनी वाले वातावरण से आखिरकार नुकसान कनाडा को ही अधिक होगा।

हिंसा का मानस

पढ़ाई-लिखाई का स्तर ऊंचा उठने, खानपान, फैशन, रहन-सहन आदि मामलों में आधुनिकता बोध पैदा होने के बावजूद स्त्रियों को लेकर भारतीय समाज में पुरुषवादी सत्ता शिथिल नहीं हो पाई है। इसी का नतीजा है कि स्त्रियों के खिलाफ अपराध हर बार बढ़े हुए ही दर्ज होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के पास इस वर्ष अभी तक बारह हजार छह सौ शिकायतें पहुंचीं, जिनमें से ज्यादातर गरिमा के साथ जीने के अधिकार को ध्वस्त करने से संबंधित थीं। उनमें घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, छेड़छाड़, पीछा करने, यौन उत्पीड़न, बलात्कार तथा बलात्कार की कोशिशों की शिकायतें दर्ज कराई गईं। इनमें पांच सौ अठारह शिकायतें ऐसे मामलों में पुलिस की उदासीनता को लेकर भी दर्ज कराई गईं। सबसे अधिक शिकायतें उत्तर प्रदेश से आईं। इससे एक बार फिर तमाम जागरूकता अभियानों, स्त्री और पुरुष में बराबरी की कोशिशों, स्त्री सुरक्षा के उपायों आदि के दावों पर प्रश्नचिह्न लगे हैं। उत्तर प्रदेश में स्त्री सुरक्षा के दावे सबसे ज्यादा बढ़-चढ़ कर किए जाते हैं, मगर स्त्री पर हिंसा की सबसे अधिक शिकायतें वहीं से मिली हैं।

दरअसल, स्त्रियों के प्रति अत्याचार का सिलसिला इसलिए नहीं रुकने पा रहा कि आम भारतीय समाज उन्हें सम्मान की नजर से देखता ही नहीं। बेशक कुछ परिवारों में लड़कियों को पढ़ाई-लिखाई, नौकरियों और रोजगार वगैरह में प्रोत्साहन दिया जाने लगा है, मगर विडंबना है कि शिक्षित और नौकरीशुदा महिलाएं भी प्रताड़ना से मुक्त नहीं हो पाई हैं। ऐसी महिलाओं को पुरुष मानसिकता के अलग दुश्चक्र से गुजरना पड़ता है। घरेलू वातावरण में पुरुषवादी अहं का टकराव बड़ी आसानी से हिंसा में परिणत हो जाता है। रोजगार की जगहों पर यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न का जटिल घेरा है, तो समाज के विभिन्न स्तरों पर उसकी आजादी और गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रश्नांकित होते रहते हैं। महिला आयोग जरूर स्त्रियों के खिलाफ हो रहे इन अमानवीय व्यवहारों को लेकर कुछ सख्त कदम उठाते देखे जाते हैं, पर जब शासन के स्तर पर भी महिलाओं को लेकर संकीर्ण नजरिया बना हुआ है, तो उन्हें कितना न्याय मिल पाता होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। जब तक स्त्री को लेकर समाज का मानस नहीं बदलेगा, उसके खिलाफ हिंसा नहीं रुकेगी।

विकास में बाधक लैंगिक भेदभाव

यह ठीक है कि इस दौर में बेटियों को लेकर समाज की सोच बदल रही है, परिवार बेटियों के पालन-पोषण और शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के सामूहिक मन में बेटियों को लेकर एक अजीब-सी नकारात्मकता है।

रोहित कौशिक

विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत दो पायदान नीचे खिसककर 129वें स्थान पर पहुंच गया। इस सूचकांक में भारत पड़ोसी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के बाद पांचवें स्थान पर है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा में नामांकन के मामले में भारत ने सबसे अच्छी लैंगिक समानता प्रकट की है। आर्थिक भागीदारी और अवसर मापदंडों में भी हल्का सुधार हुआ है। आर्थिक समानता अंक पिछले चार वर्षों में ऊपर की ओर बढ़ा है। विश्व आर्थिक मंच के अनुसार विश्व ने लैंगिक असमानता को 68.5 फीसद तक कम कर दिया है, लेकिन वर्तमान गति से पूर्ण लैंगिक समानता प्राप्त करने में 134 वर्ष का समय लगेगा। इस रपट में भारत के संदर्भ में लैंगिक अंतर सूचकांक की बात छोड़ दें तो भी यह किसी से छिपा नहीं है कि इस प्रगतिशील दौर में भी महिलाओं को कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हम उन्हें जरूरी सुरक्षा व्यवस्था तक उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। एक तरफ महिलाएं सफलता की नई कहानियां लिख रही हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि दूसरी तरफ उन पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यह विचार का विषय है कि महिलाओं के संदर्भ में बड़ी-बड़ी बातें करने वाला यह समाज इस मुद्दे पर खोखला आदर्शवाद क्यों अपना लेता है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अभी तक महिलाओं को सम्मान देना नहीं सीख पाए हैं, लेकिन महिलाएं हमारे इस व्यवहार से बेपरवाह हमें सम्मान देने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। हमारे देश की बेटियों ने यह कई बार सिद्ध किया है कि अगर उन्हें प्रोत्साहन और सम्मान दिया जाए तो वे हमारे देश को अंतरराष्ट्रीय फलक पर एक नई पहचान दिला सकती हैं। मगर हमारे समाज में आजादी के इतने वर्षों बाद भी बेटियां वह सम्मान प्राप्त नहीं कर पाईं, जिसकी वे हकदार हैं। यह ठीक है कि इस दौर में बेटियों को लेकर समाज की सोच बदल रही है, परिवार बेटियों के पालन-पोषण और शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हमारे समाज के सामूहिक मन में बेटियों को लेकर एक अजीब-सी नकारात्मकता है। समाज की यह नकारात्मकता लड़कियों के आत्मविश्वास को कम करती है। जो लड़कियां इस नकारात्मकता को चुनौती के रूप में लेती हैं वे एक न एक दिन सफलता का परचम जरूर लहराती हैं।

यह विडंबना ही है कि शिक्षित होने के बावजूद हम अभी आत्मिक रूप से विकास नहीं कर पाए हैं। पितृसत्तात्मक समाज में लड़कियों को रोज नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस दौर में हमारे समाज के एक छोटे से तबके में लड़कियों को पूरी छूट दी जाने लगी है, लेकिन यहां उनकी चुनौतियां अलग तरह की होती हैं। कुल मिलाकर पितृसत्तात्मक समाज लड़कियों के लिए अनेक तरह के अवरोध खड़े कर रहा है। यह समाज इन अवरोधों के समर्थन में अलग तरह के तर्क गढ़ता है। यह जानते हुए भी कि इन तर्कों का कोई आधार नहीं है, यह समाज इन तर्कों को नियमों की तरह लड़कियों पर लादता है। जब हम इन आधारहीन नियमों को सिर्फ लड़कियों पर लादते हैं, तो एक तरह से हम पितृसत्ता को पुनः प्रतिष्ठापित करते हैं। इक्कीसवीं सदी में भी अगर लड़कियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करने पर ताने सुनने पड़ें तो हमें यह सोचना होगा कि हमारी प्रगतिशीलता में कहां कमी रह गई है?

> **केवल खोखले आदर्शों वाली बड़ी-बड़ी बातें करने से समाज में प्रगतिशीलता नहीं आती है। प्रगतिशील बनने के लिए हमें बहुत-सी सड़ी-गली परंपराओं को तोड़ना, त्यागना पड़ता है। केवल डिग्रियां बटोरकर शिक्षित हो जाना ही समाज की प्रगतिशीलता का पैमाना नहीं है। शिक्षा ग्रहण कर समाज के हर वर्ग के उत्थान में उसका उपयोग करना ही सच्ची प्रगतिशीलता है। इस दौर में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या हम लड़कियों और महिलाओं के संदर्भ में सच्चे अर्थों में प्रगतिशील हैं? क्या लड़कियों को पढ़ाना-लिखाना और आधुनिक परिधान पहनने की अनुमति देना ही प्रगतिशीलता है?**

केवल खोखले आदर्शों वाली बड़ी-बड़ी बातें करने से समाज में प्रगतिशीलता नहीं आती है। प्रगतिशील बनने के लिए हमें बहुत-सी सड़ी-गली परंपराओं को तोड़ना, त्यागना पड़ता है। केवल डिग्रियां बटोरकर शिक्षित हो जाना ही समाज की प्रगतिशीलता का पैमाना नहीं है। शिक्षा ग्रहण कर समाज के हर वर्ग के उत्थान में उसका उपयोग करना ही सच्ची प्रगतिशीलता है। इस दौर में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या हम लड़कियों और महिलाओं के संदर्भ में सच्चे अर्थों में प्रगतिशील हैं? क्या लड़कियों को पढ़ाना-लिखाना और आधुनिक परिधान पहनने की अनुमति देना ही प्रगतिशीलता है? दरअसल, हम प्रगतिशीलता का अर्थ बहुत संकुचित कर देते हैं। इक्कीसवीं सदी में भी अगर हम लड़कियों की रक्षा नहीं कर सकते तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता।

दुर्भाग्यपूर्ण है कि खेल आदि अपनी रुचि के विषयों में भी लड़कियों को अनेक स्तरों पर चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। छोटी उम्र में अनेक लड़कियों को समाज के डर से अपने शौक की कुर्बानी देनी पड़ती है। इसीलिए हमारे देश में बहुत सारी महिला प्रतिभाएं जन्म ही नहीं ले पाती हैं या फिर असमय दम तोड़ देती हैं। जो महिला प्रतिभाएं परिवार के प्रोत्साहन से खेलों की तरफ रुख करती है, उन्हें भी अनेक पापड़ बेलने पड़ते हैं।

खेल जगत में भी महिला खिलाड़ियों को पग-पग पर पितृसत्ता की चुनौती झेलनी पड़ती है और बार-बार महिला होने का खमियाजा भुगतना पड़ता है। कुछ समय पहले महिला खिलाड़ियों के शोषण की घटनाएं प्रकाश में आई थीं। कई बार ऐसी घटनाएं प्रकाश में नहीं आ पाती हैं और खिलाड़ियों को ताउम्र यह दर्द झेलना पड़ता है। ऐसी घटनाओं और ऐसे वातावरण को देखकर अक्सर परिवारों का मनोबल भी टूट जाता है और वे अपनी बेटियों को खेल के क्षेत्र में भेजने से कतराने लगते हैं। रही-सही कसर खेल जगत में पसरी राजनीति पूरी कर देती है।

विडंबना यह है कि एक तरफ बेटियां खेलों में पसरी राजनीति से जूझती हैं, तो दूसरी तरफ समाज में पसरी राजनीति उनकी राह में कांटे बिछा देती है। बेटियों और महिलाओं के खिलाफ समाज में पसरी यह राजनीति आखिरकार सामाजिक विकास को पीछे धकेलती है। फलस्वरूप, बेटों और बेटियों में अनेक स्तरों पर एक अंतर बना रहता है। यह अंतर विद्यमान रहना दुर्भाग्यपूर्ण है।

इस दौर में भी बेटियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध की बढ़ती घटनाएं और उन पर घर के भीतर और बाहर लगातार हो रहे हमले इस बात का प्रमाण हैं कि हम आज भी अपनी सोच नहीं बदल पाए हैं। इस तथ्य को गलत सिद्ध करने के लिए यह कहा जा सकता है कि सारा समाज ऐसा नहीं है, लेकिन वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तमाम उदाहरण हैं, जिनसे बार-बार यह बात सामने आती है कि हमारी सोच में कोई न कोई खोट जरूर है। सुखद यह है कि इस माहौल में भी लड़कियों और महिलाओं के हौसले बुलंद हैं और वे लगातार सफलता की नई कहानियां लिख रही हैं। अब जरूरत इस बात की है कि हम लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाएं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि इस दौर में लैंगिक भेदभाव हमारे समाज पर काले धब्बे की तरह है।

समय का मोल

दुनिया मेरे आगे

अतुल चतुर्वेदी

संसार में समय का महत्त्व बहुत से लोग जानते हैं। अक्सर बुजुर्ग और अनुभवी लोग, जिन्होंने स्वयं जवानी में काफी समय बर्बाद किया होता है, अपना उदाहरण देते हुए समय की उपयोगिता का उपदेश देते हैं, लेकिन कोई भी उदाहरण तब तक प्रभावी नहीं होता, जब तक आप उसको अपनाकर उदाहरण पेश न करें। आज की युवा पीढ़ी ही नहीं, घर की महिलाओं और बुजुर्गों के पास समय व्यतीत करने और वक्त काटने के कई संसाधन मौजूद हैं। हालांकि यह सब संसाधन समय की बर्बादी के अस्त्र-शस्त्र ही हैं। मोबाइल या कंप्यूटर पर निरुद्देश्य कुछ न कुछ खोजते या देखते रहना, ओटीटी चैनलों या वेबसाइटों और अन्य टीवी चैनलों पर कार्यक्रम, मोबाइल पर गेम की लत आदि ऐसे ही समय खपाने वाले साधन हो चुके हैं।

समय को गंवाना दरअसल जीवन के उन अवसरों को गंवाना है जो आपका भविष्य पलट सकते हैं। समय वह मूल्यवान संपत्ति है, जिसे गंवाने के बाद पूर्ति हम कभी भी नहीं कर सकते। विदेश में समय की पाबंदी पर बहुत महत्त्व दिया जाता है, जबकि हमारे देश में समय पर किसी काम को पूरा करने, कहीं पहुंचने को लेकर एक प्रकार की उदासीनता पाई जाती है। समय को लेकर आमतौर पर लापरवाही का बर्ताव देखा जाता है। अमूमन बैठकों या मीटिंग में देर से पहुंचना और काम को समय पर पूरा न करना सामान्य आदतें हैं, जो कर्मचारियों में देखी जा सकती हैं। सरकारों का रवैया भी इस संदर्भ में बहुत उपेक्षा से भरा हुआ है। जन सामान्य में कहावत है कि आखिर सरकारी काम है। सरकारी काम के बारे में माना जाता है कि चलताऊ रवैया और धीमी गति। ऐसे आरोप आम रहे हैं कि सुबह का मूल्यवान समय आमतौर पर कर्मचारी बातचीत, चाय-पानी और अखबार पढ़ने में व्यतीत कर देते हैं। हालांकि ऐसे कर्मचारियों के बीच ही कई लोग बेहद कर्मठ भी होते हैं।

> **समय परिवर्तनशील है। वह बदलता रहता है। मगर समय उनका ही बदलता है, जो इसको कर्म की ताकत से बदलने की चाहत रखते हैं। हाथ पर हाथ धरे भाग्यवादियों का समय कभी नहीं बदलता। समय को बदलने के लिए साहस भी चाहिए और दृढ़ संकल्प शक्ति भी।**

समय को बचाने के लिए कई पुस्तकें 'टाइम मैनेजमेंट' यानी वक्त का प्रबंधन पर लिखी गई हैं। समय प्रबंधन के लिए कुछ लोग सलाह देते रहे हैं। मसलन समय को बचाने के लिए हमें पहले से ही रूपरेखा बना लेनी चाहिए। एक रात पहले ही सुबह संपन्न किए जाने वाले कार्यों की सूची बना लेनी चाहिए। एक-सी प्रकृति के कार्य एक साथ कर लेने चाहिए। जिस बहुउद्देश्यीय या बहुआयामी काम को कारपोरेट जगत में बहुत उपयोगी और अनिवार्य माना जाता है, उसको लेकर कुछ विद्वान नकारात्मक विचार रखते हैं। कई काम एक साथ करना व्यक्ति को एक चीज पर केंद्रित नहीं रहने देती और इससे उसकी एकाग्रता में कमी आती है। इससे हम लंबे और गंभीर काम नहीं कर सकते हैं। इस तरह एक साथ कई काम करने से विचार करने और सोचने-समझने की क्षमता या आइक्यू भी कम होता है।

समय की बर्बादी को कम करना है तो हमें फोन पर भी संक्षिप्त बातचीत करनी चाहिए। सीधे बातचीत के मूल मुद्दे पर आना चाहिए, न कि एक छोटी बात कहने के लिए लंबी भूमिका बनाते रहें। ध्यान रखने की जरूरत है कि दुनिया उनका ही ध्यान रखती है जो अपने समय का ध्यान रखते हैं और समय कभी सबका एक तरह नहीं रहता। कहा जाता है कि एक वक्त के बाद किसी के भी दिन फिरते हैं। तो क्या नैनो सेकंड की गणना करने वाली दुनिया में हमारे पास इतना समय है कि हम दस या बारह वर्ष या इससे ज्यादा का इंतजार किस्मत के भरोसे करते रहें। कवि मैथिलीशरण गुप्त ने लिखा था- 'संसार में किसका समय है एक-सा रहता सदा, हैं निशि-दिवा-सी घूमती सर्वत्र विपदा-संपदा।' यानी समय परिवर्तनशील है। वह बदलता रहता है। मगर समय उनका ही बदलता है जो इसको कर्म की ताकत से बदलने की चाहत रखते हैं। हाथ पर हाथ धरे भाग्यवादियों का समय कभी नहीं बदलता। समय को बदलने के लिए साहस भी चाहिए और दृढ़ संकल्प शक्ति भी। नियम और अनुशासन भी चाहिए।

इससे संबंधित एक अहम पहलू यह है कि समय के महत्त्व को न केवल हमें समझना होगा, बल्कि दूसरे के समय की कीमत भी पहचाननी होगी। कामकाजी पेशेवर, चिकित्सक, कलाकार और वकील आदि के पास समय की बहुत कमी होती है और इसे हमें व्यस्तता का अभिनय नहीं, उसकी मजबूरी समझ कर सम्मान करना चाहिए। हम जीवन का बहुत-सा हिस्सा व्यर्थ की बातों में गप्पें मारने, सोने और आलस में बर्बाद कर देते हैं। समय की अहमियत तब समझ में आती है, जब कुछ पल की देरी की वजह से हम कई बेहद अहम अवसर चूक जाते हैं। याद कर सकते हैं किसी खिलाड़ी के सेकंड के सौवें हिस्से से किसी पदक से चूक जाना। यह सब समय की महत्ता के उदाहरण हैं।

समय की वाणी और नब्ज की समझ भी सबको होनी चाहिए। उचित अवसर देख कर अपनी बात कहनी चाहिए। रहीम ने लिखा है- 'अब दादुर वक्ता भए हमें पूछिए कौन?' समय की यह समझ भी जरूरी है आजकल। समय ही है जो इंसान को महान और रंक दोनों बनाता है। कुछ लोग जब सफल नहीं होते हैं तो परिस्थितियों को कोसते रहते हैं। जबकि अपने समय प्रबंधन को ठीक करने की जरूरत है। हम समय को मुट्ठी में करें, उस पर राज करें, न कि उसके गुलाम बनें। उसके लिए हमें कामों को तेजी से निपटाना होगा। योजनाबद्ध काम करने होंगे।

संभावनाओं के द्वार

यह डिजिटल युग है और हर चीज दिन-प्रतिदिन डिजिटल होती जा रही है। संचार के क्षेत्र में भी डिजिटलीकरण का बड़ा प्रभाव देखा जा रहा है। इसमें ओटीटी मंचों की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे कई कारण हैं। दरअसल, यह लचीला और सुविधाजनक है। यह प्रयोक्ताओं को विभिन्न विकल्प प्रदान करता है और वे अपनी पसंद के अनुसार सामग्री चुन सकते हैं। तीसरा, यह अधिक किफायती है, क्योंकि इनकी सदस्यता लेने की लागत केबल टीवी की तुलना में काफी कम है। हालांकि, ओटीटी मंचों की बढ़ती लोकप्रियता का मतलब यह नहीं है कि पारंपरिक मीडिया समाप्त हो गया है। टेलीविजन अभी भी लोकप्रिय है और कुछ लोग अभी भी अखबार-पत्रिकाएं पढ़ना पसंद करते हैं। हम कह सकते हैं कि नया मीडिया और ओटीटी मंच मनोरंजन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। वे न केवल लोगों को उच्च गुणवत्ता वाला मनोरंजन प्रदान कर रहे हैं, बल्कि फिल्म और टेलीविजन कलाकारों के लिए भी नई संभावनाओं का द्वार खोल रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में नया मीडिया और ओटीटी मंच किस तरह विकसित होते हैं और वे हमारे मनोरंजन के अनुभव को कैसे और अधिक बेहतर बनाते हैं।

– चंदन कुमार नाथ, बरपेटा, असम

आतंक के पांव

इन दिनों जम्मू-कश्मीर अशांत है। आतंकी आम नागरिकों और पुलिस, सेना के जवानों को अपना निशाना बना रहे हैं। हाल ही में तीर्थयात्रियों की बस पर हमला कर नौ श्रद्धालुओं को मार डाला। सुरक्षा बल के जवान व पुलिस वालों पर आए दिन हमले हो रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, मगर पाक से प्रशिक्षित ये आतंकी किस रास्ते से घाटी में घुस रहे हैं? उन घुसपैठ के रास्तों को खोज कर, वहीं पर क्यों नहीं उन्हें रोक दिया जाता है? स्थानीय लोगों में से भी कुछ लोग दिग्भ्रमित होकर आतंकियों का साथ देने की कोशिश करते हैं। बिना किसी मजबूत संरक्षण के इतने बड़े हमले संभव नहीं हैं। चाहे जो भी हो केंद्र सरकार को इस नासूर को खत्म करने के लिए सख्त कार्रवाई करने से गुरेज नहीं करना चाहिए। नागरिकों और सुरक्षा बल के जवानों की बेशकीमती जान की रक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

– हेमा हरि उपाध्याय 'अक्षत', उज्जैन

प्रदूषण का कहर

'प्रदूषण का प्रहार झेलती महिलाएं' (लेख, 15 जून) पढ़ा। इसमें प्रदूषण को महिला केंद्रित करके देखा गया है। आमतौर पर अक्सर महिलाओं को हर कार्य, समस्या आदि में नगण्य समझा जाता रहा। इसका असर घर से बाहर, सभी मोर्चों पर देखा गया। घर में परिवार का खाना बनाने से लेकर कई बार पशुओं की देखरेख का काम भी महिलाएं संभालती हैं। इस क्रम में वे कई स्तर पर प्रदूषण की मार झेलती हैं। मगर आज महिलाओं ने ही स्वयं की चिंता करते हुए परिवर्तन का बीड़ा उठाया है। इस संबंध में जो भी काम किए जा रहे हैं, उनकी गंभीरता समझी जा सकती है। महिलाओं की चिंता और मुद्दे पर सख्ती से काम करना दो अलग पहलू हैं। अगर धरातल पर उतरकर सच्चाई के साथ काम किया जाए, तो निश्चित ही प्रदूषण से छुटकारा पाया जा सकता है। सभी जीवों को प्रभावित करता है। बच्चों और बुजुर्गों को जल्दी प्रभावित करता है।

– इंदु मणि, जयपुर

नकल का रोग

पिछले कुछ वर्षों से प्रतियोगितात्मक और उच्च परीक्षाओं में धांधली की खबरों ने कई परीक्षाओं को अविश्वसनीय बना दिया है। यह गंभीर विषय है, जिसमें न केवल राज्य या केंद्र सरकार दोषी है, बल्कि परीक्षार्थी से लेकर अभिभावक, शिक्षा माफिया और कोचिंग संस्थान तक के कुछ लोग दोषी हैं। हाल में नीट की परीक्षा का मामला सामने है, जिसमें परीक्षा समिति पर अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं। सरकार भी संदेह के घेरे में आती है। नीट की परीक्षा में भविष्य के चिकित्सक बैठते हैं। अगर इसमें अयोग्य विद्यार्थियों का चयन होगा तो सहज ही समझा जा सकता है कि समाज का स्वास्थ्य और जीवन कैसे हाथों में सौंपा जा रहा है। इन परीक्षाओं की शुचिता को बनाए रखने के लिए शासन-प्रशासन दोनों को ही कठोरतम कदम उठाने होंगे, ताकि परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनी रहे और योग्यता व प्रतिभा कुंठित न हो।

– नरेंद्र टोंक, मेरठ

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। गुरुवार, 20 जून 2024

तानाशाहों का गठजोड़

24 साल के अंतराल के बाद हुई रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन की उत्तर कोरिया यात्रा ने न सिर्फ चौंकाया है बल्कि अंतरराष्ट्रीय हलकों में चिंता भी बढ़ाई है। इस यात्रा से दोनों देशों की करीबी बढ़ने के स्पष्ट संकेत मिले ही हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि इस करीबी से किस तरह के तात्कालिक और दूरगामी नतीजे सामने आ सकते हैं।

यात्रा की टाइमिंग | पूतिन की यह यात्रा अंतरराष्ट्रीय हलकों में बन रही इस धारणा को गलत साबित करने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है कि वह विश्व मंच पर अलग-थलग पड़ते जा रहे हैं। यात्रा ऐसे समय हुई है, जब कुछ ही दिन पहले इटली में G7 देशों की शिखर बैठक हुई और उसके बाद स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति सम्मेलन में 80 देशों ने साझा बयान के रूप में किए गए शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। हालांकि भारत अपने स्वतंत्र और संतुलित रुख को बरकरार रखते हुए उस प्रस्ताव से अलग रहा।

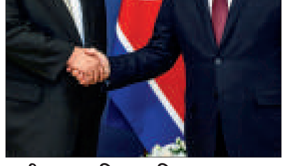

करीब आए किम-पूतिन

स्ट्रैटिजिक पार्टनरशिप | उत्तर कोरिया पहुंचने पर पूतिन का जैसा भावपूर्ण स्वागत हुआ और जिस तरह से किम जोंग उन खुद एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के बाद उनके साथ एक ही गाड़ी में गेस्ट हाउस गए, उसे देखते हुए साफ है कि दोनों तरफ से आपसी करीबी को रेखांकित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। यूक्रेन युद्ध जिस तरह से लंबा खिंचता दिख रहा है उसमें उत्तर कोरिया के सहयोग की रूस को सख्त जरूरत भी है। हालांकि दोनों पक्ष हथियारों के आदान-प्रदान की खबरों का खंडन करते हैं, लेकिन दोनों ने कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटिजिक पार्टनरशिप समझौता किया है जिसमें पूतिन के ही मुताबिक किसी भी एक देश पर हमला होने की सूरत में 'द्विपक्षीय सहयोग' का वादा है।

रुख में बदलाव | लंबे समय से विश्व मंच पर अलगाव झेल रहे उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन के लिए भी रूस की करीबी काफी मायने रखती है। अतीत में रूस नॉर्थ कोरिया के अवैध हथियार कार्यक्रम की संयुक्त राष्ट्र समर्थित जांच और उस पर लगे प्रतिबंधों का समर्थन कर चुका है। लेकिन यूक्रेन युद्ध से उपजी जरूरतों और पश्चिमी देशों से बढ़ती दूरी के मद्देनजर उसके रुख में बदलाव आया है। मार्च में नॉर्थ कोरिया द्वारा सुरक्षा परिषद प्रतिबंधों के उल्लंघन की स्वतंत्र जांच से जुड़े प्रस्ताव को रूस ने वीटो कर दिया।

किम के मंसूबे | ऐसे में रूस की ओर से मिलने वाली तकनीकी सहायता उत्तर कोरियाई तानाशाह के मंसूबों को कैसी दिशा देगी, यह सवाल सबके मन को मथ रहा है। ध्यान रहे, अब तक चीन उत्तर कोरिया के समर्थन में खड़ा नजर आने वाला एकमात्र प्रमुख देश रहा है। हालात की मजबूरियों में ही सही, पर तानाशाहों का जैसा गठजोड़ उभरता दिख रहा है, उस पर सतर्क नजर रखने की जरूरत है।

साड्डी दिल्ली

गुरुद्वारे का खास नाम

विवेक शुक्ला

अगर आप देशबंधु गुप्ता रोड या करोलबाग की गलियां नाप चुके हैं, तब आपने इस गुरुद्वारे को अवश्य देखा होगा। नाम है गुरुद्वारा रिफ्यूजी सिंह सभा। इसे उन लोगों ने बनाया, जो देश के बंटवारे के बाद राजधानी में अपना सब कुछ गंवाकर आए थे। उस दिन गुरुद्वारा रिफ्यूजी सिंह सभा के बाहर सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर छबील लगी थी। वहां कुलबीर सिंह मिले। उनका सारा बचपन और जवानी इसी गुरुद्वारे के पीछे गुजरी। बताने लगे कि गुजरांवाला, लाहौर, मियांवाली वगैरह से यहां आकर बसे सिखों और हिंदुओं ने इसे बनवाया था। ये सब करोलबाग, अजमल खान रोड, आनंद पर्वत आदि में रहते थे। जब इस गुरुद्वारे का नाम रखने का सवाल उठा, तो इसके हजूर सिंह, हरनाम सिंह चावला, ज्ञानी आसा सिंह जैसे संस्थापकों की एक राय थी कि इसके नाम में रिफ्यूजी शब्द आए। 1950 में जब यह बना, तब देशबंधु रोड को ओरिजिनल रोड कहा जाता था। इस बीच, दुनिया आज (20 जून) वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मना रही है। बंगाली मार्केट से चंद कदमों की दूरी पर स्थित रिफ्यूजी मार्केट में शायद इसकी किसी को जानकारी नहीं है। इधर, दुकानें 1950 के दशक में शरणार्थी परिवारों को आवंटित हुईं थीं। वक्त बदला और बहुत सी दुकानें और उनके मालिक बदल गए। पर मनचंदा बुक स्टोर और इसके मालिक मनचंदा जी अब भी आबाद हैं। मनचंदा जी 80 वसंत देख चुके हैं। बाबर रोड की रिफ्यूजी मार्केट एकमात्र इस तरह की मार्केट है, जिसके नाम में ही रिफ्यूजी आता है। वैसे खान मार्केट, कमला मार्केट, खन्ना मार्केट, गफ्फार मार्केट, मेहरचंद मार्केट वगैरह भी शरणार्थियों के लिए बनाई गई थीं। लोधी रोड की खन्ना मार्केट और मेहरचंद मार्केट के क्या कहने। इन दोनों का नाम रखा गया था केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मेहर चंद खन्ना के नाम पर। खन्ना साहब पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत (अब खैबर-पख्तूनख्वा) में खान अब्दुल जब्बार खान की कैबिनेट में थे, जिनके नाम पर खान मार्केट स्थापित हुई थी। अब इन सबमें शरणार्थियों की दूसरी-तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। तिब्बती शरणार्थियों के लिए एक मार्केट जनपथ में बनी। तिब्बत मार्केट 1967 में बसाई गई थी। दलाई लामा के साथ 1959 में आए तिब्बती तो गिनती के ही नजर आते हैं। उनके बच्चे ही दुकानों पर बैठे होते हैं। इसे बसाने वालों में सरदार मोहन सिंह और भाई मोहन सिंह थे। ये क्रमशः कोका-कोला और रैनबैक्सी फार्मा के संस्थापक थे। सरदार मोहन सिंह के नाम पर ही मोहन सिंह प्लेस है।

Subrata Dhar

एकदा

राज सिंहासन डांवाडोल

4 सितंबर, 1939 की एक शाम अली सरदार जाफरी, सिब्ते-हसन, असरारुल हक मजाज लखनऊ के एक चायखाने पर बैठ बहस कर रहे थे। बात हो रही थी कि अंग्रेज अपने कुत्ते का नाम टीपू क्यों रखते हैं। तीनों इस नतीजे पर पहुंचे कि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान से अपनी नफरत का इजहार करने के लिए यह तरीका इख्तियार किया है। इसी मुद्दे पर अभी गुफ्तगू जारी थी कि सिब्ते हसन उठे और कहीं चले गए। लौटे तो गोद में एक खूबसूरत सा कुत्ते का बच्चा था। तीनों ने उसका नाम रखा नेल्सन। अंग्रेजों से टीपू सुल्तान की तौहीन का इंतकाम लेना मकसद था। एक रोज मेफेयर सिनेमा हॉल में तीनों फिल्म देखने गए। नेल्सन का भी टिकट लिया। लेकिन बड़ी तकरार के बाद भी नेल्सन को अंदर नहीं जाने दिया गया। ये लोग बाहर निकले। यूनिवर्सिटी के नौजवान सिनेमा हॉल की तरफ जा रहे थे। ये लोग जोर-जोर से नेल्सन की बातें सब को बताने लगे। एक अंग्रेज पुलिस वाला नशे में धुत सिनेमा हॉल की तरफ जाता दिखा। उसने अपनी बेंत से नेल्सन को छेड़ा। ये तीनों नेल्सन-नेल्सन कहकर आवाजें देने लगे। नेल्सन भौंकता जाता, अंग्रेज का पारा चढ़ता जाता। मजाज यह सब देखकर बहुत खुश हुए और गाने लगे, 'बोल अरी ओ धरती बोल, राज सिंहासन डांवाडोल।' वह अंग्रेज इन लोगों से हाथापाई करता कैसरबाग तक आ गया। नशे में धुत्त उस अंग्रेज की टोपी उतार कर सिब्ते हसन ने नेल्सन के सिर पर लगा दी और गोद में उसे दबाए तीनों पतली गली से यही गाते हुए निकल लिए। यह थे हमारे देश के हिम्मती शायर, जो किसी न किसी तरह से अंग्रेजों का हौसला पस्त करने में जुटे रहते थे।

Subrata Dhar

संकलन : **नाइश हसन**

किताबों में बदलाव पर सही है विवाद?

आमने-सामने

राजनीतिक नज़रिए से सिलेबस में बदलाव तो किए जाते रहे हैं

उमेश चतुर्वेदी

भारतीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए जब भी पाठ्यक्रम और उससे जुड़ी पुस्तकों में बदलाव होता है तो वह विवाद का विषय बन जाता है। NCERT की किताबों में हालिया बदलावों से हुए विवाद को भी इन्हीं संदर्भों में देखा जाना चाहिए। वैसे, ये बदलाव सालाना प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

क्या है प्रक्रिया | बदलाव के लिए विषय विशेषज्ञों की एक टीम काम करती है। वह इस बारे में सुझाव देती है। फिर उन पर विशेषज्ञों की दूसरी टीम विचार करती है। तब जाकर कहीं बदलाव होता है। राजनीति शास्त्र की पुस्तकों की विशेषज्ञ समिति के प्रमुख विद्वान संजय दुबे के मुताबिक, बदलाव हवाई नहीं होते। हर विषय की किताब में विषय से जुड़ी ताजा जानकारियां दी जाती हैं। चूंकि राजनीति शास्त्र और इतिहास से राजनीति जुड़ी होती है, इसलिए इन विषयों की किताबों पर विवाद सबसे ज्यादा होता है।

विवादों के पीछे क्या है

- बदलावों को राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा
- पहले भी होते रहे हैं राजनीति से प्रेरित बदलाव
- सिख विरोधी दंगे नहीं शामिल किए गए कोर्स में

पहले जानते हैं कि आखिर विवाद किन बदलावों पर हो रहा है। छठी से लेकर बारहवीं तक की नागरिक शास्त्र, इतिहास और राजनीति विज्ञान की किताबों में कुछ नई चीजें जोड़ी गई हैं तो कुछ चीजों को नए संदर्भों में रखा गया है और कुछ को हटा दिया गया है। जैसे-

- अयोध्या विवाद से जुड़ी चार पेज की सामग्री को सिर्फ दो पेज में समेट दिया गया है।
- आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा का जिक्र हटा दिया गया है।
- छह दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा ढहाने की घटना में कारसेवकों की भूमिका हटा दी गई है।
- अयोध्या के विवादित ढांचे के ध्वंस के बाद हुई हिंसा के भी संदर्भ हटाए गए हैं।
- अयोध्या की घटनाओं पर BJP की ओर से जो अफसोस जताया गया था, उसे भी हटा दिया गया है।
- हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब जैसे मुगल सम्राटों की कथित उपलब्धियों की जानकारी देने वाली दो पेज की सूची भी किताब से हटा दी गई है।

अक्सर होता है विवाद | NCERT की किताबों में जब इन विवरणों को शामिल किया गया था, तब भी विवाद हुआ था। और तो और, तब इन पुस्तकों को तैयार करने वाली समिति के समन्वयक रहे प्रो. संजय दुबे ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। नियमों के अनुसार, ये किताबें बिना समन्वयक के हस्ताक्षर के जारी नहीं की जा सकती थीं। तब NCERT की शासी परिषद में शामिल एक विश्वविद्यालय के तत्कालीन उप-कुलपति से हस्ताक्षर कराकर जारी किया गया था।

UPA सरकार में बदलाव | दिलचस्प यह है कि बाल मन को ऐसी एकतरफा जानकारी देने वाली किताबें 2004 में आईं, UPA 1 की सरकार के दौरान तैयार की गई थी। मई 2004 में मनमोहन सरकार के मानव संसाधन मंत्री बनते ही अर्जुन सिंह अपने पसंदीदा अधिकारी सुदीप बनर्जी को मंत्रालय में लेकर आए। NCERT के निदेशक के रूप में वामपंथी सोच के प्रो. कृष्णकुमार को नियुक्त किया। योगेंद्र यादव को NCERT का सलाहकार बनाया गया। यादव ने अपने लोगों की टीम बनाई और वाजपेयी सरकार के दौरान तैयार किताबों को रद्दी की टोकरी में फेंककर नई किताबें पाठ्यक्रम में शामिल की गईं।

BJP समर्थक निराश | BJP की अगुआई वाली सरकार का लगातार तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। लेकिन अभी तक किताबें उस तेजी से नहीं बदली गईं, जिस तेजी से अर्जुन सिंह के कार्यकाल में योगेंद्र यादव और कृष्णकुमार की टीम ने बदला था। इसलिए कई बार BJP समर्थक निराश नजर आते हैं। उनका तर्क होता है कि जब मनमोहन सरकार आनन-फानन में किताबें बदल सकती है, वाजपेयी सरकार की दो साल की मेहनत से तैयार किताबों को कूड़े के हवाले कर सकती है तो मोदी सरकार के दौरान ऐसा क्यों नहीं हुआ?

जहां राजनीति, वहां विवाद | NCERT के प्रोफेसर रहे प्रमोद दुबे ध्यान दिलाते हैं कि जहां राजनीति होती है, वहां विवाद होता ही है। योगेंद्र यादव राजनेता भी हैं। स्वराज्य अभियान नाम से पार्टी चलाते हैं, राहुल गांधी के सलाहकार हैं तो इन बदलावों पर विवाद होना ही था।

84 दंगे क्यों नहीं | बड़ी बात यह है कि चाहे गोधरा कांड हो या अयोध्या की विवादित मस्जिद का ध्वंस, इन घटनाओं को पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया गया, ताकि सांप्रदायिकता के बारे में छात्रों को बताया जा सके। ऐसे में सवाल तो यह भी उठना चाहिए कि 1984 के सिख विरोधी दंगों को इन किताबों में क्यों नहीं शामिल किया गया। सच तो यह है कि किताबें बदलते वक्त बीस साल पहले सिलेक्टिव अप्रोच अपनाई गई।

बच्चों पर प्रभाव | गुजरात के सीएम मोदी और BJP को निशाना बनाया गया। संयोग ही है कि जब किताबों में ये तथ्य जोड़े जा रहे थे, तब NCERT की शासी परिषद में मोदी विरोधी तीस्ता सीतलवाड़ भी शामिल थीं। NCERT के निदेशक दिनेश सकलानी एक सवाल करते हैं कि क्या बच्चों को हिंसा की जानकारी दी जानी चाहिए?

राजनीतिक चश्मा | असल में होना यह चाहिए कि किताबों में दी जाने वाली सूचनाएं और जानकारियां राजनीतिक चश्मे से तैयार न हों। प्रगतिशील बौद्धिकता अक्सर जानकारियों को अपने चश्मे से तैयार कर छात्रों के सामने परोस देती है। आज के दौर के ज्यादातर पाठ्यक्रम इसके गवाह हैं। NCERT की किताबों से जिन जानकारियों, संदर्भों को हटाया जा रहा है, वे राजनीतिक चश्मे से तैयार की गई हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

कोर्स में बदलाव के पीछे हिंदुत्ववादी राजनीति पर आधारित सोच है

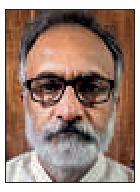

अनिल सिन्हा

NCERT फिर से विवादों में है। इस बार मुद्दा बना है राजनीति शास्त्र की किताबों में फेरबदल। इन किताबों के लेखन और संपादन से जुड़े दो मुख्य सलाहकारों, योगेंद्र यादव और सुहास पलशीकर ने अपना नाम किताब से हटाने को कहा है। ऐसा न करने पर अदालत जाने की धमकी भी दी है।

बार-बार विवाद | NCERT स्कूली किताबों का पाठ्यक्रम तय करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था है। सवाल उठता है कि क्या ऐसे विवाद इस संस्था की छवि के लिए ठीक हैं? सवाल यह भी है कि आखिर ऐसे विवाद पैदा क्यों हो रहे हैं? ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई जैसे गंभीर काम में जुटी यह संस्था बार-बार विवादों में फंस जाती है?

बदलाव की दिशा | यादव और पलशीकर ने NCERT को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि ये फेरबदल पूर्वाग्रहों से भरे हैं और शैक्षणिक कसौटियों पर खरे नहीं उतरते। उनके मुताबिक, ये बदलाव कुछ खास राजनीतिक उद्देश्यों से किए गए हैं। पूछा जा सकता है कि क्या बच्चों को शिक्षित करने के काम में राजनीति उचित है? लेकिन ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि इस राजनीति की दिशा क्या है? क्या ये बदलाव बच्चों के व्यक्तित्व को सही दिशा में ले जाते हैं? उन्हें ऐसा नागरिक बनाते हैं जो असहमतियों का आदर करे और हर समुदाय, धर्म व संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव रखे?

जटिल है मसला | यादव और पलशीकर ने प्रस्तावित बदलावों का विरोध करते हुए साल भर पहले ही अपना नाम हटाने का पत्र दिया था। काउंसिल का कहना है कि कॉपीराइट के तहत फेरबदल का अधिकार उसके पास है और लेखक अपने को उससे अलग नहीं कर सकते। ऊपर से मामूली दिखने वाला यह मामला वास्तव में बेहद जटिल है। आखिरकार बदले गए शब्दों से खुद को जोड़ने के लिए किसी लेखक को बाध्य कैसे किया जा सकता है?

कोरोना की आड़ | पिछली बार बदलावों के पीछे कोरोना से पढ़ाई में हुई बाधा को कारण बताया गया था। तब मशहूर इतिहासकार रोमिला थापर ने आरोप लगाया था कि बदलाव एक खास विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने मुगलों के इतिहास को काटने-छांटने पर सवाल उठाए थे। भारतीय इतिहास के इतने महत्वपूर्ण काल को हटाने के बाद इतिहास की कौन सी समझ बन सकती है?

बाबरी मस्जिद की पहचान | राजनीति शास्त्र में अभी किए गए बदलाव भी वैसे ही हैं। ये हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित हैं। इन बदलावों के जरिए बाबरी मस्जिद के अस्तित्व को ही नकार दिया गया है। इसे 'तीन गुंबदों वाला ढांचा' बताया गया है। उसके ध्वंस की कहानी गोल कर दी गई है।

जो हिस्सा हटाया गया | वह सारा हिस्सा हटा दिया गया है जिसमें बताया गया था कि बाबरी मस्जिद किसने बनाई और इससे संबंधित विवाद क्या था। इसमें बताया गया था कि किस तरह मस्जिद का ताला खुलने के बाद मुस्लिम और हिंदू संगठनों ने धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिशें शुरू कर दी थीं। इसमें उन सारी घटनाओं का उल्लेख था कि किस तरह सोमनाथ से अयोध्या की रथयात्रा निकाली गई, किस तरह छह दिसंबर 1992 को कारसेवक अयोध्या में जुटे और बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। इसमें ध्वंस के बाद फैली हिंसा का भी जिक्र था। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन BJP सरकार को अदालत की अवमानना का दोषी करार दिए जाने और तत्कालीन मुख्यमंत्री को एक दिन की प्रतीकात्मक सजा दिए जाने का भी उल्लेख इस हिस्से में था। ये सारी चीजें हटाई गई हैं।

बदलावों पर है क्या आपत्ति

- बाबरी विवाद के ब्योरों में की गई काट-छांट
- धार्मिक उन्माद के नुकसान बताते हैं वे ब्योरे
- NCERT का रवैया पूर्वाग्रहरहित नहीं है

धार्मिक उन्माद के नुकसान | काउंसिल की दलील है कि बच्चों को हिंसा और दंगों की नफरत भरी बातें बताकर नकारात्मकता से भरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हटाए गए अंशों पर गौर करें तो यह साफ हो जाएगा कि ये पन्ने बच्चों को बाबरी मस्जिद गिराने की हिंसात्मक घटना से भारतीय समाज और लोकतंत्र को हुई क्षति के बारे में बताते हैं। वे पन्ने धार्मिक उन्माद से होने वाली हानि के प्रति बच्चों को सचेत करते हैं।

एकतरफा समझ | असल में, बदले गए पन्ने अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद को BJP और RSS के नजरिए से पेश करते हैं और इसे लेकर देश के दूसरे संगठनों और राजनीतिक दलों की राय को पूरी तरह दरकिनार करते हैं। इन पन्नों में कहा गया है कि किस तरह राम जन्मभूमि स्थल का विवाद कानूनी तरीके से सुलझाया गया। लेकिन विवाद की जानकारी दिए बगैर और यह बताए बिना कि मामले के अदालत में होने के बाद भी कुछ संगठनों ने कानून हाथ में लेते हुए मस्जिद गिरा दी, एक निष्पक्ष और व्यापक राय कैसे बनाई जा सकती है?

निष्पक्ष हो रुख | NCERT के एक खास विचारधारा की ओर झुकाव के कई और उदाहरण हैं। उसने इतिहास की पुस्तक में भी ऐसे फेरबदल किए हैं। महात्मा गांधी की हत्या से संबंधित अध्याय में भी उसने नाथूराम गोडसे की राजनीतिक पहचान छिपा ली है और इस लाइन का अप्रत्यक्ष समर्थन किया है कि गांधी जी का 'सहृदय आचरण' बहुत से भारतीयों को नापसंद था। एक लोकतांत्रिक देश में शिक्षा का मानदंड तय करने वाली संस्था को निष्पक्ष होना चाहिए।

AI Image

मुझसा दूजा नहीं के कॉम्प्लेक्स ने आ घेरा

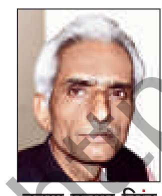

कृष्ण प्रताप सिंह

अवध की गंगा-जमुनी तहजीब के कद्रदानों ने उसकी झोली में बेशुमार प्रशंसाएं डाल रखी हैं। इतनी मुक्तकंठ प्रशंसाएं कि किसी भी अन्य तहजीब को उससे ईर्ष्या होने लग जाए। लेकिन वक्त के साथ इस खुशकिस्मती से एक बदकिस्मती भी आ जुड़ी है। बदकिस्मती यह कि उसके एक हिस्से का इन प्रशंसाओं को अदब के साथ सिर झुकाकर यानी विनम्र स्वाभिमान के साथ स्वीकार करने का अभ्यास जाता रहा है। इसलिए वह फूलकर कुप्पा हुआ ही रहता है।

उसमें इतना सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भर गया है कि वह 'हमचुनी दीगरे नेस्त' (मुझ जैसा दूजा नहीं) से आगे जाना या देखना ही गवारा नहीं करता। भले ही उसकी (गंगाजमुनी) तहजीब के निरालेपन की इमारत को बुलंद रखने के लिए रेती-पानी, सुर्खी-चूना व ईंट-गिट्टी ढोने और रंग-रोगन, नक्काशी व संगतराशी करने वाले तक उसके 'विक्टिम' (पीड़ित) बनकर रह जाएं।

क्या आश्चर्य कि इन पीड़ितों का क्षोभ गाहेबगाहे कवियों की सर्जना का विषय भी बनता आया है। तभी तो युवा कवि अदनान कफील दरवेश अपनी 'अब तो सब सही है' शीर्षक कविता में जब लिखते हैं- 'हमें भी यकीन आ ही गया अब/आना ही था एक दिन/कि कोई भाईचारा नहीं था कभी यहां/न कोई गंगा-जमुनी तहजीब थी/ये सब तो बुजुर्गों की कब्रों से उठती धूल थी/जो बैठ गई', तो 'हमचुनी दीगरे नेस्त' के अलमबरदारों को कुछ देर तो अपना मुंह छिपाना ही पड़ता है।

अकारण नहीं कि हिंदी के वरिष्ठ कवि प्रकाश चंद्रायन अपने कविता-संग्रह 'पददलित मातृभूमि की आत्मा' की 'गंगोजमन तहजीब' शीर्षक कविता में सभ्यता समीक्षकों को संबोधित करते हुए उनसे यही सवाल पूछते हैं, 'सच-सच बताएं/कोई शाही तहजीब मिली आपको/जिसकी बुलंदी में खूनी बुनियाद न हो?' फिर खुद ही जवाब देते हैं, 'खून से ही लिखी गईं हुक्मी सभ्यताएं/और लिखी जा रही हैं।' 'मस्तूल नहीं, पेंदे में दर्ज होता है (उनका) तड़पता सच/(उसे देखें तो) दिख जाएगा साझी विरासत का रिसता जिस्म। यह भी कि 'कहां तक आह और कितनी दूर तक कराह है', 'शिखर पर गंगोजमन (तो) तल पर जुल्मोसितम' क्यों है। यह भी कि उसके 'गप के इतिहास में मिल्लत की मिसालें हैं, भूगोल में तो अपनी-अपनी जान के पड़े लाले हैं'। अन्यथा ऐसा क्यों होता कि हुजूरान तो खानदानी सफेदपोश और अवाम पुश्त-दर-पुश्त पांवपोश!

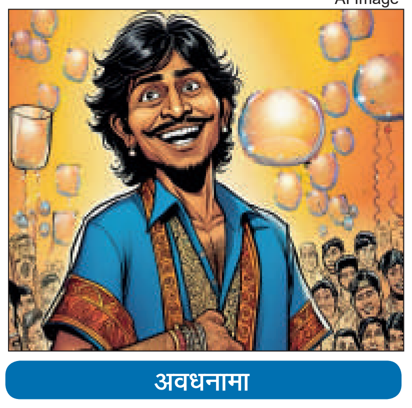

AI Image

अवधनामा

चंद्रायन यहीं नहीं रुकते, सभ्यता समीक्षकों को थोड़ी और 'असुविधा' में डालते हैं, 'कहते हैं सन सत्तावन में उठी गंगोजमन की लहर/ फिर क्यों टूटा सन सैंतालीस तक टेम्स का कहर?/ आपोआप तो नहीं घुला तहजीब में बहुरंगा जहर/कुछ पूछताछ कुछ छानबीन कुछ खोजखबर, जर्द पन्नों में, ढूहों-टीलों पर तो डालें पैनी नजर। इसे गंगोजमन कहें कि जमनोगंग। उनकी आंखें अब बेपानी गड्ढे हैं।/ गड्ढों में तहजीब के ऐसे-ऐसे अवशेष हैं कि वक्त के रोंगटे खड़े हो जायें/दिशाएं भी सिहर जाएं।'

उनकी मानें तो ये सवाल उनके ही नहीं हैं, 'पूछती हैं इस तहजीब के आख्यान से बाहर की गई नदियां (भी)/वे भी जो सुखा दी गईं-/ कि क्या हम सभ्य नहीं।/कि हमने महाजीवन को नहीं पाला-पोसा/कि हमारी वत्सल गोद में नहीं हुआ सभ्यताओं का सृजन? मिल-जुल की बात करो हो तो फकत गंगा-जमुना ही क्यों/मिलते हैं अरब सागर-हिंद महासागर/ मिले हैं मैदान-पठार-पहाड़/मिल ही जाते हैं बागोबहार-गर्दोगुबार। जो नहीं मिलते, वे हैं ताज और तलवारें और इसीलिए गंगोजमन में कभी एक हांड़ी में न पकी सामूहिक खिचड़ी न खीर।

अंत में सबसे मार्मिक प्रश्न, जिसका आरंभ में जिक्र कर आए हैं, '(इस तहजीब के लिए) किसने ढोया रेती-पानी, सुर्खी-चूना, ईंट-गिट्टी/ किसने किया रंग-रोगन, नक्काशी-संगतराशी?' और इसकी गाथाओं में इन सबका कहीं जिक्र क्यों नहीं है? 'तहजीब के बुर्ज में किस तहखाने में कहां हैं स्त्रियां?/किस कोठे-अटारी कोने-अतरे में दबी हैं सिसकियां/गंगा और जमुना भी तो हैं स्त्रियां। जैसे पूछ रहीं नदियां, वैसे ही पूछ रहे खेत-खलिहान। /अशराफ-अभिजात की दिलजमई तो नहीं ये किस्सागोई/खून-पसीने की धुलाई तो नहीं ये गीत-गवनाई।/सफेद जाजम पर सुखासीनों के बोलवचन तो सुखदाई/ दुखदाई ही रहेगी हाशिये की बुक्काफाड़ रुलाई?'

प्रसंगवश, अवध के बड़े-बुजुर्ग बताते हैं कि इस सूबे का नाम सब-कुछ 'औंधा' करके या कि ढक तोप और छिपछिपाकर कर रखने की इस अंचल की 'परंपरा' से निकला है। लेकिन अब नए वक्त की नई रोशनी में इन प्रश्नों को कब तक औंधा करके रखा जा सकता है?

गर्मी के ताप जैसा नहीं, मन वसंत जैसा सुहावना हो

सलिल पांडेय

सूरज तप रहा है। तापमान इतना अधिक है कि कण-कण जल रहे हैं। नवांकुरित पौधे तो झुलस ही रहे हैं, बड़े-बूढ़े पीपल, बरगद और नीम जैसे पेड़ों की भी चमक-दमक कुछ कम हो गई है। कल-कल करके गाती नदियों के स्वर भी गायब हैं, नदियां सूख गई हैं। सूरज की किरणों पर टिकी प्रकृति की जब यह हालत है, तब जीव-जंतुओं के क्या हाल हो रहे हैं, यह तो सामान्य समझ की बात है। इस तपिश को झेल न पाने पर अस्तित्व तक समाप्त हो जा रहा है। 'बचाओ-बचाओ' की पुकार हो रही है। पेड़-पौधे लगाने के आह्वान हो रहे हैं। बहुमंजिले इमारतों के बजाय प्राचीन काल के मिट्टी के घर की तारीफ हो रही है। पाश्चात्य संस्कृति की जगह अब भारत के ऋषियों-मुनियों के संदेशों को सराहा जा रहा है। चेतावनी अलग से दी जा रही है कि इन बदलावों को समय से नहीं समझे तो प्रलय सुनिश्चित है। बिना परमाणु बम के ही यह धरती आग का गोला बनकर फट जाएगी और जितना भी खोखला विकास है, सब धू-धू करके खाक हो जाएगा।

प्रकृति के इन भयावह पहलुओं को प्रवृत्तियों से जोड़कर देखा जाए तो कुछ इसी तरह के हालात इंसान के अपने जीवन में भी दिखाई पड़ने लगेंगे। इसका कारण यह है कि जो बाहर घटित होता है, कुछ उसी तरह अंतर्जगत में भी घटित होता रहता है। ब्रह्मांड और पिंड में समानता तो है ही। बाहरी जगत में हिंसक पशु दिखाई पड़ते हैं तो मन भी पशु का रूप लेता है। फिर अंदर-बाहर हिंसा ही हिंसा का साम्राज्य हो जाता है। अंदर के स्तर पर शारीरिक क्षति होती है। रक्त जलता है, ब्लड प्रेशर प्रभावित होता है। तंत्रिका प्रणाली क्षतिग्रस्त होती है तो मन का हिंसक रूप अपनों के ही हितों को निगलने लगता है।

यह तब होता है जब बाहरी जगत में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ बनने के लिए मन ग्रीष्म ऋतु के सूरज सा हो जाता है। फिर तो संवेदनाओं का पानी सूखने लगता है। प्रकृति यह संदेश दे रही है कि जैसे सूरज की तपन नहीं बर्दाश्त हो रही है, ठीक उसी तरह मन को भी ग्रीष्म के सूरज जैसा नहीं बल्कि शरद या वसंत ऋतु के लुभावने सूरज की तरह बनाने की जरूरत है। इसी संवेदना को जीवंत रखने के लिए मनीषियों ने पग-पग पर स्नेह-प्रेम की वर्षा की है। दैनिक पूजा-पाठ हो या किसी भी विशेष अवसर पर कोई यज्ञ-अनुष्ठान आयोजित किया जा रहा हो, तब 'स्वस्तिमंत्र' यानी कल्याणकारी मंत्र पढ़े जाते हैं। इन मंत्रों में सूर्य, चंद्रमा, अंतरिक्ष, पृथ्वी की शांति से लेकर जल, पेड़-पौधे, वनस्पतियों और अग्नि तक की शांति की कामना की जाती है।

इन सारे प्रकृति के तत्वों के बहाने शरीर-संचालन के सारे कल-पुर्जों की शांति की कामना का आशय यही है कि जब शरीर की हरेक कोशिका तक सुचारू ढंग से काम करेंगे, तभी मन भी सुचारू और सुव्यवस्थित रह सकता है। भौतिक स्तर पर देखें तो मकान बनाते समय नींव को सर्वाधिक मजबूत किया जाता है। नींव जितनी मजबूत होगी, मकान उतना ही मजबूत होगा और उसी के आधार पर मकान को ऊंची-ऊंची अट्टालिकाओं का रूप दिया जाना संभव हो सकेगा। साधारण मकान और भव्य महल की इसी अभियांत्रिकी के बल पर जीवन में यश-कीर्ति के रूप को भव्य बनाया जा सकता है।

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
hindi.speakingtree.in

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ पेपर लीक बड़ी समस्या

19 जून का संपादकीय 'फिर न आए ये नौबत' पढ़ा। बेलगाम बढ़ती बेरोजगारी से देश का युवा जूझ रहा है। इससे उसमें आक्रोश भी है। सुरक्षित भविष्य के लिए सेवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कई-कई साल कड़ी मेहनत करने के बाद भी शिक्षित नौजवान कामयाब नहीं हो पाते हैं। कई बार उनकी उम्र निकल जाती है और अपने करियर पर उन्हें समझौता करना पड़ता है। अफसोस 'पेपर लीक' जैसी गड़बड़ियों के कारण अक्सर युवाओं की उम्मीदें ढह जाती हैं। ऐसा ही एक उदाहरण NEET में देखने को मिला। पेपर लीक की इस घटना ने बड़ा सवाल छोड़ा है।

माम चंद सागर, ईमेल से

■ संघ का योगदान

यह पत्र 19 जून के लेख 'RSS चीफ की बात का क्या है मतलब' से संबंधित है। संघ और बीजेपी में दूरी हो या न हो लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि एक समय दो सांसदों की पार्टी कहलाने वाली BJP अगर लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बना पाई है तो उसे इस मुकाम तक पहुंचाने में संघ की अहम भूमिका रही है। संघ के कार्यकर्ताओं ने दिन-रात मेहनत करके BJP की मदद की है। BJP प्रमुख नड्डा ने संघ के बारे में जो बयान दिया वह अनुचित है। इसमें उनके और BJP के अहंकार की झलक दिख रही थी। मोहन भागवत ने आत्मावलोकन करने की जो बात कही है, वह बिलकुल सही है।

बाल गोविंद, नोएडा

■ सदन के सत्र पर निगाहें

तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद में 71 मंत्रियों को जगह दी और अब लोकसभा स्पीकर के पद को लेकर चर्चा तेज है। 24 जून से शुरू हो रही संसद के 8 दिवसीय विशेष सत्र में स्पीकर का चुनाव एक चुनौती बना हुआ है। केंद्र हो या राज्य, गठबंधन की सरकार बनती है तो स्पीकर की भूमिका अहम हो जाती है। सदन के सबसे अनुभवी और वरिष्ठ सदस्य को स्पीकर बनाया जाता है। इस बार स्पीकर का चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है।

दीपा सिन्हा, ईमेल से

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

दलाई लामा से मिलने आए US के नेता, चीन भड़का – खबर
– चीन को कोई बता दे, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है!

सुप्रिया गोयल

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बृहस्पतिवार • 20 जून • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

दूसरों के मामलों में न्याय हो यह सभी को भाता है।
-इतालवी कहावत

शीर्ष अदालत का सख्त रुख

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा के आयोजन में किसी की तरफ से 0.001 प्रतिशत लापरवाही भी हुई हो, तब भी उससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ मंगलवार को पांच मई को हुई परीक्षा में छात्रों को कृपांक दिए जाने समेत अन्य शिकायतों से संबंधित दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिकाओं पर अन्य लंबित याचिकाओं के साथ अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी। याचिकाओं में परीक्षा में अनियमितता बरते जाने की सीबीआई जांच और नीट-यूजी परीक्षा नये सिरे कराने की मांग वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। अदालत ने एनटीए और केंद्र सरकार से याचिकाओं पर दो हफ्ते के भीतर अपने जवाब दाखिल करने को कहा है। लोक सभा चुनाव

परिणाम आने की गहमागहमी के बीच ही नीट-यूजी 2024 परीक्षा के परिणाम भी घोषित किए गए थे। अनेक परीक्षार्थियों के टॉपर्स होने और खासी संख्या में परीक्षार्थियों को कृपांक दिए जाने की जानकारी होने के बाद लगा कि दाल में कुछ काला है। बाद के घटनाक्रम में कुछ गिरफ्तारियां हुईं और पटना से लेकर गोधरा तक कई परीक्षा केंद्रों पर व्यापक स्तर पर अनियमितताएं बरती जाने की बातें सामने आने लगीं। परीक्षा में धांधली के संकेत मिलने लगे और परीक्षार्थियों के परिजनों के साथ ही अनेक संगठनों और राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। कुछ परीक्षार्थियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मेडिकल की पढ़ाई पर अभिभावक खासा खर्च करते हैं। अभ्यर्थी छात्र सामाजिक जीवन से कटकर मेडिकल पाठयक्रम में प्रवेश परीक्षा की तैयारी में रात-दिन एक कर देते हैं। दरअसल, अभ्यर्थियों की संख्या को देखते हुए मेडिकल कॉलेजों में सीटें पर्याप्त नहीं हैं। जरूरी है कि सरकार सीटें बढ़ाने के लिए ढांचागत आधार को मजबूत करे। एनटीए के वजूद में आने से पहले सीबीएसई और राज्य शिक्षा बोर्ड पीएमटी की परीक्षा आयोजित करते थे जिसके आधार पर प्रवेश आसानी से मिल जाता था। लेकिन इस बीच अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ने और एनटीए जैसे निकाय को मेडिकल के अलावा अन्य तमाम परीक्षाओं का आयोजन करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। इतने बोझ से एनटीए का ढांचा कमजोर दिखलाई पड़ने लगा है, उसके सामने मैनपावर की समस्या भी है। बहरहाल, जरूरी हो गया है कि छात्रों के साथ न्याय हो और इसके लिए रि-नीट-यूजी के अलावा कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता।

बढ़ती गर्मी, घटता पानी

गर्मी के कारण हाल बेहाल है। समूचा उत्तर भारत तप रहा है। बुजुर्गों की स्मृति में भी नहीं है कि उन्होंने पहले कभी इतनी प्रचंड गर्मी की लगातार मार सही हो। दिल्ली और एनसीआर जैसे क्षेत्रों से लू के कारण मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और दूसरी तरफ जब देश की राजधानी दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है तो देश के जलाभाव वाले क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी, उसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। जो हो रहा है, वह अनायास या अचानक नहीं हो रहा है। दुनिया भर के पर्यावरणविद् और जलवेत्ता वर्षों से इस स्थिति की आशंका के प्रति चेतावनी जारी करते रहे हैं। भारत में भी बदलते तापमान और तद्जन्य समस्याओं को लेकर लगातार अपनी बातें सामने रखते रहे हैं। पानी के संकट को लेकर और देश भर में भूजल स्तर की डरावनी गिरावट को लेकर भी चेतावनियां जारी होती रही हैं। इसका कारण खोजने के लिए अतिरिक्त अन्वेषण की जरूरत नहीं है।

असंतुलित विकास की भेंट चढ़े देश के वन जंगल, निर्ममता से नष्ट किए गए स्थानिक जल स्रोत और जल संसाधनों पर तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण यह स्थिति पेश हुई है। देश भर में गांव-देहातों तक जिन छोटी-छोटी नदियों का जाल बिछा हुआ था और जो पोखर तालाब जल के संरक्षण के मुख्य वाहक होते थे, वे अब कहीं दिखाई नहीं देते। मनुष्य के अनियंत्रित लालच और हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार ने स्थितियों को कई गुना जटिल किया है तिस पर राजनीतिक दलों की बेहयाई समस्या की आग में घी डालती रहती है। सबसे ज्यादा मौजूदा उदाहरण इस समय दिल्ली का है। दिल्ली में दिल्लीवासियों की कथित सेवा को समर्पित आम आदमी पार्टी की सरकार है, और केंद्र में देश हित के लिए जीने-मरने का दावा करने वाली भाजपा सरकार है और तमाशा यह है कि दोनों ही पार्टियों के प्रतिनिधि दिल्ली के जल संकट के लिए एक दूसरे पर पूरी बेशर्मी से हल्ला बोल रहे हैं। जब दिल्ली के लोग पानी के लिए त्राहि त्राहि कर रहे हैं उस समय दो जिम्मेदार पार्टियों और उनकी सरकारों के इस रवैये को शर्मनाक ही कहा जा सकता है। कहने में कोई संकोच नहीं कि अगर वास्तविक समस्याओं के प्रति जिम्मेदारी राजनीतिक दलों को रुख इतना गैर-जिम्मेदार है, तो देश और इसकी राजधानी को आने वाले भयानक संकटों से कोई नहीं बचा पाएगा।

कटाक्ष/ सहीराम

शपथ भी, चपत भी

शपथ तो होनी ही थी जी, पर चपत नहीं होनी थी। जी नहीं, हम उस चपत की बात नहीं कर रहे, जिसकी बात सब कर रहे हैं। जी वही चपत, जो कंगना जी को पड़ी। शायद जा तो रही थीं वे भी शपथ लेने ही, पर चपत पड़ गई। नहीं पड़नी चाहिए थी। वो कोई अरविंद केजरीवाल थोड़े ही हैं कि कोई भी चपत लगा जाए, कोई भी स्याही फेंक जाए। बल्कि वो तो कन्हैया कुमार भी नहीं कि कोई भी चपत लगा दे, कोई भी कूट दे। अच्छी बात यह रही कि इन चपतों और इन कुटाइयों ने ही उन्हें नेता बना दिया, वरना कहीं मास्टरी कर रहे होते। खैर, हम तो कंगना जी को पड़ी चपत की बात ही नहीं कर रहे। हम तो जनता को लग रही चपत की बात कर रहे हैं। जो जनाब पहली चपत तो पड़ी नीट के परीक्षार्थियों को। उनका रिजल्ट भी उसी दिन आया जिस दिन लोक सभा चुनावों का आया।

क्योंकि शपथ में अभी देर थी। कोई अकेले भाजपा को तो सरकार बनानी नहीं थी। सरकार बनाने के लिए इधर नीतीश जी को मनाना था और उधर नायडु जी को। हालांकि बाद में उनकी हुड़क को देखकर लगा कि वे तो मनने को तैयार ही बैठे थे। जैसे प्रेयसी को आई लव यू की कहने की ही देर होती है, उसके बाद गले लगने में देर नहीं होती। खैर जी, क्योंकि शपथ में अभी देर थी, तो सोचा चलो, पहले चपत ही लगा ली जाए। सो, दूसरी चपत लगाई टोल टैक्स वालों ने। पहले तेल कंपनियां इंतजार करती थीं कि कब चुनाव निपटें और वे तेल की कीमत बढ़ा कर जनता को चपत लगाएं। अब टोल वालों ने भी कुछ उसी अंदाज में चपत लगा दी। वैसे टोल रोड का बनना जरूरी नहीं। वह अधूरा पड़ा रहे तब भी टोल लिया जा सकता है। यह नया कायदा है। खैर जी, टोल टैक्स वालों की चपत के बाद दूध वालों ने चपत लगाई। ये हरौला-बरौला से आने वाले दूधिए नहीं थे। वे दूसरी तरह से चपत लगाते हैं। यह तो कोऑपरेटिव और सरकारी डेयरियां थीं, जिन्होंने चपत लगाई। उन्हें लगा होगा कि जब तक सरकार में माल-मलाई बंटे-जिसे विरोधी जूतों में दाल बंटना भी कहते हैं-तब तक हम भी अपनी माल-मलाई का इंतजाम कर लेते हैं। सो, अगली चपत उन्होंने जनता को कस के लगाई। तो कंगना जी को पड़ी चपत की निंदा करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। पर जनता को पड़ी इन चपतों की निंदा कोई न करता। क्यों?

ये कैसा विरोध

सामयिक

डॉ. ब्रह्मदीप अलूने

वे माओवादी हिंसा को दरकिनार करके इसे गरीब आदिवासियों का विद्रोह कहती हैं। करीब डेढ़ दशक पहले उन्होंने रेड कॉरिडोर के केंद्र माने जाने वाले बस्तर की गुपचुप यात्रा की और दंडकारण्य में माओवादियों के साथ काफी वक्त बिताया। वे माओवादियों को भाई, साथी या कॉमरेड कह कर लाल सलाम कहने में फख्र महसूस किया करती थीं। उन्हें संविधान और लोकतंत्र आदिवासियों की खिलाफत का अस्त्र नजर आता है। 1997 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित अरुंधती रॉय अपनी किताब 'वॉकिंग विद द कॉमरेड्स' में लिखती हैं-'भारतीय संविधान, जो भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है, संसद द्वारा 1950 में लागू किया गया। यह जनजातियों और वनवासियों के लिए दुःख भरा दिन था। संविधान में उपनिवेशवादी नीति का अनुमोदन किया गया और राज्य को जनजातियों की आवास भूमि का संरक्षक बना दिया गया। मतदान के अधिकार के बदले में संविधान ने उनसे आजीविका और सम्मान के अधिकार छीन लिए।'

अरुंधती अपनी इस किताब में माओवादियों को आंतरिक सुरक्षा का खतरा बताए जाने का मखौल उड़ाती हैं। भारत की यह ख्यात लेखिका मानवाधिकार के मुद्दों पर सरकार पर हमले करने से परहेज नहीं करतीं। अरुंधती कश्मीर में तैनात फौज को जनता की दुश्मन बताती हैं। उन्हें संसद पर हमले के प्रमुख आरोपी अफजल गुरु से हमदर्दी रही। अपने ब्लॉग में वह भारत की पूरी न्याय प्रक्रिया पर कटाक्ष करते हुए कहती हैं-'लेकिन अब जब अफजल गुरु को फांसी दे दी गई है, तो मुझे उम्मीद है कि हमारी सामूहिक अंतरात्मा संतुष्ट हो गई होगी। या फिर हमारे खून का प्याला अभी भी आधा ही भरा है?' 2010 में राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने सार्वजानिक रूप से कहा-'कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था और उस पर भारत के सशस्त्र बलों ने जबरन कब्जा कर लिया था।'

कश्मीर की पृथकतावादी ताकतों के लिए अरुंधती पसंदीदा चेहरा हैं, और उनके विचारों को वे भारत के बौद्धिक वर्ग की आवाज कह कर दुनिया भर में प्रचारित करते हैं। 2010 में दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। उन पर भारत विरोधी भाषण देने और कश्मीरी अलगाववाद का समर्थन करने का आरोप लगाया गया। अब अरुंधती रॉय के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मुकदमा चलेगा। अरुंधती अच्छी लेखिका हैं, और उन्हें पसंद करने वाले देश-विदेश के कई लोग हैं, जिन्हें लगता है कि अरुंधती पर मुकदमा कायम करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने जैसा है। 2023 के

फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले में सलमान रुश्दी ने अरुंधति पर मुकदमा चलाने के कदमों की आलोचना करते हुए कहा था-'वह भारत की महान लेखिकाओं में से एक हैं, और बहुत ईमानदार और जुनूनी इंसान हैं। उन मूल्यों को व्यक्त करने के लिए उन्हें अदालत में लाने का विचार शर्मनाक है।'

भारत की विविधता और जटिलता में बहुत सारे विरोधाभास हैं, और इसे स्वीकार भी किया जाना चाहिए। अरुंधती ने अपनी लेखनी और आंदोलनों में हिस्सा लेकर इन्हें समाज के सामने लाने में महती भूमिका निभाई है। आजादी और स्वतंत्रता की पक्षधर इस लेखिका को 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अरुंधती भारतीय लेखिका के रूप में देश-विदेश में आमंत्रित की जाती हैं, लेकिन वे अक्सर भारत की छवि को निरंकुशता के करीब ले आती हैं। अरुंधती गरीब आदिवासियों के लिए भारतीय संविधान को शोषण के अस्त्र के रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाई पड़ती हैं।

संविधान का अवलोकन करें तो उनके दावों से उलट आदिवासियों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास के लिए कई उपबंध शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 15(4) अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक उन्नति के लिए विशेष प्रावधान सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 46, राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 350 विशिष्ट भाषाओं, लिपियों या संस्कृतियों के संरक्षण के अधिकारों का प्रावधान करता है। लोकतांत्रिक देश में व्यापक प्रतिनिधित्व के लिए संविधान में संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान भूमि अधिग्रहण आदि के कारण जनजातीय आबादी के विस्थापन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं।

भारत का रेड कॉरिडोर का क्षेत्र सशस्त्र विद्रोह के लिए जाना जाता है, और यह इलाका हिंसाग्रस्त रहा है। अरुंधती आदिवासियों के हितों के लिए मुखर रहें, यह उनका अधिकार है लेकिन संविधानिक तंत्र को शोषित वर्ग के खिलाफ प्रचारित करने की उनकी कोशिशें भारत की आंतरिक शांति को भंग करती दिखाई पड़ती है। भारत का संविधान अभिव्यक्ति की आजादी को देश के रचनात्मक विकास के लिए जरूरी तो बताता है लेकिन देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा के लिए भी सजग है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए में देश की एकता एवं अखंडता को हानि पहुंचाने के प्रयास को देशद्रोह के रूप में परिभाषित किया गया है। देशद्रोह के अंतर्गत शामिल हैं, सरकार विरोधी गतिविधि और उसका समर्थन, देश के संविधान को नीचा दिखाने का प्रयास और कोई ऐसा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, लिखित या मौखिक कृत्य जिससे सामाजिक स्तर पर देश की व्यवस्था के प्रति असंतोष उत्पन्न हो।

अरुंधती ने अपने एक लेख में कहा था-'एक मछुआरे के लिए यह मान लेना कितना गलत है कि वह अपनी नदी को अच्छी तरह जानता है।' दरअसल, अरुंधती को भारत, उसके विरोधाभास, समस्याएं, संविधान और लोकतंत्र को ठीक तरीके जानने और समझने की जरूरत है। वे महात्मा गांधी की भूमिका और उनके कद की आलोचना भी कर चुकी हैं। उन्होंने गांधी के उस संदेश को समझने का प्रयास ही नहीं किया कि सामाजिक न्याय की समस्याओं के हल लोकतांत्रिक और अहिंसा के रास्ते भी तलाशे जा सकते हैं। अरुंधती रॉय और उन जैसे बुद्धिजीवी अभिव्यक्ति की आजादी का कवच धारण कर संविधानिक ढांचे और लोकतंत्र को अक्सर चुनौती देते हैं। यह उनका अधिकार हो सकता है, लेकिन देश उनसे बेहतर नागरिक होने की भी अपेक्षा करता है।

अरुंधती ने अपने एक लेख में कहा था-'एक मछुआरे के लिए यह मान लेना कितना गलत है कि वह अपनी नदी को अच्छी तरह जानता है।' दरअसल, अरुंधती को भारत, उसके विरोधाभास, समस्याओं, संविधान और लोकतंत्र को ठीक से जानने-समझने की जरूरत है। वे महात्मा गांधी की भूमिका, उनके कद की आलोचना कर चुकी हैं। अरुंधती रॉय और उन जैसे बुद्धिजीवी अभिव्यक्ति की आजादी का कवच धारण कर संविधानिक ढांचे और लोकतंत्र को चुनौती देते हैं

- भारत में घरेलू एयर कंडीशनर (रूम एसी) का बाजार वित्त वर्ष 2028-29 तक 12 प्रतिशत की सालाना दर से बढ़कर 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है
- वोल्टास की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, बढ़ती गर्मी, बढ़ती खर्च योग्य आमदनी तथा उपभोक्ता वित्त तक आसान पहुंच के साथ ही बेहतर जीवन शैली की चाह जैसे कारकों से घरेलू एसी खंड की वृद्धि को बढ़ावा मिलने की संभावना है

(मीडिया इन्पुट्स)

भाजपा हाईकमान ने 2024 के चुनाव में फडणवीस और योगी को कमतर आंका। महाराष्ट्र और यूपी में एनडीए को 2019 के बरक्स 56 सीटों (यूपी में 32 और महाराष्ट्र में 24) का नुकसान हुआ। भाजपा 296 तक पहुंच जाती तो टीडीपी/जेडीयू/आरएलडी की जरूरत नहीं पड़ती। फडणवीस को उपमुख्यमंत्री पद के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए था। तिकड़मी मानसिकता के चलते ही तो विदेशियों ने भारत को गुलाम बना लिया था।

मिन्हाज मर्चेंट, लेखक
@MinhazMerchant

बहुत कुछ करना बाकी

रेल हादसा | अनिरुद्ध गौड़

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गत सोमवार को बड़ा रेल हादसा हो गया। अगरतला से सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस को न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से 30 किमी. दूर रंगापानी स्टेशन के पास मालगाड़ी ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 11 लोगों की मौत और करीब 50 लोगों से अधिक घायल हो गए। एक तरफ जहां देश में सुपर फास्ट वंदेभारत जैसी ट्रेन पटरी पर दौड़ रही हैं, रेल सेवाओं के आधुनिकीकरण, ऑटोमेशन में तेजी लाने की दिशा में काम किया जा रहा है, तो रेल भिड़ंत की घटनाएं रेल सेवाओं के प्रबंधन पर सवाल उठा रही हैं।

ट्रेन हादसों से जहां करोड़ों की आर्थिक क्षति होती है वहीं यात्रियों की असामयिक मौत प्रियजनों को सदैव के लिए पीड़ा दे जाती है। रेलवे सुरक्षा आयोग की 2022-23 रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार 2020-2021 में 2 गंभीर सहित कुल 22 दुर्घटनाएं, 2021-22 में 2 गंभीर सहित कुल 35 दुर्घटनाएं और 2022-23 में 4 गंभीर सहित 48 रेल दुर्घटनाएं हुईं। इनमें रेलवे कर्मचारियों की गलती से 2021-22 में 15 और 2022-23 में 34 दुर्घटनाएं हुईं जबकि पिछले 10 वर्ष में कुल 897 रेल दुर्घटनाएं हुईं। इनमें 87 गंभीर दुर्घटनाएं रहीं। हालांकि 2013-14 के बाद से रेल दुर्घटनाओं के ग्राफ में कमी का रुझान है। दुर्घटनाओं से रेलवे संपत्ति की क्षति की बात करें तो पिछले 10 वर्ष में रेलवे को 2015-16 में 64.46 करोड़ रुपये की सर्वाधिक क्षति हुई। 2020-21 ऐसा वर्ष रहा जिसमें सबसे कम 36 लाख क्षति रही जबकि 2021-22 में 3.15 करोड़ और 2022-23 में 55.81 करोड़ रुपये की क्षति हुई। इस घटना में रानीपतरा रेलवे स्टेशन और चत्तर हाट जंक्शन के बीच स्वचालित सिग्नल प्रणाली सुबह 5.50 बजे से खराब थी। सिग्नलिंग प्रणाली फेल होने पर स्टेशन मास्टर ने कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी को 'टीए 912' लिखित अधिकार पत्र जारी कर लाल हुए सिग्नलों को पार करने की अनुमति दी थी। एक ही ट्रैक पर जा रही मालगाड़ी ने लापरवाही के चलते कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। भीषण टक्कर से गार्ड डिब्बे के परखचे उड़ गए। पार्सल रैक

का डिब्बा उछल कर मालगाड़ी के इंजन पर जा चढ़ा और कई डिब्बे पटरी से इधर-उधर छिटक गए। मालगाड़ी के लोको पायलट और कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड की मौत हो गई। रेलवे बोर्ड की चेयरमैन एवं सीईओ जया वर्मा सिन्हा का दावा है कि प्रथम दृष्टया जांच में सामने आ रहा है कि हादसा मानवीय चूक के कारण हुआ। लोको पायलट ने सिग्नल को तोड़ा जिससे मालगाड़ी की कंचनजंगा एक्सप्रेस से जोरदार टक्कर हुई।

हादसा कई प्रश्न खड़े कर रहा है कि आखिर, मालगाड़ी के लोको पायलट से यह चूक कैसे हुई? मालगाड़ी की स्पीड इतनी तेज क्यों रही? खराब सिग्नल क्यों जल्दी से ठीक नहीं हो सका? संचालन के बीच लापरवाही का क्या कारण रहा? जिस रेल सुरक्षा कवच का डंका बजाया जा रहा था वह इस ट्रैक पर अब तक क्यों नहीं लगा?

दो जून, 2023 को ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस सहित तीन टेनों की टक्कर लोग भूले नहीं हैं, जिसमें 296 की मौत और करीब एक हजार लोग घायल हुए थे। 29 अक्टूबर, 2023 को आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम-रायगड़ा पैसेंजर स्पेशल ट्रेन हादसे, विशाखापत्तनम-पलासा पैसेंजर टक्कर और 13 यात्रियों की मौत सहित 12 अक्टूबर, 2023 को बिहार के बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन के समीप पटरी से उतरी कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे में 4 की मौत और 75 घायल की घटनाओं से रेलवे ने शायद सीख नहीं ली है।

रेल हादसे न हों उसके लिए रेलवे करीब दो साल पहले सुरक्षा कवच सिस्टम लाई थी। लेकिन आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत निर्मित रेलवे का यह कवच सिस्टम बेहद धीमी गति से रेलवे मार्गों पर लगाया जा रहा है। भारत में कुल 68,083 किमी. रेल नेटवर्क है। आठ साल पहले फरवरी, 2016 में इस कवच सिस्टम का पहली बार यात्री ट्रेन में लगा कर ट्रायल किया गया था। अभी तक रेलवे 1465 किमी. ट्रेन रूट पर ही कवच सिस्टम लगा सकी है। दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-हावड़ा रेलमार्ग पर 2951 किमी. में कवच सिस्टम लगाने का काम बाकी है जबकि 35,736 किमी. और रेलमार्ग पर कवच सिस्टम लगाने की मंजूरी मिली है। रेलवे बोर्ड चेयरमैन का कहना है दिल्ली-गुवाहाटी में कवच लगाना अगली योजना में है। उनका दावा है कि पूरे भारत के रेलवे ट्रैक पर मिशन मोड में धीरे-धीरे कवच लगाने की योजना है। इस पर भी सवाल है कि सुरक्षा के लिए यदि कवच लगाने का काम इसी तरह धीमी चाल से चलता रहा तो पूरे 68,083 किमी. रेलवे ट्रैक पर कवच लगाने में दशकों लग जाएंगे। बड़ा सवाल यह भी है कि रेलवे द्वारा पदों की भर्ती में देरी भी इन हादसों की ओर इशारा करती है। रेलवे के पास जुलाई, 2023 तक करीब ढाई लाख पद रिक्त थे।

यू-टर्न | डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी

गति और विकास, दोनों का संबंध अटूट है। गति का कम होना विकास को कम कर देता है। गति का रुकना, प्रगति पर पूर्ण विराम लगा देता है। किंतु प्रगति के मार्ग में रुक कर पीछे मुड़ना तो अधोगति है। कुरु क्षेत्र के मैदान में युद्ध से पूर्व अर्जुन अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर शत्रुओं को देखना चाहते थे। शौर्य का प्रतीक गांडीव धनुष उनके हाथों में शोभायमान था। तरकश में रखे बाण शत्रु के रक्त के प्यासे थे। श्री कृष्ण भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच रथ को स्थापित किया और कहा, 'देखो, अर्जुन! अपने शत्रुओं को भली-भांति देख लो!' लेकिन अर्जुन ने कुछ और देखा। हां, अर्जुन ने सामने सेना में पितामह, गुरु, वरिष्ठजनों, चाचाओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, श्वसुरों तथा शुभचिंतकों को देखा। दूर से आए शिखंडी और जयद्रथ आदि कई रिश्तेदारों को भी देखा। जब कुंतीपुत्र अर्जुन अपने रिश्तेदारों को देखते हैं तो करुणा के अतिरेक में अवसाद में पड़ जाते हैं। यह अर्जुन का यू-टर्न था। अब हर व्यक्ति से जुड़ी पुरानी यादें अर्जुन की आंखों के सामने से तीव्र गति से गुजर रही थीं। मोह विवेक को ढंक रहा था। कुछ क्षण पहले का उत्साही अर्जुन अब अवसादी और दुःखी हो चुका था। महंतस्वामी महाराज समझाते हैं कि कभी-कभी यह यू-टर्न हमारे जीवन का भी हिस्सा बन जाता है। जहां भी मोह प्रबल होता है वहां अंधकार प्रवेश कर जाता है। मोह ही है जो हमें आंखों के होते हुए भी अंधा बना देता है। मोह के कारण ही अज्ञानता और नासमझी तेजी से कम करने लगते हैं। अर्जुन अपने शत्रुओं को देखता है लेकिन 'मोह' के कारण वह उन्हें अपना रिश्तेदार मानता है। भूल जाता है कि जिन कौरवों को अपना भाई मानता है, उन्हीं लोगों ने कपट से उसका राज्य हड़प लिया है। जो लोग बुजुर्ग, चाचा, दादा, गुरु थे, वे तब चुप रहे जब भरी सभा में उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। जिन्हें वह अपना चाचा और रिश्तेदार मानता है, वे सब अब उसके विरोधी दुश्मन बनकर उसके सामने उसे मारने के लिए आ खड़े हुए हैं। मोह अगर अर्जुन जैसे महान एकाग्र, श्रेष्ठ धनुर्धारी और परम विवेकी को डिगा सकता है, तो हमारी क्या दशा होगी?

रीडर्स मेल

डेली वर्कर्स पर गर्मी का कहर

भारत में भीषण गर्मी से डेली वर्कर्स विशेषकर डिलीवरी कर्मियों, ईंट-भट्ठों पर काम करने वालों और दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए कामकाजी परिस्थितियां गंभीर हो गई हैं। भीषण गर्मी ने खुला काम करने वाले वर्कर्स के लिए कठोर कार्यस्थितियों और चुनौतियों को उजागर किया है। भीषण गर्मी में कई लोग खुले वातावरण और गर्म मौसम में काम करने के लिए मजबूर हैं। यह उनके जीवन-यापन का एकमात्र साधन है। ऐसे लोग अक्सर काफी गरीबी में जीने के लिए विवश होते हैं। साफ पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं से भी वंचित झुग्गियों के घर टिन या तारपोलिन की छतों के नीचे तपती गर्मी झेलते हैं। चूंकि ये काम ज्यादातर खुले वातावरण में ही करने पड़ते हैं, तो इन लोगों के बीमार पड़ने का खतरा भी ज्यादा रहता है। इनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए चल रहे प्रयासों और पहलों को विकसित किया जाना चाहिए जिससे उनकी भलाई सुनिश्चित हो सके।

प्रियंका सौरभ, ई मेल से

थानों में अमानुषिक अत्याचार क्यों

कुछ घटनाएं बार-बार घटती हैं, उन्हें हल्के में लिया जाता है। पुलिस थाने में कथित आरोपियों पर अमानुषिक अत्याचार की घटनाएं नई नहीं हैं। पुलिस आरोपियों को पकड़ कर थाने में रखती है। जुल्म कबूलने के लिए उन्हें पीटती है। पिटाई से कई लोगों की मौत हो गई है। अभी की खबर है कि पुलिस ने एक जने को पकड़ा, भूखा रहने के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस व्यक्ति को अभिरक्षा में रख सकती है। उसे प्रताड़ित करने का हक किसने दिया। प्रायः ऐसा ही होता है। पुलिस उसे प्रताड़ित करती है। ऐसी घटनाएं बार-बार आने पर भी पुलिस वालों को दंडित नहीं किया जाता, बल्कि विभाग का मामला होने के कारण पुलिस वालों का बचाव किया जाता है। पुलिस को यह हक किसने दिया कि किसी को प्रताड़ित करे। जो व्यक्ति किसी पर जुल्म करे, चाहे वह पुलिस वाला ही क्यों न हो, उसे भी आम व्यक्ति मान कर बराबर की सजा दी जाए।

दिलीप कुमार गुप्ता, बरेली

सुरक्षा तंत्र मजबूत करे रेलवे

जैसे-जैसे रेलों की संख्या बढ़ती जा रही है, मानवीय भूलों के कारण रेल हादसों में भी इजाफा हो रहा है, खराब होती सिग्नल प्रणाली के कारण भी दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, रेलवे की सुरक्षा प्रणाली कवच रेल दुर्घटनाओं को रोकने का एक कारगर उपाय है, जिसे रेलवे के कई रूटों पर लगाना अभी शेष है। कवच प्रणाली को सभी रूटों पर लगा दिया जाएगा तो रेल यात्रा 100% सुरक्षित होने लगेगी। हाल में हुई रेल दुर्घटना और पूर्व में हुए रेल हादसों की प्रमुख वजह सिग्नल प्रणाली में खराबी रही। यदि कवच प्रणाली लग चुकी होती तो एक ही रेलवे ट्रैक पर दो ट्रेनों का आना संभव नहीं होता और यदि भूलवश हरी झंडी दे भी दी गई थी तो दोनों ट्रेनों के एक ही ट्रैक पर होते ही पांच किमी. दूर ही उनमें ब्रेक लग जाते जिससे दुर्घटना हो ही नहीं सकती थी। रेलवे के आधुनिकीकरण और हाई स्पीड ट्रेन चलाने से पहले रेलवे और सरकार को रेलवे का सुरक्षा तंत्र मजबूत करना होगा।

संजय डागा, इंदौर

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 307

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

पुनरोद्धार नालंदा

नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन सुखद और अविस्मरणीय है। परिसर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत की शैक्षणिक विरासत और जीवंत सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रतीक है। इसमें कोई शक नहीं कि यह विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय गौरव है और इसे बहुत लगाव और गुणवत्ता के साथ विकसित करना चाहिए। जो पवित्रता और गरिमा लगभग 800 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय को प्राप्त थी, उसकी बहाली अगर आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय अपने नए परिसर में कर सके, तो यह पूरे मानव समाज की बड़ी सेवा होगी। वैसे, नालंदा विश्वविद्यालय की परिसर के साथ स्थापना का कार्य पहले भी किया जा सकता था, पर इसे नष्ट करने की जो त्रासद स्मृतियां हैं, वह नए दौर में भी बार-बार राह में आ खड़ी हो जाती थीं। हम ऐसे देश के वासी हैं, जहां किसी का दिल दुखाने वाली बात सोचना भी अमानवीयता है, तभी तो उस आक्रांता के नाम पर आज भी एक रेलवे स्टेशन है, जिसे भारतीय संस्कृति से भयंकर घृणा थी। अब भारत की नई पीढ़ी अगर शांतिपूर्वक सुधार या बदलाव की ओर बढ़ी है, तो उसका स्वागत करना चाहिए।

वास्तव में इस विश्वविद्यालय के पुनर्जीवन की कल्पना भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग के रूप में की गई थी। उद्घाटन समारोह में 17 देशों के दूतावास प्रमुखों की मौजूदगी सहज ही प्रमाण है कि प्राचीन विश्वविद्यालय की स्मृति दुनिया के एक बड़े क्षेत्र में लोगों के ज्ञान संस्कार में शामिल है। करीब 1,600 साल पहले स्थापित मूल नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। उस पुरानी भव्यता, प्राचीनता और गुणवत्ता के साथ नालंदा विश्वविद्यालय की वापसी तो कतई संभव नहीं, पर जो भी विश्वविद्यालय स्थापित या विकसित हो रहा है, उस पर अनेक देशों के गुणी लोगों की निगाह रहेगी। ध्यान रहे, भारत के अलावा 17 देशों ने नालंदा विश्वविद्यालय को समर्थन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। यह भी ध्यान रहे कि गैर-सनातन व विविध धर्म वाले देशों की सरकारें भी नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्जीवन देखना चाहती हैं। मतलब, यह आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान के विस्तृत पटल पर तमाम वैमनस्य भुलाकर आगे बढ़ने की जरूरत और बढ़ती समझ का भी प्रमाण है। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मेलजोल के अभाव और कट्टरता की वजह से ही प्राचीन नालंदा का विनाश हुआ था। भारतीय समाज में जब कट्टरता घटी और समझ बढ़ी, तभी नालंदा के पुनर्जीवन का विचार अवतरित हुआ।

इसमें कोई शक नहीं कि यह विशेष विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय गौरव है और इसे बहुत लगाव व गुणवत्ता के साथ विकसित करना चाहिए।

अब यह स्वर्णिम इतिहास में दर्ज है कि नालंदा के प्राचीन खंडहरों के पास ही नया परिसर स्थापित हुआ, जिसका निर्माण साल 2017 में शुरू हुआ था। वैसे, साल 2007 में, जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तभी फिलीपींस में आयोजित दूसरे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का फैसला लिया गया था। मनमोहन सिंह सरकार ने ही साल 2010 में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। साल 2014 में 14 छात्रों के साथ पढ़ाई-लिखाई का क्रम भी शुरू हुआ। इस सुखद सपने को नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वतंत्र परिसर देकर जिस तरह आगे बढ़ाया है, उसकी प्रशंसा होनी ही चाहिए। अच्छे कामों और अच्छी परंपराओं को बल मिलता रहे। दीप से दीप जलाने और आगे बढ़ते जाने का यही सही तरीका है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले
20 जून, 1949

दिल्ली के सवाल पर नेहरू

दिल्ली, १९ जून। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने आज दिल्ली प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन में अपने ८० मिनट के भाषण में देश के सामने उपस्थित लगभग सभी प्रश्नों पर प्रकाश डाला। देश के विविध हिस्सों में कम्यूनिस्ट उपद्रवों की चर्चा करते हुए आपने कहा कि हिन्दुस्तान के कम्यूनिस्ट हमारी आजादी के पौधे को ही उखाड़ फेंकना चाहते हैं। शरत बाबू की जीत के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी अहमियत को कम करना असलियत से आंखें बन्द करना है। आपने कहा कि अगर अब भी कांग्रेसजन अपने दिलों को टटोलने को तैयार नहीं हैं तो अच्छा है हम शान के साथ कांग्रेस को खत्म कर दें और कोई दूसरा काम शुरू कर दें।

देश के पूंजीपतियों को चेतावनी देते हुए नेहरूजी ने कहा कि अगर उन्होंने उद्योग-धंधों में अपने पैसे न लगाये तो बहुत सम्भव है कि जनता के दबाव से सरकार को पुरानी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बदलने में तेजी से कदम उठाने पड़ें। भारत के नये विधान के बारे में प्रधानमंत्री ने बताया कि भारतीय गणतंत्र का एलान करने के लिए २६ जनवरी १९५० का शुभ दिन निश्चित किया गया है। आपने यह भी प्रकट किया कि १९५० की सर्दियों में आम चुनाव हो सकेंगे।

सम्मेलन द्वारा दिल्ली प्रान्त में जिम्मेदार हुकूमत के लिए की गई मांग का उल्लेख करते हुए नेहरूजी ने कहा कि यहां भी अन्य प्रान्तों की तरह जिम्मेदार हुकूमत होनी चाहिए, इस बारे में कोई दोराय नहीं हो सकती। मगर देश की राजधानी होने के कारण यहां बहुत से सवाल ऐसे पैदा होते रहते हैं, जिनका दिल्ली में रहने वालों से कोई सरोकार नहीं होता। अमरीका की राजधानी वाशिंगटन का इन्तजाम भी वहां की केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। चूंकि राजधानी देश की सब बातों का केन्द्र बन जाती है, इसलिए उसे किसी अलग प्रान्तीय राज्य के मातहत करने में बहुत से पेच पड़ जाते हैं। मगर केन्द्रीय समस्याओं की वजह से दिल्ली प्रान्त के १५ लाख लोगों को मजबूर किया जाये यह भी कोई मुनासिब चीज नहीं है। हम कोई ऐसा तरीका निकाल रहे हैं जिससे यहां के लोगों को भी उनके हकूक मिल जायें और राजधानी के नाते दिल्ली की जो हैसियत है, वह भी बनी रहे।

ब्रिटिश चुनाव में फिर भारतवंशी बयार

यहां स्कैन करें

हर्ष वी पंत | प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन

यहां भारतवंशियों की पहचान बदल रही है और वे नेतृत्व की भूमिका में आने लगे हैं। नतीजतन, भारत से जुड़े मुद्दे प्रभावी दिखने लगे हैं। इसकी झलक पिछले चुनाव में भी दिखी थी।

अगले महीने की 4 तारीख को ब्रिटेन में आम चुनाव होने जा रहे हैं। अगर ये अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक होते, तो साल के आखिरी महीनों में मतदान होता। मगर भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने समय-पूर्व चुनाव में उतरने का फैसला किया, जिसकी वाजिब वजह भी थी। दरअसल, सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की लोकप्रियता तेजी से गिर रही थी। मतभेद पार्टी के अंदर भी थे। 14 साल से भले ही यह सत्ता में है, लेकिन नेतृत्व के मोर्चे पर पिछले कुछ वर्षों में पार्टी में उथल-पुथल की स्थिति बनी हुई है। लिहाजा, प्रधानमंत्री सुनक का मानना था कि पार्टी के अंदरूनी मतभेद को खत्म करने और जनता का भरोसा फिर से जीतने के लिए चुनाव में उतरना सही होगा। आर्थिक मोर्चे पर देश को मिले फायदे से उन्हें अपनी इस योजना को साकार करने में मदद मिली।

बहरहाल, ऋषि सुनक भले ही सत्ता में वापसी के सपने देख रहे हैं, पर चुनावी रुझान विपरीत हैं। ये बता रहे हैं कि ये चुनाव न सिर्फ ब्रिटिश राजनीति पर दूरगामी असर डाल सकते हैं, बल्कि इसे बुनियादी रूप से बदल भी सकते हैं। कई आंकड़ों में तो विरोधी लेबर पार्टी की बड़ी जीत की संभावना जताई जा रही है। समर्थकों की नजर में यह दूसरे विश्व युद्ध के बाद पार्टी की सबसे बड़ी जीत हो सकती है। असल में, साल 1997 में टोनी ब्लेयर ने लेबर पार्टी को मध्यमार्गी बनाकर और 'न्यू लेबर' की वकालत करके कंजर्वेटिव पार्टी से सत्ता छिनी थी। मगर 2010 में डेविड कैमरन के नेतृत्व में कंजर्वेटिव सांसद फिर से सरकार बनाने में सफल रहे। यहां तक कि 'ब्रेग्जिट' के बाद भी उन्हें सफलता मिली और कंजर्वेटिव को 'पार्टी ऑफ गवर्नेंस' कहा जाने लगा। अब लेबर पार्टी भी मध्यमार्ग पर चल पड़ी है।

वैसे, इस चुनाव में कुछ छोटी पार्टियां की भी अहम भूमिका हो सकती है। मसलन, ब्रेग्जिट के एक महत्वपूर्ण किरदार नाइजले फराज की रिफॉर्म यूके पार्टी कंजर्वेटिव के वोट काटती दिख रही है। बेशक, यह बहुत ज्यादा सीटें न जीत सके, लेकिन नई पार्टी के तौर पर अपनी धमक जरूर दिखा रही है। यह संकेत है कि कंजर्वेटिव के प्रति बेरुखी के कारण लोगों का भरोसा दूसरी पार्टियों में बढ़ा है।

सत्तारूढ़ दल के प्रति यह नाराजगी यूं ही नहीं पनपी है। विशेषकर, कोविड महामारी के बाद से लोगों की आर्थिकी बहुत नहीं संभल सकी है। यहां रहने का खर्च बढ़ गया है और महंगाई भी ज्यादा है। लिहाजा, यह धारणा बन चली है कि 'शासन के लिए' बनी पार्टी अब देश संभालने में सक्षम नहीं रही। इसी तरह, आप्रवासन भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। कहा गया था कि ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन को इस मामले में स्वायत्तता मिल जाएगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। नेशनल हेल्थ सर्विस जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में फंड की कमी, टैक्स का बढ़ना आदि मुद्दे भी कंजर्वेटिव की सियासी जमीन ढीली कर रहे हैं।

ये चुनाव ब्रिटेन में रहने वाले करीब 20 लाख भारतवंशियों के लिए भी अहमियत रखते हैं। इनकी भूमिका चुनावों में लगातार बढ़ रही है। वहां हिंदू-मुस्लिम-सिख संबंधी मुद्दे भी उठ रहे हैं। 'हिंदू फॉर डेमोक्रेसी' नाम के समूह ने हिंदू घोषणापत्र तक जारी कर दिया है। पहले भारतवंशियों का वोट लेबर पार्टी को जाता था, लेकिन जैसे-जैसे यह आबादी समृद्ध होती गई, कंजर्वेटिव की तरफ इसका रुझान बढ़ता गया है। साल 2019 के चुनाव में 10 से अधिक भारतवंशियों का चुना जाना इसी की तस्दीक कर रहा था, जिनमें ऋषि सुनक एक बड़ा नाम थे। यहां भारतवंशियों की पहचान बदल रही है और वे नेतृत्व की भूमिका में आने लगे हैं। नतीजतन, भारत से जुड़े मुद्दे चुनावों में प्रभावी दिखने लगे हैं। इसकी झलक पिछले चुनाव में भी दिखी थी, जब भारतीय उच्चायोग के सामने खालिस्तानियों के हिंसक प्रदर्शन का समर्थन लेबर पार्टी के कुछ नेताओं ने किया था, जिसके विरोध में भारतवंशियों ने कंजर्वेटिव का साथ देकर उनको सत्ता दिला दी। भारतवंशियों पर कंजर्वेटिव की पकड़ अब भी मजबूत है, क्योंकि उसकी नीति भारत के हित में रही है। इतना ही नहीं, यहां भारतवंशियों की एक बड़ी आबादी कारोबार में लिप्त है और कंजर्वेटिव को बिजनेस-समर्थक पार्टी माना जाता है।

भारत से जुड़े मुद्दे यहां के चुनावों में किस कदर हावी रहते हैं, इसका एक ताजा उदाहरण है, कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार द्वारा कश्मीर मुद्दे को उठाना। चूंकि ब्रिटेन के कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों में पाकिस्तान से आए प्रवासियों का प्रभुत्व है, इसलिए यहां भारत-विरोधी नैरेटिव भी खूब चलाए जाते हैं। इस बार भी टोरी उम्मीदवार मार्को लोंगी ने एक पत्र लिखकर मतदाताओं से अपील की कि कश्मीर के मुद्दे को यदि संसद में उठाना है, तो लेबर पार्टी के बजाय उनको वोट दिया जाए। हालांकि, इसकी काफी तेज प्रतिक्रिया हुई है। खुद कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर इस पत्र को लेकर तीखा विरोध देखा गया है। वास्तव में, यहां भारतवंशियों की भूमिका जिस तेजी से बदली है, दोनों बड़ी पार्टियां खुद को भारत-समर्थक बताने की कोशिशों में है। इसी कारण, पिछले कुछ वर्षों में ब्रिटेन ने भारत के प्रति अपनी कूटनीति भी बदली है।

ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब ब्रिटेन भारत की तुलना में पाकिस्तान और चीन के साथ खड़ा दिखता था, क्योंकि अंदरूनी राजनीति उसे इस्लामाबाद के खिलाफ जाने नहीं देती और बीजिंग के साथ उसके अहम आर्थिक रिश्ते थे। मगर डेविड कैमरन के कार्यकाल में यह स्थिति बदली और द्विपक्षीय रिश्ते में लगातार सुधार किया गया। खासतौर से, ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन को नए बाजार और नई विदेश नीति की जरूरत थी, जिस कारण ब्रिटिश शासकों ने हिंद-प्रशांत पर जोर देना शुरू किया। यहां उन्होंने नए सहयोगी ढूंढ़े और सत्ता का संतुलन साधने का प्रयास किया। चूंकि हिंद-प्रशांत का एक बड़ा खिलाड़ी भारत है, इसलिए नई दिल्ली के साथ लंदन ने अपने सामरिक और आर्थिक, दोनों संबंध बेहतर किए। उम्मीद है, यह रिश्ता ब्रिटेन में संभावित सत्ता परिवर्तन के बाद भी कायम रहेगा, क्योंकि भारत तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भरोसा यह भी है कि उस मुक्त व्यापार समझौता पर भी अब आखिरी सहमति बन जाएगी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि समय-पूर्व चुनाव के कारण इसे टाल दिया गया है। अगर यह समझौता साकार हुआ,, तो दोनों देशों के रिश्ते एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

लगातार बढ़ती गरमी से बढ़ी सबके स्वास्थ्य की चिंता

यहां स्कैन करें

के श्रीनाथ रेड्डी | जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ

साल 2024 भले ही मानव इतिहास में अब तक के सबसे गरम वर्ष के रूप में रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया है, पर आश्चर्य नहीं, अगर यह साल 2025 के हाथों अपना खिताब खो बैठे। आने वाले वर्षों में गरमी के रिकॉर्ड बार-बार बनेंगे-टूटेंगे, क्योंकि जलवायु संकट गहराता चला जाएगा। मानवीय मूर्खताओं का आभार, जो गरम हवाओं की मुख्य वजह बन गई हैं। अनुमान लगाया गया है कि एक अरब भारतीयों ने अप्रैल 2022 में 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान महसूस किया था। मई-जून 2024 में यह संख्या और अधिक हो जाएगी। तापमान बढ़ने से स्वास्थ्य पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि गरमी शरीर व दिमाग को बहुत पीड़ा देती है।

इन दिनों लू की वजह से मौतें भी खूब हो रही हैं। शरीर में पानी की कमी से रक्त वाहिकाओं पर गरमी का दबाव बढ़ जाता है, जिससे थक्के जमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और मस्तिष्क आघात व दिल का दौरा पड़ता है। गुरदे में रक्त का प्रवाह कम होने से गुरदा शिथिल पड़ सकता है या खराब भी हो सकता है। फेफड़ों की पुरानी बीमारी बिगड़ सकती है। मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य विकार बढ़ सकते हैं। यहां तक कि मोतियाबिंद में तेजी से आंखों की रोशनी भी खराब हो सकती है।

शिशु और छोटे बच्चे वयस्कों की तुलना में ज्यादा असुरक्षित होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में पानी की मात्रा अधिक होती है और शारीरिक प्रणालियां प्रभावी ताप अनुकूलन के लिए तीव्र प्रतिक्रिया को सक्षम करने को पर्याप्त परिपक्व नहीं होती हैं। बुजुर्ग भी काफी असुरक्षित हैं। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गुरदे की शिथिलता या कैंसर जैसे रोगों के मरीज भी ऐसे ही होते हैं। अत्यधिक गरमी के कारण गर्भावस्था के प्रतिकूल परिणाम भी सामने आते हैं। स्वाभाविक ही है कि हाल के वर्षों में जलवायु संकट से निपटने की ओर वैश्विक स्तर पर ध्यान जाने लगा है और लोग सावधान होने लगे हैं।

लू को स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए आपातकाल मानते हुए व्यक्तिगत, घरेलू, स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर उपाय होने चाहिए।

साल 2015 में पेरिस के कॉप सम्मेलन में जलवायु अनुकूलन की जरूरत को स्पष्ट किया गया था, तो दुबई में 2023 कॉप ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राष्ट्रीय क्षमताओं को मजबूत करने की जरूरत को रेखांकित किया था। अब यह अच्छी तरह स्पष्ट हो चुका है कि निम्न व मध्यम आय वाले देशों ने जलवायु संकट बढ़ाने में कम योगदान दिया है, वहीं गरीब या अभावग्रस्त देश जलवायु संकट के सबसे बुरे शिकार हैं। इसलिए उन्हें अनुकूलन की सर्वाधिक जरूरत है।

अब दुनिया के एक बड़े हिस्से में लू से बचाव के उपाय व्यक्तिगत, घरेलू, स्थानीय व राष्ट्रीय स्तर पर होने चाहिए। सीधे सूरज के नीचे या संपर्क में आने से बचना चाहिए। विशेष रूप से सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर निकलने पर तीव्र गरमी से बचने के उपाय करने चाहिए। गरमी के समय में ढीले-ढाले, हल्के रंग के सूती कपड़े पहनकर छायादार रास्तों पर चलने को तरजीह देनी चाहिए। सिर को टोपी और आंखों को धूप के चश्मे से बचाना समझदारी है। ये सभी सामान्य सूचनाएं हैं, लेकिन जब लोग इन सामान्य सावधानियों के प्रति उदासीन रहते हैं, तो उनके स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडराने लगता है। कमजोर लोगों के लिए थोड़ी देर की लापरवाही भी बहुत भारी पड़ती है। तरल पदार्थ के सेवन के मुख्य स्रोत के रूप में पानी का सेवन बहुत बढ़ा देना चाहिए। एसी, कूलर, पंखे घर को ठंडा रखने में मदद करते हैं, जबकि गीले परदे विकल्प के रूप में काम कर सकते हैं। घर में और उसके आस-पास हरे-भरे क्षेत्रों का शीतलन प्रभाव होता है। नशा और कैफीनयुक्त पेय पदार्थों के सेवन से बचना ही बेहतर है। बढ़ती गरमी से बचना अब एक सामूहिक नागरिक जिम्मेदारी है। गांव हो या शहर, बचाव के तमाम उपाय मिलकर करने चाहिए।

विशेष रूप से गरमी 'महामारी' से निपटने के लिए, शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में आपातकालीन परिवहन सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। लोगों को हीट स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति को तत्काल ठंडक पहुंचाने के लिए प्रथम उपचार की खातिर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। बढ़ते तापमान को देखते हुए आने वाले समय में जब अत्यधिक गरमी एक सामान्य घटना बन जाएगी, तब लोगों को उसके अनुरूप तैयार रखना जरूरी हो गया है, ताकि कोई जीवन खतरे में न पड़े।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

मनुष्य असीम हो नहीं सकता

किसी साधक ने मूझसे पूछा, 'आखिर क्या कारण है कि तमाम उपलब्धियों के बावजूद हर मनुष्य को एक समय पर यह महसूस होता है कि वह शक्तिशाली नहीं है?'

दरअसल, इस संसार में सब कुछ सीमित है, इसलिए क्षमताएं और संसाधन भी सीमित हैं। व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी शक्ति अनंत नहीं हो सकती, क्योंकि उसका अस्तित्व सीमित है। सिर्फ परम पुरुष के पास अनंत शक्ति है। मनुष्य के पास एक शरीर है और उसके शरीर से सूक्ष्म उसका मन है। चूंकि मन सूक्ष्म होता है, इसलिए उसकी क्षमता अधिक होती है। फिर भी, मन की क्षमताएं सीमित हैं, क्योंकि यह एक सीमित दायरे में ही सोच सकता है। आपका मस्तिष्क इस दुनिया के हर विचार को ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे, एक सामान्य व्यक्ति को अतिमानस जगत, यानी मन की सूक्ष्मतर परतों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके लिए स्वयं को समझना आसान नहीं है और दूसरों को समझाना भी आसान नहीं है।

कई लोगों को आत्मा के प्रवचन सुनने का अवसर ही नहीं मिलता। जो सुनते हैं, उनमें से कई समझ नहीं पाते। समझने की क्षमता रखने वालों में कुछ ही लोग सुनते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। विचारों को ग्रहण करने की क्षमता बहुत सीमित है। यहां तक कि अगर विचार की एक अवधारणा बनती है, तो दिमाग की वास्तविक समझ में गहरा प्रतिबिंब और शोध शामिल होता है। यह क्षमता बहुत कम लोगों के पास होती है। एक व्यक्ति जो समझ गया है, उसे व्यक्त करना भी बहुत मुश्किल होता है। अब गरमी के उदाहरण को ही लें; लोग किसी वस्तु की गरमी को दो चरम सीमाओं के बीच सहन कर सकते हैं। मगर जब गरमी एक निश्चित तापमान से अधिक बढ़ जाती है, तब किसी के पास इसको सहन करने की क्षमता नहीं रह जाती। इसी तरह, जब ठंड बहुत बढ़ जाती है, तो लोगों के पास इसे भी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं बचती।

ऐसी चीजें हमारी क्षमता की सीमितता के कारण होती हैं। हम निम्न से उच्च प्रकाश तीव्रता की एक विशिष्ट सीमा के भीतर वस्तुओं को देख सकते हैं। इससे कम प्रकाश स्तर पर या चमक के एक निश्चित स्तर से परे देखने में असमर्थ होते हैं। इसलिए, मनुष्य को सीमाओं के भीतर काम करना पड़ता है। अहंकार, श्रेष्ठता बोध और बाकी सब कुछ एक दायरे में सिमटा हुआ है।

मनुष्य की ताकत, उसका अहंकार, श्रेष्ठता बोध और बाकी सब कुछ एक दायरे में सिमटा हुआ है, उसका मस्तिष्क इस दुनिया के हर विचार को ग्रहण नहीं कर सकता।

दूसरी ओर, यदि आप परम पुरुष की ऊर्जा और क्षमता के बारे में सोचेंगे, तो महसूस करेंगे कि परम पुरुष इस ब्रह्मांड के निर्माता हैं। लेकिन मनुष्य इस विशाल सृष्टि को पूर्ण रूप से न तो सुन सकता है और न ही देख सकता है। वह परम पुरुष की विशाल रचना का एक प्रतिशत भी देख या सुन नहीं सकता।

श्री श्री आनंदमूर्ति

आशुतोष राणा | अभिनेता

पानी का अनियंत्रित प्रवाह बाढ़ बनकर गांवों को बहा देता है और वाणी का अनियंत्रित प्रवाह संबंधों को मिटा देता है। पानी व वाणी पर नियंत्रण करके ही हम अपनी बस्ती और हस्ती की रक्षा कर सकते हैं।

अनुलोम-विलोम
प्रियंका गांधी

चुनावी राजनीति में उतरने का सही फैसला

प्रियंका गांधी की खासियत क्या है? वह संगठन में सबको साथ लेकर चलने में दक्ष हैं, हाजिर जवाब हैं, दबाव में भी निखरना जानती हैं और सबसे बड़ी बात, लोगों से सीधा मुखातिब होती हैं। यही कारण है कि कई लोग उनमें उनकी दादी इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं। कांग्रेस के पास जब ऐसी शख्सियत है, तो उनको चुनावी राजनीति से भला क्यों दूर रखा जाए! इसीलिए प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाने का फैसला उचित है। यहां इस बहस का कोई अर्थ नहीं कि वह उप-चुनाव से क्यों सदन में आना चाहती हैं? सच तो यह है कि इस बार मतदाताओं ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है और उसे सम्मानजनक सीटें दी हैं। ऐसे में, वायनाड जैसी सीट को जाया करने का कोई मतलब नहीं है। लोकसभा में जब भाई और बहन एक साथ सरकार को घेरेंगे, तब वह काफी प्रभावी स्थिति होगी। वैसे भी, प्रियंका काफी दक्ष नेता हैं और सीधे, पर शालीन हमला करने में विश्वास करती हैं। राहुल गांधी ने अब खुद को साबित कर दिया है, इसलिए भाई-बहन की यह जोड़ी संसद में कांग्रेस की रणनीति को आगे बढ़ाने में काफी कारगर साबित हो सकती है।

प्रियंका के वायनाड से उप-चुनाव लड़ने से दक्षिण में पार्टी के आधार में इजाफा ही होगा। वायनाड के मतदाताओं की मांग नेहरू-गांधी परिवार के ही किसी सदस्य की थी। चूंकि, मुश्किल दिनों में केरल के लोगों ने कांग्रेस को संभाला है, इसलिए वायनाड के लोगों की मांग को पूरा करना आवश्यक था। यहां यह समझने की भूल न की जाए कि पूरी तरह राजनीति में आ जाने से उनकी छवि धूमिल होगी, अलबत्ता वह कहीं अधिक मजबूती से उभर सकती हैं। उनके जरिये कांग्रेस महिलाओं को साधने का प्रयास कर सकती है और संसद में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठा सकती है। इससे महिलाओं की कांग्रेस से नजदीकी बढ़ सकती है। आम चुनाव, 2024 में एनडीए की पुनर्वापसी की एक बड़ी वजह यह भी है कि महिला वोटरों ने प्रधानमंत्री पर भरोसा किया है। कांग्रेस इस वोटबैंक में सेंध लगाने का प्रयास कर सकती है। रही बात उत्तर प्रदेश की, तो राहुल गांधी का रायबरेली में रहना आवश्यक था। यहां विधानसभा उप-चुनाव होने वाले हैं और आम चुनाव में पार्टी ने जैसा प्रदर्शन किया है, उससे अगले विधानसभा चुनाव के लिए संगठन बनाने में उसे अभी से जुट जाना चाहिए। चूंकि राहुल अब स्थापित नेता बन चुके हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में वह कहीं ज्यादा प्रभावी होंगे। प्रियंका पर कांग्रेस का दांव एक सटीक रणनीति है।

सोनाली, टिप्पणीकार

उप-चुनाव लड़ने से छवि प्रभावित होगी

यह किसी भी दल का आंतरिक फैसला होता है कि वह अपने नेताओं को कहां से और कब चुनाव लड़ाए? इसके लिए वह दल की वर्तमान स्थिति और भविष्य का विधिवत आकलन करता है। हां, यह अलग बात है कि जनता उस निर्णय पर अपनी सहमति दे अथवा नहीं, यह तो चुनावी नतीजे से स्पष्ट होता है। इस पृष्ठभूमि में यदि प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले को देखें, तो निस्संदेह संभावना यही अधिक है कि कांग्रेस के फैसले को जनता मंजूर कर लेगी, लेकिन कुछ बातें हैं, जो बताती हैं कि वायनाड जैसी सुरक्षित सीट से उप-चुनाव के जरिये लोकसभा पहुंचने की प्रियंका गांधी की रणनीति उचित नहीं है।

प्रियंका यूं तो अपनी माता सोनिया गांधी का चुनाव प्रचार अपने भाई राहुल गांधी के राजनीति में आने के पहले से कर रही हैं। यह भी एक वजह है कि आम विमर्श में आमतौर पर उनको राहुल गांधी की तुलना में अधिक परिपक्व व मीडिया के सामने कहीं अधिक सहज नेता माना जाता है। अब तक वह पार्टी में सांगठनिक तौर पर सक्रिय रही हैं और सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत, सुखविंदर सिंह सुक्खू बनाम प्रतिभा सिंह या डीके शिवकुमार बनाम सिद्धारमैया जैसे कई अंतर्कलहों से पार पाने में सफलता हासिल की है। इस कारण, चुनावी राजनीति से वह दूर भी रहीं, जो आज के संदर्भ में भी उचित फैसला था। संसदीय राजनीति में सक्रियता से वह संगठन से दूर हो सकती हैं, जिसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है।

प्रियंका को चुनाव में उतारना कांग्रेस की मजबूरी हो सकती है, मगर उन्हें खुद किसी सुरक्षित सीट से अपनी संसदीय पारी का आगाज नहीं करना चाहिए था। इससे गलत संदेश जाएगा। अव्वल तो वह आम चुनाव में किसी क्षेत्र में अपना भाग्य आजमातीं, लेकिन अब जब ऐसा नहीं हो सका, तो वायनाड जैसी किसी सुरक्षित सीट से ठीक उसी तरह का दांव खेला जा सकता था, जिस तरह अमेठी में कांग्रेस ने रणनीति अपनाई और अपने एक आम कार्यकर्ता पर भरोसा किया। इससे प्रियंका की छवि भी कमजोर नहीं होती और पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह बढ़ जाता।

बहरहाल, पार्टी के फैसले से लगता है कि उनको दक्षिण भारत में धकेलकर राष्ट्रीय फलक और इसकी धुरी उत्तर प्रदेश से उनको दूर किया जा रहा है, ताकि भाई राहुल के लिए राह आसान हो सके। यहां तो बस यही शेर याद आता है-

कभी हवा, कभी लहरें, तो कभी भंवर,
कश्ती इम्तहान लेंगे/ बस साहिल पर उतर जाना, कितने माहिर हो सब जान लेंगे।

दिनेश सिंह, चिकित्सक

https://t.me/AIINewsPaperPaid

कई बार संकोच ही सफलता की राह बाधित कर देता है

हद पार करता कनाडा

कनाडा की संसद ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत की पहली बरसी पर जिस तरह उसे श्रद्धांजलि दी, वह आतंकवाद का बेशर्मी से किया जाने वाला महिमामंडन है। एक आतंकी के प्रति आंसू बहाकर केवल खालिस्तानी आतंकियों के प्रति ही नरमी का परिचय नहीं दिया गया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया गया कि कनाडा सरकार संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए भारत से संबंध बिगाड़ने पर तुली हुई है। कनाडा सरकार की इस हरकत से यह भी साफ है कि चंद दिनों पहले वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इटली में भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार को लेकर जो कुछ कहा था, वह छलावा था और वह खालिस्तानी आतंकियों-अतिवादियों के प्रभाव में आकर अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक मर्यादा भी भूल चुके हैं। कनाडा की संसद ने जिस हरदीप सिंह निज्जर को याद किया, वह वही है, जिसे भारत ने आतंकी घोषित किया था और जो फर्जी दस्तावेजों के साथ कनाडा जाने में सफल रहा था। खालिस्तानी अतिवादियों की गुटीय लड़ाई में उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन कनाडा सरकार ने बिना किसी प्रमाण इसका दोष कथित भारतीय एजेंट पर मढ़ा। माना कि जस्टिन ट्रूडो की अल्पमत सरकार खालिस्तानी चरमपंथी जगमीत सिंह के नेतृत्व वाले दल के समर्थन से सत्ता में टिकी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह भारत में अलगाववाद और आतंकवाद की पैरवी करने वाले तत्वों की जी-हुजूरी करने लगें। वह यही कर रहे हैं। ऐसा करके वह भारत से संबंध खराब करने के साथ ही कनाडा की छवि और आतंरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि कनाडा में सक्रिय खालिस्तानी किस तरह नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त हैं और उनके इशारे पर पंजाब में टारगेट किलिंग होती रहती है। जस्टिन ट्रूडो इससे अनजान नहीं हो सकते कि खालिस्तानी आतंकियों ने किस तरह एअर इंडिया के विमान कनिष्क को बम से उड़ा दिया था, जिसमें तीन सौ से अधिक लोग मारे गए थे। इनमें से अधिकांश भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे, फिर भी कनाडा सरकार ने इस भयावह आतंकी घटना की ढंग से जांच नहीं की थी और इसी कारण केवल एक खालिस्तानी आतंकी को मामूली सजा हुई थी। यह अच्छा हुआ कि वैंकूवर स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास 23 जून को कनिष्क विमान हादसे की बरसी पर एक आयोजन करने जा रहा है। और भी अच्छा होगा कि नई लोकसभा में भी इस घटना का स्मरण कर कनाडा सरकार को शर्मसार किया जाए। कनाडा सरकार के प्रति सख्ती का परिचय देना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि कनाडा में खालिस्तानी आतिवादी खुलेआम भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने में लगे हुए हैं। वे कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों, उनके धार्मिक स्थलों और भारत के राजनयिकों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन गए हैं।

बांधों की देखरेख जरूरी

बिहार में दो से तीन दिनों में मानसून के आने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अब तक कई जिलों में बाढ़ से बचाव की तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं। बाढ़-सुखाड़ के पूर्व की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सतर्क करने के बाद जिलों में अधिकारी सक्रिय हुए हैं। प्रखंडों में भी समीक्षा बैठकें शुरू हुई हैं। ऐसी ही एक बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि मुजफ्फरपुर जिले में कई जगहों पर बांध क्षतिग्रस्त हैं। कटरा से शिवदासपुर के बीच बागमती परियोजना के बांध में दर्जनों जगह रेनकट होने से इसके टूटने का खतरा बना हुआ है। ऐसी स्थिति सिर्फ मुजफ्फरपुर की ही नहीं है, कई अन्य जिलों में भी कमजोर तटबंधों की मरम्मती का काम पूरा नहीं हो पाया है। इन क्षतिग्रस्त बांधों को यथाशीघ्र दुरुस्त कर लेना होगा। बांधों के साथ स्लुस गेटों की भी देखरेख करनी होगी। सड़कों पर पड़ने वाले पुल-पुलियों के नीचे जमी गाद को भी हटाने की जरूरत है। बांधों की मजबूती और उनकी देखरेख के लिए पहले ही राशि जारी कर दी गई थी। कहने की जरूरत नहीं कि बाढ़ से बचाव के लिए जिन योजनाओं पर काम चल रहा है, उसकी सख्त मानीटरिंग की जाए, ताकि काम पर कोई सवाल नहीं उठे। उत्तर और पूर्व बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इन जिलों में मानसून से पहले हर वर्ष बचाव की तैयारी होती है। तटबंधों की मरम्मती का काम शुरू होता है, लेकिन बारिश के बाद इसके टूटने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि इसकी जिम्मेदारी तय हो।

मानसून से पहले बाढ़ जैसी आपदा से बचाव की तैयारी पूरी कर लेनी होगी। कई जिलों में नदियों पर बने बांध क्षतिग्रस्त हैं, जिसकी मरम्मत जरूरी है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या एक साथ दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगना चाहिए?

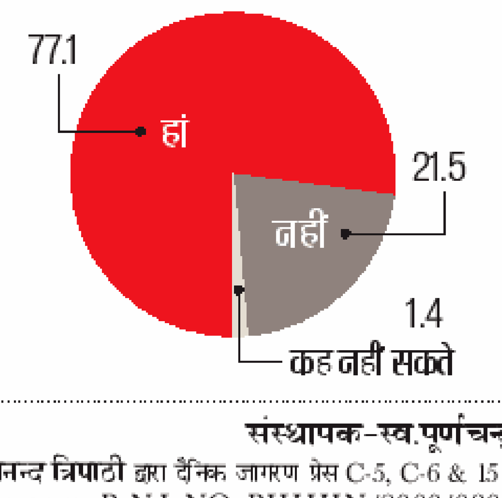

आज का सवाल

क्या लोकसभा उपाध्यक्ष पद के लिए विपक्ष की दावेदारी सही है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

मोदी और मुसलमान

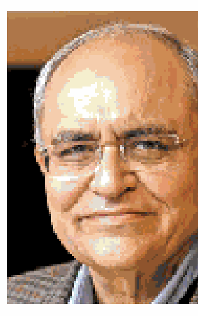

बलबीर पुंज

जब आजादी से पहले गांधी-नेहरू-पटेल मुस्लिमों का दिल नहीं जीत पाए, तो मोदी-शाह-योगी इसमें कैसे सफल हो सकते हैं?

अवधेश राजपूत

भाजपा लगातार तीसरी बार अपने दम पर बहुमत पाने से क्यों चूक गई? इसे लेकर समीक्षाओं का दौर जारी है। भाजपा के अपेक्षा से कमजोर प्रदर्शन का एक कारण यह भी सामने आया है कि मुस्लिम मतदाताओं ने भाजपा के खिलाफ रणनीतिक रूप से एकजुट होकर मतदान किया। सीएसडीएस-लोकनीति के सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जहां 65 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम मतदाताओं ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया। उत्तर प्रदेश में तो यह आंकड़ा 92 प्रतिशत तक रहा। भाजपा को जिन राज्यों में सीटों के संदर्भ में सर्वाधिक क्षति पहुंची, उनमें सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश का नाम है। यहां वह पिछली बार के मुकाबले आधी से कम सीटें जीत सकी। क्या वाकई मोदी सरकार या फिर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुस्लिम-विरोधी हैं? जैसा कि अक्सर वामपंथियों, स्वयंभू सेक्युलरवादी भाजपा विरोधी दलों द्वारा नैरेटिव गढ़ा जाता है?

क्या मुस्लिम समाज मोदी सरकार से इसलिए नाराज था, क्योंकि उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय हो रहा था? मोदी सरकार में ऐसी बीसियों योजनाएं है, जिनका लाभ करोड़ों लाभार्थियों को बिना किसी जातीय-मजहबी भेदभाव के आज भी मिल रहा है। देश की जनसंख्या में मुसलमानों की आबादी 15 प्रतिशत से अधिक है, फिर भी 'कौशल भारत योजना' के 1.23 करोड़ लाभार्थियों में लगभग 23 प्रतिशत मुस्लिम हैं। 'जनधन योजना' के अंतर्गत 52 करोड़ से अधिक खाते खुले, जिनमें सवा दो लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा है। इनमें 42 प्रतिशत खाते मुसलमानों के हैं। केवल उत्तर प्रदेश की बात करें तो 'प्रधानमंत्री आवास योजना' के 35 प्रतिशत, 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के 37 प्रतिशत, 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' के 30 प्रतिशत लाभार्थी मुस्लिम हैं। जबकि राज्य में मुस्लिम आबादी करीब 20 प्रतिशत है। जबकि मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में उनकी हिस्सेदारी 24-30 प्रतिशत है। इसके बावजूद राज्य में 90 प्रतिशत से अधिक मुसलमानों ने भाजपा को हराने के लिए वोट दिया। आखिर इस अंधविरोध का कारण क्या है?

भारतीय मुस्लिम समाज के एक बड़े वर्ग में कथित 'उपेक्षा', 'असंतोष' और 'असुरक्षा' का भाव पिछले 10-20 वर्षों से नहीं, अपितु आजादी के कई दशक पहले से व्याप्त है। तब इसे दूर करने के लिए गांधी जी ने उस घोर मजहबी और विशुद्ध विदेशी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसका तत्कालीन भारतीय मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं था। गांधी जी ने अप्रैल 1947 में वायसराय लार्ड माउंटबेटन के समक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों में अंतरिम सरकार की कमान सौंपने का प्रस्ताव तक रख दिया था, परंतु तत्कालीन मुस्लिम नेतृत्व टस से मस नहीं हुआ। वह इस्लाम के नाम पर अलग देश की मांग पर अड़ा रहा और अंततः भारत का विभाजन हुआ, जिसमें लाखों लोगों की जान गई। मुस्लिम समुदाय के बड़े हिस्से में भाजपा-विरोधी द्वेष-पूर्वाग्रह उनके उसी ऐतिहासिक अलगाव का हिस्सा है, जो सर सैयद अहमद खां के 'द्विराष्ट्र सिद्धांत' के समय से चला आ रहा है। हालिया चुनाव में मुस्लिम समाज ने इसी मंशा के साथ कांग्रेस सहित अन्य भाजपा विरोधी दलों का समर्थन किया।

क्या विभाजन से पूर्व कांग्रेस और मुस्लिम वर्ग में मधुर संबंध थे? 1937-38 में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों में मुस्लिमों पर अत्याचारों की जांच हेतु पीरपुर समिति का गठन किया। उसने रिपोर्ट में गोरक्षा, वंदे मातरम्, तिरंगा, दंगा, हिंदी भाषा और बहुसंख्यकवाद आदि विषयों को लेकर कांग्रेस को 'सांप्रदायिक' बताया था। बाद में अंग्रेजों और वामपंथियों के समर्थन से इन आरोपों को इस्लाम के नाम पर भारत के विभाजन हेतु मुख्य तर्क बनाया गया। यह आरोप एक सदी बाद भी जस का तस है। तब यह आरोप इकबाल-जिन्ना की मुस्लिम लीग ने वामपंथियों-अंग्रेजों के साथ मिलकर गांधी-पटेल-नेहरू की कांग्रेस पर लगाए थे और आज वही आक्षेप सोनिया-राहुल-प्रियंका की कांग्रेस मार्क्स-मैकाले मानसपुत्रों के साथ मिलकर मोदी-शाह-योगी की भाजपा पर लगा रही है।

आम चुनाव के दौरान ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी ने सार्वजनिक मंच से भाजपा को हराने के लिए 'वोट जिहाद' का आह्वान किया था। चुनाव परिणामों से ऐसा लगता है कि असल में ऐसी कोई संकल्पना सचमुच अस्तित्व में आ गई है। यह भी एक तथ्य है कि जिन राज्यों में 'वोट-जिहाद' के कारण भाजपा अपने बलबूते बहुमत लाने से चूक गई, वे राज्य स्वतंत्रता से पहले पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक आंदोलित थे। उस समय मुस्लिम लीग का समर्थन ही पाकिस्तान की हामी भरने जैसा था। तत्कालीन बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और बांबे (महाराष्ट्र) आदि राज्यों के भी 85-100 प्रतिशत मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का साथ दिया था। हालांकि उनमें से अधिकांश भारत छोड़कर गए ही नहीं और कांग्रेस में शामिल होकर एकाएक 'सेक्युलर' बन गए। इनमें मुस्लिम लीग के भी कई नेता थे, जैसे कि मोहम्मद इस्माइल। स्वतंत्रता से पहले वह जिन्ना और सांप्रदायिक आधार पर देश विभाजन के कट्टर समर्थक थे। 'अपने सपनों का पाकिस्तान' बनने के बाद इस्माइल न केवल लीग के अन्य कई नेताओं के साथ भारत में ही रह गए, बल्कि उन्होंने 1948 में मुस्लिम लीग के भारतीय संस्करण इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आइयूएमएल का गठन भी किया। यह दल 'सेक्युलर' तमगे के साथ भाजपा-विरोधी मोर्चे आइएनडीआइए का हिस्सा है। कुछ समय पहले राहुल गांधी ने इसे पक्का सेक्युलर दल करार दिया था। इसी दल के ईटी मोहम्मद बशीर ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के एकमात्र मुस्लिम प्रत्याशी अब्दुल सलाम को केरल की मलप्पुरम सीट पर साढ़े पांच लाख से अधिक वोटों से हराया।

कटु सत्य यही है कि भारतीय मुसलमानों के एक वर्ग को वही मुस्लिम नेता पसंद है, जो विचारों से कट्टरपंथी हो या वे उन्हीं स्वयंभू सेक्युलर दलों के मुख्य रूप से निकट हों, जो इस्लामी कट्टरता को पुष्ट करने में उनका प्रत्यक्ष-परोक्ष सहयोग करते हैं। यही कारण है कि उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम सरीखे मुसलमानों के बजाय मोहम्मद शहाबुद्दीन, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और औवेसी बंधु जैसे मुस्लिम नेता ही अधिक भाते है। यक्ष प्रश्न यही है कि जब आजादी से पहले गांधी-नेहरू-पटेल भारतीय मुसलमानों का दिल नहीं जीत पाए, तो अब इसमें मोदी-शाह-योगी कैसे सफल हो सकते हैं?

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)
response@jagran.com

दलबदलुओं के लिए कठिन होती राह

डा. जगदीप सिंह

यह एक शुभ संकेत है कि चुनावों में दलबदलू उम्मीदवारों के हारने का प्रतिशत बढ़ रहा है

लोकसभा चुनाव के परिणामों ने दल बदलने वाले नेताओं के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है। खासतौर पर हार का स्वाद चखने वाले ऐसे नेता अब अपने भविष्य को लेकर मंथन करने के क्रम में हैं। एक तो दल बदलने से लाभ नहीं मिला, वहीं अब पुरानी पार्टी में लौटने की गुंजाइश भी समाप्त है। वैसे अब ऐसे नेताओं के जीतने की संभावना भी कम होती जा रही है। इस बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दलबदल करने वाले नेताओं को जनता ने समर्थन नहीं दिया। चुनाव से पहले हर नेता भाजपा के टिकट को जीत की गारंटी मान रहा था। यही कारण रहा कि बड़ी संख्या में दूसरे दलों के नेता भाजपा में शामिल हुए, मगर टिकट पाने वाले ऐसे 25 में 20 नेता लोकसभा चुनाव हार गए। भाजपा का टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं का हाल भी कुछ अलग नहीं रहा। कांग्रेस का टिकट पाने वाले छह में से पांच नेता चुनाव हार गए। दल बदलना नेताओं के लिए नई बात नहीं है। नेता कई कारणों मसलन-टिकट न मिलने, दूसरी पार्टी में जीत की संभावना अधिक दिखने आदि से पार्टी बदलते हैं। इस वजह से देश में कई बार राजनीतिक अस्थिरता का दौर देखा गया है। सरकारें प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय खुद का अस्तित्व बचाने पर ज्यादा जोर देती रही हैं। पिछली सदी के सातवें दशक में 'आया राम-गया राम' का जुमला विधायकों के लगातार दलीय निष्ठा बदलने की पृष्ठभूमि में ही बना था।

भारतीय राजनीति में दलबदल का इतिहास काफी पुराना है। पहले और चौथे लोकसभा चुनाव के बीच दो दशक की अवधि में दलबदल के 542 मामले सामने आए थे। दलबदलू नेताओं के लिए सबसे अच्छा 1977 का आम चुनाव रहा था। आपातकाल के ठीक बाद हुए इस चुनाव में इंदिरा गांधी से मुकाबले के लिए कई राजनीतिक ताकतों ने हाथ मिलाया। तब चुनाव में उतरे 2,439 उम्मीदवारों में से 6.6 प्रतिशत यानी कुल 161 दलबदलू थे। इनकी सफलता दर 68.9 प्रतिशत थी, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। 1980 के लोकसभा चुनाव में कुल 4,629 उम्मीदवारों में से 377 यानी 8.1 प्रतिशत दलबदलू थे। इनमें से 20.69 प्रतिशत सफल हुए। 1984 का साल कांग्रेस में आने वाले दलबदलुओं के लिए अच्छा साबित हुआ। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर चल रही थी। तब कांग्रेस ने 32 दलबदलू उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 26 को जीत मिली। 1984 में भाजपा ने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। तब पार्टी से 62 दलबदलू उम्मीदवार लड़े थे, लेकिन किसी को भी जीत नहीं मिली।

मतदाताओं को नहीं भाए दलबदलू प्रत्याशी • फाइल

अगर 2004 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो कुल उम्मीदवारों में दलबदलू उम्मीदवारों का हिस्सा 3.9 प्रतिशत था और उनकी सफलता दर 26.2 प्रतिशत थी। 2014 में भाजपा के टिकट पर लड़ने वाले दलबदलू उम्मीदवारों की सफलता दर 66.7 प्रतिशत थी, वहीं कांग्रेस के लिए यह आंकड़ा 5.3 प्रतिशत था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 8,000 से अधिक उम्मीदवारों में अलग-अलग दलों के 195 दलबदलू उम्मीदवार मैदान में थे। इनमें से केवल 29 को ही जीत मिली। तब भाजपा के कुल उम्मीदवारों में 5.3 प्रतिशत दलबदलू थे, जिनमें से 56.5 प्रतिशत को जीत मिली। कांग्रेस के कुल उम्मीदवारों में 9.5 प्रतिशत दलबदलू थे, जिनमें से जीत सिर्फ पांच प्रतिशत को मिली। इस प्रकार 2019 के आम चुनावों में दलबदलू नेताओं की सफलता दर 15 प्रतिशत से कम रही, जबकि 1960 के दौर में औसतन लगभग 30 प्रतिशत दलबदलू नेता चुनाव जीत रहे थे।

ऐसा नहीं है कि इसे रोकने के लिए उपाय नहीं किए गए हैं। देश में एक मजबूत दलबदल विरोधी कानून है, जो नेताओं को दलीय निष्ठा बदलने से रोकता है। हालांकि यह कानून उस स्थिति में प्रभावी नहीं रह जाता, जब किसी दल से दो तिहाई जनप्रतिनिधि टूटकर किसी अन्य दल में शामिल होते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीतिक दल के सदस्य सांसदी या विधायकी से अयोग्य होने से बच जाते हैं। कानून में कमी यह है कि अयोग्यता से राहत दलबदल के पीछे के कारण के बजाय सदस्यों की संख्या पर आधारित है। इसका अंतरदलीय लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ता है और दल से जुड़े सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। लोकतंत्र में संवाद का अत्यंत महत्व है। जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसकी अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है, परंतु यह कानून जनता का नहीं, बल्कि दलों के शासन की व्यवस्था अर्थात 'पार्टी राज' को बढ़ावा देता है।

दुनिया के कई परिपक्व लोकतंत्रों में दलबदल विरोधी कानून जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों में यदि जनप्रतिनिधि अपने दलों के विपरीत मत रखते हैं या पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट करते हैं, तो भी वे उसी पार्टी में बने रहते हैं, परंतु भारत में कोई नेता पार्टी लाइन से अलग, किंतु महत्वपूर्ण विचार रखे तो भी उसे नहीं सुना जाता। इन सभी कारणों से भारतीय राजनीति में दलबदल एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। लोकतंत्र में जनता मतदान द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को संसद या विधानसभा के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनती है, लेकिन जब वह धन और पद के लालच में किसी अन्य दल में चला जाता है तो उसके विश्वास को ही तोड़ता है। आज की परिस्थितियों को देखते हुए दलविहीन लोकतंत्र ही भारत के लिए बेहतर है। ऐसा लोकतंत्र जिसका आदर्श समाज हो तथा जिसमें विरोधी और प्रतियोगिता-प्रतिस्पर्धा का स्थान व्यापक लोक कल्याण से प्रेरित सहयोग एवं सर्वोदय की भावना ने लिया हो।

(लेखक राजनीतिशास्त्री हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

स्वार्थ की विफलता

स्वार्थ में दो शब्द हैं। एक है स्व और दूसरा है अर्थ। इसमें से 'स्व' का अर्थ है अपना और 'अर्थ' का आशय है कामना की पूर्ति। इस तरह इस शब्द का अर्थ है अपनी इच्छा की पूर्ति। यह मनुष्य के जीवन की एक ऐसी वृत्ति है, जो उसे जन्म से ही प्राप्त होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी जो-जो कामना है, उसकी पूर्ति निरंतर होती रहे। इसकी इस चाह में सर्वप्रथम यह इच्छा होती है कि उसका यह शरीर सुंदर हो, सबल हो तथा स्वस्थ बना रहे। किंतु यह विडंबना है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। वह चाह कर भी अपनी इच्छा से न तो सुंदर हो सकता है, न सबल रह सकता है और न ही स्वस्थ रह सकता है। सुंदरता प्रकृति के अधीन है। जैसे ही प्रकृति ने चाहा वैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है। उसकी सबलता भी प्राकृतिक वातावरण तथा इसके खान-पान के अधीन होती है। स्वास्थ्य तो पूरी तरह से प्रकृति के अधीन ही है। इसी तरह से व्यक्ति यह सोचता है कि वह अपने माता-पिता, भाई-बंधु तथा पुत्र-पुत्रियों को भी स्वस्थ एवं प्रसन्न देखे। उसका पारिवारिक समूह पीड़ित तथा दुखी न रहे। किंतु स्थिति फिर भी वही होती है, जिससे वह कुछ करने की स्थिति में नहीं होता। सभी अपने-अपने कर्म के आधार पर फल भोगते हैं। कोई सुखी होता है तो कोई दुखी। कोई अपने जीवन में संपन्नता का अनुभव करता है और दूसरा लाख प्रयत्न करने के बाद भी विपन्न रहने से बच नहीं पाता। इसीलिए यह स्पष्ट है कि यह सब कुछ जो भी होता है, वह विधि-विधान का संयोजन है।

इस सबके विपरीत भी यदि व्यक्ति यह चाह ले कि उसे केवल अपना स्वार्थ ही सिद्ध करना है तब भी उसकी कामना की पूर्ति और संसार के भोग का सामर्थ्य उसके हाथ में नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है-जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, वचन और कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिसको पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए।

डा. गदाधर त्रिपाठी

पाठकनामा

pathaknama@pat .jagran.com

राष्ट्रीय हितों पर हो सशक्त संवाद

'राष्ट्रीय हितों पर बने सहमति' शीर्षक से लिखे आलेख में विवेक काटजू ने वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों का सटीक चित्रण करते हुए सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के मुद्दों पर सभी राजनीतिक दलों को सहमति बनाकर एकजुटता से काम करने से देश को लाभ मिलेगा। आज के दौर में जब राजनीतिक दलों के बीच टकराव चरम पर है, तब राष्ट्रीय हितों पर सहमति बनाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास किसी भी देश की नींव होते हैं। इन मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब देश सुरक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत होगा, तभी हम सभी की प्रगति संभव है। एक राष्ट्रीय नीति आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और पत्रकार शामिल हों। यह आयोग नियमित अंतराल पर मिलकर राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श और सर्वसम्मति से निर्णय ले। इससे न केवल त्वरित और प्रभावी निर्णय संभव होंगे, बल्कि देश की एकता और अखंडता भी बनी रहेगी। मीडिया की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे निष्पक्ष और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग करनी चाहिए। सनसनीखेज समाचारों से बचते हुए राष्ट्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव की आवश्यकता है। हमें बच्चों को शुरू से ही राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की महत्ता समझानी चाहिए। इसके लिए स्कूलों और कालेजों में संबंधित पाठ्यक्रम शामिल किए जाने चाहिए। अंत में हमें यह समझना होगा कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा में ही हमारी सुरक्षा और विकास निहित है। यदि हम सभी मिलकर काम करें तो निःसंदेह हमारा देश प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू सकता है।

अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

जी-7 की औपचारिक सदस्यता मिले

'राष्ट्रीय हितों पर बने सहमति ' शीर्षक आलेख में विवेक काटजू ने देश के सभी नवनिर्वाचित सांसदों को सलाह दी है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर सार्वजनिक विमर्श से लेकर संसद में कटुता का भाव त्याग कर सरकार का साथ दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मोर्चों पर त्वरित फैसलों के साथ शुरू हुआ। शपथ ग्रहण के कुछ दिनों के भीतर, पीएम मोदी जी-7 बैठक में भाग लेने के लिए इटली के अपुलीया गए, जो तीसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने के बाद उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा थी। जी-7 में भारत की भागीदारी विकसित पश्चिमी देशों को शामिल करने, एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति के रूप में भारत के उदय को दोहराने और वैश्विक दक्षिण की चिंताओं को स्पष्ट करने के बारे में थी। भारत दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन यह जी-7 का सदस्य नहीं है, क्योंकि इसे अभी भी एक विकासशील देश माना जाता है। अब तक, भारत ने 11 बार जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है और प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार पांच बैठकों में भाग लिया है। भारत जैसे देश प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे हैं। इसलिए, भारत को जी-7 समूह की औपचारिक सदस्यता से बाहर रखने का कोई मतलब नहीं है।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार।

आतंकियों की कमर तोड़ी जाए

जम्मू में फिर से बढ़ती आतंकी घटनाएं चिंता की बात है। हालांकि इसको देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्चस्तरीय बैठक में वहां के हालात की समीक्षा करते हुए आतंक को कुचलने के जो निर्देश दिए। जम्मू संभाग के रियासी क्षेत्र में श्रद्धालुओं की एक बस को आतंकियों ने ठीक उस दिन निशाना बनाया जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी अपने सहयोगियों के साथ शपथ ले रहे थे। यह आतंकी हमला एक तरह से तीसरी बार सत्ता संभालने वाली मोदी सरकार को दी जाने वाली सीधी चुनौती ही था। इस हमले के बाद आतंकियों ने जिस प्रकार एक के बाद एक डोडा, कठुआ आदि इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए, उससे उनके दुस्साहस का ही पता चलता है। एक लंबे समय से यह प्रकट हो रहा है कि आतंकियों ने कश्मीर के बजाय जम्मू को अपने निशाने पर ले लिया है। जम्मू संभाग के वे इलाके आतंकियों के गढ़ बन गए हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। इन इलाकों में आतंकियों की बढ़ी हुई गतिविधियों से यह भी स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान नए सिरे से जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को फैलाने में जुट गया है। इसकी पुष्टि पिछले दिनों कठुआ में मारे गए दो पाकिस्तानी आतंकियों से भी होती है। आवश्यक केवल यह नहीं है कि जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकियों की कमर तोड़ी जाए, बल्कि यह भी है कि पाकिस्तान को नए सिरे से यह बताया जाए कि उसे भारतीय भूभाग में आतंक फैलाने की कीमत चुकानी पड़ेगी।

-अजय कुमार, पटना

X पोस्ट

आइसक्रीम में कटी अंगुली निकल रही है, चाकलेट सिरप में मरा चूहा निकल रहा है, फ्लाइट के खाने में ब्लेड मिल रहा है और डिलीवरी बाक्स में सांप आ रहे हैं। देश में यह चल क्या रहा है?

जितेंद्र शर्मा @capt_ivane

लखनऊ में नदी किनारे के विशाल इलाके से अवैध कब्जा कोर्ट के आदेश से खाली कराया गया है। वहां अब न कोई अवैध मंदिर बचा है और न अवैध मस्जिद। न अवैध मदरसा और न अवैध गुरुकुल। सब कुछ समतल। कोई भेदभाव नहीं। अतिक्रमण से आजादी।

दिलीप मंडल @Profdilipmandal

कांग्रेस ने पूरे चुनाव भर महंगाई दूर करने का नारा लगाया। खटाखट जैसी बातें कहीं और चुनाव खत्म होते ही कर्नाटक में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ाए। फिर कहा हमें हमारी गरीब कल्याण स्कीम के लिए पैसे चाहिए। यह कैसा चक्र है? यह कैसी अर्थव्यवस्था?

संकेत उपाध्याय @sanket

नीट में गड़बड़ियों का दावा करने वाली आयुषी पटेल के दस्तावेज ही कूटरचित निकले। उसका पूरा मामला फर्जी साबित हुआ। विपक्ष के कई नेताओं ने उसके समर्थन में मुहिम चलाई थी। आखिर बच्चों को कौन गुमराह कर रहा है?

परवेज अहमद @parvezahmadj

जनपथ

नालंदा की ना रही उन्हें तनिक भी याद,
जेएनयू बनवा दिया उठता जहां विवाद।
उठता जहां विवाद लगें विद्रोही नारे,
हैं जिसके उत्पाद कन्हैया भैया प्यारे।
कुछ लोगों में पूज्य रहा वह खिलजी गंदा,
फूंका जिसने आय यहां अपनी नालंदा!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 69

प्रवाह
महोत्सव विश्वास का 75
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

कोई भी व्यक्ति अपने राजनीतिक विरोधी से दुर्व्यवहार कर चुनाव नहीं जीत सकता। -डेविड फ्रूम

बिहार में एक और पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। पिछले कुछ वर्षों में यहां से पुलों के ढहने की इतनी ज्यादा खबरें आई हैं कि अब अररिया में पुल ढहने की खबर चौंकाती कम, चिंतित ज्यादा करती है। बिहार सरकार को सच्चाई के साथ सामने आना चाहिए और दोषियों के खिलाफ अविलंब कदम भी उठाने चाहिए।

एक पुल और

बिहार के अररिया जिले के सिकटी ब्लॉक में बकरा नदी पर बन रहे पुल के एक हिस्से के ढह जाने की घटना चौंकाती है, लेकिन इससे ज्यादा गंभीर और चिंतित करने वाला तथ्य यह है कि पिछले कुछ वर्षों में यहां से पुलों के ढहने की इतनी ज्यादा खबरें आई हैं कि बिहार में अब पुलों का ढहना सामान्य लगने लगा है। इससे राज्य सरकार की छवि पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि कुछ ही महीने पहले मार्च में सुपौल में कोसी नदी पर एक निर्माणाधीन पुल के तीन स्लैब गिरने से एक मजदूर की मौत व आठ लोग घायल हुए थे। इसी तरह, पिछले वर्ष जून में भागलपुर जिले में गंगा नदी पर बना चार लेन का पुल ढह गया था, जिसका निर्माण 1,716 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा था। ध्यान देने वाली बात है कि यह वही पुल था, जिसका एक हिस्सा अप्रैल, 2022 में ढहने के बाद से ही इसके निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल के आरोप लगने लगे थे। पिछले साल तो आईआईटी, रुड़की के विशेषज्ञों से जांच कराने की बात भी उठी थी। लेकिन बकरा नदी के पुल के एक हिस्से का ढहना तो यही बताता है कि काम करने के सरकारी तौर-तरीकों में कुछ बदलाव नहीं आया है। प्रथमदृष्ट्या, यह मामला भ्रष्टाचार और लापरवाही का प्रतीत होता है। ऐसे पुलों का निर्माण निजी ठेकेदारों द्वारा होता है, लेकिन जिम्मेदारी अंततः सरकार की होती है। जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, तो यह सवाल उठता है कि आखिरकार विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता की निगरानी कैसे की जाती है? बकरा नदी पर पुल जिस तरह से भरभरा कर गिरा, उससे साफ प्रतीत होता है कि पुल निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया। ऐसे में, पुल निर्माण की जांच कर रहे ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारी का यह कहना कि विश्वसनीय नहीं लगता कि नदी के बहाव के पैटर्न की वजह से पुल ढहा है। बकरा नदी का पुल पिछले

एक दशक में बिहार में ढहे तमाम पुलों की फेहरिश्त में नया नाम है, लेकिन जो बात इन सभी दुर्घटनाओं को जोड़ती है, वह है इन सभी में किसी न किसी स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतों का मिलना। बार-बार ऐसे हादसे होने से पुल के पूरे होने में समय तो लगता ही है, इसकी लागत भी बढ़ती है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ढहा हुआ पुल सड़क परिवहन मंत्रालय के अधीन नहीं था और इसका निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया गया था। ऐसे में, बिहार सरकार को न केवल इस पुल से जुड़ी सच्चाई के साथ सामने आना चाहिए, बल्कि दोषियों के खिलाफ अविलंब कदम भी उठाने चाहिए।

राजनीति पहले जैसी शालीन नहीं हो सकती?

राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के बीच सहज सौहार्द और शालीनता के उदाहरण बिरले हो चले हैं। राजनीतिक हिंसा-प्रतिहिंसा को धीरे-धीरे सामान्य मान लिया गया है। ऐसे में ओडिशा की मिसाल सूरज की तपिश में शीतल हवा की भांति है।

लोकसभा-विधानसभा चुनाव की गहमागहमी में एक महत्वपूर्ण घटना की जाने-अनजाने में अनदेखी जैसी हो गई। ओडिशा में 24 वर्ष बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है। वहां भाजपा पहली बार बीजू जनता दल (बीजेडी) को परास्त करके अपने बल पर सरकार बनाने में सफल हुई है। जब 12 जून को शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तब न केवल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्य विपक्षी दल बीजेडी के मुखिया नवीन पटनायक शामिल हुए, बल्कि भाजपा नेतृत्व ने उन्हें मंच पर भी स्थान दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के शीर्ष नेता पटनायक से सहज होकर मिले।

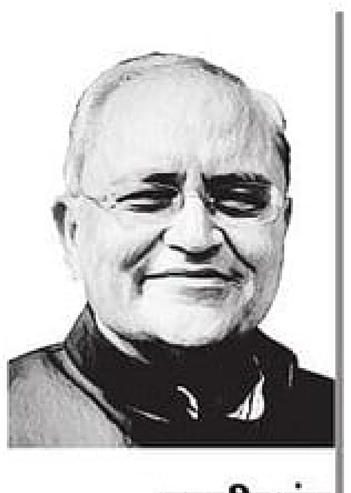

बलबीर पुंज
भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सदस्य

इतना ही नहीं, चुनाव के बाद ओडिशा में राजनीतिक हिंसा की भी कोई खबर नहीं आई। यह सब इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओडिशा के पड़ोस पश्चिम बंगाल में भाजपा समर्थकों और भाजपा के पक्ष में मत करने वाले को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कोपभाजन का शिकार होना पड़ रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी ममता सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है। आखिर भारतीय राजनीति में राजनीतिक-वैचारिक विरोधी को प्रतिद्वंद्वी के बजाय शत्रु मानने की विकृति कहां से आई?

स्वतंत्रता से पहले भी विभिन्न राजनीतिज्ञों में मतभिन्नता थी। परंतु वे एक-दूसरे का सम्मान करते थे। एक ही ध्वज के तले संवाद होता था। कुछ पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय कांग्रेस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग भी मिलकर काम कर चुके थे। तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 'भारत-रत्न' पंडित मदन मोहन मालवीय ने न केवल वर्ष 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की, बल्कि कांग्रेस में सक्रिय रहते हुए हिंदू महासभा के पांच विशेष सत्रों की अध्यक्षता भी की। इसी तरह गांधीजी वीर सावरकर को 'भाई' कहकर संबोधित करते थे, तो वह संघ के अनुशासन से प्रभावित थे। आचार-विचार में मतभेद होने के बाद नेताजी

सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई, 1944 में गांधीजी की प्रशंसा करते हुए उन्हें पहली बार 'राष्ट्रपिता' की संज्ञा दी थी। भारतीय जनसंघ (अब भाजपा) के सह-संस्थापक डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और संविधान-निर्माता डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर, दोनों कांग्रेस विरोधी थे। स्वतंत्रता से पहले डॉ. श्यामाप्रसाद हिंदू महासभा, तो डॉ. आंबेडकर अनुसूचित जाति संघ के नेता थे। परंतु गांधीजी की सलाह पर इन दोनों गैर-कांग्रेसी नेताओं के साथ पैंथिक पार्टी के बलदेव सिंह, जस्टिस पार्टी के आर. के. षण्मुखम चेट्टी को भी स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। संभवतः यह स्वतंत्र भारत की पहली गठबंधन सरकार थी।

स्वतंत्रता पश्चात प्रारंभिक वर्षों में भी राजनीतिक शालीनता और शुचिता तुलनात्मक रूप से ऐसी ही थी। यह प्रतिरोधी विचारधाराओं के ध्वजवाहक पं. नेहरू द्वारा अटलजी के प्रधानमंत्री बनने की 'भविष्यवाणी' और वाजपेयी द्वारा नेहरू के निधन पर व्यक्त भावुक श्रद्धांजलि देने तक में स्पष्ट है। वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध में संघ की निस्वार्थ राष्ट्रसेवा देखने और पूर्वाग्रह के बादल छंटने के बाद 1963 में गणतंत्र दिवस परेड में पं. नेहरू द्वारा आरएसएस को आमंत्रित करने, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के आमंत्रण पर संघ के तत्कालीन सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर (गुरुजी) के सामरिक बैठक में पहुंचने, मई, 1970 और मई, 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा वीर सावरकर के सम्मान में डाक-टिकट जारी करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की प्रशंसा करने, 1973 में गुरुजी के निधन पर इंदिरा गांधी द्वारा शोक प्रकट करते हुए उन्हें राष्ट्र-जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला विद्वान और प्रभावशाली व्यक्ति बताने और संघ की शाखाओं में प्रातः स्मरण में गांधीजी को स्थान देने आदि से भी यह वातावरण परिलक्षित होता है।

भारतीय सनातन संस्कृति में हजारों वर्षों से संवाद और असहमति को स्वीकार करने की परंपरा रही है। लाखों-करोड़ों हिंदू गौतम बुद्ध को श्रीराम-श्रीकृष्ण की भांति भगवान विष्णु का अवतार मानते है। इस पृष्ठभूमि में बाकी धार्मिक धाराओं का यथार्थ सर्वविदित है। भारत में राजनीतिक-वैचारिक विरोधियों को दुश्मन जैसा मानने का चलन वामपंथ की प्रणाली से प्रारंभ हुआ। हिंसा और असहमति रखने वालों के प्रति असहिष्णु होना-इसके केंद्र में है। दशकों से वामपंथ के गिरफ्त रहा प. बंगाल और केरल 'राजनीतिक रक्तपात', 'दूसरे विचार के प्रति असहिष्णुता' और 'विरोधियों की हत्याओं' के मामले में सर्वाधिक दागदार है।

अविभाजित भारत में वामपंथ की राजनीतिक इकाई का उदय 26 दिसंबर, 1925 में हुआ था। भले ही इस असहिष्णु दर्शन ने कालांतर में 'भारत छोड़ो आंदोलन' में ब्रितानियों के लिए मुखबिरी की, गांधीजी-नेताजी के लिए अपशब्द कहे, पाकिस्तान के जन्म में दाई की भूमिका निभाई, भारतीय स्वतंत्रता को अस्वीकार किया, भारत को 17 देशों का समूह बताया, 1948 में भारतीय सेना के खिलाफ हैदराबाद के जिहादी रजाकरों को पूरी मदद दी, 1962 की लड़ाई में चीन का समर्थन किया, इसके बावजूद वामपंथ से देश की मुख्यधारा की राजनीतिक शुचिता अप्रभावित रही।

लेकिन जब 1969-71 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी अल्पमत सरकार को बचाने के लिए वामपंथियों का समर्थन लिया, तो यह राष्ट्रीय मुख्यधारा का हिस्सा बन गया। इससे कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र तक बदला। कांग्रेस द्वारा देश पर आपातकाल थोपकर हजारों विरोधियों को जेल में ठूंसना-इस घालमेल का प्रारंभिक लक्षण था। यह स्वभाव वर्ष 2004 में मणिशंकर अय्यर द्वारा बतौर मंत्री अंडमान-निकोबार की जेल से सावरकर के विचारों को हटाने से लेकर अब तक स्वघोषित सेक्यूलरवादियों द्वारा भाजपा-संघ-मोदी के नाम पर अक्सर गरियाने और मुखर घृणा भाव दिखाने आदि की शक्ल में जारी है। दलों और नेताओं के बीच सहज सौहार्द और शालीनता के उदाहरण बिरले हो चले हैं। इस पृष्ठभूमि में ओडिशा के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जो कुछ घटित हुआ, वह सूरज की तपिश में शीतल हवा की भांति है। यह घटनाक्रम निस्संदेह, भारतीय लोकतंत्र के हृष्ट-पुष्ट स्वास्थ्य को दर्शाता है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

एलन वाट्स

अहंकार से छुटकारा पाने का मार्ग इसे खत्म करने में नहीं, बल्कि इसकी भ्रामक प्रकृति को पहचानने में निहित है। यह पहचान कर कि अहंकार एक विचार भर है, हम इसके जाल को समझना शुरू कर सकते हैं।

अहंकार हमारा बनाया हुआ एक भ्रम है

लोग कहते हैं कि आप रातों-रात मानव स्वभाव नहीं बदल सकते। आप हमसे अहंकार छोड़ने के लिए कह रहे हैं। यह तो सबसे कठिन काम है। पर वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि अहंकार मौजूद ही नहीं है। अहंकार एक सामाजिक रूप से निर्मित पहचान, एक मनगढ़ंत आत्मभावना है। अहंकार एक मिथक है और वास्तव में संपूर्णता की अस्थायी और आकस्मिक अभिव्यक्ति है। अहंकार सच्चा स्व नहीं है, बल्कि स्व का प्रतीक मात्र है। चूंकि यह सामाजिक परिस्थितियों और भाषा के माध्यम से विकसित एक भ्रामक बनावट है, इसलिए यह हमें बाकी ब्रह्मांड से अलग करने का काम करता है, और फिर इसी से अलगाव और वियोग की भावना पैदा होती है। यह ठीक वैसा ही है, जैसे हर लहर खुद को समंदर से अलग मान सकती है। हालांकि, यह सोचना ही भ्रामक है। लहर अलग नहीं है, बल्कि समुद्र का एक आंतरिक हिस्सा है। इसी तरह अहंकार या 'मैं' मौलिक रूप से ब्रह्मांड से जुड़ा है। अपने स्वयं के जीवन पर नियंत्रण की हमारी धारणा काफी हद तक अहंकार द्वारा बनाकर रखा गया एक भ्रम है। अहंकार को एक अलग और नियंत्रित करने वाली इकाई बताने वाली गलत धारणा कई मनोवैज्ञानिक समस्याओं की ओर ले जाती है, जिसमें चिंता, अवसाद और अलगाव की भावनाएं शामिल हैं। इसीलिए यह हमारे अधिकांश दुखों का मूल कारण भी है। अहंकार सचेत ध्यान का एक बिंदु है, जो लगातार परेशानी की आशंका और चिंता पैदा करता रहता है। अहंकार सुरक्षा और स्थिरता की अपनी निरंतर खोज में, भय और रक्षात्मकता को बनाए रखता है और इस तरह यह हमें हमारे परिवेश और स्वयं से अलग करता है। हम अपने अहंकार से छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि यह वास्तव में मौजूद नहीं है। इसकी कोई भौतिक वास्तविकता नहीं है। यह तो बस आपका खुद का प्रतीक है, जिसे हम अपनी असली पहचान समझने की भूल कर बैठते हैं। अहंकार से छुटकारा पाने या मुक्ति का मार्ग इसे खत्म करने में नहीं, बल्कि इसकी भ्रामक प्रकृति को पहचानने में निहित है। यह पहचान कर कि अहंकार एक मात्र विचार भर है, हम इसके भ्रमों को समझना शुरू कर सकते हैं। अहंकार एक अलग स्वयं की हमारी भावना की कहानी है, जो हम खुद को बताते हैं। इसे समझने में हम इस कहानी से अपने लगाव को छोड़ना शुरू कर सकते हैं। संगीत को समझने के लिए आपको इसे सुनना चाहिए। लेकिन जब तक आप सोच रहे हैं, 'मैं यह संगीत सुन रहा हूं', तब तक आप सुन नहीं रहे हैं। अहंकार ('मैं सुन रहा हूं') के साथ पहचान करने का कार्य ही हमें वर्तमान क्षण का पूरी तरह से अनुभव करने और उससे जुड़ने से रोकता है। यह द्वंद्व की भावना पैदा करता है। अहंकार के भ्रम को पहचान कर हम अपने अस्तित्व को अधिक प्रत्यक्ष और प्रामाणिक रूप से अनुभव करना शुरू कर सकते हैं और खुद की बाधाओं से मुक्त हो सकते हैं।

'मैं' की समझ

सूत्र

अहंकार को एक भ्रम के रूप में देखने की अवधारणा पर विचार करें और देखें कि यह दृष्टिकोण आपकी वर्तमान समझ के साथ कैसे मेल खाता है? इस पर भी विचार करें कि अहंकार को खत्म करने की कोशिश करना ही उसके भ्रम को मजबूत करता है। अहंकार से मुक्ति के बिना हमें जीवन में शांति कभी नहीं मिल सकती। जिस दिन हम यह समझ लेंगे कि 'मैं' एक झूठ और भ्रम है, उसी समय हमारे जीवन की नई यात्रा शुरू हो जाएगी।

दूसरा पहलू

लद्दाख के मटाइन गांव के पास पांडवकालीन महल हुआ करता था और यहां की झील हर चार माह में अपना रंग भी बदलती है।

माइनस 40 पर भी नहीं जमता द्रौपदी मंदिर की झील का पानी

सोनमर्ग से कारगिल जाने का रास्ता कठिन तो है, लेकिन सैलानियों को सबसे ज्यादा बर्फबारी भी यहीं पर मिलती है। जैसे ही कश्मीर की सीमा समाप्त होने पर लद्दाख क्षेत्र शुरू होता है, तो सबसे पहले एक छोटा-सा गांव मटाइन पड़ता है। खास बात यह है कि गांव में लोग गर्मियों के दिनों में रहते हैं, सर्दियों में अधिक बर्फबारी के कारण दूसरे ठिकाने तलाश लेते हैं। यहां पर जगह-जगह बोर्ड भी लगे होते हैं, दुनिया के दूसरे सबसे सर्द इलाके द्रास में आपका स्वागत है।

खैर, मटाइन गांव से कारगिल की ओर कुछ सौ मीटर चलते ही निगाह पड़ती है द्रौपदी कुंड पर। पास में ही एक बड़ा कमरा था। दरवाजा खटखटाया, तो पता चला कि वह एक नूडल पॉइंट है। सैलानी कम आने की हालत में इसे चलाने वाले दोनों लोग अंदर आराम कर रहे थे। कमरे की अपनी खासियत थी। उसकी दीवारों पर बहुत से संदेश लिखे हुए थे। पूछने पर बताया गया कि यहां आने वाले बाइकर्स याद के लिए यह संदेश लिखते हैं। दोबारा आते हैं, तो फिर नई तारीख के साथ उसके नीचे नया संदेश लिख कर जाते हैं। नूडल पॉइंट के संचालकों में से एक नवीन राणा से जब पास में लगे द्रौपदी कुंड के बोर्ड के बारे में पूछा, तो सामने की पहाड़ी की ओर इशारा कर बताया कि वहां पर पांडवों का महल हुआ करता था। वह वनवास काटने के लिए यहां आए थे। उनका तो यह भी मानना है कि वह महल आज भी है, पर वहां पर जाना असंभव सा है। नवीन ने बताया कि द्रौपदी यहां पर केश धोने के लिए आती थीं, इसलिए इसका नाम द्रौपदी कुंड पड़ा। इसी के पास में द्रौपदी का मंदिर है और कुंड से अलग एक झील है। यह झील भी पांडवकालीन ही है और हर चार माह में पानी का रंग बदल जाता है।

नितिन यादव

मटाइन गांव से कारगिल की ओर कुछ सौ मीटर चलते ही निगाह पड़ती है द्रौपदी कुंड पर। पांडवों के वनवास के दौरान द्रौपदी इसी कुंड में अपने केश धोने के लिए आती थीं।

पहाड़ पर साल भर बर्फ जमी रहती है, पर इसका पानी ग्लेशियर के पिघलने से नहीं आता है, बल्कि जमीन के नीचे इसका अपना स्रोत है। बर्फ पिघलती भी है, तो पानी बह जाता है, लेकिन झील के पानी में नहीं मिलता।

पहाड़ पर साल भर बर्फ जमी रहती है, पर इसका पानी ग्लेशियर के पिघलने से नहीं आता है, जमीन के नीचे इसका अपना स्रोत है। बर्फ पिघलती भी है तो आसपास से पानी बह जाता है, लेकिन झील के पानी में नहीं मिलता। यहां पर तापमान माइनस 40 तक भी चला जाता है, लेकिन झील का पानी कभी नहीं जमता है। सामान्य पर्यटकों के अलावा, यहां बड़ी संख्या में लोग अपने बर्तनों के साथ पानी भरकर ले जाने के लिए आते हैं। यह कहा जाता है कि इस पानी को पीने से गैस की बीमारी ठीक हो जाती है और डायबिटीज के मरीजों के लिए भी रामबाण है। मान्यता यह भी है कि इस झील के पानी में मांसाहार नहीं पकता है। प्रमाणिकता पूछने पर नवीन तपाक से कहते हैं-आप खुद पानी भरकर ले जाइए और बाद में बताना कि जो कहा, वह सही है या नहीं।

आंकड़े

कोयले की खपत

भारत में कोयले की खपत कई क्षेत्रों में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग बिजली उत्पादन में होता है।

क्षेत्र	खपत
बिजली	63.13
लौह-इस्पात	7.83
सीपीपी	4.36
सीमेंट	2.5
अन्य	13.16

नोट : आंकड़े मीट्रिक टन में हैं। | स्रोत : MoSPI

मथुरा की एक मालिन प्रतिदिन ब्रज में सब्जी-भाजी और फल-फूल बेचने के लिए आती थी, उसकी एक ही इच्छा थी कि वह कान्हा को हाथों से स्पर्श करे।

पूरी हुई सुखिया की चाह

अंतर्यात्रा
संकलित

मथुरा की एक सुखिया नाम की मालिन ब्रज में प्रतिदिन साग-भाजी और फल-फूल बेचने के लिए आती थी। वह कान्हा को देखकर काफी खुश होती थी। उसकी इच्छा थी कि वह अपने हाथों से श्रीकृष्ण का स्पर्श करे। सुखिया रोज इसी चाह में साग-भाजी लेकर मथुरा से गोकुल जाती थी कि आज तो कान्हा उसे मिल जाएंगे।

मुरली मनोहर सुखिया के मनोभाव को समझते थे। वह जैसे ही टोकरी लेकर नंदरानी (यशोदा माता) के आंगन में पहुंचती, वैसे ही कान्हा खेलने के बहाने घर से निकल जाते। वह मन मसोसकर रह जाती और कहती कि श्यामसुंदर तुम इतने निष्ठुर क्यों हो? कई बार तो ऐसा होता था कि स्पर्श तो दूर सुखिया को कान्हा के दर्शन भी नहीं होते थे। सुखिया जैसे ही पहुंचती, कन्हैया घर से निकल जाते। यह सिलसिला कई वर्ष चला। अब तो सुखिया के मन में मुरली मनोहर को स्पर्श करने की इतनी तड़प जागृत हो गई कि उसे हर जगह कान्हा दिखाई देते थे।

मालिन की चाह जब पराकाष्ठा पर पहुंच गई, तो वह एक दिन देखती है कि सामने से कान्हा अपने हाथों में धान भरकर उसकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। कन्हैया जैसे ही पास पहुंचे, तो सुखिया ने उनके हाथों को फलों से भर दिया। कान्हा का स्पर्श पाकर सुखिया इतनी भावविह्ल हो गई कि उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। भक्ति के चरम को प्राप्त करने पर भगवान श्रीकृष्ण ने सुखिया को मुक्ति प्रदान की।

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 5 जनवरी, 1951

संघ राजनीतिक क्षेत्र में उतरेगा पुराना काम भी चलेगा

संघ राजनैतिक क्षेत्र में उतरेग
पुराना काम भी चलेगा

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यकारिणी के एक प्रमुख अधिकारी ने बताया कि बिगड़ती हुई अंतरराष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए और राष्ट्र उत्थान को ध्यान में रखते हुए संघ अपने को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में परिवर्तित कर देगा।

क्षेत्रीय संतुलन और पाकिस्तान

विदेश नीति पर पुनर्विचार समय की मांग है। ऐसे में, नई सरकार के समक्ष पाकिस्तान समेत सभी सार्क देशों के साथ संतुलन बनाने की चुनौती होगी।

केएस तोमर | विदेश नीति

भारत की 'पड़ोसी पहले' की नीति 1947 से ही विदेशी संबंधों का अहम हिस्सा रही है। यह पड़ोसियों से संबंध मजबूत बनाने, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, पड़ोसियों के साथ साझा मुद्दों का हल निकालने पर केंद्रित है, जिसे चीन की खतरनाक विस्तारवादी और कर्ज नीति से निपटने के लिए शीर्ष प्राथमिकता देने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में पड़ोसी देशों एवं हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं की मौजूदगी से स्पष्ट है कि नई दिल्ली इन देशों को कितना महत्व देती है। समारोह में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मॉरिशस के प्रधानमंत्री एवं सेशेल्स के उपराष्ट्रपति और श्रीलंका तथा मालदीव के राष्ट्रपति मौजूद थे। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू का शामिल होना रणनीतिक दृष्टि से इसलिए अहम था, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं। भारत ने 'पड़ोसी पहले' की नीति के तहत दक्षिण एशियाई

देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर हमेशा जोर दिया है। इसका लक्ष्य क्षेत्र में शांति, सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। अतीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सार्क नेताओं को निमंत्रण देना, दक्षिण एशिया में नई शुरुआत का संकेत था। मोदी के तीसरे कार्यकाल में दक्षिण एशिया के छोटे देशों के जरिये क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारतीय दृष्टिकोण में भू-राजनीतिक बदलाव की उम्मीद है। मालदीव की नकारात्मकता के बावजूद भारत ने संयम बरता है, जिससे संबंधों में सुधार की गुंजाइश है।

मालदीव और नेपाल चीन के प्रलोभन में फंसे हुए हैं। इसलिए भारत को क्षेत्रीय संतुलन बनाकर राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना होगा। वहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देना, इसके जवाब में मोदी का भी धन्यवाद कहना काफी कुछ बयां करता है। नवाज शरीफ ने लिखा कि 'आइए, हम नफरत को आशा में बदलें और दक्षिण एशिया के दो अरब लोगों की नियति को आकार देने के लिए अवसरों का लाभ उठाएं।' प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत जवाब दिया कि 'भारत के लोग हमेशा शांति, सुरक्षा और प्रगतिशील विचारों के लिए खड़े हैं। अपने लोगों की भलाई और सुरक्षा के लिए आगे बढ़ाना हमेशा हमारी प्राथमिकता रहेगी।'

उल्लेखनीय है कि 2014 में जब मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो नवाज शरीफ भी शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री मोदी के साथ बेहतर रिश्ते रहे हैं। मोदी ने पाकिस्तान से संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास भी किया था। वर्ष 2015 में मोदी अचानक नवाज शरीफ को 66वें जन्मदिन की बधाई देने लाहौर पहुंचे थे और उनकी नातिन मेहरुनिस्सा की शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए थे। हालांकि पाकिस्तानी सेना को यह पहल पसंद नहीं आई थी। इससे पहले 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान का दौरा करके संबंधों में नरमी लाई थी। कूटनीति के सिद्धांतों के अनुसार, भले ही दोनों देशों के बीच संबंधों की निरंतरता को शत्रुता नियंत्रित करती हो, फिर भी बातचीत जारी रहनी चाहिए। अगर पाकिस्तान ईमानदारी दिखाए और सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करना बंद करे, तो भारत फिर से बातचीत शुरू कर सकता है। विशेषज्ञ इस पर एकमत हैं कि चीनी राष्ट्रपति भारत के साथ शत्रुता का भाव रखते हैं, जबकि पाकिस्तान से बातचीत शुरू होने पर अमेरिका भी सहज महसूस करेगा।

हालांकि अब स्थितियां बदली हैं और नवाज शरीफ और सेना भारत से रिश्ते में सुधार के लिए एकमत होते दिख रहे हैं, लेकिन आईएसआई को कश्मीर में हिंसा को बढ़ावा देने वाले आतंकियों को समर्थन देना बंद करना होगा। वहीं, प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को पाकिस्तान को माली हालत से बाहर निकालने के लिए आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से व्यापार रोक दिया था। भारत अभी जल्दबाजी में पाकिस्तान के साथ व्यापार का कोई निर्णय भी नहीं लेगा।

नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से पड़ोसी देशों पर गहरा असर हुआ है। मोदी अगले पांच वर्ष तक देश की कमान संभालेंगे, ऐसे में विदेश नीति पर पुनर्विचार करना समय की मांग है। साथ ही, सार्क देशों के साथ संबंध सुधारते हुए पाकिस्तान के साथ गतिरोध खत्म करने की पहल करनी होगी, पर पाकिस्तान को कश्मीर फोबिया से बचना होगा।

चिंतन

खालिस्तानी आतंकवाद को पनाह देना बंद करे कनाडा

कनाडा को आतंकवाद पर अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा। आतंकवाद पर सिलेक्टिव रवैया उसे ही भारी पड़ सकता है। भारत आतंकवाद के खिलाफ दशकों से लड़ रहा है। भारत खालिस्तानी आतंकवाद और कट्टर इस्लामिक आतंकवाद दोनों का सामना कर रहा है। दोनों आतंकवाद को खादपानी विदेशी सरजमीं से मिल रही है। खालिस्तानी गतिविधियों में लिप्त लोग बरसों से कनाडा में रह रहे हैं। कनाडा आंख मूंदे हुए है। अभी आतंकवाद पर भारत ने कनाडा को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जवाब भी ऐसा कि इससे न केवल ट्रूडो सरकार बल्कि दुनिया भर के खालिस्तानी आतंकी भी तिलमिला जाएं। खालिस्तानी आतंकवाद का समर्थन करने के मुद्दे पर भारत के बार-बार कहने के बावजूद कनाडा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ आया। कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की बरसी पर अपनी संसद में मौन रख कर भारत को चिढ़ाने का प्रयास किया, तो भारत ने कनाडा को कनिष्क विमान बम विस्फोट की याद दिला कर बताया है कि उसके यहां कैसे वर्षों से खलिस्तानी आतंकवाद जड़ जमाए हुए है, और वो पोसक बना हुआ है। आतंकवाद को लेकर अगर कनाडा नहीं संभला तो उसकी हालत भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसी हो सकती है, जहां आतंकवाद अब इन देशों के लिए भ्रस्मासुर साबित हो रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपनी राजनीति के लिए आग से खेल रहे हैं, हालांकि कनाडा में अब उनकी लोकप्रियता तेजी से गिर रही है, कनाडा के गैर सिख वासियों के बीच ट्रूडो की साख तेजी से गिरी है। अभी जी-7 की बैठक में पीएम नरेन्द्र मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से अलग से मुलाकात की है और खालिस्तानी आतंकवादियों को संरक्षण को लेकर भारत की चिंता को जाहिर की है। इसके तुरंत बाद कनाडाई संसद का खालिस्तानी आतंकवादी व भारत में वांछित निज्जर की हत्या की बरसी पर मौन रखना दर्शाता है कि उसे भारत की चिंता की परवाह नहीं है। अब भारत ने भी कनिष्क विमान बम विस्फोट की 39वीं बरसी 23 जून को मनाने का फैसला किया है। नागरिक विमानन के इतिहास में सबसे जघन्य आतंकवाद से संबंधित हवाई दुर्घटना कनिष्क बम विस्फोट को याद करते हुए वैंकूवर स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारत आतंकवाद की समस्या से निपटने में सबसे आगे है और इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। मॉन्ट्रियल-नई दिल्ली एयर इंडिया 'कनिष्क' उड़ान संख्या 182 में 23 जून 1985 को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरने से 45 मिनट पहले विस्फोट हो गया था, जिससे विमान में सवार 86 बच्चों सहित सभी 329 लोग मारे गए थे। इनमें से 268 भारतीय मूल के कनाडाई थे व 24 भारतीय थे। यह नागरिक उड्डयन के इतिहास में सबसे जघन्य आतंकवाद-संबंधी हवाई दुर्घटनाओं में से एक थी। इस बम विस्फोट का आरोप सिख आतंकवादियों पर लगाया गया था। यह विस्फोट कथित तौर पर 1984 में स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए किए गए 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' के प्रतिशोध में किया गया था। कनाडा की संसद में खालिस्तानी आतंकी के महिमामंडन और खालिस्तान चरमपंथियों को खुली छूट भारत को अस्वीकार्य है। कनाडा में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी को भी भारत बर्दाश्त नहीं करेगा।

सुशासन के प्रतीक-छत्रपति शिवाजी

विशेष
शिवप्रकाश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को स्मरण करते हुए कहा 'कुछ ही दिनों में देश छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्यारोहण की 350वीं वर्षगांठ मनाएगा, उनका जीवन ध्येय पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देता है।' छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 1731 को रायगढ़ में हुआ था। पुर्तगाली एवं ब्रिटिशों सहित अनेक विदेशी लेखकों ने छत्रपति शिवाजी की तुलना महानतम सेनापति नेपोलियन, सीजर, सिकंदर के साथ करते हुए उनकी वीरता, प्रशासनिक कुशलता एवं युद्ध शैली की प्रशंसा की है। हम शिवाजी के जीवन आदर्श से प्रेरणा लेकर अपने देश को आत्मनिर्भर, विश्व वन्दनीय भारत बनाएं।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत के उपलक्ष्य में आयोजित धन्यवाद भारत कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को स्मरण करते हुए कहा 'कुछ ही दिनों में देश छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्यारोहण की 350वीं वर्षगांठ मनाएगा, उनका जीवन ध्येय पथ पर बढ़ने की प्रेरणा देता है।' छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 1731 को रायगढ़ में हुआ था। अंग्रेजी तिथि के अनुसार 6 जून 1974 की पुण्यतिथि थी। पुर्तगाली एवं ब्रिटिशों सहित अनेक विदेशी लेखकों ने छत्रपति शिवाजी की तुलना महानतम सेनापति नेपोलियन, सीजर, सिकंदर के साथ करते हुए उनकी वीरता, प्रशासनिक कुशलता एवं युद्ध शैली की प्रशंसा की है।

16 फरवरी 1630 ई. शिवनेरी किले में शिवाजी महाराज का जन्म शाहजी भोंसले एवं माता जीजाबाई के परिवार में हुआ। उनके जन्म के समय परिस्थिति कैसी थी इसका वर्णन समर्थ गुरुरामदास महाराज ने अपने 12 वर्ष के भारत भ्रमण के बाद इस प्रकार किया "या भूमंडलाचे ढायी, धर्मरक्षा ऐसा नाही" इस समय इस भूमंडल पर धर्मरक्षक कोई नहीं है। संपूर्ण देश में कोई भी मंदिर सुरक्षित नहीं है। सामान्य जनता मुगलों के अत्याचार से कराह रही है, किसी भी नदी का जल पवित्र नहीं है जिससे अभिषेक किया जा सके। इस विकट परिस्थिति में छत्रपति शिवाजी ने अपने रणकौशल एवं बुद्धिकौशल से स्वराज की स्थापना की। उनके कुशल प्रशासन को देखने के बाद पुनः स्वयं समर्थ रामदास महाराज ने कहा "आचारशील, विचारशील, न्यायशील, धर्मशील, सर्वज्ञ सुशील जाणता राजा।" किसी भी कार्य की सफलता का आधार नेतृत्वकर्ता के सहयोगी कैसे है इस पर निर्भर करता है। शिवाजी ने सहयाद्रि में निवास करने वाले सामान्य गरीब, किसान, युवकों में स्वराज की प्रेरणा जगाई। समाज के सामान्य वर्ग से निकले इन्हीं योद्धाओं ने अपने जीवन की बाजी लगाकर स्वराज स्थापना का श्रेष्ठतम कार्य किया। औरंगजेब अपनी सेना के एक-एक सेनापति से तुलना करते हुए शिवाजी के सेनापतियों की विशेषता का वर्णन करते हुए कहता है "वे झुकते नहीं, रुकते नहीं, थकते नहीं और बिकते भी नहीं।" छत्रपति शिवाजी का शासन लोक कल्याण एव पारदर्शिता से युक्त था। वित्त प्रबंधन को लेकर वे सदैव सजग थे। मंत्रालयों की समीक्षा करते समय उन्होंने अपने लेखपाल से पूछ लिया कि कल तक का हिसाब दैनिंदनी में चढ़ा अथवा नहीं, नकारात्मक उत्तर होने पर लापरवाही के लिए कठोर दंड भी दिया। लगान के उचित संग्रह में लापरवाही पर देश कुलकर्णी आपाजी से जुर्माना भी लिया एवं पद मुक्त भी किया। भ्रष्टाचारविहीन शासन छत्रपति शिवाजी के शासन का वैशिष्टय था। भ्रष्टाचारयुक्त शासन के लिए उन्होंने रिश्वत लेने पर अपने सौतेले मामा मोहिते को भी कारागार में डाल दिया था। 13 मई 1671 के अपने पत्र में वे लिखते हैं कि अगर आप जनता को तकलीफ देंगे, कार्य सम्पादन में रिश्वत मागेंगे तो जनता को लगेगा कि इससे तो मुगलों का शासन ही अच्छा था। छत्रपति शिवाजी ने अपने स्वराज

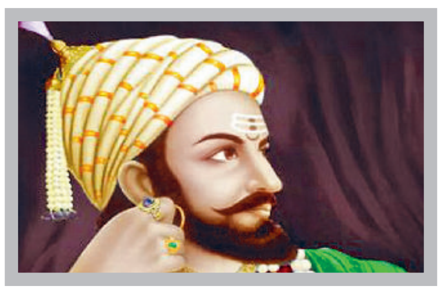

संचालन के लिए अष्ट प्रधान शासन प्रणाली की व्यवस्था दी थी। शिवाजी जहाँ एक दूरदर्शी योद्धा थे, वहीं वह एक कुशल प्रशासक भी थे। स्वदेशी जलपोत निर्माण के लिए मुंबई के पास कल्याण एवं भिवंडी में उनके द्वारा स्थापित जलपोत निर्माण करवाना, व्यापार एवं सुरक्षा के प्रति उनकी दृष्टि की ओर इंगित करता है। अंग्रेजों से तोप निर्माण की तकनीक न मिलने पर उन्होंने फ्रांस के सहयोग से पुरन्दर किले पर तोपखाना स्थापित कराया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का यह मन्त्र वर्तमान की सरकार का मन्त्र भी बना है। भूमि का मापन, पैदावार का मूल्यांकन, आपदा में होने वाली हानि के मूल्यांकन की व्यवस्था शिवाजी महाराज ने उस समय की थी। सिंचाई के लिए बांध, तालाबों, कुएं, बावड़ी एवं जलाशयों का निर्माण उनकी दूरदर्शिता को प्रकट करते हैं। स्वस्थ भूमि, स्वस्थ उत्पाद, स्वस्थ पर्यावरण के लिए फसलों में विविधता, फलदार वृक्षों को लगवाना उनकी कृषि एवं पर्यावरण के प्रति दृष्टि को प्रकट करते हैं।

महिलाओं के प्रति उनके हृदय में सम्मान एवं महिलाओं के प्रति कुदृष्टि डालने पर कठोर दंड उनके शासन की व्यवस्था थी। मुस्लिम महिला गोहरबानू के प्रति उनके उदगार काश मेरी मां भी इतनी सुन्दर होती, सखोजी गायकवाड़ को दंड उनकी न्यायप्रियता को प्रकट करते हैं। स्वराज के हित को प्रथम रखते हुए उन्होंने व्यापारिक संबंध सभी से रखे थे। व्यापार के लिए मध्य एशिया के देशों तक उन्होंने संबंध बनाए थे। उसमें मस्कट के इमाम भी प्रमुख थे। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि को अपने राज्य संचालन का आधार बनाया। उनके शासन में वृद्ध, बीमार एवं बच्चों को छोड़कर अन्य किसी के लिए भी मुफ्त सुविधा की व्यवस्था नहीं थी। छत्रपति शिवाजी की शासन प्रणाली में स्वभाषा एवं स्वसंस्कृति को विशेष महत्व था। गुलामी के प्रतीकों को हटाकर स्वाभिमानी समाज जागृत करने के लिए उन्होंने किलों के नामों को नामांतरण भी किया। उर्दू और फारसी के शब्द बदलकर स्वराज संचालन के लिए 1400 हिन्दी शब्दों का कोष भी बनाया था। शिवाजी की गुप्तचर व्यवस्था, शत्रु को पहचानने की उनकी अचूक दृष्टि उनको शेष भारतीय राजाओं से अलग करती है। उत्तर भारत की मुग़ल शक्ति एवं दक्षिण की आदिलशाही, कुतुबशाही के भेद का उन्होंने उचित उपयोग किया था। शत्रु की कमजोरी उनके साथ जैसे को तैसा व्यवहार शाइस्ताखान, अफजलखान एवं औरंगजेब से युद्ध करते समय उन्होंने अपनाया था। व्यापार एवं सुरक्षा के लिए नौसेना के महत्व को पहचान कर सिंधुदुर्ग सहित समुंद्र किनारे अनेक दुर्गों की स्थापना उन्होंने की थी। शिवाजी ने न केवल हिन्दवी साम्राज्य स्थापित किया, बल्कि सम्पूर्ण समाज में स्वराज, स्वधर्म के प्रति समर्पण की भावना भी जागृत की। देशभर में स्वराज की रक्षा के लिए संघर्षरत समस्त राजाओं के प्रेरणा पुंज भी वह बने। अपनी माता की मृत्यु के समय भी बिना अवकाश लिए वे राज्य का सूत्र संचालन करते रहे। स्वराज संस्थापन के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करना ही उनकी प्रेरणा थी। स्वराज स्थापन यह "श्री" का कार्य है यह मान कर उन्होंने सम्पूर्ण जीवनभर संघर्ष किया। अपने सहयोगियों में भी उन्होंने यही भाव कूट-कूट कर भरा था। सहयोगियों से वे कहते थे कि हमारे कार्य की दिशा ठीक है यह पवित्र कार्य है। हमारा कार्य पवित्र होने के करण पवित्र अदृश्य शक्तियां हमारा सहयोग करेंगी। मां तुलजा भवानी एवं परमेश्वर पर यह आस्था ही उनके संघर्ष की प्रेरणा थी। निमित्तता के इसी निस्वार्थ भाव के कारण उन्होंने एक कागज पर लिखकर अपना राज्य अपने प्रेरणा स्रोत समर्थ रामदास स्वामी महाराज की छोली में डाल दिया था।

हिन्दवी स्वराज्य की स्थापना के इस पुनीत अवसर पर हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन आदर्श से प्रेरणा लेकर अपने देश को आत्मनिर्भर, आर्थिक सम्पन्न, सुरक्षित एवं सांस्कृतिक मूल्यों से संरक्षित कर विश्व वन्दनीय भारत बनाएं।

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया **edit@haribhoomi.com** पर दे सकते हैं।

टेक के खतरे
शैलजा सिंह

एआई में अंतर्निहित समस्याएं

हम सभी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बारे में बहुत कुछ सुना और पढ़ा है। आप में से कइयों ने संभवतः उपलब्ध हो रहे अनगिनत एआई उपकरणों में से कुछ का उपयोग भी किया होगा। कुछ लोगों के लिए, एआई एक जादू की छड़ी की तरह लगता है, जो हर मुश्किल आसान कर सकता है, लेकिन ताजा अध्ययन के मुताबिक, एआई परफेक्ट नहीं है। इसमें खतरनाक अंतर्निहित समस्याएं हैं, जिन्हें ठीक करना मुश्किल है। इसमें कोई दोराय नहीं कि एआई डिजिटल दुनिया को तेजी से बदल रही है, यह वह तकनीक है, जो मानव मस्तिष्क की तरह कृत्रिम मेधा की संरचना विकसित कर रही है। इसके बहुत लाभ हैं, हर क्षेत्र में एआई का प्रवेश हो रहा है। एक ही काम को बार-बार दोहराना, डिजिटल सहायक, मानवीय त्रुटि को दूर करना, जोखिम भरे काम करना, बिना थके उपलब्धता, त्वरित निर्णय लेना, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट ऑटोमेशन, रोबोटिक्स व लॉजिस्टिक्स, भविष्यसूचक विश्लेषण, नवाचार और रचनात्मकता, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण आदि एआई के फायदे हैं। लेकिन इसके नुकसान भी हैं, जिसके चलते इसको बनाने वाले से लेकर इसके उपयोग करने वाले तक दुनिया की सरकारों को चेता रहे हैं कि एआई को नियंत्रित रखने के लिए सरकारें नया कानून बनाएं। आई उपयोगकर्ताओं के लिए कई नुकसान पैदा करता है। उनमें से कुछ में प्रौद्योगिकी पर निर्भरता और आलोचनात्मक सोच की कमी, कम मानवीय संपर्क, डेटा गोपनीयता और सुरक्षा में नैतिक चिंताएं, तकनीकी सीमाएं और त्रुटियां आदि शामिल हैं। जैसे, न्यूयॉर्क शहर के एक चैटबॉट ने लोगों को कानून तोड़ने की सलाह दी, और गूगल का एआई ओवरव्यू लोगों को चट्टानें खाने के लिए कह रहा है। मुद्दे की बात यह है कि एआई प्रणाली की कुछ अंतर्निहित कमियां हैं।

वास्तविक दुनिया में परेशानी : सभी एआई प्रणालियों के लिए अंतर्निहित मुद्दों में से एक यह है कि वे वास्तविक दुनिया की सेटिंग्स में 100% सटीक नहीं हैं। उदाहरण के लिए, एक पूर्वानुमानित एआई प्रणाली को अतीत के डेटा बिंदुओं का उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाएगा। यदि एआई को कुछ नया मिलता है - जो प्रशिक्षण डेटा में किसी भी चीज़ के समान नहीं है - तो यह संभवतः सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगा। एक काल्पनिक उदाहरण के रूप में, आइए एआई-संचालित ऑटोपायलट प्रणाली से सुसज्जित एक सैन्य विमान लें। यह प्रणाली अपने प्रशिक्षण ज्ञान आधार की बदौलत कार्य करेगी। लेकिन एआई सिर्फ गणितीय गणना है। एक प्रतिकूल स्थिति ऐसी बाधाएं पैदा कर सकती है जिसे विमान एआई देख नहीं सकता क्योंकि वे प्रशिक्षण डेटा में नहीं हैं, जिससे संभावित विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।

प्रशिक्षण डेटा में पूर्वाग्रह : आपने एआई द्वारा पक्षपातपूर्ण निर्णय लेने के बारे में सुना होगा। आमतौर पर, पूर्वाग्रह तब होता है जब हमारे पास असंतुलित डेटा होता है। सरल शब्दों में, इसका मतलब यह है कि एआई प्रणाली को प्रशिक्षित करते समय, हम इसे एक प्रकार के परिणाम के बहुत सारे उदाहरण और दूसरे प्रकार के बहुत कम उदाहरण दिखा रहे हैं। आइए एक एआई प्रणाली का उदाहरण लें जो किसी व्यक्ति द्वारा अपराध करने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए प्रशिक्षित है। यदि सिस्टम को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अपराध डेटा में ज्यादातर समूह ए (मान लीजिए, एक विशेष जातीयता) के लोग हैं और समूह बी से बहुत कम लोग हैं, तो सिस्टम दोनों समूहों के बारे में समान रूप से नहीं सीख पाएगा। परिणामस्वरूप, समूह ए के लिए इसकी भविष्यवाणियों से ऐसा प्रतीत होगा कि ये लोग समूह बी की तुलना में अपराध करने की अधिक संभावना रखते हैं। यदि सिस्टम का उपयोग बिना सोचे-समझे किया जाता है, तो इस पूर्वाग्रह की उपस्थिति के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एआई को पूर्वाग्रह बनाए रखने से रोकने के लिए संतुलित डेटा का होना महत्वपूर्ण है।

ऑफ़लाइन प्रशिक्षण की समस्या : एआई के साथ एक और समस्या तब उत्पन्न हो सकती है जब इसे ऑफ़लाइन प्रशिक्षित किया गया हो और यह उस समस्या की गतिशीलता के साथ अद्यतित न हो, जिस पर इसे काम करना है। एक सरल उदाहरण किसी शहर में दैनिक तापमान की भविष्यवाणी करने के लिए विकसित की गई एआई प्रणाली होगी। इसके प्रशिक्षण डेटा में इस स्थान के तापमान डेटा पर सभी पिछली जानकारी शामिल है। एआई का प्रशिक्षण समाप्त होने और तैनात होने के बाद, मान लीजिए कि एक गंभीर जलवायु घटना सामान्य मौसम की गतिशीलता को बाधित करती है। चूंकि भविष्यवाणियां करने वाली एआई प्रणाली को उस डेटा पर प्रशिक्षित किया गया था जिसमें यह व्यवधान शामिल नहीं था, इसलिए इसकी भविष्यवाणियां तेजी से गलत हो जाएंगी।

(लेखिका साहित्यकार व टेक विशेषज्ञ हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

भगवान के चरणों में अर्पित करना ही ज्ञान

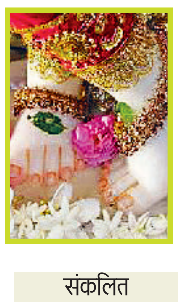

संकलित
दर्शन

सर्व सामर्थ्य होते हुए भी अहंशून्य होकर स्वयं को भगवान के चरणों अर्पित कर देना ही ज्ञान, भक्ति और कर्म की परिपूर्णता है। भगवान के परम भक्त बालिपुत्र अंगद ने रावण की सभा में अपना एक पैर रोपकर अपने मुष्टिप्रहार से रावण के दसों मुकुटों को सिर से गिरा दिया था, वहीं चार मुकुटों को बीच में उछालकर भगवान के पास भेज दिया था। लंका से लौटकर आए अंगद से जब भगवान श्रीराम ने पूछा कि तुमने ये मुकुट कहां और कैसे प्राप्त किए, तब अंगद ने धर्म और ईश्वर से विमुख व्यक्ति की तात्विक व्याख्या की है। अंगद विनम्र भाव से कहते हैं, प्रभु! ये चार मुकुट नहीं, राजनीति के चार पद हैं, जिन पर चलकर व्यक्ति व्यवहार करते हुए भी परमार्थ को प्राप्त कर लेता है। रावण आपसे और धर्म से विमुख हो चुका है, इसलिए राजनीति के चारों चरणों (साम, दाम, दंड और भेद) का दुरुपयोग कर रहा था, इस कारण मुकुट के रूप में ये चारों उसको छोड़कर आपकी शरण में आ गए हैं। रावण ने शेष छह मुकुट जो सिर पर धारण कर रखे हैं, वे साधक के जीवन में रहने वाली षड्संपत्ति (शम, दम, उपरति, तितीक्षा, श्रद्धा और समाधान) हैं। चूंकि रावण उनका भी दुरुपयोग कर रहा था, इसलिए ये षड्संपत्ति न रहकर विकार बनकर रावण के सिर पर शासन कर रहे हैं, जो उसके विनाश के कारण बनेंगे। मेरे प्रभु! गुण तो केवल वे ही हैं, जिन्हें आपने स्वीकारा है। शेष सब अवगुण ही हैं। गुणों का योग जब तक भगवान से नहीं होगा, तब तक व्यक्ति उसका उपयोग और कहां करेगा?

जीवन का, जीवन बीमा

संकलित
प्रेरणा

दो मित्र थे, बड़े परिश्रमी और मेहनती। अपने परिश्रम से दोनों एक दिन बड़े सेठ बन गए। दोनों ने बड़ा व्यवसाय खड़ा कर लिया। पहले सेठ ने अपनी सारी संपत्ति का बीमा करवा लिया। उसने अपने मित्र को बार बार यही परामर्श दिया की वह भी अपनी सम्पत्ति का बीमा करवा ले। परन्तु दूसरे मित्र ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। दुर्भाग्य से एक दिन शहर में आग लग गई। दोनों की सारी संपत्ति जल कर राख हो गई। पहले सेठ ने बीमा करवा रखा था इसलिए उसे सारी संपत्ति वापिस मिल गई जबकि दूसरा मित्र निर्धन बन गया। मगर हाथ पछताने के अतिरिक्त उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। मनुष्य का यह जन्म भी सेठ की संपत्ति के समान है। हम सभी को मालूम है की एक दिन इस शरीर को भस्म होना है मगर हम हैं की जीवन के इस अटल सत्य को जानकर भी अनसुना कर देते हैं। हम इसका कभी बीमा नहीं करवाते। न सत्कर्म करते है, न अभ्यास और वैराग्य द्वारा मोक्ष मार्ग को सिद्ध करते हैं, न योग मार्ग के पथिक बनते है, न ईश्वर का साक्षात्कार करते है। इसके विपरीत भोग, दुराचार, पाप, राग-द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान, अहंकार, असत्य आदि के चक्कर में अपना बीमा ही करवाना भूल जाते हैं। वेद में अनेक मन्त्रों के माध्यम से जन्म-मरण और मुक्ति की पवित्र शिक्षा को कहा गया हैं- शरीररूप बंधन में आकर जीवात्मा जहां तहां भटकता है- वेद शरीर नश्वर है इसके रहते हुए जो श्रेष्ठ कर्म किया जा सके करले अपने को संभाल के परमात्मा का स्मरण कर-वेद जीवात्मा वासनावश ऊंची नीची योनियों में शरीर धारण करता है।

अंतर्मन

आज की पाती

रेलवे की फिर लापरवाही घातक साबित हुई

समय-समय पर रेलवे की लापरवाही बहुत से लोगों की जान को आफत में डाल देती है और जान पर भी भारी पड़ जाती है, लेकिन रेलवे पता नहीं क्यों ऐसे हादसों से सबक नहीं लेता है। अब रेलवे की लापरवाही पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमा पर देखने को मिली। वहां मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में कुछ लोगों की जान चली गई और कुछ घायल हो गए। अगर मालगाड़ी की रफ्तार तेज होती तो फिर न जाने और कितने लोगों की जान पर यह रेलवे की लापरवाही पड़ जानी थी। कुछ महीने पहले ओडिशा में बहुत ही दिल दहलाने वाला ट्रेन हादसा हुआ था। यहां तीन ट्रेनें आपस में टकराई थी। इस हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली गई और बहुत से लोग घायल हुए थे। ऐसा ही हादसा आंध्र प्रदेश में भी हुआ था। *-सुशील त्यागी, कांकेर*

करंट अफेयर

आतंकवाद का मुकाबला करने में भारत सबसे आगे

नागरिक विमानन के इतिहास में सबसे जघन्य आतंकवाद से संबंधित हवाई दुर्घटना कनिष्क बम विस्फोट को याद करते हुए वैंकूवर स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारत आतंकवाद की समस्या से निपटने में सबसे आगे है और इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। मॉन्ट्रियल-नयी दिल्ली एअर इंडिया 'कनिष्क' उड़ान संख्या 182 में 23 जून 1985 को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरने से 45 मिनट पहले विस्फोट हो गया, जिससे विमान में सवार सभी 329 लोग मारे गए। इनमें से अधिकांश भारतीय मूल के कनाडाई थे। इस बम विस्फोट का आरोप सिख आतंकवादियों पर लगाया गया था। यह विस्फोट कथित तौर पर 1984 में स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए किए गए 'ऑपरेशन ब्लूस्टार' के प्रतिशोध में किया गया था। भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने बम विस्फोट की बरसी पर एक स्मृति कार्यक्रम की योजना बनाई है। वैंकूवर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने मंगलवार को 'एक्स' पर लिखा, 'भारत आतंकवाद के खतरे का मुकाबला करने में सबसे आगे है और इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है।'

ऑफ बीट

मजे के लिए पक्षियों को तीखे रसायन की तलाश

पक्षियों को विभिन्न कारणों से तीखे रसायनों की तलाश रहती है। कुछ पक्षी सड़े फलों को बड़े चाव से खाते हैं और इसके दुष्परिणाम भुगतते हैं। कुछ पक्षी बदबूदार चींटियों के संपर्क में रहते हैं। ये चींटियाँ उपयोगी रोगाणुरोधी और कीट विकर्षक का उत्पादन करती हैं। हमारे हालिया शोध में, मेरे सहयोगियों और मैंने नॉरफ़ॉक द्वीप के हरे तोतों को शिकार के दौरान अपने पंखों और त्वचा पर काली मिर्च के पेड़ की छाल और कोंपलों लगाते हुए देखा। हमारा मानना है कि यह किसी पक्षी द्वारा परजीवियों से छुटकारा पाने के लिए पौधों के पदार्थ का उपयोग करने का एक दुर्लभ उदाहरण है। लेकिन इसमें और भी कुछ हो सकता है। ऐसा लगता है कि ये पक्षी इस सब में आनंद ले रहे हैं। एक सदी से भी अधिक समय से, वैज्ञानिक चींटी के उद्देश्य पर उलझन में हैं। जब पक्षी इस तरह के व्यवहार में संलग्न होते हैं, तो वे या तो सक्रिय रूप से चींटियों को फैलाते हैं या बस चींटियों को अपने पंखों के माध्यम से चलने देते हैं। बचाव में चींटियाँ फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं। क्या पक्षी इस एसिड से मजा लेते हैं? हो सकता है कि काली मिर्च के पेड़ की छाल का औषधीय प्रभाव भी अधिक हो। इसकी अत्यधिक संभावना है कि ऐसी स्व-चिकित्सा उत्तेजक होती है।

ट्रेंड

प्रतिबद्धता दोहराते हैं

विश्व सिकल सेल दिवस पर, हम इस बीमारी पर काबू पाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। पिछले साल, हमने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया था। हम जागरूकता पैदा करने, सार्वभौमिक जांच, जैसे पहलुओं पर काम कर रहे हैं।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

शिक्षा यात्रा के 23 साल पूरे

15,000 किलोमीटर की देशव्यापी 'शिक्षा यात्रा' के समापन के 23 साल पूरे हो गए हैं। हमने मांग की कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाए। हमारे प्रयासों के परिणामस्वरूप 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया।

-कैलाश सत्यार्थी, नोबेल विजेता

सदन ज़ोर से नहीं चलेगा

कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि सदन का तापमान बढ़ने वाला है। अब सदन जबरन ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं चलेगा। अब 14 मिनट राहुल गांधी के बोलने पर 11 मिनट स्पीकर नहीं दिखाए जाएंगे। मनबढ़ई और तानाशाही का इलाज जनता ने कर दिया।

-सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस नेता

तुरंत सम्मान दें

मेरे गुरु मुझसे कहते हैं, "इस कहावत को स्वीकार न करें कि 'सम्मान अर्जित किया जाता है', बल्कि तुरंत सम्मान दें, और यह व्यक्ति पर निर्भर है कि वह अपने व्यवहार के आधार पर इसे बनाए रखे या खोए।

-हर्ष गोयनका, उद्योगपति

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid https://t.me/AllNewsPaperPaid

Want to get these Newspapers Daily at earliest

1. AllNewsPaperPaid
2. आकाशवाणी (AUDIO)
3. Contact I'd:- https://t.me/Sikendra_925bot

Type in Search box of Telegram
@AllNewsPaperPaid And you will find a
Channel
Name All News Paper Paid Paper join it and
receive
daily editions of these epapers at the earliest

Or you can tap on this link:

https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid